त्रैमासिक
अक्टूबर-दिसम्बर 2003
यह अंक : बीस रुपये

दायित्वबोध

उन बुद्धिजीवियों की पत्रिका जिन्होंने जनता का पक्ष चुना है

डब्ल्यूएसएफ : साम्राज्यवाद का नया ट्रोजन हार्स

डब्ल्यूएसएफ का अर्थशास्त्र और राजनीति

डब्ल्यूएसएफ का नियन्ता कौन?

भूमण्डलीकरण के 'नानाविध विकल्प'

साम्राज्यवाद की हिफाजत में जुटा सामाजिक जनवाद

'भागीदारी जनवाद' की असलियत

कहां से आता है धन

हजारों भागीदार, पर दुश्मन कौन?

सिर्फ मजदूर वर्ग मिटा सकता है पूंजीवादी पिशाच को

उपन्यास अंश 'एक तयशुदा मौत'

वर्ल्ड सोशल फोरम और एन.जी.ओ. की राजनीति पर विशेष अंक

एक नये क्रान्तिकारी नवजागरण–प्रबोधन की मुहिम के सहयात्री बनें!

दायित्वबोध उन बुद्धिजीवियों की एक वैचारिक पत्रिका है जिन्होंने जनता का पक्ष चुना है, जो विश्व ऐतिहासिक विपर्यय एवं पुनरुत्थान के वर्तमान दौर में भी बेहतर भविष्य से नाउम्मीद नहीं हैं, जो इस बेहतर भविष्य को दूर और उसके लिए नये सिरे से लड़ाई की तैयारी को कठिन मानते हुए भी उससे किसी न किसी रूप में अपने को जोड़े हुए हैं और जो क्रान्तियों की नयी श्रृंखला की सर्जना के लिए आज एक नये क्रान्तिकारी वैचारिक–सांस्कृतिक नवजागरण एवं प्रबोधन के महाउद्यम में, जुट जाने के लिए तत्पर हैं।

विगत 9 वर्षों के दौरान इस महाउद्यम के बेहद छोटे अंग के रूप में दायित्वबोध ने अपनी यात्रा जारी रखी है। दायित्वबोध अपने मिशन में किस हद तक सफल रहा है, यह तय करने का काम हम पाठकों पर छोड़ देते हैं। हां, अपने तईं हम लगातार असन्तोष के शिकार रहे हैं कि पत्रिका की सामग्री में विविधता और सृजनात्मकता का उस स्तर का समावेश नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी परिकल्पना में है। बहरहाल, हमारे तईं, यह असन्तोष जारी रहना चाहिए, तभी पत्रिका उत्तरोत्तर अधिक परिपक्व होती जायेगी।

अपनी छोटी से टीम और अनेक प्रकार की तकनीकी दिक्कतों के कारण हम दायित्वबोध को अभी नियमित नहीं कर पा रहे हैं, इसके प्रति हमारा सर्वाधिक असन्तोष है, और जाहिर है पाठकों का भी। चूंकि पूरी टीम प्रत्यक्ष राजनीतिक–सामाजिक–सांस्कृतिक जनकार्रवाइयों में भी भरपूर शिरकत करती है, इसलिए भी अक्सर अंक नियमित करने में दिक्कतें आती हैं। अपने पाठकों–सहयोगियों–शुभचिन्तकों का सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है। लेकिन, अब भी पत्रिका का एक सम्पूर्ण आत्मनिर्भर आर्थिक ताना–बाना नहीं खड़ा हो सका है। पत्रिका को नियमित न बना पाने में यह भी एक अहम कारण रहा है।

इसलिए, पत्रिका को नियमित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रखते हुए इसके आर्थिक ताने–बाने को ज्यादा टिकाऊ स्वरूप देने के लिए हम एक **'विशेष सहभागिता अभियान'** चला रहे हैं। हम अपने सभी पाठकों–सहयोगियों–शुभचिन्तकों से इस अभियान में भरपूर सहयोग की अपील करते हैं। यह सहयोग हमारी मुहिम को जारी रखने में बेहद मूल्यवान होगा।

. . . .

'विशेष सहभागिता अभियान' में आप इस तरह सहयोग कर सकते हैं :

- ⇨ पत्रिका का एक स्थायी कोष बनाने के लिए सहयोग दें।
- ⇨ पत्रिका की आजीवन सदस्यता लें। आजीवन सदस्यता राशि रु. 1000 है।
- ⇨ पत्रिका की वार्षिक सदस्यता लें। वार्षिक सदस्यता रु. 60.00 है (डाक व्यय रु. 12 अतिरिक्त)। अपने मित्रों-सहकर्मियों को भी सदस्यता हेतु प्रेरित करें।
- ⇨ पत्रिका के मद में अपने मित्रों-सहयोगियों से धनराशि एकत्र करें।
- ⇨ पत्रिका के वितरण में हाथ बटायें।
- ⇨ पत्रिका के अंकों पर अपने-अपने क्षेत्रों में चर्चाएं आयोजित करें और इसकी रपट हमें भेजें।
- ⇨ पत्रिका से नियमित संवाद जारी रखने के लिए हमें अपनी बेबाक प्रतिक्रिया-सलाह-सुझाव भेजें।

आप धनराशि मनीऑर्डर अथवा दायित्वबोध के नाम से चेक या ड्राफ्ट (लखनऊ में देय) से भेज सकते हैं।
पता : 29, यू.एन.आई. अपार्टमेंट, जीएच-2, सेक्टर-11, वसुंधरा, गाजियाबाद-201010

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

सम्पादक मण्डल, 'दायित्वबोध'

तमाम चमकीले शब्दों के गुंजलक रचने के बावजूद विश्व सामाजिक मंच के विभिन्न नीति-विषयक दस्तावेजों-घोषणाओं के अध्ययन से इसकी राजनीति और इसके अघोषित उद्देश्य एकदम दिन के उजाले की तरह साफ हो जाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व सामाजिक मंच का उद्देश्य भूमण्डलीकरण की नीतियों का विरोध करना या आज की साम्राज्यवादी दुनिया से भिन्न किसी दूसरी दुनिया के निर्माण के लिए दुनिया की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी को किसी एक मोर्चे के तहत लामबन्द और संगठित करना नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष को संगठित होने व आगे बढ़ने से रोकना है, उसे दिग्भ्रमित और विखण्डित करना है। ...विश्व सामाजिक मंच के साझा विरोध की रणनीति के सम्बन्ध में, हमारी पहली स्पष्ट धारणा यह है कि यह स्पष्टतः सिर्फ एक मुद्दे पर केन्द्रित होनी चाहिये और वह हैसाम्राज्यवाद के एक 'सेफ्टी वाल्व' और 'ट्रोजन हॉर्स' के रूप में काम करने वाले विश्व सामाजिक मंच के चरित्र, संरचना और वर्ग सहयोगवादी राजनीति के व्यापकतम सम्भव 'एक्सपोजर' के लिए प्रचार और एजिटेशन का एक ठोस कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे अमल में लाना। विश्व सामाजिक मंच की राजनीति को समग्रता में 'एक्सपोज' किया जाना चाहिये। विश्व सामाजिक मंच जिस तरह वर्ग-विभेद के प्रश्न को ओझल करके मुद्दों को वर्गेतर आधार पर खण्ड-खण्ड में बांटकर विमर्श आयोजित करता है, यदि हम भी अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति के लिए विषय-विभाजन के उसी फ्रेमवर्क को कमोबेश स्वीकार करेंगे तो हम विरोधी के 'ट्रैप' में ही उलझ जायेंगे, समाजवाद को एकमात्र विकल्प बताते हुए भी बात बिखर जायेगी और एक अकादमिक कसरत बन कर रह जायेगी तथा विश्व सामाजिक मंच के 'एक्सपोजर' और उसके विरुद्ध जनमानस तैयार करने का कार्यभार प्रभावी ढंग से नहीं हो सकेगा।

इस अंक में

अपनी बात

विश्व सामाजिक मंच : साम्राज्यवाद का नया 'ट्रोजन हॉर्स' 5

वर्ल्ड सोशल फोरम पर एक परिसंवाद (सिम्पोज़ियम)

राज्यवर्ग विरोधों की असाध्यता की उपज लेनिन 22

वर्ल्ड सोशल फोरम का अर्थशास्त्र और राजनीति आस्पेक्ट्स आफ इंडियाज इकोनामी 23

डब्ल्यूएसएफ, एनजीओ और हमारा दृष्टिकोण एआईपीआरएफ 40

वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा प्रस्तुत भूमण्डलीकरण के 'नानाविध विकल्प' पी.जे. जेम्स 52

हजारों भागीदार, पर दुश्मन कौन? जूलियो टुरा 55

विश्व सामाजिक मंच के सम्बन्ध में कुछ सवाल प्रतिरोध के स्वर 56

मदर्स ऑफ प्लाजा डि मेयो का वक्तव्य 60

डब्ल्यूएसएफ : साम्राज्यवाद का नया मोहरा युवाभारत 61

वर्ल्ड सोशल फोरम : व्यवस्था की सेवा में जुटा सामाजिक जनवाद 70

केवल मजदूर वर्ग ही पूंजीवाद के पिशाच का खात्मा कर सकता है 71

अनुत्तरित प्रश्न फर्मिन गोंजालेज 74

यूरोपीय सोशल फोरम का नियंता कौन? 76

पोर्तो अलेग्रे 2002 : दो सम्मेलनों का सच जेम्स पेत्रास 78

पोर्तो अलेग्रे2 के प्रतिनिधियों की एक बानगी 81

भागीदारी बजट : राज्यतंत्र का हिस्सा बना लेने की प्रक्रिया एलन बेंजामिन 82

ट्रेड यूनियन सोलिडेरिटी कमेटी, मुंबई द्वारा डब्ल्यूएसएफ के भारतीय आयोजकों को भेजा पत्र 84

उपन्यास अंश

एक तयशुदा मौत मोहित राय 86

कविता

भिखमंगे! 89

परिशिष्ट

साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता 91

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण एवं युद्ध के खिलाफ मुम्बई प्रतिरोध 2004 क्यों 93

वर्ल्ड सोशल फोरम का चार्टर 94

वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए धन कहाँ से आया 95

"पूँजीपति वर्ग का एक हिस्सा समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, जिससे कि पूँजीवादी समाज को बरकरार रखा जा सके।
"अर्थशास्त्री, दानवीर, मानवतावादी, श्रमजीवी वर्गों के जीवन-यापन की अवस्थाओं के सुधारक, खैरात बाँटने के प्रबंधकर्ता, पशु रक्षा समितियों के सदस्य, शराबबंदी के कट्टर समर्थक, प्रत्येक कल्पनीय प्रकार के छोटे-मोटे सुधारकसभी इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इस तरह के समाजवाद का पूरी की पूरी पद्धतियों के रूप में विशदीकरण किया गया है।"

कम्युनिस्ट घोषणापत्र से

दायित्वबोध

वर्ष–10 अंक–2
अक्टूबर–दिसम्बर 2003

सम्पादक मण्डल
विश्वनाथ मिश्र
अरविन्द सिंह

आवरण एवं सज्जा
रामबाबू

सम्पादकीय कार्यालय :
29, यू.एन.आई. अपार्टमेंट, जीएच-2
सेक्टर-11, वसुंधरा, गाजियाबाद-201010
फोन : (0120) 3096414

ईमेल : **dayitvabodh@rediffmail.com**

एक प्रति : 15 रुपये / यह अंक : 20 रुपये
वार्षिक : 60 रुपये (डाक व्यय 15 रुपये अतिरिक्त)
आजीवन : 1000 रुपये

●

सम्पादन एवं संचालन
पूर्णतः अवैतनिक एवं अव्यावसायिक
कम्पोजिंग : **कम्प्यूटर प्रभाग,**
राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ-226 010

स्वत्वाधिकारी विश्वनाथ मिश्र द्वारा एम. आई.जी. 134, राप्तीनगर फेज-एक, गोरखपुर से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा आफसेट प्रेस, नखास, गोरखपुर से मुद्रित

अपनी बात

विश्व सामाजिक मंच : साम्राज्यवाद का नया 'ट्रोजन हॉर्स'

विश्व सामाजिक मंच (वर्ल्ड सोशल फोरम) का चौथा वार्षिक सत्र आगामी 16 जनवरी से 21 जनवरी 2004 तक मुंबई में होने जा रहा है। फोरम का यह सालाना जलसा वर्ष 2001 से हर वर्ष जनवरी के महीने में ब्राजील की एक प्रान्तीय राजधानी पोर्तो अलेग्रे में हुआ करता था, जहाँ इसका जन्म हुआ था। अब पहली बार यह आयोजन अन्यत्र हो रहा है।

सुदूर दक्षिणी अटलांटिक तट से अरब सागर के गर्म किनारे आते-आते वे सारे मुद्दे और सवाल पूरी तरह गरमा उठे हैं, जो विश्व सामाजिक मंच के जन्म के समय से ही इस या उस संगठन या आन्दोलन द्वारा उठाये जाते रहे हैं। आज इस मंच की चर्चा और प्रभाव जितना विश्वव्यापी है, इसका विरोध भी उतना ही विश्वव्यापी है।

कहने को यह मंच भूमण्डलीकरण और नवउदारीकरण के विरोध, एक मानवकेन्द्रित विश्व के निर्माण, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों, पर्यावरण-सुरक्षा आदि के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा करता है। साथ ही यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि यह किसी किस्म की साझा कार्रवाई का मोर्चा या संगठन न होकर केवल विचार-विमर्श और उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर सक्रिय संगठनों/आन्दोलनों के बीच समन्वय-सामंजस्य स्थापित करने का काम करेगा। तब यहीं यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठ खड़ा होता है कि विश्व सामाजिक मंच की राजनीति क्या है, इसकी संरचना और कार्य-प्रणाली क्या है, इसके स्रोत-संसाधन कहाँ से आते हैं और यह कि आखिरकर भूमण्डलीकरण का, साम्राज्यवाद की वर्तमान नीतियों-रणनीतियों का विरोध यह मंच किस प्रकार करेगा? विश्व सामाजिक मंच का नारा है, 'एक दूसरी दुनिया संभव है' ('अनदर वर्ल्ड इस पॉसिबल')। यह दूसरी दुनिया कैसे सम्भव है और इसका स्वरूप क्या होगा?

विश्व सामाजिक मंच का उद्देश्य भूमण्डलीकरण की नीतियों का विरोध करना या आज की साम्राज्यवादी दुनिया से भिन्न किसी दूसरी दुनिया के निर्माण के लिए दुनिया की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी को किसी एक मोर्चे के तहत लामबन्द और संगठित करना नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष को संगठित होने व आगे बढ़ने से रोकना है, उसे दिग्भ्रमित और विखण्डित करना है।

तमाम चमकीले शब्दों के गुंजलक रचने के बावजूद विश्व सामाजिक मंच के विभिन्न नीति-विषयक दस्तावेजों-घोषणाओं के अध्ययन से इसकी राजनीति और इसके अघोषित उद्देश्य एकदम दिन के उजाले की तरह साफ हो जाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व सामाजिक मंच का उद्देश्य भूमण्डलीकरण की नीतियों का विरोध करना या आज की साम्राज्यवादी दुनिया से भिन्न किसी दूसरी दुनिया के निर्माण के लिए दुनिया की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी को किसी एक मोर्चे के तहत लामबन्द और संगठित करना नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष को संगठित होने व आगे बढ़ने से रोकना है, उसे दिग्भ्रमित और विखण्डित करना है। यह राजनीतिक उद्यम वस्तुतः विश्व-पूँजीवाद की आन्तरिक प्रणाली ('इंटरनल मैकेनिज्म') का ही एक जरूरी अवयव है, जिसे वित्तीय पूँजी के भूमण्डलीकरण की जारी परिघटना की अपनी स्वतंत्र गति से पैदा होने वाली विस्फोटक सामाजिक स्थितियों को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के उद्देश्य से एक प्रतिसन्तुलनकारी शक्ति के रूप में साम्राज्यवाद के दूरदर्शी नीति निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और फोर्ड फाउंडेशन, आक्सफेम, हाइनरिख बोल फाउंडेशन, ऐक्शन एड आदि उन शीर्ष नीति-निर्धारक संस्थाओं द्वारा संघटित किया गया है, जो विश्वस्तर पर जनसंघर्षों एवं क्रान्तियों को रोकने व तोड़ने के लिए विगत आधी सदी से नीतियाँ बनाती रही हैं और फिर उनके क्रियान्वयन के लिए, खासतौर पर गैर-सरकारी संगठनों के जरिये धन मुहैया कराती रही हैं।

दरअसल क्रान्तियों और वर्ग संघर्षों के शताब्दियों लम्बे इतिहास से शासक पूँजीपति वर्ग ने भी काफी कुछ सीखा है। वह जानता है कि पूँजी का स्वतंत्र तर्क यदि निर्बाध रूप में काम करे तो पूँजीपति लोगों की हड्डियों का पाउडर बनाकर बाजार में खुलेआम बेचेंगे, लुटेरे साम्राज्यवादी कुत्तों की तरह लूट के

माल के बँटवारे के लिए लड़ेंगे और पूरी दुनिया की जनता तब इस लूट के विरुद्ध जल्दी ही सड़कों पर उतर पड़ेगी और पूँजीवादी व्यवस्था को मिट्टी में मिला देगी। पूरी दुनिया के पूँजीवादी सिद्धांतकर, पार्टियाँ और राज्यसत्ताएँ इसी कारण से पूँजीवादी ढाँचे को बनाये रखने के लिए पूँजी की स्वतंत्र आंतरिक गति की राह में तरह-तरह के स्पीड ब्रेकर्स बनाती हैं, सामाजिक अंतरविरोधों को तीखा होने से रोकती हैं और तरह-तरह के छद्मावरणों से उसके असली चरित्र पर पर्दा डालने की हरचंद कोशिशें करती हैं। वे जनता की फौरी माँगों के समक्ष एक हद तक झुकती भी हैं तथा बुर्जुआ जनवाद के तमाम वैधिक विभ्रमों को आखिरी सम्भव हद तक (यानी तब तक, जब तक कि व्यवस्था के अपरिहार्य संकटों और वर्ग संघर्ष का दबाव पूँजीपति वर्ग को नग्न-निरंकुश वर्ग-अधिनायकत्व की स्थापना के लिए विवश न कर दे) बनाये रखना चाहती हैं। दबाव को कम करते रहने के लिए तरह-तरह के 'सेफ्टी वाल्व' बनाये जाते हैं, व्यवस्था की हिफाजत के लिए दूसरी-तीसरी सुरक्षा पंक्तियाँ खड़ी की जाती हैं, जनसंघर्षों को दिग्भ्रमित एवं विघटित करने के लिए नेतृत्व के भीतर के पतित और कमजोर तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और जनता के बीच तरह-तरह के 'ट्रोजन हॉर्स' अलग-अलग तरीकों से भेजे जाते हैं। विश्वस्तर पर या किसी देश के स्तर पर जन-प्रतिरोध व्यवस्था के दायरे के बाहर न संगठित होने पाये, इसके लिए शासक वर्ग के नीति-निर्धारक हमेशा ही, व्यवस्था के दायरे के भीतर, प्रतिसन्तुलनकारी शक्ति के रूप में एक विरोध-पक्ष की रचना करते हैं। स्पष्ट चरित्र वाली बुर्जुआ पार्टियाँ जब निष्प्रभावी हो जाती रही हैं, तो पूरी दुनिया की संसदीय जनवादी व्यवस्थाओं में समाजवाद का नाम लेने वाली सामाजिक जनवादी पार्टियाँ तथा मार्क्सवाद और क्रान्ति का रट्टा लगाते हुए संसद में बहसबाजी करने वाली संशोधनवादी पार्टियाँ विरोध का मिथ्याभास रचने की, जनता में झूठी उम्मीदें पैदा करने और फिर उसे निराश एवं दिग्भ्रमित करने की तथा उसके विरोध को व्यवस्था की चौहद्दी में कैद रखने के लिए सुधारों के टुकड़ों-पैबन्दों की माँग करते रहने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हैं। ट्रेड यूनियन संघर्षों में मजदूरों को महज आर्थिक माँगों एवं सुधारों तक सीमित रखने और राजनीतिक संघर्षों से उन्हें दूर रखते हुए, अर्थवाद के द्वारा भी संसदीय वामपन्थी पार्टियाँ इसी काम को अंजाम देती हैं।

विश्व सामाजिक मंच भी वास्तव में विश्व-पूँजीवाद का एक ऐसा ही 'सेफ्टी वाल्व' है। यह साम्राज्यवाद का एक नया 'ट्रोजन हॉर्स' है। इसका मूल उद्देश्य भूमण्डलीकरण-कुचक्र के लाजिमी नतीजे के तौर पर तीखे होते जा रहे वर्ग-अंतरविरोधों की आँच पर पानी के छींटें मारना है, विशेषकर एशिया-अफ्रीका-लातिन अमेरिका के देशों में फिर से उग्र होते जा रहे वर्ग-संघर्षों की गति को रोकना है, जनता के संघर्षों को द्वितीयक महत्व के या गौण मुद्दों पर खड़ा करके तथा खण्ड-खण्ड में बाँटकर वर्गीय एकजुटता की प्रक्रिया को बाधित करना है और उन्हें सुधारवाद के दलदल में धँसा देना है। इसका उद्देश्य भूमण्डलीकरण का विरोध करना नहीं बल्कि "मानवीय चेहरे" वाले भूमण्डलीकरण की वकालत करना है, वित्तीय पूँजी के बेरोकटोक प्रवाह पर कुछ अंकुश लगाकर, विशेषकर उड़नछू पूँजी या सट्टा पूँजी के कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले विस्फोटक विनाशकारी प्रभावों की गति को मद्धम करना है और इस तरह एक हद तक 'स्पीड ब्रेकर' का काम करना है।

स्पष्ट चरित्र वाली बुर्जुआ पार्टियाँ जब निष्प्रभावी हो जाती रही हैं, तो पूरी दुनिया की संसदीय जनवादी व्यवस्थाओं में समाजवाद का नाम लेने वाली सामाजिक जनवादी पार्टियाँ विरोध का मिथ्याभास रचने की तथा जनता के विरोध को व्यवस्था की चौहद्दी में कैद रखने के लिए सुधारों के टुकड़ों-पैबन्दों की माँग करते रहने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हैं।

शामिल कौन हैं और पैसा कौन दे रहा है?

विश्व सामाजिक मंच की संरचना और कार्य-प्रणाली की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे विश्लेषण से पहले ही, यदि महज यह जान लिया जाये कि इस मंच के संघटक संगठन कौन हैं और इसका वित्त-पोषण कौन कर रहे हैं तो इसके चरित्र को लेकर भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। विश्व सामाजिक मंच के आधे से अधिक संगठन साम्राज्यवादी पैसे से संचालित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हैं और इसके खुले वित्तपोषकों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दाता कुख्यात फोर्ड फाउण्डेशन है। इसके बाद आक्सफेम और हाइनरिख बोल फाउण्डेशन और ऐक्शन एड जैसी सबसे बड़ी फण्डिंग एजेंसियों का नम्बर आता है। विभिन्न चैनलों से विश्व बैंक, फ्रांस, ब्राजील की और अन्य देशों की सरकारों का पैसा और दर्जनों अन्य फण्डिंग एजेंसियों का पैसा भी मंच को मिल रहा है। गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त मंच में शामिल दूसरी श्रेणी दुनियाभर के किसिम-किसिम की सामाजिक जनवादी पार्टियों और संसदीय वामपंथी/संशोधनवादी पार्टियों से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों की है। ये सामाजिक जनवादी और संशोधनवादी निजीकरण-उदारीकरण के इस दौर में महज 'पब्लिक सेक्टर' को बचाने की गुहार लगाते हुए और "बाजार समाजवाद" की जुगाली करते हुए भूमण्डलीकरण-कुचक्र का भागीदार बनते हुए जनता की नजरों में इस कदर नंगे हो चुके हैं कि व्यवस्था की दूसरी सुरक्षा-पंक्ति के रूप में प्रभावी होने की क्षमता काफी हद तक खो चुके हैं। इस स्थिति में, प्रासंगिक बने रहने का इनके सामने यही रास्ता बचा था कि

एनजीओ के साथ "पवित्र गठबन्धन" बनाकर विश्वस्तर पर साम्राज्यवाद की नयी, दूसरी सुरक्षा-पंक्ति के निर्माण में भागीदार बन जायें। गैर सरकारी संगठनों से ही मिलती-जुलती एक तीसरी श्रेणी "नये सामाजिक आन्दोलनों" ('न्यू सोशल मूवमेंट्स'एनएसएम) और "नागरिक समाज" (सिविल सोसायटी) के संगठनों की है, जो बाँध, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों को अलग-थलग रूप में उठाकर आन्दोलन करते हैं, या दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों, बंधुआ या बाल मजदूरों आदि के मसलों को समाज की वर्गीय संरचना से या वर्गीय उत्पीड़न से काटकर स्वतंत्र-स्वायत्त रूप में उठाते हैं तथा मानवाधिकारों, भागीदारी जनतंत्र, भागीदारी बजट आदि की बातें करते हैं। ये जनान्दोलन वर्गीय आधार पर आर्थिक-राजनीतिक आन्दोलनों से अलग-थलग रहते हुए जनता की वर्गीय चेतना को कुंद करते हैं, राजनीति और राज्यसत्ता के प्रश्न को हाशिये पर धकेलकर उसका विराजनीतिकरण (डीपोलिटिसाइजेशन) करते हैं और जनता की वर्गीय एकजुटता को खण्ड-खण्ड में बाँटने का काम करते हैं। संघर्ष के मुद्दों को स्थानीयकृत और स्वायत्त बनाते हुए ये संगठन सामाजिक क्रान्ति के सर्वसमावेशी चरित्र को और राज्यसत्ता के केन्द्रीय प्रश्न को दृष्टिओझल कर देते हैं। एक चौथी श्रेणी, निस्सन्देह थोड़े से क्रान्तिकारी वामपंथियों की भी है, जो अपने वैचारिक अधकचरेपन और दक्षिणपंथी अवसरवादी भटकावों के कारण, कुछ मतभेदों के बावजूद विश्व सामाजिक मंच में बने हुए हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि वे मंच के विमर्शों में हिस्सा लेकर बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर लेंगे, साम्राज्यवादी एजेण्टों को 'एक्सपोज' और अलग-थलग कर देंगे या "भीतर से संघर्ष करके" मंच को सही पटरी पर ला देंगे। ऐसे लोगों का विश्व सामाजिक मंच में होना वस्तुतः मंच के निर्माताओं-सूत्रधारों की रणनीति की सफलता ही है। ये अधकचरे या भटकावग्रस्त वामपंथी हालांकि कुछ ही हैं, पर वे शत्रु के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता।

विश्व सामाजिक मंच की संरचना और कार्यप्रणाली की चर्चा से पहले इसके निर्माण की पृष्ठभूमि को भी संक्षेप में जान लेना जरूरी है, क्योंकि इससे भी चीजों को समझने में मदद मिलेगी।

कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला और कैसे आगे बढ़ा?

विश्व सामाजिक मंच जैसे किसी मंच की सोच का जन्म फ्रांसीसी और ब्राजीली सामाजिक जनवादियों एक गँठजोड़ में ढूँढ़ा जा सकता है। इस गँठजोड़ के पीछे, सामाजिक जनवाद की एक साझा जमीन के अतिरिक्त, दोनों ही पक्षों के अपने-अपने कारण थे। नब्बे के दशक के मध्य में फ्रांसीसी पब्लिक सेक्टर के संकट ने फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों को विवश किया कि वे सामाजिक जनवादी मुँह से गुहार लगायें और अमेरिकी चौधराहट का परोक्ष प्रतिकार करते हुए निजीकरण-उदारीकरण की रफ्तार को कुछ नियंत्रित करने के लिए "मानवीय चेहरे वाले भूमण्डलीकरण" के नारे को कुछ बल देने का काम करें। 1997 में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के संकट के विस्फोट के चलते विश्वस्तर पर, उदारीकरण की गति को कुछ हद तक नियंत्रित-विमंदित करने की जरूरत शासक वर्गों के सफों में भी तेजी से महसूस की जाने लगी थी। राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सीमान्तों का तेज संकुचन तीसरी दुनिया के देशों के शासक बुर्जुआ वर्गों को भी इस माँग पर बल देने के लिए विवश कर रहा था। निजीकरण -उदारीकरण इन देशों के शासक वर्गों की जरूरत और विवशता दोनों थी (और है), पर वे भरसक उसी नियंत्रित रफ्तार के हामी थे, जिससे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले उन देशों में सामाजिक विस्फोट की स्थिति न उत्पन्न हो जाये। साथ ही, अधिशेष-विनियोजन में अपनी हिस्सेदारी की यथासम्भव हिफाजत की नीयत से भी वे अपने बाजारों को एकदम से खोल देने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। ब्राजील उन पिछड़े देशों में सबसे आगे था जहां भूमण्डलीकरण-कुचक्र के दुष्परिणाम सबसे पहले सामने आये। अपने-अपने कारणों से फ्रांसीसी शासक वर्ग और ब्राजीली शासक वर्ग ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों और काफी हद तक उनके प्रभाव से संचालित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की संरचनागत समायोजन की नीतियों पर अंधाधुंध अमल का विरोध किया। फ्रांसीसी और ब्राजीली सामाजिक जनवादियों के बीच की वक्ती एकता की यही जमीन थी। फ्रांसीसी मासिक पत्रिका '*ल मोंद दिप्लोमातीक*' ने दिसम्बर, 1997 में अपने सम्पादकीय में यह प्रस्ताव रखा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाहों पर नियंत्रण के लिए एक विश्वव्यापी आन्दोलन संगठित किया जाना चाहिये। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य सट्टा पूँजी की उस अनियंत्रित आकस्मिक आवाजाही पर लगाम लगाना था जो विश्व बाजार में अस्थिरता, पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं के सहसा ध्वंस, और परिणामतः जनविद्रोहों या व्यापक जनउभारों का खतरा पैदा कर रही थी। इससे भूमण्डलीकरण की जारी प्रक्रिया को ही खतरा हो सकता था। यह सब साम्राज्यवादियों के लिए खतरनाक था। अमेरिकी तंत्र के थिंक टैंक भी इस पर सोच रहे थे। नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टॉबिन सट्टेबाजी वाले वित्तीय लेन-देन पर कर लगाने का प्रस्ताव पहले ही रख चुके थे, जिसका उल्लेख आज टॉबिन टैक्स के नाम से किया जाता है। '*ल मोंद*

सिएटल की घटना ने अमेरिका और पूरे पश्चिम के साम्राज्यवादियों को इस मसले पर सोचने की आसन्नता महसूस करायी कि भूमण्डलीकरण की नीतियों के स्वतःस्फूर्त जन-विरोध को पालतू बनाने और समायोजित करने के लिए, मौजूदा विश्व-व्यवस्था के दायरे के भीतर एक विरोध-पक्ष संगठित करना, विरोधी स्वर के लिए एक चैनल बनाना और एक 'सेफ्टी वॉल्व' बनाना जरूरी है।

दिप्लोमातिक' के सम्पादक ने अपने प्रस्तावित आन्दोलन का नाम सुझायाः *'एसोसिएशन फॉर द टॉबिन टैक्स इन एड ऑफ दि सिटीजन्स'* जिसे लघु रूप में *'अटैक'* (ATTAC) कहा गया और यही नाम आज चलन में है।

'अटैक' ने अपने प्रारम्भिक अभियान दावोस में *विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम)* के सालाना आयोजनों के मौकों पर चलाये। लेकिन उसके नेतागण यह भी नहीं चाहते थे कि उनके लोकरंजक नारों से प्रभावित होकर भूमण्डलीकरण-विरोधी आम आबादी भारी संख्या में आ जुटे और विश्व आर्थिक मंच की बैठक ही मुश्किल हो जाये। 1999 में विश्व व्यापार संगठन की सिएटल में हो रही मंत्रिस्तरीय बैठक के समय जबर्दस्त आन्दोलन और सड़कों पर झड़प की जो स्थिति पैदा हो गयी, उससे उनकी आशंकाओं को और अधिक बल मिला। सिएटल में भूमण्डलीकरण की नीतियों में सुधार और पैबन्द की माँग करने वाले भाँति-भाँति के सामाजिक जनवादियों, ट्रेड यूनियन के अर्थवादी नेताओं, पर्यावरणवादियों, बुर्जुआ चरित्र के नागरिक अधिकार आन्दोलनकर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के लोगों के साथ ही अप्रत्याशित रूप से अमेरिका के अश्वेत एवं आप्रवासी मजदूर, बेरोजगार युवा और दूसरे देशों से गये ऐसे लोग भी उमड़ पड़े थे जो विश्व व्यापार संगठन के स्वरूप और प्रस्तावों का विरोध कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप की क्रान्तिकारी वाम राजनीति की धाराओं से प्रभावित एक छोटी सी आबादी भी इसमें शामिल थी। सिएटल की घटना ने अमेरिका और पूरे पश्चिम के साम्राज्यवादियों को इस मसले पर सोचने की आसन्नता महसूस करायी कि भूमण्डलीकरण की नीतियों के स्वतःस्फूर्त जन-विरोध को पालतू बनाने और समायोजित करने के लिए, मौजूदा विश्व-व्यवस्था के दायरे के भीतर एक विरोध-पक्ष संगठित करना, विरोधी स्वर के लिए एक चैनल बनाना और एक 'सेफ्टी वॉल्व' बनाना जरूरी है। भूमण्डलीकरण के आर्थिक नीति-निर्माताओं और सिद्धान्तकारों का हिस्सा वित्तीय पूँजी के निर्बाध स्वतः प्रवाह के रास्ते में कुछ स्वचालित ब्रेकों और स्पीडब्रेकरों वाली आन्तरिक प्रणाली पर पहले से ही बल दे रहा था। अस्सी के दशक से ही, तीसरी दुनिया के देशों में साम्राज्यवादी वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। जाहिर था कि जब इसी उद्देश्य से कोई विश्व मंच बनाया जाता तो उसके सबसे उपयोगी और विश्वसनीय संघटक वे ही बनते। उधर, सामाजिक जनवादियों और संसदीय वाममार्गियों की पूँजीवादी व्यवस्था की दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में निष्ठा, विश्वसनीयता और उपयोगिता पूरी बीसवीं सदी के दौरान, बार-बार, हर बार, पूरी तरह सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन सोवियत संघ के पतन और नकली समाजवाद के पतन के बाद उनका सामाजिक आधार काफी संकुचित हो चुका था। उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों ने आर्थिक संघर्षों की गुंजाइशों को पहले हमेशा से अधिक कम कर दिया था और संशोधनवादी अब छोटे-मोटे आर्थिक आन्दोलनों को भी रैडिकल तेवर देने की क्षमता खो चुके थे। यूरोप के देशों से लेकर भारत और लातिन अमेरिकी देशों तक में सत्ता में भागीदारी करते हुए सभी जनविरोधी नयी आर्थिक नीतियों को लागू करने की उनकी विवशता ने उन्हें जनता की नजरों में काफी नंगा कर दिया था और "बाजार समाजवाद" टाइप उनके नारों को भी। अब पुनःसंस्कार किये बिना उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जा सकता था। विश्व सामाजिक मंच के फोरम पर सामाजिक जनवाद के ऐसे पुनः संस्कार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम स्वयंसेवी संगठनों, "नये सामाजिक आन्दोलनों" और तथाकथित "नागरिक समाजों" (सिविल सोसायटीज-स्वयंसेविता प्रायोजित जनसंगठनों का नया नामकरण) के साथ सामाजिक जनवादी और संशोधनवादी पार्टियों के जनसंगठनों का गठबंधन कायम करके संपन्न किया गया। सिएटल के बाद 2000 में 'अटैक' के नेतृत्व की ब्राजील की सामाजिक जनवादी पार्टी-ब्राजीली वर्कर्स पार्टी के साथ बातचीत हुई और आनन-फानन में विश्व सामाजिक मंच की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी। ब्राजील में उस समय भूमण्डलीकरण के विरोध में गरमा-गरम लोकरंजक बातें करते हुए वर्कर्स पार्टी और उसके नेता लूला ने (जो आज ब्राजील का राष्ट्रपति है) तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी। रियो ग्रांदे दो सुल प्रान्त में इसी पार्टी की सरकार थी और इसकी राजधानी पोर्तो अलेग्रे का नगर प्रशासन भी इसी के हाथों में था। विश्व सामाजिक मंच के नियमित सालाना जलसे के लिए पोर्तो अलेग्रे सर्वथा अनुकूल था। छह महीने के भीतर मंच की रूपरेखा तैयार हो गयी। 'अटैक' और ब्राजीली वर्कर्स पार्टी के अतिरिक्त दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक जनवादियों के नेतृत्व वाले जनसंगठन इसमें शामिल हो गये और जनवरी 2001 में इसका पहला वार्षिक आयोजन हुआ। यह पहले ही तय किया गया था कि यह आयोजन हर वर्ष तभी हुआ करेगा जब दावोस में विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग चल रही हो।

विश्व सामाजिक मंच को विश्व पूँजीवादी तंत्र की बुनियाद पर चोट करने वाले खतरों को रोकने के लिए एक आन्तरिक अवरोधन-प्रणाली, एक प्रतिसन्तुलनकारी शक्ति और एक 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में संगठित किया गया है। मूलतः इसका काम विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के एक पूरक की भूमिका निभाना है।

इस तरह, विश्व सामाजिक मंच के उद्भव की कहानी ही इसके उद्देश्य को दिन के उजाले की तरह साफ कर देती है। फ्रांसीसी सरकार और बुर्जुआ वर्ग के पैसे से वहां के सामाजिक जनवादियों द्वारा गठित 'अटैक' और ब्राजील वर्कर्स पार्टी के सामाजिक जनवादियों के गँठजोड़ ने जो खिचड़ी पकायी, उसका

वास्तविक उद्देश्य भूमण्डलीकरण का विरोध करते हुए कोई विकल्प प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि भूमण्डलीकरण के चेहरे को "मानवीय" बनाना है, साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी जनता के संघर्षों को ऐक्यबद्ध करने के बजाय उन्हें खण्ड-खण्ड में बाँटकर विघटित कर देना, जनता की मुखर होती वर्ग-चेतना को कुंद कर देना, उसका विराजनीतिकरण कर देना और वैकल्पिक कार्यक्रम देने के नाम पर संघर्ष के प्रश्न को अकर्मक विमर्श की चौहद्दी में बांधकर निराशा और विकल्पहीनता का माहौल तैयार करना है। विश्व सामाजिक मंच को विश्व पूँजीवादी तंत्र की बुनियाद पर चोट करने वाले खतरों को रोकने के लिए एक आन्तरिक अवरोधन-प्रणाली, एक प्रतिसन्तुलनकारी शक्ति और एक 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में संगठित किया गया है। मूलतः इसका काम विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के एक पूरक की भूमिका निभाना है। आश्चर्य नहीं कि इसके पहले आयोजन से ही साम्राज्यवादी धन से सुधारवादी कार्रवाइयों में लिप्त गैर सरकारी संगठन ही इसके आधे से अधिक घटक हैं और नीति-निर्धारक निकायों की कमान पूरी तरह से उनके हाथों में है।

गैर सरकारी संगठनों के बारे में 'दायित्वबोध' में पहले भी काफी सामग्री दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इनके उद्देश्य राजनीति और चरित्र के बारे में तथा इनके इतिहास के बारे में संक्षिप्त चर्चा यहां जरूरी है, ताकि विश्व सामाजिक मंच की असलियत को जानने में कोई कोर-कसर नहीं रह जाये।

क्या हैं, कैसे और क्यों पैदा और विकसित हुए और क्या करते हैं गैर-सरकारी संगठन?

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखें तो गैर सरकारी संगठनों की सुधारवादी राजनीति हमें पूँजीवाद के जन्मकाल से ही देखने को मिलेगी। मार्क्स और एंगेल्स ने 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' में ही इसका स्पष्ट उल्लेख इस रूप में किया थाः

"पूँजीपति वर्ग का एक हिस्सा समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, जिससे कि पूँजीवादी समाज को बरकरार रखा जा सके।

"अर्थशास्त्री, दानवीर, मानवतावादी, श्रमजीव वर्गों के जीवन-यापन की अवस्थाओं के सुधारक खैरात बाँटने के प्रबंधकर्ता, पशु रक्षा समितियों के सदस्य, शराबबंदी के कट्टर समर्थक, प्रत्येक कल्पनीय प्रकार के छोटे-मोटे सुधारक-सभी इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इस तरह के समाजवाद का पूरी की पूरी पद्धतियों के रूप में विशदीकरण किया गया है।"

इस किस्म के पूँजीवादी समाजवादी चिंतन के आधार पर उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में बहुतेरी ऐसी संस्थाए-समितियां कार्यरत थीं जो उत्पादन के पूँजीवादी सम्बंधों को समाप्त करने के बजाय मात्र राजनीतिक सुधारों द्वारा मेहनतकश जनता की भौतिक अवस्थाओं के सुधार को ही वांछनीय और व्यावहारिक बताती थीं। वह महज ऐसे प्रशासकीय सुधारों की बात करती थीं *"जो किसी हालत में पूँजी और श्रम के सम्बन्धों में परिवर्तन नहीं लाते और ज्यादा से ज्यादा पूँजीवादी सरकार का प्रशासन-खर्च कम कर देते हैं और उसके प्रशासकीय कार्यों को कुछ सरल बना देते हैं"* (कम्युनिस्ट घोषणापत्र)। ऐसी संस्थाओं को पूँजीपतियों और चर्च से मुक्तहस्त सहायता मिला करती थी।

तीसरी दुनिया के देशों में बाजार के विकास एवं विस्तार के लिए कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम करा लेने के चलते स्वयंसेविता का "थर्ड सेक्टर" अतिशय लाभ देने वाला सेक्टर बन गया। व्यवस्था के पायों और आधार को मजबूती देने वाले राजनीतिक उपकरण के साथ ही यह पूँजीवादी उत्पादन तंत्र का एक महत्वपूर्ण सेक्टर भी बन गया।

ऐसी संस्थाओं की उपयोगिता बुर्जुआ वर्ग के सिद्धान्तकारों और बुर्जुआ राजसत्ता ने भली-भाँति महसूस की और उपनिवेशों में इनकी एक सर्वथा नयी उपयोगिता भी ढूंढ निकाली। एशिया-अफ्रीका-लातिन अमेरिका के उपनिवेशों में काम करने वाले विभिन्न किस्म के चैरिटी संगठन, जिसमें चर्च की मिशनरी संस्थाएं प्रमुख थीं, तब एनजीओ के मुख्य रूप बनकर उभरे। सुधार कार्यों, शिक्षा और धर्म प्रचार की आड़ में उपनिवेशवादी शक्तियों की संस्कृति और मूल्यों का प्रचार करना, जनता में उनका सामाजिक आधार और सामाजिक अवलम्ब (सोशल प्रॉप्स) तैयार करना तब ऐसे संगठनों का प्रमुख काम था। ऐसे पुराने किस्म के चैरिटी संगठन आज भी मौजूद हैं और ज्यादातर अपने रूप बदलकर उसी काम में लगे हुए हैं, जिसे आधुनिक गैर सरकारी संगठन अंजाम दे रहे हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध और अक्तूबर क्रान्ति के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने प्राकृतिक आपदा और युद्ध के विनाश की स्थिति में राहत कार्य के "मानवतावादी सत्कर्म" की आड़ लेकर एनजीओ के धंधे में हाथ डाला। प्रत्यक्ष हमला, घुसपैठ और तोड़-फोड़ के जरिये सोवियत संघ में समाजवाद को तबाह करने में विफलता के बाद अमेरिका ने राहत कार्य को हथियार बनाया। सोवियतसंघ में 1921 के अकाल के दौरान मुख्यतः 'अमेरिकन रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन' (एआरए) नामक गैर सरकारी संगठन के जरिये वहां अनाज, कपड़ा और दवाओं की भारी मदद भेजी गयी। इस मदद का मूल उद्देश्य समाजवादी देश को उदार आर्थिक नीतियों की ओर धकेलकर पूँजीवादी सम्बन्धों को बल प्रदान करना तथा अमेरिकी पूँजीवाद की तरफ सोवियत जनता को आकृष्ट करना था। इसका एक ओर अंतर्निहित तात्कालिक उद्देश्य था, जो इस

तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि एआरए के माध्यम से पाँच लाख चालीस हजार टन अनाज सोवियत संघ भेजे जाने के चलते अमेरिकी बाजार में अनाज की कीमतों में स्थिरता आ गयी, जो बाजार की एक फौरी जरूरत थी। आगे चलकर यही तरकीब दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, पूरे यूरोप के देशों में भी कम्युनिस्ट सत्ता को कमजोर और विघटित करने के लिए सफलतापूर्वक आजमायी गयी। नये किस्म के अमेरिकी गैर-सरकारी संगठनों ने साम्राज्यवाद की सेवा के अधिक उन्नत, अधिक परिष्कृत और अधिक संगठित तौर-तरीके अपनाये।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ध्वस्त यूरोप का पुनर्निमाण सभी साम्राज्यवादी शक्तियों की, और विशेष तौर पर, शीर्ष स्थान पर काबिज होने वाले अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक फौरी जरूरत था। इस काम में सरकारी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ही पुराने चैरिटी संगठनों और नये किस्म के गैर सरकारी संगठनों ने हिस्सा लिया। बाजार के विकास के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का काम राहत के मानवतावाद की आड़ में गैर सरकारी संगठनों के जरिये काफी सस्ते में हो जाता था। उजरती गुलामी को समाज-कल्याण का जामा पहनाने और श्रम शक्ति को जमकर निचोड़ने की यह तरकीब अगले पचास वर्षों में काफी उन्नत हुई। तीसरी दुनिया के देशों में बाजार के विकास एवं विस्तार के लिए कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम करा लेने के चलते स्वयंसेविता का "थर्ड सेक्टर" अतिशय लाभ देने वाला सेक्टर बन गया। व्यवस्था के पायों और आधार को मजबूती देने वाले राजनीतिक उपकरण के साथ ही यह पूँजीवादी उत्पादन तंत्र का एक महत्वपूर्ण सेक्टर भी बन गया।

पचास और साठ के दशक में, विशेषकर जॉन केनेडी के राष्ट्रपतित्व काल के दौरान, अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों की रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये जो उपनिवेशों की कमोबेश समाप्ति के बाद, साम्राज्यवाद के नये दौर की जरूरतों और विशेष तौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक थे। चीन के बाद, कोरिया की क्रान्ति, क्यूबा की क्रान्ति, वियतनामी क्रान्ति के अग्रवर्ती विकास, पूरे हिन्दचीन के क्रान्तिकारी संघर्ष, इण्डोनेशिया, फिलीप्पीन्स आदि देशों में संघर्षरत कम्युनिस्टों की बढ़ती शक्ति अफ्रीका के विजयोन्मुख राष्ट्रीय मुक्ति युद्धों और समाजवादी देशों तथा कम्युनिज्म के प्रति उनके झुकाव को देखते हुये केनेडी प्रशासन ने कम्युनिज्म के विरुद्ध एक प्रभावी गारण्टी के रूप में विदेशी सहायता को हथियार बनाया। स्व-सहायता, सामुदायिक विकास, युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण, साक्षरता कार्यक्रम और कृषि विकास योजनाओं में सालाना अरबों अमेरिकी डालर की रकम सीधे सरकारी खजाने से निकलकर गैर सरकारी संगठनों के जरिये इन कामों में लगी। अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने भी तीसरी दुनिया की बुर्जुआ सत्ताओं के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों के जरिये इन कामों में धन लगाया। सबसे गरीब देशों में 'काम के बदले अनाज' और 'स्कूलों में दोपहर का भोजन' जैसी स्कीमों की शुरुआत हुई। गैर सरकारी संगठनों के इन कामों के निहित राजनीतिक उद्देश्यों के साथ एक आर्थिक उद्देश्य भी था। अमेरिका और पश्चिम के अन्य देशों का अतिरिक्त अनाज इनके जरिये तीसरी दुनिया के देशों में भेजकर साम्राज्यवादी अपने घरेलू बाजार में अनाज की कीमतों को गिरने से रोकने का काम किया करते थे और आज भी करते हैं।

सत्तारूढ़ होने के बाद तीसरी दुनिया के देशों के बुर्जुआ वर्ग ने भी गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और उन्हें अपने ट्रस्टों और सरकार के मंत्रालय के जरिये मुक्त हस्त अनुदान देने की शुरुआत की। वर्ग-संघर्ष की धार कुन्द करने के लिए और नीति-निर्धारण में मदद के लिए उन्हें भी गैर सरकारी संगठनों की उतनी ही जरूरत थी जितनी साम्राज्यवादियों को।

अमेरिकी साम्राज्यवाद पोषित गैर सरकारी संगठनों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक स्थितियों-विशिष्टताओं को समझने में और तदनुरूप नीतियाँ निर्धारित करने में अमेरिकी शासक वर्ग की, और सामान्यतः सभी साम्राज्यवादियों की, विशेष मदद की। फोर्ड फाउण्डेशन जैसी संस्थाएँ अपनी शोधवृत्तियों-अनुदानों के जरिये बुद्धिजीवियों को खरीदकर यह काम पहले से ही करती रही थीं और यहाँ तक कि वामपंथ प्रभावित सांस्कृतिक आन्दोलन के प्रतिकार के लिए भी लगातार धन देकर वैचारिक मुहिम संगठित किया करती थीं। सत्तर के दशक में विशेष तौर पर, भारत और अन्य पिछड़े देशों में ऐसे तथाकथित स्वायत्त शोध संस्थान और विकास अध्ययन केन्द्र खुले जो सरकारी अनुदान से भी अधिक, विदेशी फण्डिंग एजेंसियों पर आश्रित थे और उन्हीं के दिये फ्रेमवर्क के अन्तर्गत विभिन्न शोध परियोजनाओं पर काम किया करते थे। यह प्रवृत्ति अस्सी और नब्बे के दशक में, उदारीकरण-निजीकरण लहर के आगे बढ़ने के साथ तेजी से आगे बढ़ी और आज यहां तक जा पहुँची है कि ऐसे तमाम शोध-संस्थान सरकारी अनुदान के बजाय लगभग पूरी तरह विदेशी फण्डिंग एजेंसियों पर निर्भर हो गये हैं और शोध-अध्ययन की अधिकांश परियोजनाएँ वे विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के घनिष्ठ सहकार के साथ चला रही हैं। यही नहीं, अब तो अपने संसाधन स्वयं जुटाने के सरकारी दिशा-निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों के विभाग भी गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान-सहयोग से शोध-अध्ययन का काम करने लगे हैं।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, तीसरी दुनिया के नवस्वाधीन देशों में राष्ट्रीय बाजारों का विकास और

उनके लिए जरूरी अवरचनागत ढाँचे के निर्माण की जरूरत साम्राज्यवादियों को भी थी और सत्तारूढ़ देशी बुर्जुआ वर्ग को भी। इसके लिए कृषि के आधुनिकीकरण और कृषि में पूँजी निवेश की जो नीतियाँ निर्धारित की गयीं, उसके लिए शोध-अध्ययन के काम में भी गैर सरकारी संगठनों और मुख्यतः विदेशी अनुदान से संचालित शोध-संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज यह भूमिका पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हो चुकी है।

सत्तारूढ़ होने के बाद तीसरी दुनिया के देशों के बुर्जुआ वर्ग ने भी गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और उन्हें अपने ट्रस्टों और सरकार के मंत्रालय के जरिये मुक्त हस्त अनुदान देने की शुरुआत की। वर्ग-संघर्ष की धार कुन्द करने के लिए और नीति-निर्धारण में मदद के लिए उन्हें भी गैर सरकारी संगठनों की उतनी ही जरूरत थी जितनी साम्राज्यवादियों को।

इस सन्दर्भ में विभिन्न गाँधीवादी संगठनों की भूमिका भी गौरतलब है। "स्वदेशी" और "ग्राम स्वराज्य" का रट्टा लगाने वाले ये संगठन सरकारी, और उससे भी अधिक विदेशी अनुदानों पर ही आश्रित रहे हैं और अन्य गैर सरकारी संगठनों से इनकी भूमिका और इनका चरित्र किसी भी रूप में भिन्न नहीं है।

मोटे तौर पर, गैर सरकारी संगठनों की तीन श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं, हालाँकि इन तीनों के कार्यभार मिले-जुले ही होते हैं।

पहली कोटि उन गैर सरकारी संगठनों की है, जो मुख्यतः सामाजिक कार्रवाईयों पर केन्द्रित करती हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठन बड़े बाँध, पर्यावरण, बाल मजदूरी, बँधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी के कानूनों पर अमल, स्त्री एवं दलित-उत्पीड़न आदि के मुद्दों को उठाते हैं, असंगठित मजदूरों के सहकारी उद्यम संगठित करते हैं और अलग-अलग आन्दोलन अलग-अलग इलाकों में संगठित करते हैं। इस तरह ये जनता को वर्गीय आधार पर लामबन्दी और उनके संघर्ष को राज्यसत्ता के विरुद्ध लक्षित होने से रोक कर महज कुछ सुधारों तक केन्द्रित कर देते हैं। इन सुधारों का एक लक्ष्य उन प्राक् पूँजीवादी अवरोधों को हटाना भी होता है जो बाजार के विकास में बाधक होते हैं। ऐसे गैर-सरकारी संगठन विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य एजेंसियों तथा सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, तरह-तरह के सुधारों और नीति-परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं और पूँजीवादी व्यवस्था को वर्ग संघर्ष की आँच से बचाने की हरचंद कोशिश करते हैं। ये संगठन जनता की पहलकदमी, क्षमता आदि की विशेष तौर पर दुहाई देते हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य आज यह है कि बुर्जुआ "कल्याणकारी" राज्य के विघटन के साथ ही राज्यसत्ता द्वारा शिक्षा-स्वास्थ्य आदि की रही-सही जिम्मेदारियों से भी पल्ला झाड़ लेने के बाद पैदा होने वाले सामाजिक तनाव को विस्फोट की ओर बढ़ने से रोकने में 'सेफ्टी वॉल्व' का काम किया जाये।

उत्तर-आधुनिकतावादियों और उनके सहोदरों ने गैर सरकारी संगठनों की "राजनीति विहीनता" की राजनीति को नया विचारधारात्मक आधार देने का महत्वपूर्ण काम किया। वर्ग की जगह उन्होंने लिंग, नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता आदि की अस्मिता पर जोर दिया और सामाजिक वर्ग-विश्लेषण को ही उन्होंने "वर्ग-अपचयनवाद" (क्लास-रिडक्शनिज्म) की तोहमत लगाते हुए सिरे से खारिज कर दिया। क्रान्ति के विज्ञान और तर्कणा को उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया।

दूसरी कोटि के गैर-सरकारी संगठन अपने को दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के कामों पर केन्द्रित करते हैं। साठ के दशक में ऐसे संगठन यूरोप में तेजी से फैले और फिर तीसरी दुनिया के देशों में भी इनकी पैठ बनी। ये संगठन तीसरी दुनिया के देशों में तकनीकी शिक्षा देने, स्कूल-अस्पताल आदि बनाने, स्थानीय उत्पादक संसाधनों और ग्रामीण बाजारों का विकास करने, विकास की गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाने, स्व-सहायता समूह और माइक्रो क्रेडिट सोसाइटियाँ गठित करने जैसे कामों के जरिये बाजार की शक्तियों की व्यापक पैठ-पकड़ का आधार तैयार करने का काम करते हैं। सामाजिक कार्य के आदर्शों की आड़ में बहुत कम वेतन-भत्ता पाने वाले अपने ग्रासरूट कार्यकर्ताओं और आम जनता के स्वैच्छिक सहयोग से या नाममात्र की मजदूरी देकर ये पूँजीवाद के जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का काम करते हैं। जिस काम को सरकारी तंत्र द्वारा अंजाम देने में भारी पूँजी की दरकार होती, उसे ये काफी सस्ते में निपटा देते हैं। प्रकारान्तर से कम पूँजीनिवेश करके अतिलाभ कमाने का ही यह एक रास्ता है।

तीसरी कोटि के गैर-सरकारी संगठन मुख्यतः युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्य का काम करते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौर में इस श्रेणी में मुख्यतः चैरिटी संगठन आते थे। अब बहुतेरे ऐसे संगठन हैं, जो उन देशों में राहत और निर्माण के कामों में जुट जाते हैं, जहां अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्ध और विनाश का कहर बरपा करते हैं। वियतनाम से लेकर इराक तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहाजों से बम और खाने के पैकेट साथ-साथ गिराने वाले साम्राज्यवादियों के चरित्र को देखते हुए यह जरा भी अजीब नहीं लगता। मानवीय सहायता का स्वाँग रचकर वे युद्ध से तबाह जनता के आक्रोश पर छींटें मारने का काम करते हैं ताकि युद्ध के असली मकसद को अंजाम दिया जा सके। इस काम को विभिन्न गैर सरकारी संगठन पूरा करते हैं और सामाजिक शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे

बढ़ाते हैं ताकि साम्राज्यवादी लूट और शोषण की आर्थिक प्रक्रिया शुरू की जा सके।

एनजीओ परिघटना के विकास के सर्वथा नये आयाम अस्सी के दशक में उभरकर सामने आये। इसका विस्तार अभूतपूर्व रूप से व्यापक हो गया। इसने अपनी पूरी नयी राजनीतिक शब्दावली विकसित की और उत्तर-आधुनिकतावादियों, उत्तर-संरचनावादियों, उत्तर-उपनिवेशवादियों, उत्तर-मार्क्सवादियों और सब-आल्टर्न इतिहासकारों आदि एक ही नस्ल की विभिन्न प्रजातियों ने इसका एक सैद्धान्तिक आधार तैयार करने की भूमिका निभायी। "नागरिक समाज", "भागीदारी जनतंत्र" (पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी), "भागीदारी बजट", "नये सामाजिक आन्दोलन" (न्यू सोशल मूवमेंट) आदि नये-नये आकर्षक नारे उछाले गये और शब्दावलियाँ गढ़ी गयीं। यह नयी शब्दावली विश्व बैंक-आईएमएफ-डब्ल्यूटीओ और गैर-सरकारी संगठनों के दस्तावेजों में समान रूप से पायी जाती है और अब विश्व सामाजिक मंच भी इसी शब्दावली में अपने नीति-वक्तव्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।

अस्सी के दशक में, भूमण्डलीकरण या आर्थिक नवउपनिवेशवाद के दौर में साम्राज्यवादी वित्तीय पूँजी के प्रवाह के रास्ते की सभी बाधाओं को हटाने का काम अंधाधुंध शुरू हुआ। तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रीय बाजारों के द्वार विदेशी पूँजी के लिए पूरी तरह से खोलने की शुरुआत हुई। उदारीकरण-निजीकरण की लहर चल पड़ी, जिसने भारत में नब्बे के दशक में गति पकड़ी। इन नीतियों को स्वीकारना तीसरी दुनिया के देशों के सत्तारूढ़ बुर्जुआ वर्ग की अपनी जरूरत भी थी, और बाध्यता भी। इस प्रक्रिया की तार्किक परिणति के तौर पर, न केवल 'पब्लिक सेक्टर' नामधारी राजकीय पूँजीवाद के विघटन की (विनिवेश के नाम पर) शुरुआत हुई, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से भी राज्य पीछे हटने लगा। धीरे-धीरे इन सबको बाजार की शक्तियों के हवाले किया जाने लगा। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बीते जमाने की चीज हो गया। जीने की बुनियादी सुविधाओं तक के छिनने से व्यापक आम आबादी के बीच जो व्यापक आक्रोश घनीभूत होने लगा, उस पर पानी के छींटें मारने का, उसे विघटित करने और दिशाहीन बनाने का काम तब गैर सरकारी संगठनों ने अपनी सुधारवादी सामाजिक-राजनीतिक कार्रवाईयों द्वारा व्यापक पैमाने पर शुरू किया। देखते ही देखते तीसरी दुनिया के देशों में दसियों हजार नये-नये एनजीओ कुकुरमुत्ते की तरह पनप गये। पुरानों का भी पुनःसंस्कार हो गया। जिन जिम्मेदारियों से बुर्जुआ राज्य हाथ खींच चुका था, उन्हें स्व-सहायता, सहकारिता, सामुदायिक विकास, भागीदारी जनतंत्र आदि-आदि के नाम पर गैर सरकारी संगठनों ने अलग-अलग, एक हद तक, स्वयं जनता को संगठित करके और बेरोजगार युवाओं को बहुत कम वेतन-भत्ते पर अपना कार्यकर्ता बनाकर पूरा करना शुरू किया। इससे शासकीय तंत्र के मुकाबले बाजार के विकास के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ते में तैयार हो रहा था और साम्राज्यवादियों और देशी पूँजीपतियों के मुनाफे में अकूत बढ़ोत्तरी हो रही थी। साथ ही, जनता की वर्गीय चेतना को कुन्द करने और उसके राजनीतिकरण को रोकने का काम भी प्रभावी ढंग से हो रहा था। वित्तीय पूँजी का निर्बाध प्रवाह आम जनता के जीवन पर विनाश का जो कहर बरपा कर रहा था, उसे एक हद तक नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गैर सरकारी संगठन नीचे आन्दोलन भी संगठित करते थे और ऊपर तदनुरूप नीतियां बनाने-बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और सरकारों को सलाह देने का भी काम करते थे। यह प्रक्रिया आज अत्यंत व्यापक रूप में जारी है। साम्राज्यवादियों को यह अहसास था कि भूमण्डलीकरण की नीतियां, विशेष तौर पर पिछड़े देशों की मेहनतकश और आम मध्यवर्गीय आबादी को तबाही-बर्बादी की ओर तेज गति से ढकेलेंगी जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी जनक्रान्तियों के लिए नये सिरे से जमीन तैयार होगी। उनके सिद्धान्तकारों, नीति-निर्माताओं ने तब 'सेफ्टी वॉल्व' के रूप में गैर सरकारी संगठनों की बढ़ी हुई महत्ता की नये सिरे से पहचान की। साम्राज्यवादी फंडिंग एजेंसियों ने ऐसे संगठनों को सालाना अरबों डालर की सहायता देनी शुरू कर दी। देशी बुर्जुआ वर्ग की सरकारों ने भी अपना योगदान कई गुना बढ़ा दिया।

सभी कोटि के उत्तर-विचार आर्थिक नवउपनिवेशवाद के दौर की बुर्जुआ विचारधारा हैं और एनजीओ की राजनीति के यही मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। इन्हें जोर देकर स्थापित करने के लिए बहुतेरे गैर सरकारी संगठन आज खुद को 'नागरिक समाज' की नयी संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अलग-थलग ढंग से चलाये जाने वाले आन्दोलनों और सामाजिक समुदायों की वर्गेतर अस्मिता पर बल देने वाले आन्दोलनों को आज 'नये सामाजिक आन्दोलन' का नाम देकर महिमामण्डित किया जा रहा है।

उत्तर-आधुनिकतावादियों और उनके सहोदरों ने गैर सरकारी संगठनों की "राजनीति विहीनता" की राजनीति को नया विचारधारात्मक आधार देने का महत्वपूर्ण काम किया। वर्ग की जगह उन्होंने लिंग, नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता आदि की अस्मिता पर जोर दिया और सामाजिक वर्ग-विश्लेषण को ही उन्होंने "वर्ग-अपचयनवाद" (क्लास-रिडक्शनिज्म) की तोहमत लगाते हुए सिरे से खारिज कर दिया। क्रान्ति के विज्ञान और तर्कणा को उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया। प्रबोधनकालीन बुर्जुआ भौतिकवाद से लेकर मार्क्सवाद तक को औद्योगिक समाज के आधुनिकतावादी विचार की कोटि में रखते हुए इन बुर्जुआ विचारकों ने इन्हें सर्वसत्तावादी, वर्चस्ववादी महाख्यान बताया और यह फतवा दे दिया कि इनका विखण्डन मुक्ति का एक बुनियादी प्रश्न है। सामाजिक कर्म की हर सम्भावना को उन्होंने मात्र विमर्श तक सीमित

कर दिया। नागरिक समाज की मान्य अवधारणा को खारिज करते हुए इन भाँति-भाँति के उत्तर-विचारवादियों ने उसके वर्ग-चरित्र की अनदेखी की और इस सच्चाई से इनकार किया कि नागरिक समाज में एक प्रभावी समूह अन्य समूहों पर अपने वर्चस्व को राज्यसत्ता के जरिये ही विधि सम्मत बनाता है और लागू करता है। इस तरह राज्य को इन भाड़े के विचारकों ने नागरिक समाज का विस्तार मानने की जगह दोनों को सर्वथा पृथक चीजों के रूप में प्रस्तुत किया। उत्तर-विचारवादियों ने वर्ग-संघर्ष और राज्य के अस्तित्व को दृष्टिओझल करते हुए वर्चस्व के अलग-अलग रूपों के विरुद्ध अलग-अलग संघर्ष की बात की। और यही वह काम है जो आज के आधुनिक 'ग्लोबलिस्ट', गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि विश्व बैंक, आईएमएफ से लेकर सभी गैर सरकारी संगठन और विश्व सामाजिक मंच तक उसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो उत्तर-विचारवादियों द्वारा चलन में लायी और स्थापित की गयी है। कहा जा सकता है कि सभी कोटि के उत्तर-विचार आर्थिक नवउपनिवेशवाद के दौर की बुर्जुआ विचारधारा हैं और एनजीओ के राजनीति के यही मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं। इन्हें जोर देकर स्थापित करने के लिए बहुतेरे गैर सरकारी संगठन आज खुद को 'नागरिक समाज' की नयी संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं और अलग-अलग मुद्दों पर अलग-थलग ढंग से चलाये जाने वाले आन्दोलनों और सामाजिक समुदायों की वर्गेतर अस्मिता पर बल देने वाले आन्दोलनों को आज 'नये सामाजिक आन्दोलन' का नाम देकर महिमामण्डित किया जा रहा है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि

गैर-सरकारी संगठन आर्थिक नवउपनिवेशवाद की नीतियों के एक प्रमुख प्रचारक और व्यवहार में लाने वाले अभिकर्ता हैं। सर्वोपरि तौर पर वे साम्राज्यवादी हितों के सेवक हैं, लेकिन साथ ही वे देशी बुर्जुआ वर्ग के भी हित साधक हैं।

वे तीसरी दुनिया के देशों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी की पैठ तथा बाजार के व्यापक और सूक्ष्म विस्तार के प्रभावी उपकरण हैं। पूँजीवादी विकास के कार्यों में होने वाले निवेश को वे समाज सुधार के नाम पर तरह-तरह के नारे देकर कम करते हैं। प्रशासकीय खर्चों में किफायतसारी का जरिया बनते हैं और देशी-विदेशी पूँजीपतियों के ज्यादा से ज्यादा लाभ को सुनिश्चित बनाते हैं।

पूँजीवादी शोषण को जारी रखने के लिए वे तरह-तरह से जनता के विचारों को प्रभावित करते हैं, सिद्धान्त गढ़ते हैं और उनका प्रचार करते हैं। वे इस विश्वास को पुख्ता बनाने की हरचंद कोशिश करते हैं कि पूँजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, नयी सर्वहारा क्रान्तियां सम्भव नहीं हैं और विकल्प एकमात्र यही है कि भूमण्डलीकरण की नियति को स्वीकार करते हुए बस उसे सम्भव सीमा तक मानवीय बनाने की कोशिश की जाये।

ऊपरी तौर पर राज्य-विरोधी अवस्थिति अपना कर गैर सरकारी संगठन जनता में और कुछ अधकचरे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भी भरमाने का काम करते हैं लेकिन माइक्रो लेवल पर वे स्व-सहायता, सहकारिता, सामुदायिक विकास आदि अपने उपक्रमों द्वारा निजीकरण के उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जिन्हें मैक्रो लेवल पर बुर्जुआ राज्यसत्ता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां अंजाम दे रही हैं। वे प्रकारान्तर से शिक्षा-स्वास्थ्य आदि बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाने के लिए राज्य को रास्ता देने का काम कर रहे हैं।

एनजीओ जनता की लामबन्दी की प्रक्रिया को बाधित करने के साथ ही क्रान्ति की कतारों में भरती की सम्भावना से लैस अगुवा तत्वों को, विशेषकर रैडिकल युवाओं को सामाजिक कार्यों की आड़ में भरमा-बहका कर सुधारवाद के दलदल में धंसा देते हैं, व्यवस्था में समायोजित कर लेते हैं और उन्हें भ्रष्ट कर देते हैं।

स्वयं गैर राजनीतिक होने का ढोंग करते हुए वे जनता को राजनीति और राजनीतिक पार्टियों से विमुख होने की राय देते हैं और इस तरह गैर पार्टी सक्रियतावद के जरिये जनता की चेतना का विराजनीतिकरण (डिपोलिटिसाइजेशन) का काम करते हैं।

एनजीओ सामाजिक समूहों, संस्तरों और अस्मिताओं के आधारपर विभेद पर अतिरिक्त बल देते हुए इन विभेदों के वर्गीय आधार को दृष्टिओझल करते हैं, सामाजिक वर्ग-विभेद और वर्ग-संघर्ष की अपरिहार्य सच्चाई पर पर्दा डालते हैं, जनता की वर्ग चेतना को कुन्द करते हैं और उत्पीड़ितों की वर्गीय एकजुटता को तोड़ने का काम करते हैं।

एनजीओ जनता की लामबन्दी की प्रक्रिया को बाधित करने के साथ ही क्रान्ति की कतारों में भरती की सम्भावना से लैस अगुवा तत्वों को, विशेषकर रैडिकल युवाओं को सामाजिक कार्यों की आड़ में भरमा-बहका कर सुधारवाद के दलदल में धंसा देते हैं, व्यवस्था में समायोजित कर लेते हैं और उन्हें भ्रष्ट कर देते हैं।

सर्वोपरि तौर पर, वे विश्व पूँजीवाद के प्रभावी 'सेफ्टी वॉल्व' के रूप में काम करते हैं। साथ ही, वे भूमण्डलीकरण की नीतियों के प्रभावों को उग्र वर्ग-संघर्ष के सामाजिक विस्फोटों की अनिवार्य परिणति तक पहुँचने के रास्ते में 'स्पीड ब्रेकर' का काम करते हैं।

कैसी है विश्व सामाजिक मंच की संरचना, क्या हैं इसके घोषित-अघोषित उद्देश्य, क्या है कार्यप्रणाली और क्या है इसका मूल चरित्र?

विश्व पूँजीवाद की पूँजीवादी समालोचना, पूँजीवाद के विरोध के नाम पर उसके अंतर्निहित अंतर्विरोधों को यथासंभव हल करने की कोशिश तथा उनके विस्फोटक परिणामों से व्यवस्था की हिफाजत, स्वयंस्फूर्त जनप्रतिरोधों को क्रान्तिकारी दिशा में विकसित होने से रोककर व्यवस्था के सीमान्तों के भीतर उनके समायोजन तथा वर्ग-संघर्ष और सर्वहारा-क्रान्ति की प्रक्रिया को हर तरह से क्षतिग्रस्त करने की बहुविध कोशिशों की जिस राजनीति को एनजीओ सेक्टर ने सूत्रबद्ध और संस्थाबद्ध किया है, विश्व सामाजिक मंच दरअसल उसे ही एक वैश्विक मंच का व्यापक आधार देने की कारगर पहल है। यह वर्ग-सहयोग की राजनीति की नयी-पुरानी धाराओंसामाजिक जनवाद और संशोधनवाद तथा एनजीओ सुधारवाद का सिद्धहस्त संश्लेषण है। भूमण्डलीकरण की नीतियों ने आर्थिक धरातल के अतिरिक्त राजनीतिक धरातल पर भी ध्रुवीकरण इतना स्पष्ट कर दिया है कि सभी किस्म के नकली वामपंथियों की राजनीति तथा बुर्जुआ उदारवाद-सुधारवाद की बहुरंगी धाराओं के नारों-रीतियों-नीतियों में दिखावे के फर्क भी बस नाममात्र को ही बचे हैं। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में समाजवाद का मुखौटा लगाये राजकीय पूँजीवादी ढाँचों और उन्हें चलाने वाली संशोधनवादी पार्टियों के सर्वसत्तावादी शासन के पतन के बाद तथा पूरी दुनिया में राजकीय पूँजीवादी तंत्र और "कल्याणकारी" राज्य के विघटन के बाद तरह-तरह से बाजार और समाजवाद की खिचड़ी पकाने वाले नये-पुराने नकली समाजवादी अपना प्रभाव, साख और आधार काफी हद तक खो चुके हैं। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप के कुछ देशों और तीसरी दुनिया के बहुतेरे देशों में सत्तासीन होने के बाद भूमण्डलीकरण की नीतियों पर निष्ठा से अमल करते हुए और बस उसे कुछ "मानवीय" बनाने के लिए मिनमिनाते हुए ये सभी संसदीय वामपंथी इस कदर नंगे हो चुके हैं कि एनजीओ के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर और उसमें भी छुटभैया बनकर ही अब ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं और बुर्जुआ राजनीति के खेल में बने रह सकते हैं। एनजीओ और सामाजिक जनवाद/संशोधनवाद के बीच की मधुयामिनी का यही रहस्य है।

अब जब क्रान्तिकारी वाम के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न ईमानदार अनुभववादी रैडिकल समूहों-व्यक्तियों की ओर से विश्व सामाजिक मंच के लक्ष्य, कार्यप्रणाली, वित्तपोषण आदि पर उठाये जा रहे सवालों के मद्देनजर चुनावी वाममार्गी गिरगिटों की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं, तो इनमें से जो जितना अधिक मार्क्सवादी होने का दिखावा करता है, उसे अपने अवसरवाद को छिपाने की निष्फल कोशिश में उतने ही किस्म के द्रविड़ प्राणायाम करने पड़ते हैं। इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) है। 1987 में *'दि मार्क्सिस्ट'* में लेख लिखकर पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश कारत ने एनजीओ की साम्राज्यवाद-परस्त नीतियों का विरोध किया था। आज उनकी पार्टी "नये सामजिक आन्दोलनों" के इस उभार को नवउदारवाद के विरुद्ध जनता की उमड़ती सक्रियता का एक रूप बताते हुए इनसे सहयोग-सहकार की बात कर रही है। इनकी राजनीति और वित्तपोषण की वह धूर्ततापूर्ण अनदेखी कर रही है। दरअसल सीपीएम ने एनजीओ की पश्चिम परस्त नीतियों का विरोध तब किया था, जब सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व को समाजवादी मानते हुए दो अतिमहाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा में यह सोवियत पक्ष में खड़ा था। नकली समाजवाद का दुर्ग ढहने के बाद इन अनाथ संसदीय वाममार्गियों ने चीन के "बाजार समाजवाद" के झंडाबरदारों की पूँछ पकड़ी, जो खुद ही मुक्त मंडी के नाइटक्लब में व्यभिचाररत हैं। ऐसी स्थिति में नाटकीय पैंतरापलट के अतिरिक्त सीपीएम के पास भला और रास्ता ही क्या था? आज सीपीएम स्वयं कई एनजीओ चला रही है और इनके पार्टी कार्ड होल्डर तथा बुद्धिजीवी बड़े पैमाने पर विभिन्न ऐसे एनजीओ में काम कर रहे हैं, जिनका वित्तपोषण अमेरिका और यूरोप की फण्डिंग एजेंसियां करती हैं। विश्व सामाजिक मंच में भागीदारी का औचित्य-प्रतिपादन करते हुए सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने हाल ही में कहा कि वे मंच में इसलिये शामिल हैं कि भूमण्डलीकरण विषयक विचारधारात्मक बहस को प्रभावित करने के अवसर खोना नहीं चाहते तथा विकल्प के प्रश्न के रहस्यीकरण और समाजवादी कार्यक्रम की सार्थकता के निषेध का प्रतिरोध करना चाहते हैं। यदि मंच के नीति-निर्धारक निकायों में, साम्राज्यवाद के शीर्ष बौद्धिक एजेंट के रूप में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का वर्चस्व है, यदि इसके आधे से अधिक घटक गैर सरकारी संगठन ही हैं, यदि मंच का नीति वक्तव्य ही मार्क्सवाद और समाजवादी राज्य को खारिज करता है, तो फिर प्रश्न यह है कि येचुरी साहब मंच के भीतर जारी बहस को किस तरह प्रभावित करेंगे और किन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए यह काम करेंगे? सवाल मंच की पूरी राजनीति को ही 'एक्सपोज' करने का है और यह काम भीतर घुस कर नहीं

मंच के खोमचे वाले राज्यसत्ता के बारे में बुर्जुआ विचारों का वही सड़ा माल दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी असलियत *लेनिन* ने आज से आठ दशक से भी अधिक पहले *'राज्य और क्रान्ति'* में एकदम खोलकर रख दी थी। स्पष्ट है कि मंच का "बहुलतावादी (प्लूरलिस्ट)" स्वरूप मात्र एक पाखंड है, पूँजीवाद को स्थायित्व प्रदान करने की विचारधारा और समाजवाद का विरोध इसका बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धान्त है।

हो सकता। येचुरी साहब का द्रविड़-प्राणायाम उनकी पार्टी के अवसरवादी दोगलेपन को छिपाने में पूरी तरह से विफल है।

कुछ ऐसे अनुभववादी रैडिकल, ईमानदार ट्रेड यूनियनें और अधकचरे क्रान्तिकारी वामपंथी जरूर हैं, जो वास्तव में यह भ्रम पाले हुए हैं कि विश्व सामाजिक मंच के कम से कम एक बड़े हिस्से को समाजवादी परियोजना और भूमण्डलीकरण के सक्रिय प्रतिरोध के पक्ष में ला खड़ा करेंगे और इसके लिए वे "भीतर से संघर्ष" कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कई का मोहभंग अभी ही होने लगा है। यदि इनकी ईमानदारी बनी रही तो मोहभ्रम नहीं रह जायेगा और मोहभ्रम बना रहा, तो ईमानदारी नहीं रह जायेगी। दरअसल विश्व सामाजिक मंच विभिन्न प्रगतिशील, रैडिकल, क्रान्तिकारी, वामपंथी संगठनों-व्यक्तियों को अपने दायरे में लाकर भ्रष्ट करने का 'ट्रैप' भी है। साथ ही, ऐसा करके वह व्यापक जनता व आम जनता की निगाह में अपनी साख बढ़ा लेता है और भ्रम पैदा करने की उसकी क्षमता और बढ़ जाती है।

चीजों की असलियत को समझने में किसी किस्म के संदेह की गुंजाइश न रह जाये, इसके लिए विश्व सामाजिक मंच की संरचना और कार्यप्रणाली पर तथा घोषित उद्देश्यों पर थोड़ी और चर्चा जरूरी है।

विश्व सामाजिक मंच की अंतरराष्ट्रीय परिषद में कुल अस्सी संगठन शामिल हैं जिनमें 'अटैक', ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की वर्कर्स पार्टी से जुड़ी यूनियनें व जनसंगठन, 'जेनोआ सोशल फोरम', त्रात्सकीपंथी चौथे इंटरनेशनल के कुछ हिस्से, 'अमेरिकन काउंसिल आफ सोशल साइंसेज', समीर अमीन का 'वर्ल्ड फोरम आफ आल्टरनेटिव्स' तथा विभिन्न सामाजिक जनवादी व संशोधनवादी पार्टियों के जनसंगठन और विभिन्न गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। 'ऑर्गनाइजिंग ब्राजीलियन कमेटी' मंच के अंतरराष्ट्रीय सचिवालय का काम करती है, जिस पर लूला की पार्टी और 'अटैक' के सामाजिक जनवादियों का नियंत्रण है। मंच 'नागरिक समाजों', गैर सरकारी संगठनों, और विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों, समूहों और व्यक्तियों के बीच विमर्श और तालमेल की बात करते हुए राजनीतिक पार्टियों को तो इस दायरे से बाहर रखता है, लेकिन इन पार्टियों की यूनियनों/जनसंगठनों को अपने दायरे में शामिल करता है। साथ ही वह ऐसे लोगों को व्यक्तिगत हैसियत से आमंत्रित करता है जो सरकारों या विधायिकाओं के सदस्य हैं और नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

जनवरी 2002 के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में शामिल फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल में छह सरकारी मंत्री, राष्ट्रपति के चार सलाहकार, पेरिस के मेयर, राष्ट्रपति पद के तीन उम्मीदवार तथा दक्षिणपंथी पार्टी आरपीआर के महासचिव शामिल थे। साथ ही इस सम्मेलन में बेल्जियम के प्रधानमंत्री और पुर्तगाल के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे। ये यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के वे सरगना थे, जिनके बीच तथा जिनके अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ लूट के बाँट-बखरे को लेकर चाहे जो भी अंतरविरोध हों, लेकिन भूमण्डलीकरण की नीतियों पर इनके बीच पूरी आम सहमति स्थापित है। विश्व सामाजिक मंच की इस प्रतिबद्धता की, कि वह नवउदारीकरण, साम्राज्यवाद और पूँजी के प्रभुत्व के विरोधी तथा मानवकेन्द्रित विश्व के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध संगठनों, आन्दोलनों, व्यक्तियों के बीच तालमेल, अनुभवों के आदान-प्रदान और विमर्श का काम करेगा, असलियत स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यह भेड़ियों और भेड़ों के बीच शांति स्थापना की "कोशिश" और भेड़ियों को शाकाहारी होने की नसीहत देने के अतिरिक्त भला और क्या है? आश्चर्य नहीं कि विश्व सामाजिक मंच के तीसरे जलसे का उद्घाटन करने के बाद ब्राजीली राष्ट्रपति लूला तुरंत विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए दावोस के लिए उड़ गया ताकि साम्राज्यवादी शासकों को अपनी कारगुजारियों की रिपोर्ट दे सके। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुंबई में विश्व सामाजिक मंच के चौथे आयोजन की पूर्वपीठिका के तौर पर जनवरी 2003 में हैदराबाद में एशियाई सामाजिक मंच (एशियन सोशल फोरम) का जो जलसा हुआ था उसमें मंच पर मेधा पाटकर, प्रभात पटनायक, भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और गणमान्य एनजीओ मठाधीशों के साथ "सामाजिक न्याय" के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी मौजूद थे। साम्राज्यवाद के लिए भारतीय बाजार के महत्व को देखते हुए हैदराबाद में एशियाई सामाजिक मंच के आयोजन के बाद अब मुंबई में, पहली बार पोर्तो अलेग्रे से बाहर, विश्व सामाजिक मंच का चौथा वार्षिक आयोजन होने जा रहा है। यह साम्राज्यवादी रणनीति-विशारदों की महत्वपूर्ण सफलता है कि उन्होंने सभी प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, उनके प्रभाव वाले सामाजिक आन्दोलनों, तमाम गाँधीवादी संगठनों और भाकपा-माकपा के साथ ही संसदीय वामपंथी क्लब के नये सदस्य भाकपा (माले-लिबरेशन) तक को एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। व्यवस्था की इससे बढ़िया दूसरी सुरक्षापंक्ति, इससे अधिक प्रभावी 'सेफ्टी वाल्व', इतना आकर्षक 'ट्रोजन हॉर्स' भला और क्या हो सकता था?

यह साम्राज्यवादी रणनीति-विशारदों की महत्वपूर्ण सफलता है कि उन्होंने सभी प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, उनके प्रभाव वाले सामाजिक आन्दोलनों, तमाम गाँधीवादी संगठनों और भाकपा-माकपा के साथ ही संसदीय वामपंथी क्लब के नये सदस्य भाकपा (माले-लिबरेशन) तक को एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया है। व्यवस्था की इससे बढ़िया दूसरी सुरक्षापंक्ति, इससे अधिक प्रभावी 'सेफ्टी वाल्व', इतना आकर्षक 'ट्रोजन हॉर्स' भला और क्या हो सकता था?

अब जरा विश्व सामाजिक मंच के ढांचे और कार्यप्रणाली पर निगाह डाली जाये। सबसे महत्वपूर्ण

बात यह है कि यह मंच केवल तालमेल, अनुभवों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श का एक मंच है। पहले सम्मेलन के बाद जारी 18 सूत्री घोषणापत्र, 'वर्ल्ड सोशल फोरम, इंडिया-पॉलिसी गाइडलान्स' नामक दस्तावेज और अन्य नीति विषयक वक्तव्यों में इस बात को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया है कि यह मंच किसी तरह की साझा कार्रवाई के लक्ष्य से गठित संगठन नहीं है। यह एक स्थायी "विश्व प्रक्रिया" है जो निरन्तर नये विकल्पों की खोज करेगा। यह बात किसी लाल-बुझक्कड़ की समझ से भी परे है कि साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी शक्तियों की साझा कार्रवाई के बगैर महज विचार-विमर्श से नवउदारवाद का विकल्प भला कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? मंच नवउदारवादी नीतियों के एक नहीं, बल्कि कई और निरन्तर नये विकल्पों को खोजते रहने का दावा करता है, जिसका स्पष्ट निहितार्थ साम्राज्यवाद के एकमात्र विकल्प के रूप में समाजवाद की धारणा को खारिज करना और इस मान्यता को स्थापित करना है कि आर्थिक नवउपनिवेशवाद के भूमण्डलीय और वैचारिक ढांचे के भीतर ही कई विकल्प सम्भव हैं। यूँ कहा जा सकता है कि मंच की दृष्टि में, पूँजीवाद ही अंतिम विकल्प है या 'इतिहास का अंत' है, अतः काम सिर्फ यह रह जाता है कि कुछ पैबन्द लगाये जायें, कुछ रंगरोगन किया जाये और भूमण्डलीकरण के चेहरे को थोड़ा और "मानवीय" बनाया जाये।

वैसे विश्व सामाजिक मंच अपने स्वरूप में जितना जनवादी और खुला होने का दिखावा करता है, उतना यह है नहीं। यह दावा एक धोखाधड़ी मात्र है, इसे महज इस तथ्य से समझा जा सकता है कि नस्ल, धर्म और जाति पर आधारित संगठनों के साथ ही, यह उन सभी संगठनों के अपने भीतर प्रवेश पर बंदिश लगाता है जो "सैन्य संगठन" हैं। इस श्रेणी में वे सभी संगठन शामिल हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में साम्राज्यवाद और अपने देश की बुर्जुआ सत्ताओं के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। इस श्रेणी में दुनिया भर के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, अन्य क्रान्तिकारी धाराएं, राष्ट्रीयताओं के संघर्ष, जापातिस्ता जैसे किसान संघर्षों के नेतृत्वकारी संगठन और यहां तक कि सान्दिनिस्ता और पीएलओ भी आ जाते हैं। यानी सरकारों के सदस्य और विधायिकाओं के सदस्यों की हैसियत से उन बुर्जुआ सत्ताओं के प्रतिनिधियों के लिए तो मंच के दरवाजे खुले हैं जो अपने-अपने देश की जनता को हथियारों के बूते कुचल रही हैं, उनके विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इनमें वे शामिल नहीं हो सकते, जिनके नेतृत्व में जनता इन दमनकारी सत्ताओं का सशस्त्र प्रतिकार कर रही है। इस तरह मंच शासक वर्ग की हिंसा का तो मूक समर्थन करता है, लेकिन क्रान्तिकारी हिंसा के विरोध के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। यह इतिहास की इस सचाई को पूरी तरह नकारने की कोशिश करता है कि अब तक सभी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं को सभी राज्यसत्ताएं बल और हिंसा के द्वारा ही कायम रखती रही हैं और इन राज्यसत्ताओं को बल और हिंसा के प्रयोग से ही नष्ट करके नयी सामाजिक-आर्थिक ढाँचों का निर्माण नई राज्यसत्ता स्थापित करके किया जाता रहा है। विश्व सामाजिक मंच की इस प्रतिबद्धता की दृढ़ता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उसने कोलम्बिया के 'एफएआरसी' (जो मंच में भागीदारी का इच्छुक था), अर्जेण्टीना के 'मदर्स ऑफ दि प्लाजा डि मेयो', स्पेन के बास्क ग्रुपों और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। पूरब-पश्चिम के बहुतेरे ऐसे रैडिकल जनसंगठन और ट्रेड यूनियनें, जो साम्राज्यवाद के एकमात्र विकल्प के तौर पर समाजवाद को देखती थीं और मात्र विचार-विमर्श से आगे किसी तरह की साझा कार्रवाई की रूपरेखा तय करने पर बल देती थीं, उन्हें मंच के दायरे से हरचंद कोशिश करके दूर रखा गया। कुछ यदि भीतर प्रवेश कर भी गये, तो मंच के दायरे में कुछ कर पाने की असंभवता को देखते हुए बाहर हो गये या होते जा रहे हैं। मंच की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता मार्क्सवाद और वास्तविक समाजवाद के विरुद्ध है, यह उसके चार्टर के उस अनुच्छेद से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है: *"मंच अर्थव्यवस्था, विकास और इतिहास के बारे में सभी सर्वसमावेशी (टोटैलिटेरियन) और अपचयनवादी (रिडक्शनिस्ट) दृष्टिकोणों का तथा राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण के साधन के तौर पर हिंसा का विरोध करता है।"* यही वह भाषा है, जिसका इस्तेमाल सभी बुर्जुआ और नववामपंथी मार्क्सवाद और समाजवाद का विरोध करते हुए करते रहे हैं। यह विश्व सामाजिक मंच के साथ ही इसमें भागीदार भाकपा, माकपा और भाकपा (माले) जैसे सभी नकली कम्युनिस्टों को नंगा कर देता है। यूँ तो सभी बुर्जुआ राज्यसत्ताएं हिंसा द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण कायम रखती हैं, पर उनके प्रतिनिधियों को न्यौतने में मंच को कोई ऐतराज नहीं है। राज्यसत्ता के बारे में बुर्जुआ विचारों का वही सड़ा माल मंच के खोमचे वाले दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी असलियत *लेनिन* ने आज से आठ दशक से भी अधिक पहले *'राज्य और क्रान्ति'* में एकदम खोलकर रख दी थी। स्पष्ट है कि मंच का "बहुलतावादी (प्लूरलिस्ट)" स्वरूप मात्र एक पाखंड है, पूँजीवाद को स्थायित्व प्रदान करने की विचारधारा और समाजवाद का विरोध इसका बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धान्त है।

यह बात किसी लाल-बुझक्कड़ की समझ से भी परे है कि साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी शक्तियों की साझा कार्रवाई के बगैर महज विचार-विमर्श से नवउदारवाद का विकल्प भला कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? मंच नवउदारवादी नीतियों के एक नहीं, बल्कि कई और निरन्तर नये विकल्पों को खोजते रहने का दावा करता है, जिसका स्पष्ट निहितार्थ साम्राज्यवाद के एकमात्र विकल्प के रूप में समाजवाद की धारणा को खारिज करना और इस मान्यता को स्थापित करना है कि आर्थिक नवउपनिवेशवाद के भूमण्डलीय और वैचारिक ढांचे के भीतर ही कई विकल्प सम्भव हैं।

मंच अपने चार्टर में नागरिक समाज के विभिन्न संगठनों-आन्दोलनों के बीच तालमेल करने पर, सीमान्त आबादी के आन्दोलनों को या जातिगत, लैंगिक, पहचान आदि के आधार पर संगठित आन्दोलनों को तथा स्थानीय संगठनों-आन्दोलनों को बल प्रदान करने पर और "भागीदरी जनतंत्र" को मजबूत बनाने पर बल देता है। यही हूबहू वह भाषा है जो सभी गैर सरकारी संगठनों से लेकर विश्व बैंक तक इस्तेमाल करते हैं। "नागरिक समाज" और "भागीदारी जनतंत्र" जैसे फिकरों की असलियत की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इस सारी फिकरेबाजी का मूल उद्देश्य जनता की वर्गीय एकजुटता की प्रक्रिया को तोड़ना, उसके संघर्षों को खण्ड-खण्ड में विभाजित बनाये रखना और बुर्जुआ जनवाद के नये सामाजिक अवलम्बों का विकास करना मात्र ही है। इन तमाम तरकीबों से विश्व सामाजिक मंच वस्तुतः बुर्जुआ जनवाद के विभ्रमों को बनाये रखने की, बुर्जुआ राज्यसत्ता और शासक वर्ग को जनाक्रोश का लक्ष्य बनने से बचाने की और सामाजिक क्रान्ति के विस्फोटों से विश्व पूँजीवादी तंत्र को बचाने की कोशिश करता है।

क्रान्तिकारी वामपंथ की नीति-रणनीति को लेकर कुछ प्रश्न, कुछ आपत्तियाँ-आलोचनाएँ और हमारी अवस्थिति

विश्व सामाजिक मंच के विरोधी स्वर यूरोप, लातिन अमेरिका और यहां तक कि अमेरिका से भी, इसके पहले सम्मेलन के समय से ही उठते रहे हैं। इसमें कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के साथ ही विभिन्न किस्म की प्रगतिशील, क्रान्तिकारी शक्तियाँ, ट्रेड यूनियनें, गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों के संगठन तथा मध्यमवर्गीय क्रान्तिकारी संगठनों के साथ ही भूमण्डलीकरण की नीतियों का विरोध करने वाले धनी किसानों के भी कुछ संगठन शामिल रहे हैं। पोर्तो अलेग्रे में विश्व सामाजिक मंच के पहले सम्मेलन में जब दस हजार प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक समानान्तर सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें पचास हजार लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन बुर्जुआ मीडिया ने समानान्तर सम्मेलन को कोई तरजीह नहीं दी। अब चौथे सम्मेलन तक आते-आते विश्व सामाजिक मंच का विरोध पक्ष एक व्यापक और संगठित शक्ल अख्तियार करने लगा है। विरोध पक्ष का एक प्रमुख बैनर *'मुंबई रेजिसटेंस-2004'* का है, जिसमें क्रान्तिकारी वामपंथी राजनीति से जुड़े संगठन और ट्रेड यूनियनें, कुछ स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें व जनसंगठन और कई किसान संगठन भी शामिल हैं। मुंबई में विश्व सामाजिक मंच के समांतर इस मंच का भी आयोजन होगा। एक और समानांतर आयोजन साम्राज्यवाद विरोधी *'अखिल भारतीय सम्मेलन'* के रूप में भी होगा, जिसमें भारत के दो दर्जन से भी अधिक क्रान्तिकारी वामपंथी मजदूर संगठन, छात्र-युवा संगठन, किसान संगठन और सांस्कृतिक संगठन हिस्सा ले रहे हैं।

विरोध के विभिन्न बिखरे स्वरों को एकजुट करके साझा लक्ष्य की ओर प्रभावी बनाने के लिए बहस और संवाद आज की एक फौरी जरूरत है और सर्वोपरि तौर पर यह जिम्मेदारी इस काम में लगे क्रान्तिकारी वाम की है, क्योंकि साम्राज्यवाद और उसके हितपोषक मंचों के विरुद्ध कोई साझा कार्रवाई उन्हीं की अगुवाई में प्रभावी हो सकती है। इस दृष्टि से हमारी आलोचना, हमारी राय और हमारी बहस मुख्यतः क्रान्तिकारी वाम शक्तियों को ही सम्बोधित है।

विश्व सामाजिक मंच का विरोध भूमण्डलीकरण के विरोध यानी साम्राज्यवाद और देशी पूँजीवाददोनों ही के विरोध का एक रणनीतिक प्रश्न है। यह लड़ाई राष्ट्रीय सम्प्रभुता या धनी किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों की हिफाजत (क्योंकि मालिकाने का प्रश्न तो अब हल हो चुका है) की जमीन पर खड़े होकर नहीं लड़ी जा सकती।

विश्व सामाजिक मंच के साझा विरोध की रणनीति के सम्बन्ध में, हमारी पहली स्पष्ट धारणा यह है कि यह स्पष्टतः सिर्फ एक मुद्दे पर केन्द्रित होनी चाहिये और वह हैसाम्राज्यवाद के एक 'सेफ्टी वाल्व' और 'ट्रोजन हॉर्स' के रूप में काम करने वाले विश्व सामाजिक मंच के चरित्र, संरचना और वर्ग सहयोगवादी राजनीति के व्यापकतम सम्भव 'एक्सपोजर' के लिए प्रचार और एजिटेशन का एक ठोस कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे अमल में लाना। विश्व सामाजिक मंच की राजनीति को समग्रता में 'एक्सपोज' किया जाना चाहिये। विश्व सामाजिक मंच जिस तरह वर्ग-विभेद के प्रश्न को ओझल करके मुद्दों को वर्गेतर आधार पर खण्ड-खण्ड में बांटकर विमर्श आयोजित करता है, यदि हम भी अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति के लिए विषय-विभाजन के उसी फ्रेमवर्क को कमोबेश स्वीकार करेंगे तो हम विरोधी के 'ट्रैप' में ही उलझ जायेंगे, समाजवाद को एकमात्र विकल्प बताते हुए भी बात बिखर जायेगी और एक अकादमिक कसरत बन कर रह जायेगी तथा विश्व सामाजिक मंच के 'एक्सपोजर' और उसके विरुद्ध जनमानस तैयार करने का कार्यभार प्रभावी ढंग से नहीं हो सकेगा। इस प्रश्न पर हमारी पहुंच 'मुंबई रेसिसटेंस-2004' की अपेक्षा 'अखिल भारतीय सम्मेलन' के अधिक निकट है।

दूसरी बात, विश्व सामाजिक मंच का विरोध करते हुए यदि हम वास्तव में इस स्थापना को प्रस्तुत करते हैं कि समाजवाद ही भूमण्डलीकरण का एकमात्र विकल्प है, तो बहुतेरे स्वतंत्र मजदूर संगठन, गरीब किसानों, खेत मजदूरों और विभिन्न कोटि के मध्यवर्गीय जनसंगठन तो हमारे सच्चे और स्थायी संश्रयकारी

बन सकते हैं, लेकिन बुर्जुआ फार्मरों-कुलकों के संगठनों के साथ यह बात कत्तई लागू नहीं होती। भूमण्डलीकरण के विरोध की इनकी जमीन एकदम अलग है और यह एक किस्म के 'प्रतिक्रियावादी यूटोपिया' की जमीन है। लाभकारी मूल्य के लिए या खेती के मुनाफे को बनाये रखने के लिए लड़ने वाले ये मालिक किसान भूमण्डलीकरण से अधिक समाजवाद के विरोधी हैं। भूमण्डलीकरण का विरोध करते हुए वे वस्तुतः कुल विनियोजित अधिशेष में अपनी भागीदारी घटाने के विरुद्ध लड़रहे हैं। पूँजीवादी विकास के साथ ही उद्योग के अनुपात में खेती का पीछे छूटते जाना मध्यम किसानों के एक बड़े हिस्से तक को उजाड़ कर सर्वहारा बनने के खतरे तक पहुँचा देता है और मालिकाने की कसक के बावजूद उसे विकल्प पूँजीवाद के सीमान्तों के बाहर दीखने लगता है, जिसे स्वीकारना अंततः उसकी विवशता होती है। पर धनी किसान के साथ यह बात नहीं लागू होती। उसका संकट मुनाफा घटने का संकट है। साम्राज्यवादियों और छोटे-बड़े देशी पूँजीपतियों के बाद वह शोषण और शासन का सबसे छोटा पार्टनर है, जिसे बाँट-बखरे में सबसे अधिक "अन्याय" का शिकार होना पड़ता है और पूँजीवादी विकास के साथ ही पैदा होने वाले संकट का बोझ भी उद्योग के मुकाबले कृषि को और पूँजीपतियों के मुकाबले फार्मरों-कुलकों को अधिक झेलना पड़ता है। उदारीकरण की नीतियों और विशेषकर विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के चलते कृषि क्षेत्र में अनिवार्यतः जो ध्रुवीकरण होने वाला है, वे उसे रोकना चाहते हैं। यही उनका 'प्रतिक्रियावादी यूटोपिया' है। इसमें मजदूर और जनता के अन्य वर्गों की कोई साझेदारी नहीं हो सकती। उल्लेखनीय है कि 'मुंबई रेजिसटेंस-2004' में *भारतीय किसान यूनियन* और *कर्नाटक राज्य रैयत संघ* जैसे धनी किसानों-फार्मरों के राजनीतिक वर्चस्व वाले संगठन भी शामिल हैं। ये भूमण्डलीकरण की नीतियों से अपने मुनाफे की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, चाहे इनके तेवर जितने भी रैडिकल क्यों न हों! इनको साथ लेकर भला इस नारे को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है कि *'समाजवाद ही एकमात्र विकल्प है।'* विश्व सामाजिक मंच का विरोध भूमण्डलीकरण के विरोध यानी साम्राज्यवाद और देशी पूँजीवाददोनों ही के विरोध का एक रणनीतिक प्रश्न है। यह लड़ाई राष्ट्रीय सम्प्रभुता या धनी किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों की हिफाजत (क्योंकि मालिकाने का प्रश्न तो अब हल हो चुका है) की जमीन पर खड़े होकर नहीं लड़ी जा सकती। यह बात इस नारे से भी स्पष्ट है कि 'समाजवाद ही एकमात्र विकल्प है!' वस्तुतः क्रान्तिकारी वाम के जो संगठन आज भी जनवादी क्रान्ति की सोच पर डटे हुए हैं और धनी किसानों को साथ लेने के लिए लाभकारी मूल्य की लड़ाई लड़ने तक का ठेका लिए हुए हैं (जो कि स्पष्टतः एक सर्वहारा-विरोधी प्रतिक्रियावादी मांग है) उनकी यह गलती "तर्कसंगत" है कि वे विश्व सामाजिक मंच जैसे किसी साम्राज्यवादी कुचक्र के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे में धनी किसानों के संगठनों को साझीदार बनायें। तर्कसंगत तो यही होता कि साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा भूमण्डलीकरण के दौर में तीसरी दुनिया के देशों के "पुनर्औपनिवेशीकरण" (जैसा कि नयी जनवादी क्रान्ति की समझ बताती है) के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति के आकांक्षी "राष्ट्रीय" बुर्जुआ के कुछ संगठनों को भी वे खोज लेते और उन्हें भी संयुक्त मोर्चे का साझीदार बना लेते! बहरहाल, हमारी यह स्पष्ट समझ है कि ऐसा कोई भी मोर्चा न तो प्रभावी हो सकता है और न ही टिकाऊ।

विश्व सामाजिक मंच की राजनीति को समग्रता में 'एक्सपोज' किया जाना चाहिये। मंच जिस तरह वर्ग-विभेद के प्रश्न को ओझल करके मुद्दों को वर्गेतर आधार पर खण्ड-खण्ड में बांटकर विमर्श आयोजित करता है, यदि हम भी अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति के लिए विषय-विभाजन के उसी फ्रेमवर्क को कमोबेश स्वीकार करेंगे तो हम विरोधी के 'ट्रैप' में ही उलझ जायेंगे, समाजवाद को एकमात्र विकल्प बताते हुए भी बात बिखर जायेगी और मंच के 'एक्सपोजर' और उसके विरुद्ध जनमानस तैयार करने का कार्यभार प्रभावी ढंग से नहीं हो सकेगा।

तीसरी बात, हमारी यह भी स्पष्ट समझ है कि भूमण्डलीकरण और विश्व सामाजिक मंच के विरुद्ध आनन-फानन में रंगे-बिरंगे संगठनों-समूहों-व्यक्तियों को जोड़कर झटपट कोई अंतरराष्ट्रीय मोर्चा-संगठन बना लेने की प्रवृत्ति अव्यावहारिक और लक्ष्य को अंततः नुकसान ही पहुँचाने वाली सिद्ध होगी। क्रान्तिकारी वाम के कुछ हलकों में आज आनन-फानन में तरह-तरह के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे और मंच बना लेने की प्रवृत्ति बुरी तरह से हावी है। इसके लिए ऐसे संगठन उसूली मसलों पर भी समझौते और लीपापोती करने तथा अस्पष्ट बात करने की तरकीबों का सहारा लेते हैं, सहमति और असहमति के मुद्दों को तार-तार साफ नहीं करते और राजनीति के बजाय संगठन को कमान में लेकर चलने की गलत पहुँच-पद्धति का सहारा लेते हैं। दरअसल, ये संगठन विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन की गलत समझ के चलते अपने जमीनी कामों में पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए बड़े-बड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने और कतारों को उनके आभामण्डल से उत्साहित बनाये रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मोर्चों और मंचों में ज्यादा से ज्यादा नाम जोड़ने के चक्कर में वे सम्भावित घटकों की वास्तविकता की कोई जाँच-पड़ताल जरूरी नहीं समझतेइस पर कोई ध्यान नहीं देते कि कौन संगठन बरायनाम संगठन है या बातबहादुरों का छोटा-मोटा समूह मात्र है। यह प्रवृत्ति बहुत अधिक गैर जिम्मेदाराना है और विश्व सामाजिक मंच के विरुद्ध सक्रिय क्रान्तिकारी वाम के विभिन्न हिस्सों में गहराई से पैठी हुई है। ऐसे संगठन फौरी तौर पर जनता में वास्तविकता से अधिक उम्मीदें जगाते हैं और फिर पहले से भी अधिक गहरी निराशा में ले जाकर धँसा देते हैं। किसी भी संयुक्त मोर्चे की वास्तविक ताकत ढेरों नामों से या हमारी मनोगत चाहत से नहीं, बल्कि घटक संगठनों की वास्तविक ताकत से, उनके जमीनी काम से तय होती है। आज

आनन-फानन में अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाकर ढेरों काम हाथ में ले लेने और कभी इस तो कभी उस देश में दौड़-दौड़ कर संगोष्ठी और सम्मेलन करने से कोई मकसद नहीं पूरा होगा। बेहतर यही होगा कि सिर्फ इस एक लक्ष्य पर ही स्पष्ट आम सहमति बनाकर और तौर-तरीके तय करके कोई साझा मंच बनाया जाये कि विश्व सामाजिक मंच और इसके मुख्य घटक एनजीओ और सामाजिक जनवादी पार्टियों की राजनीति को साझा तौर पर और अलग-अलग कार्रवाईयों के जरिये, व्यापक जनता के बीच 'एक्सपोज' किया जाये।

चौथी बात, क्रान्तिकारी वाम के कतिपय संगठनों में यह अवसरवादी प्रवृत्ति मौजूद है कि वे अपने मुखपत्रों और जनसंगठनों के अवस्थिति पत्रों में तो गैर सरकारी संगठनों की राजनीति का सही-सटीक विश्लेषण करते हैं, लेकिन व्यवहार में व्यापक जनता के बीच प्रचार और एजीटेशन द्वारा उनकी असलियत उजागर करने से बचते हैं, उनके विरुद्ध कोई मोर्चा नहीं खोलते, एनजीओ धन्धे में लिप्त, लेकिन मुँह से क्रान्तिकारी बातें करते रहने वाले तथाकथित क्रान्तिकारियों के प्रति नरम और दोस्ताना रुख अपनाते हैं और बातचीत में यह तर्क देते हैं कि गैर सरकारी संगठनों में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, जो एनजीओ के विरुद्ध व्यापक भंडाफोड़ चलाने और खुलकर उनकी आलोचना रखने से बिदक जायेंगे। यह एक गैर मार्क्सवादी, एक अवसरवादी पहुँच है। इस तर्क से तो हमें सामाजिक जनवादी और संशोधनवादी पार्टियों के प्रति भी ऐसा ही रुख अपनाना चाहिये, क्योंकि उनमें भी कुछ नासमझ, दिग्भ्रमित ईमानदार लोग मौजूद हैं। सही मार्क्सवादी पहुँच-पद्धति बताती है कि यदि गैर सरकारी संगठनों में कुछ ईमानदार जनपक्षधर लोग मौजूद भी हों, तो उन्हें फुसला-सहलाकर या पुचकार कर नहीं, बल्कि खरे शब्दों में ऐसे संगठनों की वास्तविकता बतलाकर ही क्रान्तिकारी धारा के पक्ष में लाया जा सकता है।

पाँचवी बात, गैर सरकारी संगठनों और विश्व सामाजिक मंच की राजनीति, इतिहास, भूगोल का लगभग सही विश्लेषण करते हुए भी, क्रान्तिकारी वाम के बहुतेरे ऐसे संगठन और जनसंगठन हैं, जो विश्व सामाजिक मंच के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर या तो दिग्भ्रमित और अस्पष्ट हैं, या फिर अवसरवाद के शिकार हैं। इसके एक प्रतिनिधि उदाहरण के तौर पर हम *अखिल भारतीय जन-प्रतिरोध मंच (एआईपीआरएफ)* को ले सकते हैं। एआईपीआरएफ अपने अवस्थिति पत्र में एनजीओ और विश्व सामाजिक मंच की राजनीति का विस्तृत, तथ्यपरक और मुख्यतः सही-सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और व्यापक जनता के बीच इसको 'एक्सपोज' करने का कार्यभार तय करता है। उसकी यह अवस्थिति भी सही है कि यह काम विश्व सामाजिक मंच में सीधी भागीदारी द्वारा सम्भव नहीं है, बल्कि उसके और अपने बीच विचारधारात्मक और राजनीतिक तौर पर स्पष्ट विभाजक रेखा खींच कर ही इसे अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ अवस्थिति-पत्र में यह भी लिख दिया गया है: **"इसके साथ ही, हमें विश्व सामाजिक मंच के प्रति संकीर्णतावादी रुख अपनाने से अपने को बचाना चाहिये। हमारा रुख एकता और संघर्ष का होना चाहियेजहां तक वे साम्राज्यवाद-विरोधी रुख अपनाते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं वहां तक एकता और विचारधारात्मक-राजनीतिक दायरे में उनकी गैर-वर्गीय या वर्गोपरि अवस्थिति और साम्राज्यवाद से संघर्ष करने में उनके सुधारवादी रुख के विरुद्ध संघर्ष चलाना चाहिये। यदि विश्व सामाजिक मंच स्वयं को जनता के जुझारू संघर्षों में लगाता है, तो हमें इसके साथ मिलकर संघर्ष करने की अपनी चाहत को खुले तौर पर व्यक्त करना चाहिये। हमें यह तथ्य दिमाग में रखना होगा कि विश्व सामाजिक मंच प्रगतिशील संगठनों और व्यक्तियों की एक अच्छी-खासी संख्या को आकृष्ट करने में सफल रहा है। जो अमानवीय पूँजीवादी व्यवस्था से पैदा होने वाले अलगाव और अमानवीकरण के प्रति जुगुप्सा से भरे हुए हैं, जो साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के वास्तव में विरोधी हैं और वर्तमान शोषणपूर्ण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए व्यग्र हैं। हमें उन सभी की भर्त्सना का रुख नहीं अपनाना चाहिये जो विश्व सामाजिक मंच के कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं। इसके बजाय, इन हिस्सों को विश्व सामाजिक मंच की राजनीति से अलग करने के लिए और समाज के क्रान्तिकारी रूपान्तरण के संघर्ष में उन्हें खींच लाने के लिए हमारे पास एक ठोस कार्यक्रम होना चाहिये।"** (अनुवाद हमारा, जोर मूल में)

किसी भी संयुक्त मोर्चे की वास्तविक ताकत ढेरों नामों से या हमारी चाहत से नहीं, बल्कि घटक संगठनों की वास्तविक ताकत से, उनके जमीनी काम से तय होती है। आज आनन-फानन में अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाकर ढेरों काम हाथ में ले लेने और कभी इस तो कभी उस देश में दौड़-दौड़ कर संगोष्ठी और सम्मेलन करने से कोई मकसद नहीं पूरा होगा। ...सिर्फ इस एक लक्ष्य पर ही स्पष्ट आम सहमति बनाकर कोई साझा मंच बनाया जाये कि विश्व सामाजिक मंच और इसके मुख्य घटक एनजीओ और सामाजिक जनवादी पार्टियों की राजनीति को साझा तौर पर और अलग-अलग कार्रवाईयों के जरिये, व्यापक जनता के बीच 'एक्सपोज' किया जाये।

हम समझते हैं कि यह पूरा अंश अवस्थिति पत्र के पूरे सटीक विश्लेषण पर पानी फेर देता है और उसे अंतरविरोधपूर्ण और भ्रामक बना देता है। इसका कारण या तो वैचारिक समझ का अभाव हो सकता है या फिर अवसरवादी ढुलमुलपन। विश्व सामाजिक मंच यदि सुनियोजित ढंग से साम्राज्यवाद के शीर्ष रणनीति-निर्माताओं द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशक सिद्धान्तों पर खड़ा किया गया है, यदि इसके मुख्य घटक विश्व के अग्रणी गैर सरकारी संगठन और घुटी-घुटायी सामाजिक जनवादी पार्टियां हैं और नीति-निर्देशक एवं शीर्ष कार्यकारी निकायों में यदि गैर सरकारी संगठनों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित है, तो यह रंचमात्र आशा भी एक दिवास्वप्न ही हो सकती है कि किन्हीं भी स्थितियों में मंच साम्राज्यवाद-विरोधी रुख अपनायेगा और स्वयं को जुझारू संघर्षों में लगायेगा। अव्वल तो यह कि विश्व सामाजिक मंच स्वयं ही

एकदम स्पष्ट कर देता है कि यह किसी प्रकार की साझा कार्रवाई का नहीं, बल्कि तालमेल, विमर्श और अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच है, फिर भी एआईपीआरएफ उससे जुझारू संघर्षों तक में उतर पड़ने की उम्मीद पाले रहने पर अड़ा हुआ है। विश्व सामाजिक मंच जब किसी राजनीतिक संघर्ष या कार्रवाई में उतरेगा ही नहीं तो फिर एकता बनाने या साझापन दिखाने की बात ही कहां से आती है? विश्व सामाजिक मंच न तो किसी एक फौरी ज्वलंत मुद्दे पर वस्तुगत परिस्थितियों के दबाव से स्वतःस्फूर्त ढंग से खड़ा हो गया कोई ढीला-ढाला सा मंच है, न ही यह कोई बुर्जुआ जनसंगठन है, जिसके साथ हम जनता के किसी फौरी मुद्दे पर मोर्चा बनाकर एकता और संघर्ष का दृष्टिकोण अपनायें। यह जनता का रणनीतिक संश्रयकारी तो खैर कत्तई नहीं है, इसके साथ रणकौशलात्मक साझा कार्रवाई की भी न तो कोई गुंजाइश है, न जरूरत और न ही बाध्यता। साम्राज्यवादी नीति-निर्माताओं ने समाजवाद विरोधी प्रचार के विचारधारात्मक कार्य और भूमण्डलीकरण के दौर के सुनिश्चित कार्यभारों को अन्जाम देने के लिए इसे सूझबूझ के साथ गढ़ा है। इसका दायरा और स्वरूप रणनीतिक है और आज की साम्राज्यवादी नीतियों का यह एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। इसके मुख्य घटक गैर सरकारी संगठन और सामाजिक जनवादी पार्टियों के जनसंगठन हैं। गैर सरकारी संगठन जनता की वर्गीय एकजुटता को तोड़ने के लिए वर्गेतर आधार और वर्गेतर नारेबाजियों के साथ, जनता की जिन्दगी की जिन परेशानियों और मुद्दों को लेकर यहाँ-वहाँ, अलग-थलग कुछ आन्दोलन संगठित करते रहते हैं, उनमें भी भागीदारी करना उनकी राजनीति की साख बढ़ाने और उनके बारे में भ्रम पैदा करने का ही काम करेगा तथा स्वयं क्रान्तिकारी ही वर्गोपरिता की राजनीति के शिकार हो जायेंगे। एकमात्र रास्ता यही हो सकता है कि सही जनान्दोलन का वैकल्पिक मॉडल खड़ा किया जाये और एनजीओ की असलियत उजागर करने का काम सतत चलाया जाये। यदि हमारी पद्धति सही होगी तो जनता अपने अनुभवों और हमारी बातों का मिलान करके तथा हमारे राजनीतिक नेतृत्व में खड़े मोर्चों और आन्दोलनों को देखकर सही जगह आ खड़ी होगी। किन्हीं स्थितियों में सामाजिक जनवादी पार्टियों के साथ रणकौशलात्मक संयुक्त मोर्चे बनाने की स्थितियां जरूर हो सकती हैं और उनके राजनीतिक वर्चस्व वाली ट्रेड यूनियनों के भीतर काम करने की हर गुंजाइश के इस्तेमाल के बारे में लेनिनवादी दृष्टिकोण भी एकदम स्पष्ट है, लेकिन महज इस तथ्य के नाते भी विश्व सामाजिक मंच के साथ मोर्चा बनाने और एकता और संघर्ष का रुख अपनाने की दलील नहीं गढ़ी जा सकती। बहरहाल, सबसे बुनियादी बात तो यह है कि मंच जब राजनीतिक कार्रवाई का माध्यम है ही नहीं तो फिर एकता और संघर्ष की बात ही कहाँ से आती है? शायद साम्राज्यवाद-विरोधी पहुँच में जनता के मुद्दों पर कुछ एकता ढूँढकर कुछ संयुक्त वक्तव्य जारी करने की बात एआईपीआरएफ के दिमाग में हो, पर ऐसा करना भी तो विश्व सामाजिक मंच के बारे में भ्रम पैदा करने और उसकी साख बढ़ाने का ही काम करेगा। दरअसल, अवस्थिति-पत्र में यह हिस्सा कुछ उन ईमानदार साम्राज्यवाद विरोधी, लेकिन विश्व सामाजिक मंच के बारे में दिग्भ्रमित तत्वों को, जो विश्व सामाजिक मंच में शामिल हैं, दिमाग में रखकर डाला गया है कि कहीं वे बिदक न जायें। दरअसल, एआईपीआरएफ ऐसे तत्वों के साथ वास्तविकता बताकर, संघर्ष और साफगोई के जरिये एकता बनाने की सही राजनीति के बजाय तुष्टीकरण और हेलमेल की व्यवहारवादी राजनीति के सहारे उन्हें सही पक्ष में ला खड़ा करना चाहता है। बेशक, हम इस विचार से सहमत हैं कि विश्व सामाजिक मंच के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी लोगों की भर्त्सना नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उनमें कुछ ईमानदार प्रगतिशील तत्व भी हैं। लेकिन उनके सामने मंच के बारे में अपनी समझ को तो साफगोई के साथ रखना ही चाहिये। आज नहीं तो कल, जब वे अपने अनुभवों से हमारे मूल्यांकन को सही पायेंगे और उनकी ईमानदारी बनी रहेगी तो वे सही जगह आ खड़े होंगे। विश्व सामाजिक मंच द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष या जुझारू जनान्दोलन खड़ा करने की नितांत हवाई अपेक्षा पालकर और उसके प्रति एकता और संघर्ष का रुख अपनाने की घोषणा करके एआईपीआरएफ ऐसे तत्वों को सही अवस्थिति पर लाने की जगह उन्हें और अधिक दिग्भ्रमित करने का ही काम कर रहा है।

एआईपीआरएफ के अवस्थिति-पत्र का यह अंतरविरोध एक तरह का उदारतावाद है। "वामपंथी" संकीर्णता के छोर से दक्षिणपंथी अवसरवाद के दूसरे छोर तक जाने की क्रमिक यात्रा के मध्य कभी-कभी इन दोनों का अजीबो-गरीब दिलचस्प मिश्रण संगठनों की नीतियों-क्रियाकलापों में देखने को मिलता है। एक जगह संकीर्णतावाद पर अमल करना तो दूसरी जगह संकीर्णतावाद के विरुद्ध चेतावनियाँ जारी करते हुए उदारतावादी अवस्थिति पर जा खड़े होनाअति वाम से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए, बीच के समय में ऐसा प्रायः देखने को मिलता है।

●

"वामपंथी" संकीर्णता के छोर से दक्षिणपंथी अवसरवाद के दूसरे छोर तक जाने की क्रमिक यात्रा के मध्य कभी-कभी इन दोनों का अजीबोगरीब दिलचस्प मिश्रण संगठनों की नीतियों-क्रियाकलापों में देखने को मिलता है। एक जगह संकीर्णतावाद पर अमल करना तो दूसरी जगह संकीर्णतावाद के विरुद्ध चेतावनियाँ जारी करते हुए उदारतावादी अवस्थिति पर जा खड़े होनाअति वाम से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए, बीच के समय में ऐसा प्रायः देखने को मिलता है।

वर्ल्ड सोशल फोरम

पर

एक परिसंवाद

(सिम्पोज़ियम)

'दायित्वबोध' का यह विशेष अंक एक परिसंवाद के रूप में संयोजित किया गया है।

भारत में क्रान्तिकारी और परिवर्तनवादी शक्तियों तथा प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के बड़े हिस्से के बीच डब्ल्यूएसएफ को लेकर कई तरह के रुख मौजूद हैं। डब्ल्यूएसएफ के स्वरूप, भूमिका तथा इसके प्रति रवैये को लेकर इनमें मतभेद हैं तथा कई तरह के भ्रम बने हुए हैं। अंक को संयोजित करते समय कोशिश की है कि सभी धाराओं के विचारों का प्रतिनिधित्व यहां भारत तथा विश्व के कुछ अन्य देशों में सक्रिय क्रान्तिकारी शक्तियों के विचारों के साथ ही कुछ स्वतंत्र मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों के लेख भी शामिल किये गये हैं। परिशिष्ट में डब्ल्यूएसएफ का चार्टर तथा 'मुम्बई प्रतिरोध" और 'साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता की ओर से जारी अपील के मुख्य अंश दिये गये हैं।

डब्ल्यूएसएफ के उद्‌भव तथा इसकी भूमिका के बारे में कुछ लेखों में दोहराव पाठकों को अखर सकता है लेकिन हमने उसे संपादित करने के बजाय ज्यों का त्यों रहने दिया है ताकि सभी पक्षों की बातें अपनी पूर्णता में पाठकों के सामने आ सकें।

हमें उम्मीद है कि 'दायित्वबोध' का यह आयोजन वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रति एक सही पहुंच और सोच बनाने में मददगार साबित होगा। हमें पाठकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

सम्पादक

राज्यवर्ग विरोधों की असाध्यता की उपज

मार्क्स की शिक्षा के साथ आज वही हो रहा है, जो उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति संघर्ष में उनके नेताओं और क्रान्तिकारी विचारों की शिक्षाओं के साथ इतिहास में अक्सर हुआ है। उत्पीड़क वर्गों ने महान क्रान्तिकारियों को उनके जीवन भर लगातार यातनाएं दीं, उनकी शिक्षा का अधिक से अधिक बर्बर द्वेष, अधिक से अधिक क्रोधोन्मत्त घृणा तथा झूठ बोलने तथा बदनाम करने की अधिक से अधिक अंधाधुंध मुहिम से उत्तर दिया। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी क्रान्तिकारी शिक्षा को **सारहीन** करके, उसकी क्रान्तिकारी धार को कुंद करके, उसे भ्रष्ट करके उत्पीड़ित वर्गों को "बहलाने" तथा धोखा देने के लिए उन्हें अहानिकर देव प्रतिमाओं का रूप देने, यों कहें, उन्हें देवत्व प्रदान करने और उनके **नामों** को निश्चित गौरव प्रदान करने के प्रयत्न किये जाते हैं। मार्क्सवाद को इस तरह "संसाधित करने" में बुर्जुआ वर्ग और मजदूर आंदोलन के अवसरवादियों के बीच आज सहमति है। उस शिक्षा के क्रान्तिकारी पहलू को, उसकी क्रान्तिकारी आत्मा को भुला दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, विकृत कर दिया जाता है। उस चीज को सामने लाया जाता है, गौरवान्वित किया जाता है, जो बुर्जुआ वर्ग को मान्य है या मान्य प्रतीत होती है। सभी सामाजिक अंधराष्ट्रवादी अब "मार्क्सवादी" बन गये हैं, हंसिए नहीं! और कल तक मार्क्सवाद का संहार करने के विशेषज्ञ जर्मन बुर्जुआ विद्वान अब अधिकाधिक "राष्ट्रीय-जर्मन" मार्क्स की बात करते हैं, जिन्होंने मानो लुटेरू युद्ध चलाने के लिए ही शानदार ढंग से संगठित मजदूर यूनियनों को प्रशिक्षित किया था!

ऐसी परिस्थितियों में मार्क्सवाद की अभूतपूर्व व्यापक विकृति को देखते हुए हमारा पहला कर्तव्य राज्य के बारे में मार्क्स की असली शिक्षा की **पुनःस्थापना** करना है। इसके लिए खुद मार्क्स और एंगेल्स की रचनाओं से बहुतेरे लम्बे उद्धरण देना जरूरी है।

...अपने ऐतिहासिक विश्लेषण का निष्कर्ष निकालते हुए एंगेल्स कहते हैं :

"राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर से लाकर समाज पर लादी गयी है; और न वह 'किसी नैतिक विचार का मूर्त रूप' या 'विवेक का मूर्त और वास्तविक रूप' है, जैसा कि हेगेल कहते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि वह समाज की उपज है, जो विकास की एक निश्चित अवस्था में प्राप्त होती है; वह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि यह समाज हल न होने वाले अंतरविरोधों में फंस गया है, वह ऐसे विरोधों से विदीर्ण हो गया है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता और जिन्हें दूर करना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। परन्तु यह विरोध, परस्पर विरोधी आर्थिक हितों वाले ये वर्ग, व्यर्थ के संघर्ष में अपने को और पूरे समाज को नष्ट न कर डालें, इसलिए एक ऐसी शक्ति, जो मालूम पड़े कि समाज से ऊपर खड़ी है, आवश्यक बन गयी है ताकि इस संघर्ष को हल्का किया जा सके, उसे 'व्यवस्था' की सीमाओं के भीतर रखा जा सके। यही शक्ति, जो समाज से पैदा होती है, पर जो समाजोपरि स्थान ग्रहण कर लेती है और उससे अधिकाधिक पृथक होती जाती है, राज्य है" (छठा जर्मन संस्करण, पृष्ठ 177-78)।

यहां राज्य की ऐतिहासिक भूमिका और उसके अर्थ के सवाल पर मार्क्सवाद का बुनियादी विचार पूर्ण स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त है। राज्य वर्ग विरोधों की **असाध्यता** की उपज और अभिव्यक्ति है। राज्य उस समय, उस जगह और उस हद तक पैदा होता है, जब, जहां और जिस हद तक वर्ग विरोधों का वस्तुपरक ढंग से समाधान **नहीं हो सकता।** और उलटकर कहें, तो राज्य की मौजूदगी यह साबित करती है कि वर्ग विरोधों का समाधान असम्भव है।

ठीक इसी सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सूत्र पर दो मुख्य लाइनों पर चलने वाली मार्क्सवाद की तोड़-मरोड़ शुरू होती है।

एक तरफ तो वे बुर्जुआ और खासतौर से टुंटपूंजिया विचारधारा निरूपक, जो निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्यों के दबाव से यह मानने को मजबूर हैं कि राज्य वहीं होता है जहां वर्ग विरोध और वर्ग संघर्ष होते हैं, मार्क्स को इस तरह "सुधारते" हैं कि राज्य वर्गों के **समन्वय** का निकाय बनकर सामने आता है। मार्क्स के अनुसार अगर वर्गों का समन्वय सम्भव होता, तो राज्य पैदा नहीं हो सकता था, कायम नहीं रह सकता था। टुटपूंजिया और दकियानूसी प्रोफेसरों और इतिवृत्तकारों के यहांहर कहीं और अक्सर मार्क्स के अनुग्रहपूर्ण हवालों के साथऐसा होता है कि राज्य वर्गों का समन्वय करता ही है। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग **प्रभुत्व** का निकाय है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के **उत्पीड़न** का निकाय है, ऐसी "व्यवस्था" की सर्जना है, जो वर्गीय टकरावों को मद्धिम करके इस उत्पीड़न को कानूनी और मजबूत बनाती है। टुटपूंजिया राजनीतिज्ञों की राय में व्यवस्था वर्गों का समन्वय ही है, न कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न; टकरावों को मद्धिम करने का अर्थ है समन्वय करना, न कि उत्पीड़ित वर्गों को उत्पीड़कों का तख्ता उलटने के लिए लड़ने के निश्चित साधनों और तरीकों से वंचित करना।

लेनिन
(राज्य और क्रान्ति)

वर्ल्ड सोशल फोरम का अर्थशास्त्र और राजनीति

रिसर्च यूनिट फार पोलिटिकल इकॉनमी, मुम्बई द्वारा प्रकाशित पत्रिका **आस्पेक्ट्स आफ इण्डियाज इकॉनमी** के विशेष अंक (नं. 35 सितम्बर 2003) से साभार लिया गया यह सम्पादित अंश वर्ल्ड सोशल फोरम बनने की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया, उसे नियंत्रित करने वाली ताकतों तथा भारत में एनजीओ परिघटना को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए काफी मददगार होगा। मुम्बई में डब्ल्यूएसएफ के चौथे सम्मेलन को आयोजित करने में भाकपा और माकपा जैसी पार्टियों तथा एनजीओ की भूमिका पर भी विशेष रूप से रोशनी डाली गयी है। *सम्पादक*

वर्ल्ड सोशल फोरम और भूमण्डलीकरण के खिलाफ संघर्ष

वर्ल्ड सोशल फोरम कैसे और क्यों अस्तित्व में आया

वर्ल्ड सोशल फोरम का चौथा जमावड़ा जनवरी 2004 में मुंबई में होने जा रहा है। भारत के लिए यह कार्यक्रम अभूतपूर्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय ध्यानाकर्षण करेगा और यह अभी से भूमण्डलीकरण विरोधी हलकों में भारी दिलचस्पी, चर्चा और बहस का विषय बन गया है। भारत में और विदेश में डब्ल्यूएसएफ पर कई अंतदृष्टिपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख पहले ही लिखे जा चुके हैं। यहां हमारा उद्देश्य इन बोधों में से कुछ को इकट्ठा करना कुछ बिन्दुओं को पुष्ट करना और कुछ बिंदुओं को आगे जोड़ना है।

सिएटल के प्रदर्शन और उसके बाद

डब्ल्यूएसएफ के उद्‌भव की शिनाख्त (विपरीत तरीके से) अमेरिका के सिएटल में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नवम्बर 1999 सम्मेलन के समय हुए विरोध और टकराव के जबर्दस्त अंतर्राष्ट्रीय उभार से जोड़कर की जा सकती है। विश्व की सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं के बीच के विवादों से घिरा डब्ल्यूटीओ का यह सम्मेलन आगे चलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के भारी तूफान के फलस्वरूप निर्णायक रूप से अस्त-व्यस्त हो गया। विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे पचास हजार लोगों में पूंजीवाद विरोधी प्रचारकों, अराजकतावादियों, तीसरी दुनिया के ऋण के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने वालों, पर्यावरणवादियों और यहां तक कि अमेरिका की संगठित श्रमशक्ति के उल्लेखनीय तबकों सहित तरह-तरह के लोग शामिल थे। सम्मेलन अपनी कार्य सूची को पूरा किये बगैर पूर्ण असफलता के साथ समाप्त हुआ। भूमण्डलीकरण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने वालों के लिए सिएटल सांकेतिक विजय और इस बात का प्रमाण था कि इस तरह की लड़ाई सम्भव है और काम की है।

अगले डेढ़ वर्ष तक सिएटल से प्रेरित विरोध प्रदर्शनों की शृंखला अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और संस्थानों के हरेक प्रमुख जमावड़े को बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त करती रही। इन जमावड़ों में दाबोस में जनवरी 2000 में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक (विश्व के अग्रणी निगमों और देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा), अप्रैल 2000 में वाशिंगटन में आईएमएफ-विश्व बैंक की बसन्त ऋतु की बैठक, सितम्बर 2000 में मेलबोर्न में डब्ल्यूईएफ का शिखर सम्मेलन, सितम्बर 2000 में प्राग में आईएमएफ-विश्वबैंक की वार्षिक बैठक, दिसम्बर 2000 में नीस में यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन, जनवरी 2001 की दावोस बैठक, अप्रैल 2001 में उत्तरी-दक्षिणी अमेरिका का क्यूबेक आर्थिक सम्मेलन, जून 2001 में गोथेनबर्ग में यूरोपीय संघ का सम्मेलन, जुलाई 2001 में साल्जबर्ग में डब्ल्यूईएफ की बैठक और जुलाई 2001 में जिनेवा में समूह-8 का विश्व आर्थिक सम्मेलन शामिल है।

हर जगह सम्मेलन प्रमुखों और कारपोरेट मीडिया ने प्रदर्शनकारियों पर निरर्थक विनाश की कार्रवाइयों को अंजाम देने का आरोप लगाया।*

व्यापक संदर्भों में कहें तो वह एजेण्डा था आर्थिक घेरेबंदी को और सख्त बनाना, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को आयात, विदेशी निवेश और निजीकरण द्वारा आगे और हमले और कब्जे के लिए खुलवाना, उन्नत औद्योगीकृत देशों और तीसरी दुनिया दोनों जगहों पर श्रम शक्ति का और अवमूल्यन करना (प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से), वर्तमान की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से पूंजी का संकेन्द्रण और इस खेल में अग्रणी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच विवादों को हल करना।

*कुछ शोरूमों की खिड़कियों और मोटरगाड़ियों को क्षतिग्रस्त किये जाने के बारे में उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण चिंता के बरक्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछले दशक के दौरान रूस, पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से, बाल्कन क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील और अन्य देशों में जीवन स्तरों की तबाही पर उनकी चुप्पी गौरतलब है। बहरहाल, प्रदर्शनकारियों की कार्रवाइयों का प्रमुख तात्कालिक जोर बिल्कुल साफ था : प्रतिनिधियों के जमावड़े को बलपूर्वक रोकना और इस तरह से इन सम्मेलनों को उनका एजेंडा पूरा करने से रोकना।

केवल प्रदर्शनों से ही कभी भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की योजनाएं अवरुद्ध तो नहीं होतीं लेकिन सिएटल और उसके बाद जुझारू प्रदर्शनों की लहर कम से कम 'सामान्य कामकाज' को बाधित करने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी रही। सिएटल में सम्मेलन का उद्घाटन सत्र रद्द करना पड़ा क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि समेत सभी प्रतिनिधि पहले दिन और बाकी के दिनों में भी अपने होटलों में वस्तुतः कैद हो गये थे क्योंकि सड़कों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जम कर झड़पें हुईं। भीतर चल रही व्यापार वार्ताएं बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गईं। कोष-बैंक की वाशिंगटन बैठक के दौरान अमेरिकी सरकार को दोनों संस्थाओं के मुख्यालयों के आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में कार्यालयों को बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी वित्तमंत्री सहित तमाम शीर्ष अधिकारियों को आयोजन स्थल पर पहुंचने से रोकने में सफल रहे। मेलबोर्न में आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जान हार्वर्ड और दुनिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को आयोजन स्थल पर दूसरे प्रतिनिधियों के साथ रोक लिया गया। चूंकि तीस हजार प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश और निकासी के रास्तों को जाम कर दिया था, इसलिए प्रतिनिधियों को हेलीकाप्टरों और नौकाओं के जरिए लाना और ले जाना पड़ा। प्राग में सम्मेलन केंद्र को घण्टों तक पूरी तरह अवरुद्ध रखा गया और बहुत से संभावित प्रतिनिधि आयोजन से दूर ही रहे। नीस में एक लाख विरोध प्रदर्शनकारियों को बाहर रखने के अधिकारियों के प्रयत्नों ने स्वयं प्रतिनिधियों को ही बंधक बनाकर रख दिया। विक्टोरिया (कनाडा) में दिसम्बर 2000 में होने वाले सम्मेलन को प्रदर्शनों के भय से रद्द करना पड़ा। ऐसा ही जून 2001 में बार्सीलोना में विश्व बैंक विकास बैठक के साथ भी हुआ। जनवरी 2001 में दावोस में "अभूतपूर्व सुरक्षा" (व्यापक गिरफ्तारी और सड़क एवं रेल जाम करने) जैसा कि *फाइनेंशियल टाइम्स* ने वर्णित किया है, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को आयोजन स्थल पर पहुंचने से नहीं रोक पाई। क्यूबेक में समूचे आकर्षण का केन्द्र उत्तरी-दक्षिणी अमेरिका के मुक्त व्यापार समझौते से हटकर प्रदर्शनकारियों पर आ टिका। और स्वीडन में गोथेनबर्ग शहर का मुख्य हिस्सा वस्तुतः रणक्षेत्र में तब्दील हो गया।

हर अगली बैठक में वैधानिक और भौतिक अवरोध खड़े करके आधिकारिक रूप से आयोजन स्थल के आसपास के ज्यादा से ज्यादा स्थान को लोगों की पहुंच से दूर करने का प्रयास किया गया। जिनेवा में ये प्रयास चरम पर थे जहां पर कि आयोजन स्थल के निकट विशाल निर्जन क्षेत्र 'रेड जोन' को सुरक्षित बनाने के लिए चार मीटर ऊंची लोहे की बाड़ खड़ी की गयी थी। इलाके के निवासियों को कई दिनों तक अपने यहां आगन्तुकों की अगवानी नहीं करने दी गयी और अचूक निशानेबाजों ने छतों और बालकनियों पर मोर्चा संभाले रखा। प्रदर्शनकारियों को दूर रखने की यह व्यवस्था भी विश्व के सबसे शक्तिशाली आठ देशों के नेताओं को अपर्याप्त जान पड़ी। तभी तो वे बारूदी सुरंग निरोधी जहाजों, दक्ष गोताखोरों और विमानभेदी तोपों से सुसज्जित यूनिटों की रखवाली में 'यूरोपियन विजन' नाम के जहाज पर समुद्र के बीच में ही रुके रहे। शहर की तरफ जाने वाला रेल और हवाई यातायात रोक दिया गया, मोटरगाड़ियों के रास्ते अवरुद्ध कर दिये गये। बस, भूमिगत रेल और ट्राम यातायात बड़े पैमाने पर बन्द किया गया और भारी संख्या में लोगों को इतालवी सीमा से वापस भेज दिया गया। कहना न होगा कि 'एकीकृत यूरोप' की बात करने वाले उन्हीं अधिकारियों ने जो कि पूंजी की आवाजाही पर राष्ट्रीय अवरोधों को हटाने में व्यस्त थे, विरोधकर्ताओं की आवाजाही रोकने के लिए आक्रामक तरीके से राष्ट्रीय सीमाओं का इस्तेमाल किया। तभी तो प्राग में मार्च करने वालों ने नारा दिया : "सीमाओं को खोलो, आईएमएफ को चकनाचूर करो!"

प्रदर्शनों की इन शृंखलाओं में भाग लेने वालों के नारों और लक्ष्यों में भारी अन्तर थाइनमें सुधारवादी से लेकर क्रान्तिकारी तक शामिल थे (यहां तक कि अमेरिका में कुछ अंधराष्ट्रवादी भी थे)। अलबत्ता जैसा कि *इकोनामिस्ट* लिखता है, कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों के बीच जो चीज साझा थी वह थी स्थापित आर्थिक व्यवस्था और आईएमएफ, विश्वबैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं के प्रति नफरत। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये संस्थायें या तो इस व्यवस्था को संचालित कर रही हैं या उसकी सेवा कर रही हैं। रैलियां सचमुच उनके तरह-तरह के प्रतिभागियों के लिए पाठशाला बन गयीं : पहले की तमाम गैर राजनीतिक शक्तियां, या इकलौते मुद्दों तक सीमित शक्तियां, व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों से दो-चार हुईं और अपने अनुभव के क्रम में आमूल परिवर्तनकामी बनीं। और कमजोर होने की बजाय उनकी ताकत बढ़ती जान पड़ी : जिनेवा में डेढ़ लाख की रिकार्ड संख्या में प्रदर्शनकारी असाधारण बाधाओं से पार पाते हुए शहर तक पहुंचने में सफल रहे।

एकीकृत यूरोप की परियोजना के पीछे की शक्तियोंयूरोपीय निगमोंके लिए इन विरोध प्रदर्शनों में संगठित श्रमशक्ति की अभूतपूर्व भागीदारी, विशेष तौर पर अशुभ संकेत था। यूरोपीय निगम और उनके राजनीतिक प्रतिनिधि इकलौती महाशक्ति का प्रारूप गढ़ने के क्रम में यूरोपीय मजदूर वर्ग को उसके सभी सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों से वंचित करने के लिए कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहे हैं। सीमाओं से परे जाकर हाथ मिलाने वाली मजदूर वर्ग की जुझारू चुनौती उनकी परियोजना को खतरे में डाल देगी।

प्रत्युत्तर : दमन

शुरू से ही विरोध प्रदर्शनकारियों को भारी दमन का सामना करना पड़ा। सिएटल-1999 में आंसू गैस, (प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर कई बार कनस्तर दागे गये) डंडों, प्लास्टिक की गोलियों और अचेत कर देने वाले गोलों का प्रयोग किया गया। 600 से अधिक गिरफ्तार किये गयेप्रायः विराट "नो प्रोटेस्ट जोन" के भीतर पर्चे बांटने या यहां तक कि पर्चे लेने के लिए; राष्ट्रीय गार्ड तैनात थे; रात्रिकालीन कर्फ्यू और मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। दावोस 2000 और 2001 में पुलिस ने पानी की बौछारों (शून्य से नीचे तापमान पर) और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हवा में गोलियां दागीं, वाशिंगटन अप्रैल 2000 में आंसू गैस, मिर्ची गैस (कुछ प्रदर्शनकारियों की आंखों में छिड़काव किया गया) और बेंतों का, नीस में अचेत करने वाले गोलों और आंसू गैस का और क्यूबेक में पानी की बौछारों, आंसू गैस और रबर की गोलियों का प्रयोग किया गया।

जून 2001 का गोथेनबर्ग यूरोपीय शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़बिन्दु है। स्वीडिश पुलिस ने विरोधकर्ताओं पर न केवल घोड़ों, बेंतों और कुत्तों के साथ हमला किया, वरन पहली बार सिएटल के बाद के

प्रदर्शनों पर गोलियां भी दागीं। तीन प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, एक गम्भीर रूप से। फिर भी टोनी ब्लेयर ने यह दावा किया कि विश्व के नेताओं के जमावड़े को अस्त-व्यस्त करने वाले प्रदर्शनकारियों के प्रति "काफी उदार" रवैया अपनाया गया। उनके शब्द थे''ये लोग किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते...मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए।''

टोनी ब्लेयर की भावनाओं की तर्ज पर जिनेवा में दमन अभूतपूर्व था। एक विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनों पर रोक लगी हुई थी। पुलिस के पास शहर में किसी भी व्यक्ति को रोकने और तलाशी लेने का अधिकार था। पर्चों के वितरण पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। सम्मेलन के पहले दिन 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी कार्लो गुलियानी के सिर पर गोली मारी गई। उसने कथित रूप से पुलिस वैन पर आग बुझाने वाला उपकरण फेंका था। इस पर वैन ने पीछे हटकर गुलियानी को रौंदकर मार डाला। 21-22 जुलाई की रात्रि को पुलिस ने उस स्कूल की इमारत पर धावा बोला जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारी सोने के लिए करते थे। वहां सोने वालों को स्टील टार्चों, लकड़ी के डंडों और लात-घूसों से इस कदर पीटा गया कि 72 लोग घायल हो गये; एक दर्जन से अधिक लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा, कुछ बेहोश हो गये थे और कई लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। आखिरकार, सभी को बगैर आरोप के छोड़ दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बंदियों को थप्पड़ों, लात और घूंसे से जमकर पीटा गया और शारीरिक रूप से उनकी दुर्गति की गई जो कि कई बार अश्लील यौन प्रकृति की थी...लम्बे समय तक खाना, पानी और नींद से वंचित रखा गया, दीवार के सामने मुंह रखकर कतार बांधकर खड़ा होने और घंटों तक टांग फैलाये रखने को कहा गया और इस स्थिति को बनाये रखने में विफल रहने पर पीटा गया। इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों को प्रकट रूप से मौत की धमकी दी गयी और महिला बंदियों को बलात्कार की धमकी दी गई। फेयर-फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग"मीडिया एडवाइजरी : मीडिया मिसिंग न्यू एविडेंस एबाउट जिनेवा"

डेढ़ साल बाद इतालवी पुलिस ने संसदीय जांच में स्वीकार किया कि उसने विरोधकर्मियों के खिलाफ साक्ष्य गढ़े थे : एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्कूल में दो मोलोतोव काकटेलों को पुलिस द्वारा रखने की बात स्वीकार की और एक अन्य ने पुलिस अधिकारी को चाकू घोंपने की बात के झूठी होने की बात मानी। विरोध प्रदर्शनों के समय की 'गार्जियन' की छानबीन में पाया गया कि लूट और संवाददाताओं पर हमले के कृत्यों को अंजाम देने वाले कतिपय 'प्रदर्शनकारी' दरअसल यूरोपीय सुरक्षा बलों के गुप्त एजेंट थे। इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया जाता तो कोई हैरत नहीं होती। इस तरह यह यूरोप के नेताओं द्वारा तेजी से उभर रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन पर पूर्वनियोजित हमला था।

ज्यादा परिष्कृत प्रत्युत्तर की दरकार है

जहां आंदोलन से निपटने के लिए "जबर्दस्त" दमन आवश्यक औजार बना हुआ था, वहीं यह पर्याप्त नहीं था। क्योंकि ब्लेयर के इस दावे कि "ये लोग किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते", के विपरीत यह स्पष्ट था कि वास्तव में वे मौजूदा प्रक्रियाओं के द्वारा प्रभावित, कुछ मामलों में तो बर्बाद, यहां तक कि स्वयं *साम्राज्यवादी देशों के भीतर* की विशाल और बढ़ती हुई संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारम्भ में, कनाडियाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने आगाह किया था कि ''सिएटल और वाशिंगटन से प्रतिबिम्बित होता है कि प्रतिरोधी तबके कितने ज्यादा हो गये हैं और वह कतार कितनी अधिक है जिसमें प्रतिभागी भूमण्डलीकरण के प्रसार को बंद करने या बाधित करने की अपनी इच्छा से शामिल होंगे।'' भूमण्डलीकरण के पक्ष में आक्रामक रुख अपनाने वाला *इकोनामिस्ट* "क्रुद्ध और प्रभावी" शीर्षक वाली संपादकीय टिप्पणी में रोना रोता है कि वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ नवीकृत प्रदर्शनों का खतरा आईएमएफ और विश्व बैंक की अगले हफ्ते की सालाना बैठकों के ऊपर छाया हुआ है। यह नये तरह का विरोध प्रदर्शन महज उपद्रव से कहीं आगे की चीज है : इसे अपना रास्ता मिलता जा रहा है। अखबार चेतावनी देता है कि इस वैश्विक जुझारू प्रवृत्ति को चीजों को बदलने की थोड़ी क्षमता के साथ जनता के उपद्रव से ज्यादा कुछ भी नहीं बताकर खारिज करना बड़ी गलती होगी। निवेश पर बहुपक्षीय समझौते को अपने पहले निशाने के तौर पर लेते हुए यह पहले ही चीजों को बदल चुका है। *द इकोनामिस्ट* ने विरोध प्रदर्शनों की प्रभाविता की अपनाये गये तरीकों की नहीं वरन इस तथ्य की कि पश्चिम में उन्हें तमाम लोगों का समर्थन हासिल हैशिनाख्त की ...उनके द्वारा उठाये जाने वाले बहुत से मुद्दे भूमण्डलीकरण की नंगी सच्चाइयों के बारे में लोकप्रिय सरोकार को प्रतिबिम्बित करते हैं। गरीबों को पीछे छोड़ देने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, लोगों की तुलना में मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देने, संदिग्ध आनुवंशिकीय परिवर्द्धित खाद्यान्नों और बाकी चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाये तो आशंकाएं वास्तविक लगती हैं। सड़कों पर उग्र परिवर्तनकामी बड़े पैमाने पर इन साझा चिन्ताओं की संगठित और अतिवादी अभिव्यक्ति को स्वर दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी फर्मों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और सरकारों पर अंशतः हावी होते जा रहे हैं क्योंकि इस समय वे वृहत्तर मिजाज को प्रतिबिम्बित करते हैं। अगर उनकी जारी सफलताएं सत्ता के लिए उनकी भूख को संतुष्ट करने की बजाय प्रोत्साहित करती हैं तो भूमण्डलीकरण और आर्थिक एकीकरण को उससे कहीं अधिक खतरा हो सकता है जितना कि तमाम लोगों को लगता है।"

ज्यादा परिष्कृत प्रत्युत्तर की जरूरत थी। मेलबोर्न में प्रदर्शनकारियों द्वारा घेरे गये सम्मेलन स्थल पर विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने रहस्योद्घाटन करते हुए टिप्पणी की "मैंने अगर यहां से एक चीज सीखी तो भविष्य में संवाद का कोना स्थापित करने का प्रयास करूंगा, जहां पर यहां के कुछ व्यावसायिक व्यक्ति और सड़क के कुछ लोग एक सुरक्षित कोने में मिल सकें और विचारों का आदान-प्रदान करें।" *द इकोनामिस्ट* ने गौर किया है कि चेक राष्ट्रपति ने विरोधकर्ताओं (प्राग में) और विश्व बैंक के कर्ता-धर्ताओं के बीच बैठक की मध्यस्थता करने की असल कोशिश की..."श्री हावेल 23 सितम्बर को एक ऐसा मंच बनाने में सफल रहे जिसमें बैंक और कोष के अधिकारियों और भूमण्डलीकरण के चुनिन्दा विरोधियों द्वारा हिस्सा लिया जायेगा।" इस तरह के प्रयास नये नहीं हैं : बैंक, कोष, संयुक्त राष्ट्र और इस तरह की दूसरी संस्थायें कुछ वर्षों से प्रत्येक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जमावड़े पर समानांतर एनजीओ बैठकें प्रायोजित कर रही हैं। दिसम्बर 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ ने सचमुच स्वयं ही डब्ल्यूटीओ सम्मेलन के शुभारंभ के एक दिन पहले समानांतर सामाजिक सम्मेलन की मेजबानी की, जहां पर नये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक जुआन

सोमाविआ ने कार्यक्रम की व्याख्या की : "आज हमें जिस चीज की जरूरत है वह है आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच विश्व शासन के आरम्भिक ढांचों के भीतर सामाजिक अध्याय सृजित करने के उद्देश्य के साथ अधिक फलप्रद सहयोग...हमें ऐसे ढांचे खड़े करने होंगे जहां से सभ्य समाज की आशंकाओं और चिंताओं को पूरी तरह से स्वर देकर उनका हल प्रस्तुत किया जा सके।"

इसी जमावड़े में डब्ल्यूटीओ के पूर्व महानिदेशक रेनाहो रुगिएरो ने आगाह किया था : "आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाने वाले सभी पक्षों को अगर इस वैश्विक प्रणाली के भीतर सार्वजनिक सरोकारों के फैलते दायरे को संबोधित करने के लिए शामिल नहीं किया जाता...तो वे वैकल्पिक समाधानों की ओर मुड़ सकते हैं जो कि बहुत संभव है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के समस्त स्थापत्य को अस्थिर कर दे...निश्चित रूप से हमें बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर व्यापार उदारीकरण को आगे बढ़ाते रहना होगा। लेकिन जब तक हम सभी राजनीतिक हस्तियों के साथ आम सहमति और सहयोग हासिल नहीं कर लेते, हम व्यापार उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक समर्थन का निर्माण नहीं कर सकते।

व्यापार उदारीकरण के लिए सर्वानुमति बनाने में विरोधकर्ताओं को उलझाने को 1999 के सामाजिक सम्मेलन के प्रयास, नरमी के साथ कहें तो विफल रहे। और इसके बाद होने वाले सभी जुझारू विरोध प्रदर्शनों के जरिए यह साफ हो गया कि विरोधकर्ताओं के साथ सर्वानुमति बनाने के वे प्रायोजित प्रयत्न चूंकि उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बैनर तले आयोजित किये गये थे, जो कि विरोध कर्ताओं के निशाने पर थे, इसलिए प्रदर्शनकारियों के लिए उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी।

विश्व सामाजिक मंच खड़ा किया गया

बाद के उथल-पुथल भरे वर्ष 2000 के दौरान सिएटल की तरह के टकरावों के "विकल्प" ने उल्लेखनीय तेजी के साथ सिएटल की घटनाओं के तीन महीनों के भीतर शुरू होकर आकार ग्रहण किया।

डब्ल्यूएसएफ की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य के मुताबिक फरवरी 2000 में फ्रांसीसी एनजीओ प्लेटफार्म एटीटीएसी (अटैक) के प्रमुख बर्नार्ड कासेन, ब्राजीलियाई एनजीओ'ज के एसोसिएशन के प्रमुख व्हाइटकर ने "वर्ल्ड सिविल सोसायटी मंच" के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक की। मार्च 2000 तक औपचारिक रूप से उन्होंने पोर्टो एलिग्रे म्यूनिसिपल सरकार और रियो ग्रैंडे डो सुल की राज्य सरकार का समर्थन जुटा लिया था। उस समय दोनों पर ब्राजीलियाई वर्कर्स पार्टी का नियंत्रण था। जून 2000 में जिनेवा में वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र बैठक में रियो ग्रांडे डो सुल के उप गवर्नर ने इस तरह के आयोजन का प्रस्ताव रखा। विश्व बैंक की वेबसाइट इस बैठक से डब्ल्यू एस एफ का जन्म मानती है और वह इसका उल्लेख जून 2000 में जिनेवा में सिविल सोसायटी के प्रमुख संगठनों द्वारा खड़े किये गये नये सांगठनिक बोध के रूप में करती है।

इस राजनीतिक प्रवृत्ति ने, जो कि विरोध आंदोलन के भीतर पहले से ही मौजूद थी, उसे प्रभावित करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिये। एटीटीएसी फ्रेंड्स आफ एल' ह्यूमैनाइट और फ्रेंड्स आफ लि मौंडे डिप्लोमेटिक समेत फ्रांसीसी एनजीओ'ज के एक समूह ने नीस में यूरोपीय संघ के आगामी शिखर सम्मेलन में आयोजित किये जाने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए कार्यसूची तैयार करने के क्रम में "सिएटल के एक वर्ष बाद" शीर्षक से पेरिस में एक वैकल्पिक सामाजिक मंच को प्रायोजित किया। वक्ताओं ने आईएमएफ, विश्वबैंक-डब्ल्यूटीओ की तरह की कतिपय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिर से परिस्थिति के अनुकूल बनाने का आह्वान किया...ताकि नीचे से उदारीरकण का सृजन किया जाये और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन का निर्माण हो जो कि आईएमएफ को नष्ट करने की बजाय उसके मिशनों को फिर से परिस्थिति के अनुकूल बनाये। यूरोपीय संघ की परियोजना का जोरदार समर्थन करते हुए (जिसके केन्द्रीय लक्ष्यों में एकवस्तुतः यूरोपीय कामगारों को कठिन लड़ाइयों के बाद मिले अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के उनके विविध रूपों से वंचित करना है) आयोजकों ने "तीसरे रास्ते के आधार पर (अर्थात न तो पूंजीवाद और न ही समाजवाद) ऐसे सामाजिक यूरोप की गुहार लगाई जो कि बेरोजगारी, असुरक्षा और श्रमिक अधिकारों के अवमूल्यन के खिलाफ नीतियों को क्रियान्वित कर सके।"

आयोजकों को नीस में विरोध प्रदर्शनों में इस कार्यसूची को धोखे से शामिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां पर मजदूर संघों के यूरोपीय महासंघ (ईटीयूसी) के महासचिव ने घोषणा की, *"सिविल सोसायटी के सभी घटकों को यूरोपीय संघ के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।* हमारे प्रदर्शन का संदेश सुस्पष्ट है : ब्रसेल्स में निर्णय निर्माण ढांचों में मजदूर संघों और एनजीओ को मिलाये जाने की जरूरत है...हम इस बात से सहमत हैं कि यूरोप को और प्रतिस्पर्द्धी बनना ही होगा। लेकिन नये यूरोप को इसके अलावा अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन की सम्मानजनक गुणवत्ता समाहित करनी होगी।" यूरोपीय श्रम और पूंजी के सुखी परिवार का यह स्वप्न किसी भी कार्पोरेट के अध्यक्ष के दिल को खुशी से लबरेज कर देगा।

आइए, अब विश्व सामाजिक मंच के दो प्रमुख रचनाकारों फ्रांस के एटीटीएसी और ब्राजील की वर्कर्स पार्टी (पीटी) पर करीब से नजर डालें। इन दोनों ताकतों की पृष्ठभूमि पर नजर डालना उपयोगी रहेगा।

एटीटीएसी : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ संवाद को समर्पित

एटीटीएसी एक एनजीओ प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य विश्व की वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए विविध समूहोंकिसानों, मजदूर संघों, बुद्धिजीवियों के गंठजोड़ का निर्माण करता है। एटीटीएसी (एसोसिएशन फार दि टैक्सेशन आफ फिनानसियल ट्रांसएक्शंस फार द एड आफ सिटिजंस) के फ्रांसीसी प्रथमाक्षरों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1998 में *ली मोंडे डिप्लोमेटिक* के संपादकों बर्नार्ड कासेंस और सूसन द्वारा रोबिन टैक्स के वास्ते अभियान के लिए की गई थी। इस टैक्स को काफी पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री जेस्म रोबिन ने प्रस्तावित किया था। इसके जरिये उत्पादक और सामाजिक रूप से वांछित उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के क्रम में 0.1 फीसदी की दर पर सट्टे के वित्तीय सौदों पर कर लगाया जाता। (एटीटीएसी ने जहां पिछले कई वर्षों में अपने सरोकारों को व्यापक बनाया है वहीं उसने रोबिन टैक्स प्रस्ताव में अपने आधार का परित्याग नहीं किया है।) अमेरिकी प्रशासनों के सलाहकार रह चुके नोबल पुरस्कार विजेता संस्थान के अर्थशास्त्री टोबिन किसी भी अर्थ में अपने प्रस्ताव को उग्र परिवर्तनकारी कार्पोरेट विरोधी या भूमण्डलीकरण विरोधी नहीं समझते

थेसचमुच, उन्होंने आईएमएफ द्वारा कर राजस्वों को देखरेख किये जाने की कल्पना की थी (एटीटीएसी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा करे)। वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि के प्रभुत्व और दुनिया भर में सट्टे के सौदों की खलबलीपूर्ण गति को देखते हुए किसी भी तरह से मौजूदा विश्व वित्तीय संस्थाओं, पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बने रहने की इच्छा रखने वाले किसी भी देश द्वारा वास्तव में टोबिन टैक्स को लागू किये जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इस तरह का टैक्स कानून बनाने वाले किसी भी देश को विश्व वित्तीय समुदाय द्वारा उसके यहां से पूंजी निकालकर तुरन्त दंडित किया जायेगा। प्रभावी होने के लिए इसे संभावित रूप से दुनिया के सभी देशों या कम से कम अग्रणी शक्तियों को क्रियान्वित करना होगा, जो कि फिर इसे बाकी दुनिया पर थोपेंगी। टोबिन टैक्स प्रस्ताव एक छलावा है।

टोबिन टैक्स के अलावा, एटीटीएसी ने विश्व सामाजिक मंच पर तीन अन्य प्रस्थापनाएं : विश्व बैंक और आईएमएफ का सुधार, *बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गति को कम करने और प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए* वैश्विक आयोग, ऋण के मकड़जाल में फंसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए मध्यस्थता की कार्यप्रणाली, जहां पर ऋणदाताओं और देनदारों को अपने प्रतिनिधियों को नामित करना चाहिए *जिन्हें कि फिर मध्यस्थता के जरिए समझौते तक पहुंचना होता है।"* इस सबको सरकारों और कोष और बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ''संवाद'' के जरिए हासिल किया जाना था।

यह समझदारी एटीटीएसी की एक अग्रणी कर्ताधर्ता सूसन जार्ज के कार्य में भी प्रतिबिम्बित होती है। वह तीसरी दुनिया के ऋण को मंसूख करने के खिलाफ तर्क पेश करते हुए इसके बजाय उसकी "रचनात्मक" पुनः समझौता वार्ता की बात कहती हैं। वह सचमुच आईएमएफ की संस्था का पक्षपोषण करती हैं : "क्या दक्षिण को आईएमएफ को बदलने या खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए? यहां तक कि अगर इस तरह का भारी-भरकम कार्य संभव हो तो भी यह मेरा ध्यान गलत उद्देश्य की तरफ खींचता है, ठीक इस वजह से कि *कोष राष्ट्रेतर* है और क्योंकि यह एक उपकरण है। अगर पर्याप्त दबाव और राजनीतिक कौशल का प्रयोग किया जाये तो यह अमेरिका की रीगन सरकार के मुकाबले ज्यादा प्रबुद्ध सरकारों के लिए यह उपकरण (साधन) बन सकता है। जहां एटीटीएसी के बुद्धिजीवियों ने सिएटल बाद के हरेक प्रमुख विरोध प्रदर्शनों में मंचों और पत्रकार सम्मेलनों में प्रमुख रूप से स्थान हासिल किया, वहीं उनकी वास्तविक राजनीति तीसरी दुनिया के कर्ज को रद्द करने या "आईएमएफ को ध्वस्त करने" का आह्वान करने वाले विरोधकर्ताओं के पूरी तरह विपरीत थी।

नौकरियों की रक्षा करने के पारम्परिक ट्रेड यूनियन उद्देश्य के साथ भी एटीटीएसी का बहुत कुछ साझा नहीं था। मई 2001 के दस्तावेज (*नये अंशधारक पूंजीवाद के नियम*) में एटीटीएसी काम पर से हटाने के अधिकार की पुष्टि करता है पूंजीवादी सम्पत्ति के अधिकार में काम पर रखने और हटाने का अधिकार समाहित है। सवाल यह जानने का है कि किस बिन्दु तक यह अधिकार है। जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम नौकरियों में कटौती को अंतिम उपाय के तौर पर, कम्पनी को बचाये रखने की गारंटी देने वाली दूसरी सभी संभावनाओं के खत्म हो जाने पर, अपनाने के पक्षधर हैं।''

एटीटीएसी के लिए भूमण्डलीकरण विरोधी जुझारू विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण अर्थ में *विफल* रहे : उनमें 'विकल्पों' के 'रचनात्मक' विकास की कमी थी। एटीटीएसी के क्रिस्टोफर एग्युटन के मुताबिक, "*सिएटल की विफलता* साझी कार्य सूची और भूमण्डलीकरण के खिलाफ विश्व स्तर पर वैश्विक गंठजोड़ के साथ आगे आने की अक्षमता थी।" तभी तो डब्ल्यूएसएफ की जरूरत है। एटीटीएसी के पहले अध्यक्ष बर्नार्ड कैसेंस कहते हैं, "हम महज विरोधकर्ता नहीं हैं, हमारी यह आकांक्षा यह दिखाने के लिए विश्वसनीय विकल्पों को प्रस्तावित करने की है कि अर्थव्यवस्था और वित्त को समाज की सेवा में एक बार और रखे जाने पर दूसरी दुनिया संभव है।"

इन विकल्पों को किसके लिए प्रस्तावित किया जाना है, किन लोगों की निगाहों में उन्हें "विश्वसनीय" होना है? प्रकट रूप से उन लोगों की निगाह में जो कि अस्तित्वमान विश्व के प्रभारी हैं। विभिन्न यूरोपीय सामाजिक जनवादी सरकारें एटीटीएसी के पीछे-पीछे लगी रही हैं : सितम्बर 2001 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री लिओनेल जॉस्पिन और जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर, दोनों ही निकट भविष्य में वित्तीय बाजारों को किस तरह से नियंत्रित किया जाय विषय पर संयुक्त कार्यदल गठित करने पर सहमत हुए। एटीटीएसी फ्रांस के नेतृत्व ने जॉस्पिन के चीफ आफ स्टाफ के साथ कई बैठकें आयोजित कीं। फ्रांस की नेशनल असेम्बली ने नवम्बर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सट्टेबाजी पर टोबिन टैक्स का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया। बहुत संभव है कि इस दरबारी व्यवहार की वजह से एटीटीएसी नेतृत्व ने अफगानिस्तान में युद्ध के खिलाफ अपने यथेष्ट प्रभाव को गतिशील न किया हो। यह दरबारी व्यवहार पोर्टो अलग्रे में जारी रहेगा। उपस्थित होने वाले प्रतिष्ठित लोगों के बीच पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विधवा डेनियल मित्तरां भी होंगी। आरोप लगाया जाता है कि एटीटीएसी ने विभिन्न मंचों पर इराक और अफगानिस्तान की तरह के मुद्दों की चर्चा को बाहर रखने, और सरकारी नस्लभेद, आव्रजकों के अधिकारों और फासीवाद एवं इस्लामोफोबिया के सुस्पष्ट संदर्भों (उल्लेखों) की चर्चा को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।

सचमुच, एटीटीएसी यूरोप के सत्तारूढ़ हलकों से धन प्राप्त करने को बिल्कुल भी गलत नहीं मानता है। फ्रांसीसी बिजनेस डेली *लेस इकोस* (10/1/02) ने खबर दी, "पिछले साल एटीटीएसी ने केवल अनुदान के रूप में तीन लाख यूरो हासिल किये। चंदा देने वालों में यूरोपीय संघ का यूरोपीय आयोग, फ्रांसीसी सरकार का सामाजिक अर्थव्यवस्था विभाग शिक्षा और संस्कृति का राष्ट्रीय मंत्रालय और स्थानीय सरकारों का समूचा जमघट शामिल था। दैनिक *ली मोंडे* (1/2/02) के मुताबिक, "एटीटीएसी और ली मोंडे डिप्लोमेटिक ने फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय से विश्व सामाजिक मंच को आयोजित करने में उन्हें मदद देने के लिए 80 हजार यूरो प्राप्त किये। लेस इकोस (1/2/02) यथार्थपरक ढंग से टिप्पणी करता है, "एनजीओ जिनकी भूमिका हमेशा पारदर्शी नहीं होती, को वित्तीय मदद प्रायः बहुराष्ट्रीय निगमों से मिलती है जो कि उन्हें सावधानीपूर्वक खींचना पसन्द करते हैं ताकि उनका अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा जान पड़ेगा कि ये दो विरोधी विचारधाराएं हैं। दरअसल ये विचारधाराएं ज्यादा से ज्यादा अंतर्ग्रंथित होती जा रही हैं।"

निस्सन्देह, एटीटीएसी के निर्माण विशेषज्ञ इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि वास्तविक विकल्प को महज मौजूदा ढांचे के मुकुट पर

मढ़कर नहीं, बल्कि हर हाल में पहले *अतीत के बोझ की सफाई करते हुए* आगे बढ़ना होगा।

वर्कर्स पार्टी (पीटी) : आईएमएफ के शासन का औजार

डब्ल्यूएसएफ के गठन की पहलकदमी लेने वाली दूसरी महत्वपूर्ण ताकत ब्राजील की पीटी को मुश्किल से ही भूमण्डलीकरण विरोधी बताया जा सकता है। जब डब्ल्यूएसएफ की पहली तीन बैठकें हुईं उस समय पीटी ब्राजील के केवल एक प्रांत रियो ग्रांडे डे सुल, जिसकी राजधानी पोर्तो अलग्रे है, में सत्ता में थी। उस समय उसकी "सहभागी बजट" प्रक्रिया की बड़ी सराहना हुई। इसमें मजदूर संघों, एनजीओ और नियोक्ता एसोसिएशनों सहित समाज के विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सभा आयोजित की जाती थी। सर्वप्रथम उपलब्ध निधियों से विदेशी ऋण की पूर्ति के मद में प्रांत के योगदान के लिए जरूरी धनराशि को घटा दिया जाता। इसके बाद बाकी बची धनराशि को कैसे खर्च करें इस पर चर्चा शुरू होती। प्रत्येक एसोसिएशन को अपने सरोकार के लिए धन मांगने, उस पर बोलने के लिए समय दिया जाता और सभी प्रस्तावों पर आखिर में मतदान होता। प्राथमिकताओं के लिए पर्याप्त धन नहीं होने पर संभव है कि किसी का भी वित्त पोषण नहीं हो। साफ तौर पर इस तरह की कार्यप्रणाली का "भूमण्डलीकरण" के विरोध से कोई लेना-देना नहीं होता। यह जो करता है वह है विभिन्न शोषित सामाजिक तबकों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बैंक-कोष के समाज कल्याण के मद में कटौती उपायों के विरुद्ध असन्तोष को मद्धिम करने का काम। वाकई, विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री द्वारा संपादित आईएमएफ का प्रकाशन *वित्त एवं विकास* पीटी के ''भागीदारी बजट'' की "आर्थिक गतिविधि और सामाजिक गतिशीलता पर प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिबंधों" को घटाने में सहयोग के रूप में सराहना करता है।

अब जबकि पीटी को राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता संभालने के लिए चुन लिया गया है, उसने 'भूमण्डलीकरण' विरोधी दिखावे छोड़ दिये गये हैं। विदेशी और ब्राजीलियाई दोनों तरह के निवेशकों के मन में घर कर गई आशंका को निर्मूल करने के क्रम में अपने चुनाव से पहले पीटी के अध्यक्ष और अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने 'ब्राजीलियाई जनता के नाम लिखे पत्र' में चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं आईएमएफ द्वारा मांगे गये बजट घाटे को स्थिर रखने की प्रतिबद्धता जतायी थी। पदभार संभालने पर उन्होंने न केवल इसे पूरा किया बल्कि आगे बढ़कर 4.6 फीसदी बढ़ाकर वाल स्ट्रीट को चकित कर दिया। यह मंदी की मारी गरीबी से ग्रस्त अर्थव्यवस्था से उल्लेखनीय (निकासी) थी। आश्चर्य नहीं कि 'वाशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक के अधिकारियों ने नई सरकार द्वारा थोपी गई सख्त वित्तीय कट्टरपंथिता की प्रशंसा की। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष की मुसीबत देखते हुए लूला ने फ्लीट बोस्टन फाइनेंशियल में ग्लोबल बैंकिंग के पूर्व अध्यक्ष और "अमेरिकी वित्तीय गलियारों में अच्छी तरह जाने जाने वाले" हाइनरिख गिरेल्लेस को नियुक्त किया। "अंतर्राष्ट्रीय" निवेशक पुनः आश्वस्त हो चुके हैं : लूला ने जब से 1 जनवरी 2003 को कार्यभार संभाला है, ब्राजील को कोई 5.6 अरब डालर का विदेशी निवेश हासिल हुआ है। लूला ने इसके अलावा वेनेजुएला के ह्युगो चावेज से दूरी बना ली है। चावेज ऐसे लैटिन अमेरिकी नेता हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी नापसन्द करती है।

चूंकि ब्राजील अपने कर्ज की भरपाई और विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखे हुए हैं इसलिए 26.5 फीसदी की उसकी मूल ब्याज दर घरेलू निवेश का गला घोंटती है। ब्राजील में इस समय उत्पादन लागत का औसतन 14 फीसदी बैठता है और स्टील एवं आटो पार्ट्स उद्योग में 25 फीसदी तक के बराबर पड़ता है। एक तिहाई से अधिक आबादी आधिकारिक रूप से गरीब और 15 फीसदी बेसहारा मानी जाती है। ''ब्राजील की औद्योगिक एवं वित्तीय मुख्य भूमि वृहत्तर शाओ पाउलो क्षेत्र में बेरोजगारी 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है। ब्राजील के आर्थिक नीति निर्माता आईएमएफ की निगरानी तले बने हुए हैं, उनके ऊपर आईएमएफ के उस 30 अरब डालर के ऋणों पर भुगतानों की जिम्मेदारी है, जिसके लिए पिछली सरकार ने वार्ता की थी। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने की बहुत कम गुंजाइश बची है।"

ब्राजील के नीति निर्माता अब आईएमएफ की भाषा में बात करते हैं : "*अगर बजट अधिशेषों को टिकाये रखा जा सके* तो अगले वर्ष एक बार फिर वृद्धि में तेजी आयेगी, उनका पूर्वानुमान है कि ऐसा होगा। उनका मानना है कि आखिर में वे अधिशेषों को, ऋण का भुगतान करने से, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सड़कों व अन्य बुनियादी सांचे में सुधार लाने के मद में शिफ्ट करने में सफल हो जायेंगे। मूल बात यह है कि बजट अधिशेषों के निष्कर्षण की नीति सिर्फ आर्थिक गतिविधि को *संकुचित* कर सकती है, जिसकी वजह से सामाजिक विकास की संभावना और भी दूर छिटक जाती है।

कोई आश्चर्य नहीं कि ''पीटी के वाम धड़े के कुछ सदस्य खुलकर लूला की आलोचना कर रहे थे, और पार्टी के नेता सर्वाधिक कटु आलोचकों को धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सरकार के सुधार कार्यक्रमों के खिलाफ मत दिया तो पार्टी से निकाल दिया जायेगा।" वाम धड़े के सदस्य लूला की वर्तमान अवस्थिति का 1985 में हवाना ऋण सम्मेलन में कहे गये उनके शब्दों के साथ अंतर प्रस्तुत कर सकते थे :

"उग्र परिवर्तनवादी होकर या दिलेरी दिखाये बगैर मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी दुनिया का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। यह युद्ध खामोशी से लड़ा जा रहा है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह किसी तरह से कम अनर्थकारी है। यह युद्ध ब्राजील, लैटिन अमेरिका और व्यावहारिक रूप से समूची दुनिया पर कहर बरपा कर रहा है। सैनिकों की बजाय बच्चे मर रहे हैं, दसियों लाख घायलों की बजाय दसियों लाख बेरोजगार हैं; पुलों के विनाश की बजाय कारखाने, स्कूल, अस्पताल और समूची अर्थव्यवस्था ढह रही है...। यह अमेरिका द्वारा लैटिन अमेरिकी महाद्वीप और तीसरी दुनिया के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है। यह विदेशी ऋण के ऊपर युद्ध है, जिसका मुख्य हथियार ब्याज है जो कि एटम बम के मुकाबले ज्यादा घातक, लेजर बीम की तुलना में ज्यादा छिन्न-भिन्न करने वाला हथियार है...."

लैटिन अमेरिका में वर्ग संघर्ष की स्थिति

वास्तव में डब्ल्यूएसएफ के उद्भव को सिर्फ विश्व के अग्रणी वित्तीय संस्थानों और निकायों के खिलाफ जुझारू विरोध प्रदर्शनों के उभार की पृष्ठभूमि के बरअक्स ही देखे जाने की जरूरत नहीं है। इसके उद्भव को हर हाल में 1994 के मेक्सिको के जपातिस्ता विद्रोह

के समय से, खासकर पिछले कुछ वर्षों से समूचे लैटिन अमेरिका को अपने आगोश में लेने वाले *श्रमिकों और किसानों के संघर्षों की वेगवाही धारा* के खिलाफ थी। देखना होगा : मेक्सिको में भूमि के सवाल पर जपातिस्ता बगावत से प्रेरित दूसरे आंदोलनों का, जिसमें कई हथियारबंद हैं, उठ खड़े होना, मेक्सिको का राजनीतिक रूप से विस्तारित छात्र आंदोलन, कोलम्बिया में एफएआरसी और ईएलएन के नेतृत्व में जारी छापामार युद्ध, पेरू में जारी छापामार युद्ध, इक्वाडोर में आईएमएफ द्वारा थोपी गई नीतियों के खिलाफ बगावत जैसी स्थिति के फलस्वरूप सरकार का गिरना, वेनेजुएला में वहां के कुलीनों और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ चावेज सरकार के समर्थन में जनता का गोलबंद होना, ब्राजील में भूमिहीनों के आंदोलन द्वारा आक्रामक ढंग से भूमि पर सीधे कब्जा किया जाना, उल्लेखनीय अर्जेण्टीनिआई लोकप्रिय बगावत और अन्तरराष्ट्रीय निवेशकों के विरोध में 2001-2002 में फैक्टरियों और राजनीतिक सत्ता केन्द्रों पर कब्जा, विदेशी कब्जे को वापस न करने के लिए लगातार बाध्य करना; बोलीविया में निजीकरण विरोधी संघर्ष, जिसमें पानी के निजीकरण के खिलाफ कोचाबाम्बा का सफल संघर्ष शामिल है, और ऐसे ही अन्य संघर्ष। इस प्रकार हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका दुनिया में *वर्ग संघर्ष* का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जो अन्तरराष्ट्रीय पूंजी को टक्कर दे रहा है। इनमें से कई संघर्ष स्वतःस्फूर्त थे या बिना किसी निश्चित विचारधारा वाली ताकतों के नेतृत्व में हुए थे जो राजनीतिक जमीन और भविष्य की तस्वीर तलाश रहे थे। इसलिए अन्तराष्ट्रीय पूंजी के लिए इन संघर्षों को भी 'अटैक' जैसे संगठनों द्वारा बनाये गये रास्तों की ओर खींचना बेहद अहमियत रखता है।

इस समूची पृष्ठभूमि में 2002 में पोर्तो अलेग्रे के नगर प्रशासन ने लगभग 3 लाख डालर और रियो ग्रान्दे डो सुल राज्य की सरकार ने (जिसके अधीन यह नगर प्रशासन आता है), खर्चों में जारी कटौती के बावजूद, डब्ल्यूएसएफ के सम्मेलन का आयोजन करने के लिए 10 लाख डालर और मुहैया कराये। 2003 में, नगर प्रशासन द्वारा दिये गये पैसे में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई पर राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे धन में (पीटी के राज्य के चुनावों में हारने के फलस्वरूप) भारी कमी आई। बहरहाल, लूला के नेतृत्ववाली पीटी की नई संघीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा की गई कटौती की भरपाई करने का फैसला किया है। एटीटीएसी ने डब्ल्यूएसएफ को खड़ा करने के लिए यूरोपीय संघ के फंड को चैनल प्रदान किया। डब्ल्यूएसएफ स्वयं भी यूरोपीय संघ और फ्रांसीसी सरकार से फंडिंग प्राप्त करता है। इसके अलावा, डब्ल्यूएसएफ को धन देने वालों (डब्ल्यूएसएफ की शब्दावली में 'साझीदार') में फोर्ड फाउण्डेशन (यह हमेशा से अमेरिका की केन्द्रीय खुफिया एजेंसी और अमेरिका के समग्र सामरिक हितों के साथ निकट से तालमेल बनाकर काम करता रहा है), हाइनरिख बॉल फाउंडेशन, जिस पर नियंत्रण मौजूदा जर्मन सरकार में शामिल और युगोस्लाविया व अफगानिस्तान पर थोपे गये युद्ध की समर्थक जर्मन ग्रींस पार्टी है, (उसके नेता जोका फिशर जर्मन विदेश मंत्री हैं), और आक्सफेम (ब्रिटेन), नोविबर (नीदरलैंड) एक्शन एड (ब्रिटेन) और इसी तरह की दूसरी प्रमुख फंडिंग एजेंसियां शामिल हैं।

गौरतलब है कि डब्ल्यूएसएफ की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का एक सदस्य खबर देता है कि इन एजेंसियों से प्राप्त की गई "पर्याप्त निधियों" ने "अभी तक इससे पैदा होने वाले निर्भरता के संभावित रिश्तों पर किसी महत्वपूर्ण बहस का (डब्ल्यूएसएफ के निकायों में) सूत्रपात नहीं किया है।" फिर भी वह स्वीकार करता है कि *''फोर्ड फाउण्डेशन से फंडिंग हासिल करने के लिए आयोजकों को फाउंडेशन को यकीन दिलाना पड़ा कि वर्कर्स पार्टी इस प्रक्रिया से सम्बद्ध नहीं हैं।"* यहां दो नुक्ते ध्यान दिये जाने लायक हैं। प्रथम, यह स्थापित करता है कि दानकर्ता बांह मरोड़ने और डब्ल्यूएसएफ में शामिल विभिन्न ताकतों की भूमिका को निर्धारित करने में सक्षम थे और यह कि वे भविष्य में जुड़ने वालों की विश्वसनीयता के प्रति 'आश्वस्त' हो लेना चाहते थे। द्वितीय, अगर दानदाताओं ने पूरी तरह से पालतू (रीढ़विहीन) वर्कर्स पार्टी की भागीदारी का विरोध किया तो वे वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को दी जा रही महत्ता का और अधिक उग्र विरोध करेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। डब्ल्यूएसएफ की दूसरी और तीसरी बैठकों में सम्मिलित और निष्कासित किये जाने वालों का विवरण दिये जाने पर उद्देश्य स्पष्ट हो जायेगा।

डब्ल्यूएसएफ चार्टर

डब्ल्यूएसएफ का चार्टर सारतत्व को छिपाने के लिए शब्दों की बाजीगरी करते हुए इसे, "विकल्पों को खोजने और उनका निर्माण करने की स्थायी प्रक्रिया", ''सिविल सोयायटी के ऐसे ग्रुपों और आंदोलनों के लिए जो कि नवउदारतावाद और पूंजी के साम्राज्यवाद के किसी स्वरूप द्वारा विश्व प्रभुत्व हासिल करने के खिलाफ हैं, का खुला मिलन-स्थल" ''बहुलवादी, वैविध्यपूर्ण, गैर संगठनात्मक, गैर सरकारी और गैर पार्टी संदर्भ", और इसी प्रकार के दूसरे रूपों के तौर पर वर्णित करता है। बहरहाल, चार्टर डब्ल्यूएसएफ को किसी सार्थक कार्रवाई से रोकता है। "डब्ल्यूएसएफ की बैठकें एक निकाय के तौर पर डब्ल्यूएसएफ की तरफ से विचार-विमर्श नहीं करती।...मंच के सहभागियों को ऐसी कार्रवाई के लिए, जिसके प्रति सभी सहभागी या उनकी बहुसंख्या प्रतिबद्ध होगी, घोषणाओं या प्रस्तावों पर मत देकर या मंजूरी प्रदान कर निकाय के रूप में फैसले लेने के लिए नहीं बुलाना होगा...*इस प्रकार से यह सत्ता की अवस्थिति का गठन नहीं करता।*" इस प्रकार डब्ल्यूएसएफ के आयोजक सक्रियता और सफलतापूर्वक इराक पर अमेरिकी हमले जैसे सुस्पष्ट मुद्दे पर भी अवस्थिति अख्तियार करने से बच निकले।

डब्ल्यूएसएफ की विविधता की अपनी सीमाएं हैं। "सिविल सोसायटी'' के कुछ समूहों, या लोगों को, ज्यादा साफ शब्दों में कहें तो बाहर किया जाना है : ''मंच में न तो पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकेंके और न ही सैन्य संगठन।'' (डब्ल्यूएसएफ-इंडिया का गठन करने वाला भारतीय संगठनों का अप्रैल 2002 का भोपाल घोषणापत्र कहता है कि "विश्व सामाजिक मंच की बैठकें उन संगठनों को छोड़कर जो कि राजनीतिक कार्रवाई के तरीके के रूप में लोगों की जान लेने की कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए हमेशा खुली रहती हैं जो कि उनमें हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं)। इस प्रकार हथियार उठाकर अपने ध्येय की हिफाजत करने वाले या उसे आगे बढ़ाने वाले किसी संघर्ष का प्रवेश निषेध कर दिया जायेगा : उदाहरण के लिए अगर वियतनामियों के मुक्ति संघर्ष आज चल रहे होते हों तो डब्ल्यूएसएफ में हिस्सा लेने के अयोग्य करार दिये जाते चाहे उनकी ऐसी इच्छा क्यों न होती। इसी

प्रकार आज के फिलस्तीनी या इराकी प्रतिरोध योद्धा इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। इसके और भी बहुत से उदाहरण आसानी से गिनाये जा सकते हैं।

बावजूद इसके वही चार्टर कहता है कि "इस चार्टर की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करने वाले सरकारी नेताओं और विधानमंडलों के सदस्यों को निजी हैसियत से हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।" (डब्ल्यूएसएफ का भोपाल घोषणापत्र जोर देकर कहता है कि डब्ल्यूएसएफ बहसों से बहिष्कृत करने का इरादा नहीं रखता, यह अपने लोगों से जनादेश पाकर राजनीतिक उत्तरदायित्व के पदों पर पहुंचे ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जो कि उन बहसों से निकलने वाली प्रतिबद्धताओं में शामिल होने का फैसला करते हैं दूसरे शब्दों में वे "निजी हैसियत" से नहीं बल्कि अपनी अधिकारिक हैसियत से भाग ले रहे होते हैं)। इस बात को देखते हुए कि ये व्यक्ति राजनीतिक दलों के नेता होते हैं और इस बात के मद्देनजर कि राष्ट्राध्यक्षों के रूप में वे सैन्य संगठनों का नेतृत्व करते हैं, यह पार्टी प्रतिनिधियों या सैन्य संगठनों पर रोक लगाने वाली पहले की धारा का निषेध करता प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि दोनों धाराओं के उद्देश्य भिन्न हैं। पहली धारा कतिपय 'अवांछित' रेडिकल पार्टियों और उनकी जुझारू शक्तियों को रोकने के प्रति लक्षित है। दूसरी धारा भूमण्डलीकरण को चला रही सरकारों के प्रतिनिधियों की ही उपस्थिति को सुनिश्चित बनाती है।

सशस्त्र संगठनों की भागीदारी पर रोक लगाते हुए डब्ल्यूएसएफ का चार्टर इस बात का उल्लेख करता है कि यह उस *अमानवीकरण* की प्रक्रिया, जिससे होकर दुनिया गुजर रही है और राज्य द्वारा प्रयुक्त हिंसा के प्रति *अहिंसक* सामाजिक प्रतिरोध के लिए क्षमता में वृद्धि करेगा। " (जोर हमारा) तो इस प्रकार दुनिया शोषण के सघन होते जाने के फलस्वरूप अमानवीकृत होती जा रही है। शोषण की प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए राज्य हिंसा का सहारा ले रहे हैं, फिर भी प्रतिरोध को अहिंसक होना होगा; कार्रवाई के अहिंसक स्वरूप को बनाये रखने में विफलता किसी को भी डब्ल्यूएसएफ जमावड़े में भाग लेने से वंचित कर देगी।

दूसरी तरफ पैसे जुटाने का सवाल जून 2001 में पारित किये गये डब्ल्यूएसएफ के सिद्धान्तों के चार्टर में भी नहीं आया। भौतिकवादी होने के नाते मार्क्सवादी इस बात का उल्लेख करेंगे कि मंच की प्रकृति को समझने के लिए उसके भौतिक आधार की तरफ हमें देखना चाहिए। (वास्तव में इस बात को समझने के लिए मार्क्सवादी होना भी जरूरी नहीं। कहावत प्रचलित है कि जो जिसका खाता है उसका गाता है।) लेकिन डब्ल्यूएसएफ इस बात से सहमत नहीं है। वह "पूंजी या साम्राज्यवाद के किसी स्वरूप के विश्व प्रभुत्व" के विरुद्ध लड़ते हुए फोर्ड फाउण्डेशन जैसे साम्राज्यवादी संस्थानों से धन हासिल कर सकता है। वाकई, डब्ल्यूएसएफ का चार्टर स्पष्ट करता है कि यह ''अर्थव्यवस्था, विकास और इतिहास के सभी अपचयनवादी दृष्टिकोणों'' के खिलाफ है। यहां खास तौर से उसका इशारा मार्क्सवादी विश्लेषण से है।

डब्ल्यूएसएफ 2001, 2002, 2003

2001, 02 और 03 में वर्ल्ड सोशल फोरम का जमावड़ा तीखे अंतर को अंकित करने वाला था। पहले जमावड़े में जनता के बीच के लोगों की गतिशील उपस्थिति थी। पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या पांच हजार थी जबकि हजारों की संख्या में दूसरे ब्राजीलियाई प्रतिभागी थे। दूसरे जमावड़े में 12 हजार अधिकारिक प्रतिनिधि थे और दसियों हजार दूसरे प्रतिभागी और तीसरे जमावड़े के कुल एक लाख लोगों की उपस्थिति में प्रतिनिधियों की संख्या 20 हजार थी।

एक रिपोर्ट इस बात का ब्योरा पेश करती है कि बैठकों में किस तरह से बैंक कर्मचारियों ने 'सभी बैंकर चोर हैं' शीर्षक वाले पर्चे बांटे और डालर और यूरो बैंक नोटों को जलाया। धातु और तेल कामगारों ने फिलस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। सुबह में बेघर लोगों के संगठन ने उस इमारत पर कब्जा कर लिया जिसे एक साल पहले नगर परिषद ने राजकीय सहायताप्राप्त फ्लैटों में बदल देने का भरोसा दिलाया था। वहीं, 'भूमण्डलीकरण' विरोधी प्रदर्शनों से मिलती-जुलती विविधता इन बैठकों में भी नजर आई। हिस्सा लेने वालों में मजदूरों, किसानों और छात्रों से लेकर पर्यावरणवादी, ऋणों के विरुद्ध अभियान चलाने वाले, और एनजीओ तक थे। अलबत्ता नये जुड़ने वालों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी, अकादमीशियन और राजनीतिक शामिल थे। डब्ल्यूएसएफ की दूसरी बैठक के बारे में जेम्स पेत्रास लिखते हैं :

"फोरम साफ-साफ दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक खेमा सुधारवादियों का थाजिनमें एनजीओ वाले, अकादमीशियन और फोरम के आयोजकों का बहुलांश, एटीटीएसीटोबिन टैक्स के फ्रांस से आये हिमायती और ब्राजीलियन वर्कर्स पार्टी की सोशल-लिबरल शाखा के नेता शामिल थे। दूसरी तरफ ब्राजीलियाई भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन के उग्र परिवर्तनवादी, बुद्धिजीवी कार्यकर्ता, अर्जेंटीना के ध रना-प्रदर्शनकारी, वामपंथी पार्टियों, मजदूर संघों, शहरी आंदोलनों और सॉलिडेरिटी ग्रुपों के प्रतिनिधि थे। बैठक और सार्वजनिक प्रदर्शनों के सामाजिक संघटन में भारी अंतर था। सुधारवादी अधिकारियों द्वारा संचालित शुरुआती उद्घाटन मार्च में हिस्सा लेने वाले लोग भांति-भांति के समूहों से आये हुए थे। लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ 50 हजार लोगों के अनाधिकारिक मार्च का आयोजन रेडिकल ग्रुपों द्वारा किया गया, जिसमें कि ब्राजीलियाई कामगारों, किसानों और बेघरों के काफी बड़े जत्थे के साथ-साथ अर्जेंटीना, बोलीविया और अन्य देशों में जारी संघर्षों से आये जुझारू अंतर्राष्ट्रीयतावादी भी शामिल थे।''

नेओमी क्लीन बताते हैं कि ''कार्यशाला लगाने के इच्छुक किसी भी ग्रुप को बस आयोजन समिति से नाम प्राप्त करने भर की जरूरत थी। ''कई बार तो साथ-साथ चलने वाली कार्यशालाओं की संख्या 60 तक हो गई। वहीं, आयोजन स्थल के मुख्य मंच, जहां से एक समय में एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित करने की सुविधा थी, पर कार्यकर्ताओं का नहीं अपितु राजनीतिकों और अकादमीशियनों का दबदबा कायम था''। पेत्रास सहमतिसूचक शब्दों में कहते हैं : ''मंचों को घेर लेने वाले और अपने क्षेत्रों में आंदोलनों के बारे में जनता को सूचित करने वाले एनजीओ मार्का जाने-पहचाने कुलीन बुद्धिजीवी थे।... अधिकारिक पूर्ण सत्र और भाषण एनजीओ वालों और बुद्धिजीवियों के पक्ष में बहुत अधिक झुके हुए थे जबकि समांतर कार्यशालाओं और सेमिनारों में साम्राज्यवाद (भूमण्डलीकरण) के खिलाफ उल्लेखनीय संघर्षों से मुब्तिला सशक्त आंदोलनों से आये कार्यकर्ताओं के बीच विचारों के फलप्रद आदान-प्रदान की पर्याप्त गुंजाइश थी।

किसे सम्मिलित किया गया

डब्ल्यूएसएफ चार्टर द्वारा राजनीतिक दलों पर रोक लगाने के बावजूद पीटी के मुखिया और अब ब्राजील की संघीय सरकार के प्रमुख लूला ने उसकी तीन बैठकों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस लिहाज से पहले स्थानीय और अब राष्ट्रीय स्तर की सत्तारूढ़ पार्टी डब्ल्यूएसएफ की बैठकों में सर्वत्र उपस्थित थी। और लूला ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियों के तहत डब्ल्यूएसएफ 2003 से सीधे उड़ान भरकर विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने दावोस पहुंचे। इस प्रकार दोनों मंचों में भाग लेना संभव है।

डब्ल्यूएसएफ के दूसरे प्रतिभागियों में से कुछ लोगों की विश्वसनीयता पर गौर करना उपयोगी रहेगा। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अभी भी कमोबेश औपनिवेशिक शासन चला रही फ्रांसीसी सरकार ने अनेक कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल डब्ल्यूएसएफ में भेजे। डब्ल्यूएसएफ की आयोजन समिति जिन लोगों को उसके चार्टर की 'प्रतिबद्धताओं को स्वीकार' करने वालों के रूप में देखती है, उनमें फ्रांसीसी सहकारिता मंत्री (अफ्रीकी देशों विशेषकर पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों के विदेशी ऋण से निपटने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार), आवास मंत्री, शिक्षा मंत्री और इसी तरह के दूसरे लोग आते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएसएफ में संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा निकाय है जिसके नाम पर 1991 से बहुत से नृशंस युद्ध लड़े जा चुके हैं। डब्ल्यूएसएफ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान का विशेष संदेश पढ़ा गया। ऐसा ही दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भी किया गया।

किसी भी लिहाज से राजनीतिक पार्टियों पर रोक चुनिंदा है : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि किसी भी संख्या में "निजी तौर" पर हिस्सा ले सकते हैं, और यहां तक कि डब्ल्यूएसएफ के निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी हो सकते हैं। यह रोक वास्तव में उन लोगों को बाहर रखने की व्यवस्था करने के लिए लगाई गई है जिन्हें आयोजक बाहर रखना चाहते हैं।

और तो और इस अंतरविरोध की वजह से डब्ल्यूएसएफ के कुछेक प्रमुख प्रतिनिधियों को भी परेशान होना पड़ा। डब्ल्यूएसएफ के इतालवी संयोजक जोस लुइस डेल रोजो के मुताबिक "हमारी एक समस्या है। *कई हजार राजनीतिक मौजूद हैं, जिनमें बहुत से संसद सदस्य हैं, मुख्य रूप से यूरोप के देशों से आये हुए सांसद जिन्होंने कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध के पक्ष में मत दिया था। इनमें से बहुत से नेता स्वयं को हमारे आंदोलन के खिलाफ घोषित कर चुके हैं।* और अब वे सब अंतरराष्ट्रीय प्रेस को साक्षात्कार देते हुए यहां मौजूद हैं... हमारी समस्या खासकर फ्रांसीसी और इतालवी सांसदों को लेकर है। उदाहरण के लिए इटली के वाम जनवादी पार्टी के सचिव पिएरो फैसिनो को ही लीजिए। इस युद्ध में इटली के शामिल होने के पक्ष में वह जोरदार शब्दों में बोले थे *यही वे लोग हैं जिन्होंने जिनोआ में जब पुलिस हम लोगों को पीट रही थी तो प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के लिए स्थानीय आबादी का आह्वान किया ताकि हमें अलग-थलग करके दमनकारी राज्य मशीनरी की मर्जी पर छोड़ा जा सके*...इसे स्थानीय सरकार के राजनीतिकों का मंच होना चाहिए; लेकिन यहां तो यूरोप से आये मंजे-मंजाये राजनीतिक हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग अपनी म्युनिसिपैलटियों और क्षेत्रों में प्रवासियों को निकाल चुके हैं। इस सबका हमारे सिद्धान्तों से कोई लेना-देना नहीं।"

जर्मन प्रतिनिधिमंडल के ''बहुसंख्यक सदस्य इवानगेलिस्ये एंटविक लंगसएिस्ट (प्रोटेस्टैंट वालंटरी सर्विस ओवरसीज) की तरह के गैर सरकारी संगठनों से आये हुए थे। शिष्टमंडल का बड़ा हिस्सा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े फाउंडेशनों से मिलकर बना था : फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशनकुल 19 प्रतिनिधि, रोजा लक्जेमबर्ग फाउंडेशन9 प्रतिनिधि, हाइनरिख बोल फाउंडेशन2 प्रतिनिधि और जर्मन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स - सात प्रतिनिधि।''

अंतर्राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया संयुक्त राष्ट्र के कतिपय संगठन अंतर सरकारी निकायों पर रोक के बावजूद डब्ल्यूएसएफ में सक्रिय भागीदारी कर रहे थे। "इस तरह की दुविधाओं से एक हद तक पार पाने के लिए भागीदारी के नये रूप को खोजने का 2002 में उस समय प्रयास किया गया जबकि यह फैसला किया गया कि डब्ल्यूएसएफ में कार्यक्रमों का एक नया प्रवर्ग शामिल किया जायेगा : संवाद और विवाद की गोलमेजें। हालांकि इन गोलमेजों के जरिये *आधिकारिक प्रतिनिधियों की सूची में प्रतिबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बहस और चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।*''

एनजीओ को धन प्रमुख रूप से उन्हीं संस्थानों से मिलता है जिनसे डब्ल्यूएसएफ की जाहिरा तौर पर लड़ाई बनती है। डब्ल्यूएसएफ 2003 के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष कहते हैं, "पिछले दशक के लिए हम सिविल सोसायटी के संगठनों के साथ सक्रिय संवाद का आयोजन कर चुके हैं। इसमें उन परियोजनाओं के जरिए, जिनका हम वित्त पोषण कर रहे हैं, होने वाला संवाद शामिल है।" विभिन्न सरकारों को विश्व बैंक के ऋण का 13 प्रतिशत हिस्सा एनजीओ की "सहभागिता" के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। 2001 में इस मद में विश्व बैंक का तकरीबन 2.25 अरब डालर का कर्ज उधार लेने वाले देशों पर चढ़ा। एनजीओ इसके बदले में बैंक और कोष के लिए अपना राजनीतिक कार्य करते हैं। *द इकोनामिस्ट* ध्यान दिलाता है कि "बाहरी लोगों के लिए लम्बे समय तक अपारगम्य समझा जाने वलाा आईएमएफ अब एनजीओ को उन देशों के कार्यक्रम की रूपरेखा की बारीकियों को सिखाने के लिए सेमिनारों का आयोजन करता है ताकि वे बेहतर तरीके से कोष के कार्यकलापों की निगरानी कर सकें और कोष की ऋण पाने की शर्तों के तर्क को समझ सकें।

आईएमएफ के नये कर्ताधर्ता होर्स्ट कोहलेर एनजीओ'ज को पटाते रहे हैं। बैंक के सर्वेसर्वा जिम वोल्फेंसन लम्बे समय से उनके नक्शेकदम पर चलते हुए जी हुजूरी करते रहे हैं लेकिन बैंक में भी घुटना टेकने की प्रवृत्ति बढ़ी है...संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक मार्क मलूच ब्राउन आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें सलाह देने के लिए एनजीओ का बोर्ड है जिसमें कुछ ठीक-ठाक रेडिकल भी शामिल हैं... "

जहां डब्ल्यूएसएफ के प्रतिभागियों का बहुलांश ब्राजीलियाई था (डब्ल्यूएसएफ 2002 में 67 प्रतिशत), सबसे बड़ा गैर ब्राजीलियाई प्रतिनिधित्व उन लोगों का था जिनके पास पैसे थे या जिन्हें उन लोगों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता था जिनके पास पैसे थे और इसमें सामाजिक आंदोलन नहीं अपितु एनजीओ और संसदीय दल आते थे।

अनिवार्यतः विचार-विमर्शों का ढेर उन्हीं अर्थों में 'रचनात्मक' था, जिन अर्थों में एटीटीएसी इस शब्द का इस्तेमाल करता है। विश्व पर शासन करने वाली सत्ता के साथ 'संवाद' शुरू हो चुका है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जेम्स वोल्फेंसन ने डब्ल्यूएसएफ 2003 को भेजा अपना संदेश इन शब्दों में समाप्त किया "मेरे सहकर्मियों और मैंने डब्ल्यूएसएफ की पिछली बहसों का अनुसरण किया और इस वर्ष उभरकर आने वाले विचारों और प्रस्तावों पर हम दिलचस्पी के साथ चर्चा करेंगे...हम काफी निकट रहकर साथ-साथ काम कर सकते हैं।"

किसे बाहर रखा गया

जहां एनजीओ'ज और मौजूदा व्यवस्था के राजनीतिक नेता शहर के पंचतारा होटलों में सैलाब की तरह उमड़ पड़े, वहीं डब्ल्यूएसएफ में महत्वपूर्ण अनुपस्थितियां भी थीं। "राजनीतिक दलों" और "सैन्य संगठनों" पर चार्टर की रोक के मद्देनजर यह अपरिहार्य था कि जन विद्रोहों के प्रतिनिधियों को डब्ल्यूएसएफ के आयोजकों की तरफ से भागीदारी करने से रोका जाता। पहले डब्ल्यूएसएफ के दौरान एफएआरसी (कोलंबिया की क्रान्तिकारी सशस्त्र ताकतें, जो वहां की सरकार के खिलाफ लम्बे समय से सशस्त्र संघर्ष चला रही है और जो अमेरिका की कोलंबिया के लिए व्यापक योजना का मुख्य निशाना हैं) को कुछ प्रतिभागियों की तरफ से व्यापक सहानुभूति मिली। ब्राजील में, अमेरिका विरोधी सशक्त भावनाएं प्रायः कोलंबियाई विद्रोहियों के प्रति एकजुटता के रवैये में प्रतिबिंबित होती हैं। और तो और अनाधिकारिक कार्रवाइयां कोलंबिया की यात्रा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीयतावादी ब्रिगेडों की भर्ती करने की ओर भी निर्दिष्ट थीं। बहरहाल, दूसरी और तीसरी डब्ल्यूएसएफ बैठकों के लिए एफएआरसी प्रतिनिधियों को प्रतिभागियों के तौर पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई। लैटिन अमेरिका के भूमण्डलीकरण विरोधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक मेक्सिको के जपातिस्ता योद्धाओं को भी बाहर रखा गया, स्पष्टतः इसलिए कि वे एफएआरसी की भांति सशस्त्र बल हैं।

डब्ल्यूएसएफ 2002 में क्यूबाई प्रतिनिधिमंडल को भी न तो आधिकारिक दर्जा दिया गया और न ही महत्पूर्ण भूमिका। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज, जो कि अपनी लोकप्रिय सरकार को गिराने के अमेरिका के सघन प्रयासों से जूझ रहे हैं, को भी डब्ल्यूएसएफ 2003 में आमंत्रित नहीं किया गया। इतने पर भी जब वह आ ही गये तो प्रतिभागियों के बीच उनकी सुस्पष्ट लोकप्रियता के बावजूद आधिकारिक मंच पर उन्हें जगह नहीं दी गई।

एक गैर हथियारबंद संगठन मदर्स डि प्लाजा डि मेयो को बाहर रखा जाना भी इतना ही महत्व रखता है। यह उन मांओं का संगठन है जिनके बच्चों को 1976-83 की अर्जेंटेनियाई सैनिक तानाशाही ने 'गायब' करा दिया था। एमएसटी (भूमिहीनों का ब्राजीलियाई आंदोलन) हालांकि औपचारिक तौर पर डब्ल्यूएसएफ की ब्राजीलियाई आयोजन समिति में था, लेकिन मदर्स को इस तरह बाहर रखने को लेकर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। यह इस बात का संकेत है कि वास्तव में किसका दबदबा कायम है। एमएसटी सिर्फ मदर्स को निजी तौर पर उपस्थित होने के लिए उस संगठन की प्रमुख हेबे बोनाफिनी के लिए हवाई टिकट के साथ निमंत्रण भर भेज सका। यहां हम डब्ल्यूएसएफ 2002 के बाद अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित जनसभा में उनके भाषण के कुछ अंशों को प्रस्तुत कर रहे हैं :

"साथियो, हम द्वितीय डब्ल्यूएसएफ के मौके पर पोर्तो अलग्रे में थे। सप्ताह भर चले इस आयोजन में 50 हजार से अधिक लोगों ने शिरकत की। वहां पर हजारों युवाओं समेत दुनिया के कोने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

''इस डब्ल्यूएसएफ के तीन भिन्न स्तर थे। पहला स्तर उन लोगों का छोटा जमावड़ा था जो कि चीजों को नियंत्रित करने वाले प्रभारी थे। उनका नेतृत्व फ्रांसीसियों द्वारा खासकर 'अटैक' के लोगों और कुछ दूसरे देशों से आये अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा था।

''और इसके बाद कमीशनों और सेमिनारों का स्थान था जहां पर सभी बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों और विचारकों ने हिस्सेदारी निभायी। और इसके बाद आम कार्यकर्ता आते थे। हमने इसी स्तर पर भागीदारी की और हमने सभी तरह के लोगों से चर्चा की। अलबत्ता, सच्चाई तो यह है कि हमें डब्ल्यूएसएफ में लाया ही इसलिए गया था कि हम चुपचाप सुनेंइसलिए नहीं कि हम इसमें भागीदारी करें।

''फिदेल कास्त्रो को भागीदारी करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और न ही एफएआरसी को। यह शर्म की बात है। और न ही मदर्स आफ प्लाजा डि मेयो को आमंत्रित किया गया था।

''मैं पोर्तो अलग्रे पहुंची क्योंकि एमएसटी की तरफ से निजी तौर पर मुझे आमंत्रित किया गया था। और यह महत्वपूर्ण था कि मैं वहां थी क्योंकि मैं कुछ अन्य लोगों के साथ इस विश्व सामाजिक मंच की अपनी तीखी आलोचना को आगे बढ़ाने वाले पहले कुछ लोगों में से थी।

''हमने कहा कि सामाजिक जनवाद और समाजवाद एक ही चीज नहीं है। हमने कहा कि यूरोपीय सामाजिक जनवाद ने इस डब्ल्यूएसएफ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसका औचित्य प्रतिपादित किया। हमने कहा कि फ्रांसीसी आयोजक (अर्थात एटीटीएसी) और उनके बिरादर इस प्रक्रिया में निस्संदेह सहभागी हो सकते थे लेकिन उन्हें इसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए था।

''हमने कहा कि हमारे दृष्टिकोण से लोग इस डब्ल्यूएसएफ में भूमण्डलीकरण के खिलाफ लड़ने और संगठित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आयोजकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया कि पहले से ही यह मान लिया गया था कि हम भूमण्डलीकरण को 'मानवीय चेहरा' देने के बारे में बात करने वाले हैं।

''जिन लोगों से मैंने बात की एक भिन्न संदेश सुनने को मिला : अर्जेंटीना के सम्बन्ध में मैंने उन्हें बताया कि मदर्स प्लाजा डि मेयो ने 25 साल पहले प्लाजा डि मेयो को अपने अधिकार में ले लिया था जो कि ब्यूनस आयर्स में राष्ट्रपति के महल के ठीक सामने है।

''और मैंने कहा कि उस जगह पर जहां हमें छोड़ा गया था लाखों की संख्या में लोग नियमित रूप से जमा हो रहे हैं और देश बेचने वाले राष्ट्रपतियों की नए सिरे से लानत-मलामत कर रहे हैं।"

डब्ल्यूएसएफ में जनतंत्र

इस बात का निर्णय कौन करता है कि किसे आमंत्रित किया जाये और किसे नहीं? डब्ल्यूएसएफ खुलेपन और जनतंत्र के प्रति जहां अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है वहीं वास्तव में उसका ढांचा अपारदर्शी

और गैर जनतांत्रिक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य तिवेनेन के अनुसार, "अधिकारिक निर्णय लेने की शक्ति मुख्यतः पीटी से सम्बद्ध सेंट्रल ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन (सीयूटी), एमएसटी, और ब्राजीलियाई "नागरिक समाज" के छह छोटे-छोटे संगठनों से मिलकर बनी आयोजन समिति (ओसी) के हाथों में है। नागरिक समाज के छोटे-छोटे छह संगठनों में से पांच वित्त पोषित एनजीओ (एनजीओ का ब्राजीलियाई एसोसिएशन, एटीटीएसी, जस्टिस एंड पीस ब्राजीलियन कमेटी, ग्लोबल जस्टिस सेंटर और आर्थिक विश्लेषण संस्थान (आईबीएएसई) तिवेनेन इस बात का उल्लेख करते हैं कि हालांकि सदस्यता के लिहाज से सीयूटी और एमएसटी काफी बड़े हैं लेकिन हिस्सेदारी करने वाले ब्राजीलियाई एनजीओ में से कुछ की वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच है : उदाहरण के लिए रियो स्थित अनुसंधान संस्थान आईबीएएसई ने डब्ल्यूएसएफ के लिए धन जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

डब्ल्यूएसएफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना जून 2001 में की गई थी और वर्तमान में इसके पास आठ ब्राजलियाई ओसी सदस्यों को मिलाकर 113 संगठन हैं। हालांकि इनमें से बहुत से भागीदार सक्रिय नहीं हैं। फिर भी बीओसी और आईसी के बीच श्रम और प्राधिकार का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं है। किसी भी लिहाज से जैसा कि आईसी के सदस्यों में से स्वयं एक सदस्य तिवेनेन बताते हैं, "डब्ल्यूएसएफ के पास सामूहिक ढंग से इच्छा शक्ति का निर्माण के लिए आंतरिक कार्य-प्रणाली नहीं है।"

फैसले लिए जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे जनतांत्रिक तरीके से ही लिए जायें। हमें बताया गया है कि डब्ल्यूएसएफ का ढांचा "क्षैतिज" है। केंद्रीकृत ताकत के बगैर ही समूहों की बड़ी संख्या अंतर्क्रिया करती है। बहरहाल, कुछ ताकतें यह तय करती हैं कि किसे बुलाया जायेगा और किसे नहीं, पूर्ण अधिवेशनों और पत्रकार सम्मेलनों में किसे प्रमुखता दी जायेगी और कार्यशाला के कामों में किसे उलझाये रखा जायेगा। एक 'ऊर्ध्वाधर" ढांचे में नीचे से लेकर ऊपर तक संवाद और प्रतिवेदन के लिए गुंजाइश होती है जबकि छद्म क्षैतिज ढांचे में एक अगम्य निकाय द्वारा लिए जाने वाले ऊपर के फैसलों के लिए ही सिर्फ गुंजाइश बनती है। वहीं जनता के प्रतिनिधित्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। डब्ल्यूएसएफ के मिशन के प्रति सहानुभूति रखने वाले लेखक नोआमी क्लीन लिखी है : "मंच का सांगठनिक ढांचा इस कदर अपारदर्शी है कि यह बताना लगभग असम्भव है कि फैसले किस तरह से लिए जाते हैं या उन फैसलों की प्रकृति पर सवाल कैसे उठाये जायें। एक भी खुले पूर्ण सत्र नहीं होते और भविष्य के आयोजनों के ढांचे पर मत देने का कोई मौका नहीं आता। पारदर्शी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में पर्दे के पीछे एनजीओ छाप तीखे युद्ध लड़े जाते हैं वह भी इस बात को लेकर कि बोलने के लिए सबसे ज्यादा समय किसको मिलेगा; प्रेस तक किसको पहुंचने दिया जायेगा और इस आंदोलन के सच्चे नेता के रूप में किसे देखा जायेगा।"

इसके बाद मुश्किल से ही इस बात पर आश्चर्य होगा कि क्यों डब्ल्यूएसएफ के सत्रों को (इसके साथ-साथ जनवरी 2003 में हैदराबाद में आयोजित एशियन सोशल फोरम) का उनके बाहर आयोजित प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। क्लीन बताती हैं कि किस तरह से वर्कर्स पार्टी से टूटकर अलग हुए धड़े पीसएटीयू ने एक दूसरी दुनिया की संभावना के बारे में भाषणो में 'जब तक तुम पूंजीवाद को चकनाचूर कर समाजवाद नहीं लाते दूसरी दुनिया संभव नहीं है' के जोरदार नारे से व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया।"

विश्व सामाजिक मंच की तीन बैठकें हो चुकी हैं, वे तो केवल शुरुआत भर हैं। डब्ल्यूएसएफ एक ऐसी "स्थायी प्रक्रिया" है जिसे कि दुनिया के नये हिस्सों में प्रसार पाना है, अगली "खुली बैठक" का आयोजन भारत में होने जा रहा है और इसके बाद स्पष्ट है कि दूसरे विकासशील देशों में इसका विस्तार किया जायेगा।

अगर कोई चर्चा का परिमाण माप सके तो पहली तीन बैठकों द्वारा अभूतपूर्व परिमाणों में चर्चाएं सृजित की जा चुकी हैं। फिर भी, उस आंदोलन से जिससे यह अपने जन्म की शिनाख्त करता है, तीखा अंतर प्रस्तुत करते हुए डब्ल्यूएसएफ ने साम्राज्यवाद के खिलाफ एक भी कार्रवाई को जन्म नहीं दिया है। जैसा कि उसका चार्टर कहता है, यह सत्ता का केन्द्र नहीं है। बहरहाल, साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रही तमाम सच्ची ताकतों को अपनी सामूहिक निष्क्रियता में उलझाकर डब्ल्यूएसएफ साम्राज्यवाद के उद्देश्य की सेवा करता है।

डब्ल्यूएसएफ मुम्बई 2004 और भारत में एनजीओ परिघटना

पोर्तो अलेग्रे बैठक से उत्साहित होकर डब्ल्यूएसएफ के आयोजक मंच के प्रभाव को और आगे विस्तारित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से कोशिश करते रहे हैं। पिछले वर्ष के दौरान उन्होंने ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना सोशल फोरम की बैठक का, फ्लोरेंस में यूरोपियन सोशल फोरम, रामल्ला में फिलिस्तीनी थीमैटिक फोरम (समझौता वार्ताओं के जरिए संघर्षों के समाधान पर) हैदराबाद में एशियन सोशल फोरम और आदिस अबाबा में अफ्रीकन सोशल फोरम का आयोजन किया। ''अंतर्राष्ट्रीयकरण" की प्रक्रिया के तहत डब्ल्यूएसएफ के निकायों (ब्राजीलियाई आयोजन समिति और अंतर्राष्ट्रीय परिषद) ने डब्ल्यूएसएफ के अगले जमावड़े का आयोजन ब्राजील में नहीं अपितु भारत में करने का फैसला किया।

हैदराबाद में 2 से 7 जनवरी 2003 तक 'एशियन सोशल फोरम' के आयोजन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भारत में इस तरह के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए फोर्ड फाउण्डेशन सहित विदेशी दाता एजेंसियों से अच्छे-खासे धन की उगाही की गई। जिस तरह से ब्राजील में डब्ल्यूएसएफ की शुरुआत 'अटैक' और पीटी द्वारा की गई थी उसी तरह से भारत में भी डब्ल्यूएसएफ की बैठक का आयोजन एनजीओ और कतिपय राजनीतिक दलों, (मुख्य भूमिका में मजदूरों, छात्रों, किसानों और औरतों के अपने जनसंगठनों के साथ माकपा और भाकपा हैं), के गंठजोड़ द्वारा किया जा रहा हैं (डब्ल्यूएसएफ के आयोजन में राजनीतिक पार्टियां औपचारिक रूप से नहीं जुड़ी हैं लेकिन असल में उनके अग्रणी पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं और इस मामले में अंतर महज अकादमिक हैं)। एनजीओ से गहरे रूप में जुड़े कतिपय जन संगठन भी इससे सम्बद्ध है। जहां ये बैठक के आयोजन की पहलकदमी लेने वाली ताकते हैं वही और जो ऐसा करने के लिए पूर्णकालिक मानवशक्ति मुहैया कराने की सामर्थ्य रखती हैं वही बड़ी संख्या में दूसरी ताकतों और व्यक्तियों की कार्रवाईयों में इस या उस तरीके से, या तो चर्चाओं के आयोजक के रूप में या फिर महज प्रतिभागियों के रूप में शामिल होने की आशा है।

बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता

पोर्तो अलेग्रे की भांति यहां भी विदेशी फंडिंग दो प्रकार की है : पहली, अवरचनागत फंडिंग, जो डब्ल्यूएसएफ के केन्द्रीय निकाय के पास आती है, दूसरी, विभिन्न प्रतिभागी संगठनों के लिए फंडिंग, जो काफी बड़ी है, लेकिन जिसकी पहचान करना लगभग असम्भव है।

पहले भाग के लिए फंडिंग की नीति डब्ल्यूएसएफ की भारतीय आम परिषद द्वारा दिल्ली के बीटीआर भवन में उसकी 7-8 अप्रैल 2003 की बैठक द्वारा पारित नीति के अनुरूप है : "अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय निधियांआईसी/बीओसी द्वारा जुटाई जायेगी और उनका प्रबंध भी वही करेंगी।'' यहां किस तरह के स्रोतों का दोहन किया जा सकता है इस पर किसी सिद्धान्त की घोषणा नहीं की गई, ठीक उसी तरह से जैसे कि इस विषय पर डब्ल्यूएसएफ का चार्टर खामोश है। इससे अलग हटकर आंशिक फंडिंग नीति कहती है कि "प्रवासी भारतीयों (और) धनदाता संगठनों को छोड़कर दूसरे संगठनों और व्यक्तियों से एकजुटता कोष में योगदान के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।'' "प्रोजेक्ट वर्ल्ड सोशल फोरम 2004" दस्तावेज (विश्व सामाजिक मंच सचिवालयब्राजीलियाई आयोजन समिति और भारतीय आयोजन समिति) का अनुमान है कि 25 लाख डालर जुटाने पड़ेंगे।

बहरहाल, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, यह दाता एजेंसियों की पूरी भूमिका पर प्रकाश नहीं डालता है।

दरअसल, "प्रोजेक्ट वर्ल्ड सोशल फोरम 2004" कार्यक्रम के लिए 297 लाख डालर (लगभग 135 करोड़ रु.) के कुल खर्च का अनुमान व्यक्त करता है, जिसका बहुलांश 262 लाख डालर प्रतिनिधियों की भागीदारी का खर्च है (आवागमन, रहने की व्यवस्था और खान-पान)। इस खर्च के बड़े हिस्से का बोझ दाता एजेंसियां उठायेंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एनजीओ पदाधिकारियों और कर्मचारियों की फौज हिस्सा ले रही होगी। देश के लगभग सभी विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ मौजूद रहेंगे। उनके साथ-साथ विदेशों से तमाम एनजीओ आयेंगे। बहुतेरी विभूतियों की यात्रा भी एनजीओ द्वारा प्रायोजित की जायेगी। बहरहाल, उक्त धनराशियां डब्ल्यूएसएफ सचिवालय के खाते में दर्ज किये बगैर सीधे प्रतिनिधियों को वितरित की जायेंगी। डब्ल्यूएसएफ सचिवालय को फाउंडेशनों/दाता एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली धनराशि डब्ल्यूएसएफ की बैठक में काम आने वाली वास्तविक धनराशियों का छोटा सा हिस्सा भर है।

भारत में एनजीओ सेक्टर

आइये एनजीओ की गतिविधियों पर दृष्टिपात करते हैं। 1980 और '90 के दशक में भारत में विदेशी सहायताप्राप्त एनजीओ'ज असाधारण प्रसार देखने को मिलता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2000 तक विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के तहत तकरीबन 20 हजार संगठन पंजीकृत हो चुके थे; हालांकि इनमें से केवल 13,800 संगठनों ने ही सरकार के पास अपने खाते जमा कराये, जैसा कि जरूरी था। इन संगठनों द्वारा 1998-99 में हासिल की गई 3,925 करोड़ की कुल धनराशि 2000-01 में बढ़कर 4,535 करोड़ रु. (तकरीबन 99.3 करोड़ डालर) हो गई।

स्वतःस्फूर्त सामाजिक परिघटना नहीं

एनजीओ प्रचारित करते हैं क वे समाज से स्वतःस्फूर्त ढंग से उभरकर आये हैं, लिहाजा पहले 'स्वैच्छिक एजेंसी' और इस समय की पसंदीदा शब्दावली 'नागरिक समाज के संगठन' का चलन अस्तित्व में आया। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियां (जिनसे कि तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में छोटे-छोटे एनजीओ धन हासिल करते हैं), सरकार कारपोरेट और संस्थागत स्रोतों के धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। मिसाल के लिए, विश्व बैंक के दस्तावेज "विकास पर रिपोर्ट : 2000-2001'', के मुताबिक 1999 में विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं में सत्तर फीसदी से अधिक में एनजीओ और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल थी। सात से अधिक देशों में एनजीओ को बढ़ावा देने वाली इकलौती परियोजना की लागत 9 करोड़ डालर है।

बैंक ने अपने पदाधिकारियों में से दो को एनजीओ और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिए तैनात किया। यह संख्या आज बढ़कर 80 हो गई है। जहां तक सरकारी सहायता की बात है, एक दूसरी रिपोर्ट अमेरिका को छोड़कर दूसरे उन्नत औद्योगिक देशों से एनजीओ को 1995 में मिलने वाले 2.3 अरब डालर के बारे में बताती है। अमेरिकी सहायता को मिला देने पर यह आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच जायेगा। जैसा कि एक लेखक इसे यूं पेश करता है, "ये अति विशाल धनराशियां 'सामाजिक परिघटना' के रूप में एनजीओ की तेज वृद्धि को पेश करने की धोखाधड़ी को स्पष्ट कर देती है।"

बहुराष्ट्रीय निगम, साम्राज्यवादी सरकारें और विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र की तरह के संस्थान इस तरह धनराशियों को एनजीओ तक प्रवाहित क्यों करते हैं?

सचमुच, एनजीओ का असाधारण प्रसार कई तरह से साम्राज्यवाद की सेवा करता है।

1. एनजीओ विशेषकर वे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास जैसी विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए कार्य करते हैं, राज्य और जनता के बीच बिचौलिए के रूप में कार्य करते हैं। बहुत से राष्ट्र-राज्य जनतंत्र के छल-प्रपंच को बनाये रखने के लिए इसे उपयोगी पाते हैं जबकि वे अपने बजटों से लोगों की जीने की सर्वाधिक बुनियादी जरूरतों की भी कटौती कर रहे हैं। एनजीओ राज्य के निजी ठेकेदारों के रूप में काम करते हुए बचाव के लिए आ जाते हैं। एनजीओज का लाभ यह है कि राज्य सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। लोग एनजीओ से अधिकार के तौर पर कुछ भी नहीं मांग सकते : एनजीओ से वे जो कुछ पाते हैं वह 'दान' है।

1980 के दशक तक भारत में एनजीओ गतिविधि ग्राम्योत्थान, ये साक्षरता, औरतों-बच्चों के लिए पोषण, स्वरोजगार के लिए छोटे ऋण, जनस्वास्थ्य और इसी तरह की 'विकासपरक' गतिविधियों तक सीमित थी। 2000 में यह एनजीओ गतिविधि का प्रमुख क्षेत्र बना रहा। 97 करोड़ रुपये या कुल विदेशी निधियों का 21 फीसदी हिस्सा ग्रामीण विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मद में लगाया गया। इस आंकड़े में दूसरे 'विकासपरक' मदों को इसमें जोड़ दिया गया होगा।

परन्तु किस संदर्भ में ये विकासपरक गतिविधियां चलाई जा रही हैं? विकास के सचेतन और जबर्दस्त रूप से *विकास के दमन* के बुनियादी संदर्भ में। एक के बाद एक आने वाली भारतीय सरकारें आईएमएफ और विश्व बैंक के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास पर खर्च को 1985-90 में जीडीपी के 14.5 प्रतिशत से घटाकर 2000-01 में 5. 9 प्रतिशत तक करती रहीं। इस खर्च में कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कुटीर उद्योग, ऊर्जा और परिवहन पर खर्च शामिल है। केन्द्र और राज्यों के आंकड़े संयुक्त हैं। ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर अब थम गयी है, *प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग नाटकीय रूप से 1939-44 के अकाल के स्तर से भी नीचे चला गया है,* स्थिति अनर्थकारी है। अगर केन्द्र और राज्यों के ग्रामीण विकास पर खर्च 1985-90 की जीडीपी की उसी दर पर बने रहते तो वे 2000-01 में 124,000 करोड़ रु. नहीं हुए होते बल्कि 305,000 करोड़ रु. या वास्तविक धनराशि का ढ़ाई गुना होते।

खर्च के इस विशालकाय अंतर के साथ तुलना करने पर भारत में एनजीओ द्वारा खर्च की जा रही धनराशि नगण्य जान पड़ती है। लेकिन उनकी उपस्थिति से चारों तरफ यह विचार जाता है कि निजी क्षेत्र *राज्य द्वारा छोड़े गये अंतराल को भरने के लिए मैदान में उतर रहे हैं।* शासकों के लिए यह दोहरे रूप में उपयोगी है। 'निजीकरण' के राजनीतिक प्रचार में अड़ंगा डाल दिया गया है; और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लोग अपने अधिकार के रूप में कुछ भी मांगने में सक्षम नहीं रह गये हैं।

कुल मिलाकर यह कि एनजीओ की गतिविधियां उस आमूल सामाजिक दावों से भी पीछे हटते जाने में राज्य की मदद करती हैं एक सामाजिक उत्पाद पर जितना अभी भी लोगों के पास बचा हुआ है।

इस प्रकार, एनजीओ उन स्थानों पर बहुत अधिक तेज रफ्तार से फैल रहे हैं, जहां पर राज्य की नीतियांआम तौर पर आईएमएफ/विश्वबैंक निर्देशित नीति का हिस्सा हैखाद्यान्न, स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं से पीछे हट रही हैं। नीतियों द्वारा बरपा किया जाने वाला कहर जितना भीषण होता है पीड़ितों की सहायता के लिए एनजीओ के प्रसार को उतना ही प्रायोजित किया जाता है। (सचमुच, क्या यह सच नहीं है कि किसी देश पर हमला करने से पहले अमेरिका अग्रणी एनजीओ को धन मुहैया कर तैयार करता है ताकि तबाही का कहर बरपा होने के बाद वे 'राहत' पहुंचा सके। इसी तर्ज पर 2002 के उत्तरार्द्ध में इराक के लिए अमेरिकी कारवां में शामिल होने की अपनी तैयारी के तहत एनजीओ ने अभी भी तबाह-बर्बाद अफगानिस्तान में अपने खर्च और मानव शक्ति में कटौती करना शुरू कर दिया था।

2. अपनी मानव शक्ति की भर्ती करने के दौरान एनजीओ स्थानीय लोगों को रोजगार और मलाई का एक छोटा हिस्सा प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थानीय तौर पर प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, जिनका प्रभाव और अभियान फिर एनजीओ को लाभ पहुंचाता हो या वे अधिकारियों के संभावित विरोधी मुखर और गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हो सकते हैं, जो अन्ततः खरीद लिए जाते हैं। दोनों ही मामलों में एनजीओ द्वारा दिया जाने वाला रोजगार, हालांकि तीसरी दुनिया के देशों में बेरोजगारी के स्तर की तुलना में बेहद मामूली होता है, मौजूदा व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हुए स्थानीय राजनीतिक प्रभाव के नेटवर्क के तौर पर कार्य करता है।

3. जनता के आंदोलनों के क्षेत्र में, 'ऐक्टिविस्ट' या 'एडवोकेसी' एनजीओ बुनियादी परिवर्तन के लिए होने वाले संघर्षों को टकराव के रास्ते से वार्ताओं की ओर मोड़कर मौजूदा ढांचे को बचाये रखने में मदद पहुंचाते हैं। विश्व बैंक अपनी "विकास पर रिपोर्ट में" एनजीओ को बढ़ावा देने के अपने राजनीतिक कारणों को व्याख्यायित करता है। रिपोर्ट बताती है : "सामाजिक तनावों और बंटवारों पर औपचारिक और अनौपचारिक मंचों के ढांचों के भीतर राजनीतिक विरोधियों को एक साथ लाकर उनकी ऊर्जाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए प्रवहमान बनाकर पानी के छींटे डाले जा सकते हैं जिससे तनाव करने का एकमात्र रास्ता टकराव ही न रहे।" इस प्रकार 1970 के दशक के शुरू से ही क्रान्तिकारी आंदोलनों की सशक्त परंपरा वाले राज्य आंध्र प्रदेश में एनजीओ का व्यापक प्रसार देखने को मिल रहा है। और वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में यह अधिकतम विदेशी एनजीओ का धन पाने वाले राज्यों में है।

एनजीओ जनान्दोलनों को नौकरशाहाना बना देते हैं। पंरपरागत तौर पर जनांदोलन आत्मनिर्भर होते हैं : उन्हें अपने संसाधन जुटाने होते हैं और उनके प्रतिनिधि स्वयं लोगों के बीच से आते हैं। इन प्रतिनिधियों को इस या उस हद तक लोगों के प्रति जवाबदेह होना होता है। इसके ठीक उलट, एनजीओ के नेतृत्व वाले आंदोलन, जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए भी, एनजीओ के अधिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करते हैं जिन्हें गतिविधियों को संचालित करने के लिए दाता एजेंसियों द्वारा धन दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से, वे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, न ही उन्हें उनके द्वारा हटाया जा सकता है, इस तरह वे जनमत की परवाह किये बगैर कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। दूसरी तरफ, एनजीओ अपने दाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं ओर एक सीमा से आगे इधर-उधर जाना सहन नहीं कर सकते। *विदेशी और सरकारी धनापूर्ति को निकाल दीजिए, भारत में समूचा एनजीओ सेक्टर एक दिन में भरभराकर ढह जायेगा।*

सचमुच, एनजीओ चहुं ओर फैल चुके हैं और सहायता के जरिए आदिवासी संगठनों, दलित संगठनों, स्त्रियों के संगठनों, 'मानवाधिकार' संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों, और असंगठित श्रमिकों के संगठनों को खड़ा कर अपनी शाखाओं को वे विस्तार दे चुके हैं। भूमण्डलीकरण और उसके दुष्प्रभावों समेत किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले प्रायः एनजीओ ही होते हैं। स्वयं राजनीतिक जीवन का भी ज्यादा से ज्यादा एनजीओकरण होता जा रहा है जो कि नौकरशाहाना बन गया है और जनभावनाओं की मौजूदगी और जन प्रतिनिधित्व से कटा हुआ है।

विचारधारात्मक आधार

विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ सेक्टर ने आश्चर्यजनक एकरूपता के साथ कतिपय राजनीतिक अवधारणाओं को प्रचारित किया है। ऐसी पहली अवधारणा है वर्ग के ऊपर 'पहचान', लिंग, नस्ल, जाति राष्ट्रीयता को प्रमुखता।

इस प्रवृत्ति की विचारधारात्मक आधार, उस वैचारिक शाखा से मिलता है जिसे 'उत्तर आधुनिकतावाद' के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक धारा है जो कि दुनियाभर में सामाजिक विज्ञान के

शैक्षणिक संस्थानों में अगर इस समय प्रधान नहीं तो शक्तिशाली जरूर है। उत्तर आधुनिकतावादी *संस्थागत* प्रभुत्व को विचारधारा के रूप में उसकी स्वयं की शक्ति ने नहीं बल्कि उसे मिल रही मोटी रकमों और उसे दिये जा रहे अकादमिक रुतबे ने सुनिश्चित बनाया है। यह 1950 के दशक में फोर्ड फाउंडेशन के कार्यों की धमक है।

हालांकि, 'उत्तर आधुनिकतावाद' वास्तव में व्यवस्थित विचार नहीं है, और इसीलिए इसे ठीक- ठीक चिह्नित कर इसका खंडन करना मुश्किल है। नीचे इस विचार के एक महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा की जा रही है जो उस विषय के लिए भी प्रासंगिक है जिस पर हम यहां विचार कर रहे हैं। यह सूत्र ऐसे किसी भी विश्व दृष्टिकोण के विरुद्ध तर्क पेश करता है जो एकीकृत स्वरूप में वास्तविकता को समग्रता में आत्मसात करने की कोशिश (मोटे तौर पर या कामचलाऊ ढंग से ही) करती है। उत्तर आधुनिकतावादी तर्क पेश करते हैं कि इस तरह का विश्व दृष्टिकोण दूसरी वास्तविकताओं पर अपनी परियोजना थोप रहा है। इसके बजाय इसका मानना है कि समान रूप से प्रामाणिक *अनेक वास्तविकताएं* एक साथ मौजूद हो सकती हैं और यह कि इन वास्तविकताओं को विश्लेषित करने वाले औजार अलग-अलग होते हैं।

वर्ग-विश्लेषण और उत्तर आधुनिकतावाद सामाजिक परिघटना का एक दूसरे से एकदम विरोधी विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जिनसे सामाजिक आंदोलनों के व्यावहारिक रूपों के लिए एकदम अलग-अलग नतीजे निकलते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग विश्लेषण तर्क पेश करता है कि औरतों की बहुसंख्यक आबादी के पास मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में समाज के अन्य तबकों (दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और इसी तरह के दूसरे लोगों सहित) के साथ उनके आंदोलन में शामिल होने का उद्देश्य और भौतिक आधार होता है, यह कि औरतों की मुक्ति इस तरह के वृहत्तर संघर्ष (हालांकि विशिष्ट क्षेत्र में) से जुड़ी हुई है, यह कि पुरुष मजदूरों का पुरुष स्वामित्ववादी दृष्टिकोण खुद सभी मजदूरों के दूरगामी हितों के खिलाफ चला जाता है, और यह कि ऐसे दृष्टिकोण से छुटकारा पाने के लिए आम मजदूरों के बजाय शासक वर्गों के प्रभावों को निशाना बनाया जाना चाहिए।

बहरहाल, उत्तर आधुनिकतावाद इस तरह के विचार को "अपचयनवादी" (रिडक्शनिस्ट) मानता है (डब्ल्यूएसएफ के चार्टर में इसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है)। यहां गौरतलब यह है कि उत्तरआधुनिकतावाद सभी संघर्षों को एक ही तराजू पर रख देता है, यह मानते हुए कि लिंग, जातीयता, राष्ट्रीयता और ऐसी ही अन्य श्रेणियों की तरह वर्ग भी महज एक और सामाजिक श्रेणी है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद साझे वस्तुपरक हितों के आधार पर समाज के विभिन्न तबकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की संभावना से इंकार करता है, इसके बजाय वह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इस या उस हद तक ताकतों के परिवर्तनशील गठबंधनों के सम्मिलित होने की बात करता है।

उत्तर आधुनिकतावादी पहुंच में यह बात निहित है कि एक ही गठबंधन के सदस्य किसी दूसरे मसले पर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पुरुष श्रमिक और स्त्रियां ध्येय विशेष में एक साथ आ सकते हैं लेकिन लिंग के मुद्दे पर शत्रुवत बने रहे सकते हैं। इसमें प्रकारान्तर से यह बात निहित है कि "जनता के शिविर" और उन लोगों के शिविर जो कि जनता के शोषण और दमन के लिए जिम्मेदार हैं, के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों शिविर सभी के लिए खुले होते हैं। जब पुरुष श्रमिक, जो कि (उत्तर आधुनिकतावादी की निगाह में) औरतों के संघर्ष का निशाना होते हैं, उस डब्ल्यूएसएफ का हिस्सा हो सकते हैं जिसमें महिलाओं के संगठन भी हिस्सा लेते हैं तो फिर मजदूरों के साथ-साथ उद्योगपतियों के भी फोरम में शामिल होने को रोकने की कोई जरूरत नहीं होती। इस लिहाज से कोई भी चीज संयुक्त राष्ट्र के शिष्टमंडल को फोरम में हिस्सा लेने से रोकती नहीं है या इसी तरह फोरम के किसी महत्वपूर्ण सदस्य को विश्व आर्थिक मंच में शिरकत करने के लिए जाने से नहीं रोका जाता। उनमें से सभी मजदूर और पूंजीपति, प्रदर्शनकारी और विश्व बैंक के पदाधिकारी उस चीज के हिस्से हैं जिसे उत्तर आधुनिकतावादी सभ्य समाज कहते हैं। (इस प्रकार, डब्ल्यूएसएफ इंडिया का अप्रैल 2002 भोपाल घोषणापत्र स्पष्ट करता है कि डब्ल्यूएसएफ को न केवल मजूदरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, फेरीवालों, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, दस्तकारों, कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र के दूसरे सदस्यों, पेशेवरों के लिए बल्कि मीडिया के लिए और स्थानीय व्यवसायियों और उद्योगपतियों के साथ-साथ सांसदों, हमदर्द नौकरशाहों और राज्य के भीतर और बाहर के दूसरे सम्बद्ध तबकों के लिए स्थान बनाना होगा।" (जोर हमारा) राज्य शब्द का प्रयोग यहां स्थापित राजनीतिक प्राधिकार के अंग के अर्थ में किया गया है)

वर्ग विश्लेषण का उद्देश्य दुनिया भर में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना है जो कि सभी तरह के शोषण और दमन का खात्मा करती हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया के तमाम जनगणों को चाहे जिस और जितने भी कष्टप्रद मार्ग से होकर क्यों न गुजरना पड़े, दुनिया के लोगों की यह साझी परियोजना है।

उत्तर आधुनिकतावादी इस तरह की पहुंच को खारिज करते हैं। एडवर्ड हरमैन संक्षेप में इसे इस तरह पेश करते हैं : '''उत्तर आधुनिकतावाद' कही जाने वाली बौद्धिक प्रवृत्ति का एक प्रमुख तत्व वैश्विक समाधानों और सामाजिक विश्लेषण के वैश्विक मॉडलों को खारिज करना और उसके स्थान पर स्थानीय एवं समूहगत भिन्नताओं तथा उन तरीकों को उभारना है जो साधारण लोगों को अपने परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालने और नया स्वरूप देने में मददगार होते हैं। इसके प्रतिपादक अक्सर स्वयं को जनहितैषी और उन आधुनिकतावादियों के अभिजनवाद के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो (आधुनिकतावादी) अपने 'सारतत्ववादी' (essentialist) और 'सर्वसमावेशी' (totalitarian) सिद्धान्तों के आधार पर यह बताते हैं कि एक गैर बराबरी की जमीन पर साधारण जनों का स्वार्थों की खातिर इस्तेमाल किया गया है और उन्हें ठगा गया है।''

राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरना

स्वाभाविक रूप से, उत्तर आधुनिकतावाद के इस सम्प्रदाय में यह बात निहित है कि कोई भी इकलौती राजनीतिक शक्ति किसी देश में जनता के सभी तबकों के साझा दीर्घकालिक हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। इसी तर्ज पर भारत में एनजीओ और फंड पाने वाले विभिन्न बुद्धिजीवियों ने 1980 के दशक के शुरू से गैर पार्टी राजनीतिक

प्रक्रिया के मत को आगे बढ़ाया। यह वही समझदारी है जो कि डब्ल्यूएसएफ के राजनीतिक दलों की भागीदारी पर इस पाखंडपूर्ण रोक के पीछे काम कर रही है।

अगर राजनीतिक दलों के भाग लेने पर रोक जनसंगठनों और जनान्दोलनों को केन्द्रीय स्थान मुहैया कराने के लिए थी तो इसके मंतव्य को समझना कठिन नहीं। राजनीतिक दल वास्तव में 'व्यक्तियों' के रूप में हिस्सा लेकर डब्ल्यूएसएफ में भागीदार तो बन ही सकते हैं जैसा कि ब्राजील में डब्ल्यूएसएफ की बैठक में पीटी की अग्रणी भूमिका, इन जमावड़ों में हिस्सा लेने वाले सांसदों के झुंडों और इस तथ्य के द्वारा देखा जा सकता है कि माकपा और भाकपा मुंबई बैठक के आयोजन से जुड़ी हुई है। यहां उल्लेखनीय बिंदु वह विचारधारात्मक अवधारणा है जिसे प्रचारित करने के लिए उत्तर आधुनिकतावादी/एनजीओ सिद्धान्तकार भारी मशक्कत करते हैं : यानी यह अवधारणा कि समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करने का उद्देश्य रखने वाली कोई अकेली राजनीतिक शक्ति विभिन्न समूहों के वैविध्यपूर्ण जीवन या जीवन जीने के तरीकों पर थोपी हुई होती है।

सच्चाई यह है कि, मौजूदा व्यवस्था को चलाने वालों के लिए किसी ऐसी सुसंगत राजनीतिक शक्ति को किनारे लगाना बेहद जरूरी है जो उस व्यवस्था के विरोध में खड़े तमाम तबकों को आपस में जोड़ सके।

इस प्रकार एनजीओ जहां जनता के विभिन्न तबकों को नेतृत्व प्रदान करने वाली इकलौती राजनीतिक पार्टी की अवधारणा का विरोध करते हैं वहीं वे स्वयं अपने आप में इकलौती राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। ज्यादातर मुद्दों पर उनके बीच एक राय है। समाज के विभिन्न तबकों के व्यापक दायरे में उनकी राजनीतिक गतिविधियां स्पष्टतः फैली हुई है : वे औरतों, आदिवासियों, दलितों, असंगठित श्रमिकों, मछुआरों और झोपड़पट्टी निवासियों के संगठन चलाते हैं, इसके अलावा वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए संगठन, सांस्कृतिक संगठन और मानवाधिकार संगठन भी चलाते हैं (वाकई, गुजरात नरसंहार के पीड़ितों को राहत प्रदान करने और वहां अपराधों के दस्तावेजीकरण में एनजीओ द्वारा काफी प्रशंसनीय कार्य किये गये।

बहरहाल, अभी तक कुल मिलाकर एनजीओ को परम्परागत जनसंगठनोंट्रेड यूनियनों, किसान यूनियनों, छात्र संगठनों, महिला संगठनोंद्वारा राजनीतिक ताकत के रूप में मान्यता नहीं मिल पायी है और यह स्थिति अभी बनी हुई है कि जन संगठन जनता के विभिन्न तबकों को गोलबंद करने की बहुत अधिक क्षमता रखते हैं। अब, डब्ल्यूएसएफ की तरह के प्लेटफार्मों के जरिए एनजीओ को राजनीतिक ताकत के तौर पर स्वयं को वैध बनाने और समाज के उन तबकों के बीच अपना प्रभाव विस्तारित करने का मौका मुहैया कराया जा रहा है, जिनके पास तक पहले उनकी पहुंच बहुत कम हुआ करती थी।

माकपा का पहले का रवैया

एक महत्वपूर्ण माकपा कार्यकर्ता और अब पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश कारत ने 1988 में भारत में एनजीओ राजनीति और व्यवहार की आलोचना प्रस्तुत की। पहले-पहले यह माकपा के सैद्धान्तिक पत्र *द मार्क्सिस्ट* में प्रकाशित हुई। *'विदेशी फंडिंग और स्वयंसेवी संगठनों का दर्शन'* शीर्षक से प्रकाशित इस आलोचना में इस परिघटना का ब्यौरा पेश किया गया और उस विषय एवं नुक्तों पर जिसे यह अपने खतरों के तौर पर लेती है, तरह-तरह के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती है।

कारत ने अपने शोध प्रबंध को संक्षेप में निम्नवत रखा : भारतीय समाज में घुसपैठ करने और उसके विकास के रास्ते को प्रभावित करने के अपने रणनीतिक मंसूबे को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों/एक्शन ग्रुपों की शक्तियों का दोहन करने के लिए साम्राज्यवादी हलकों में परिष्कृत (सूक्ष्म) और विस्तृत रणनीति तैयार कर ली गई है। साम्राज्यवादी हुक्मरानों ने ही अपने अकादमिक गिरोहों के जरिये भारत में अच्छी खासी संख्या में घुसपैठ कर रहे इन ग्रुपों के लिए राजनीतिक और विचारधारात्मक आधार मुहैया कराया। इन ग्रुपों को उदारतापूर्वक फंड मुहैया कराकर साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज के महत्वपूर्ण तबकों तक सीधे तौर पर पैठ बनाने और इसके साथ-साथ इस आंदोलन को एक माध्यम के तौर पर वाम आंदोलन की शक्ति का मुकाबला करने और उसे तितर-बितर करने के लिए रचना की है...माकपा और वाम शक्तियों को साम्राज्यवाद के औजारों और हथकंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साम्राज्यवादी घुसपैठ के इस तरीके पर गहराई से विचार करना होगा। इन ग्रुपों द्वारा प्रचारित किये जा रहे दर्शन का खंडन करने के लिए विचारधारात्मक हमले की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि यह आदर्शवादी सोच के मध्यवर्गीय युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।।" (पृ. 2-3)

कारत तर्क देते हैं कि एनजीओ द्वारा अपनायी गयी नयी 'एक्टिविस्ट' की भंगिमा परिष्कृत साम्राज्यवादी रणनीति है"। एनजीओ घुसपैठ के दूसरे चरण में फंड के साथ-साथ विचारधारात्मक पैकेज भी आता है। ग्रामीण और शहरी गरीबों को उनके अधिकारों और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करने के साम्राज्यवादी एजेंसियों और सरकारों के दाता संगठनों के विचित्र नजारे का कोई भला दूसरे तरीके से कैसे व्याख्यायित कर सकता है।"

आलोचना के दौरान कारत ऐसे तमाम फाउंडेशनों का उल्लेख करते हैं जो कि वर्ल्ड सोशल फोरम और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराते हैंआईसीसीओ-नीदरलैंड, फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन, एनओवीआईबी, फोर्ड फाउण्डेशन, कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, आक्सफेम और इसी तरह के दूसरे। "यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों से मिलने वलो धन से स्वैच्छिक एजेंसियों/एक्शन ग्रुपों के समूचे नेटवर्क का रखरखाव और पोषण किया जाता है। फंड का परिमाण और इससे जुड़ी भारी-भरकम धनराशियां इस कदर ध्यान आकृष्ट करने वाली है कि यह देखकर हैरत होती है कि यह क्यों इस देश में तुरन्त अत्यावश्यक सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बना। भारत सरकार द्वारा विदेशी निधियों तक इस खुली पहुंच की अनुमति दिया जाना देश में वित्तीय तौर पर साम्राज्यवादी घुसपैठ के प्रमुख स्रोतों में से एक है।"

राजनीतिक संघर्ष के आह्वान के साथ वह अपनी बात समाप्त करते हैं : "वाम ताकतों को सभी एक्शन ग्रुपों को (अर्थात लोगों को गोलबंद करने और संगठित करने से सीधे तौर पर जुड़े) राजनीतिक सत्ताओं के तौर पर लेना चाहिये। विदेशों से धन पाने वाले ये सभी संगठन खुद-ब-खुद संदेह के दायरे में आ जाते हैं और उनके वास्तविक उद्देश्यों पर से पर्दा हटाने के लिए उनका परीक्षण किया ही जाना

चाहिये।" पृ-64

"भारत सरकार को विदेशी धन के बेरोकटोक प्रवाह की अनुमति देने के उसके मौजूदा रुख को त्यागने हेतु दबाव बनाने के लिए व्यापकतम अभियान निर्मित करना होगा। विदेशी चंदा नियमन अधिनियम, जो कि साम्राज्यवादी निधियों को इस तरह की व्यापक घुसपैठ की अनुमति प्रदान करता है, को आगे भी संशोधित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि : सभी स्वैच्छिक संगठनों का, जो कि राजनीतिक गतिविधि के किसी भी स्वरूप के लिए लोगों को संगठित करने का दावा करते हैं, (राजनीतिक पार्टियों की तरह) उन संगठनों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये, जिन पर विदेशी धन लेने के लिए रोक लगी हुई है...। एक्शन ग्रुपों की सारग्राही और छद्म रेडिकल भंगिमाओं के खिलाफ लम्बे विचारधारात्मक अभियान की सख्त आवश्यकता है।" (पृ. 64-65) वाकई वह गर्व के साथ कहते हैं कि "सर्वविदित है कि ये माकपा कतारें और कार्यकर्ता ही हैं जो कि विदेशी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक कार्य के मंसूबों को उजागर करने में देशभर में सबसे आगे रहे हैं क्योंकि वे उसके निहिताशयों को लेकर पूरी तरह से साफ हैं।" पृ-60

जबर्दस्त पैंतरापलट

माकपा की आधिकारिक अवस्थिति 1988 में इस तरह की थी। अस्सी के दशक के आखिर से तेज बदलाव प्रकट होने लगे। कई मंचों पर अब माकपा सदस्य और एनजीओ खर्चे उठाने के लिए सहयोग-सहकार करते हैं। मिसाल के लिए, 2002 में कोलकाता में आयोजित पीपुल्स हेल्थ कान्फ्रेंस, जनवरी 2003 में हैदराबाद में आयोजित एशियन सोशल फोरम या जनवरी 2004 में मुंबई में आयोजित होने वाला वर्ल्ड सोशल फोरम। इसे आगे बढ़कर, माकपा के विचारधारा निरूपक अपनी अवस्थिति के औचित्य प्रतिपादन के लिए सैद्धांतिकी विकसित करते प्रतीत होते हैं जैसा कि *फ्रंटलाइन* (15/8/03) में छपे माकपा विधायक और विकेंद्रीकरण के प्रभारी राज्य नियोजन बोर्ड के पूर्व सदस्य डा. थामस आइज़क के साक्षात्कार से देखा जा सकता है :

साक्षात्कारकर्ताः आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह का एनजीओ शुरू किया है, उनकी आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि भूमण्डलीकरण और आर्थिक साम्राज्यवाद के एजेंट हैं और उनके द्वारा आयोजित भूमण्डलीकरण विरोधी दिखायी पड़ने वाले संघर्ष और कार्यक्रम वस्तुतः साम्राज्यवादी हितों को आवश्यक रूप से बढ़ावा देने वाली चतुर रणनीति है।

आइजक : इसमें कोई भी संदेह नहीं कि तीसरी दुनिया के देशों में नागरिक समाज को प्रभावित करने के लिए तथाकथित स्वैच्छिक क्षेत्र को उपयोग में लाने की व्यापक साम्राज्यवादी रणनीति काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको जानना होगा कि ऐसे एनजीओ और इसी तरह के दूसरे नागरिक समाज के संगठन और संरचनाएं बड़ी संख्या में हैं जो किसी सामाजिक ढांचे के अत्यावश्यक संघटक अवयव हैं। लिहाजा, साम्राज्यवादी मंसूबों के बारे में सावधान रहते हुए हमें नागरिक समाज के उन संगठनों के बीच अंतर करना होगा, जो साम्राज्यवाद-भूमण्डलीकरण के समर्थक हैं और वे जो ऐसा नहीं करते।...

आइजक सिएटल विरोध प्रदर्शनों और वर्ल्ड सोशल फोरम के बीच के अंतर को धुंधला करने की कोशिश करते हैं : "और आज खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व की वास्तविकता बदल चुकी है और क्रान्तिकारी प्रक्रिया संघर्ष के नये सांगठनिक रूपों को हासिल कर रही है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक और आईएमएम के खिलाफ जनता के स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन, उनके सम्मेलन और हाल-फिलहाल में उभरे युद्ध विरोधी आन्दोलन भी हैं। केवल वे लोग ही जो कि आज की दुनिया में इन वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों से बेखबर है, यह दावा करेंगे कि डब्ल्यूएसएफ और युद्ध विरोधी आन्दोलन साम्राज्यवादी साजिश का हिस्सा हैं। वे समकालीन विश्व की क्रान्तिकारी प्रक्रिया को नहीं समझते।"

वस्तुतः इसके ठीक उलट : डब्ल्यूएसएफ, दूसरी चीजों के साथ ठीक "संघर्ष के उन नये सांगठनिक रूपों" को अपने में मिला लेने की तरफ लक्षित है जो सिएटल के विरोध प्रदर्शनों के आस-पास उभरे थे। ऊपर इसी बात को हमने कुछ विस्तार से दर्शाने की कोशिश की है।

माकपाभूमण्डलीकरण की विरोधी?

जहां माकपा अपनी 1988 की अवस्थिति को पूरी तरह से त्याग चुकी है वहीं एनजीओ पर माकपा की नई अवस्थिति पूरी तरह से हैरत में डालने वाली नहीं है। विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ का विरोध केवल साम्राज्यवाद के व्यापक विरोध के हिस्से के तौर पर ही कोई मायने रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माकपा देश के स्तर पर विरोधी दल है, जो आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ और बहुराष्ट्रीय निगमों, जिनका ये संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, के निर्देशों के आगे केन्द्र सरकार के नतमस्तक होने की आलोचना करती है। लेकिन इसके साथ ही माकपा केरल में जब-तब और पश्चिम बंगाल में स्थायी रूप से सत्तारूढ़ पार्टी है; एक ऐसी पार्टी जो सक्रिय होकर विदेशी निवेश को आमंत्रित करती है, एशियाई विकास बैंक के साथ बड़े विदेशी ऋणों के लिए वार्ता करती है, मजदूर संगठनों का दमन करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करती है, बिजली की दरें बढ़ाती है और इसी तरह के दूसरे काम करती है। दूसरे शब्दों में यह पूरी तरह से उस व्यवस्था का हिस्सा है जो भूमण्डलीकरण के ठप्पे वाले समस्त कदमों को उठा रही है।

GUCCI और अन्य इतालवी फर्मों से निवेश आकर्षित करने के लिए इटली की अपनी हाल की यात्रा से वापस लौटे प.बंगाल के नये मुख्यमंत्री अब अपने पूर्व नियोजित कोलकाता वैश्विक महोत्सव में शामिल होने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कारपोरेट जगत को निमंत्रित करने में व्यस्त हैं ताकि "बाहरी लोगों की निगाह में शहर के बारे में नजरिये को बदल सकें।" मुंबई में उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए वह यह स्पष्ट करने को बेताब हो उठे कि माकपा ने इराक पर अमेरिकी हमले के फलस्वरूप अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया है और यह कि उनकी सरकार चाहती है कि न केवल भारतीय निजी कंपनियां बल्कि विदेशी फर्में भी उनके राज्य में निवेश करें। दूसरी बात उन्होंने यह साफ की कि बंगाल में अब श्रमिकों का जुझारूपन कोई समस्या नहीं हैसचमुच उनकी "हड़तालें और श्रमिक समस्याएं महाराष्ट्र के मुकाबले काफी कम हैं।" उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि माकपा से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन सेंटर 'सीटू' इस बात से परिचित है कि अगर उद्योग नहीं होंगे तो

नौकरियां भी नहीं होंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के लिए विज्ञापन जारी किए हैं : इसके लिए "रणनीतिक भागीदारों को शामिल करके ज्वाइंट वेंचर रूपांतरण" जैसी भारी-भरकम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें "प्रबंधकीय नियंत्रण सहित 51 से 74 प्रतिशत शेयर हस्तान्तरित करने" की बात शामिल है। सरकार "जनशक्ति के उपयुक्त पुनर्गठन और वित्तीय बकायों को माफ करने पर भी उस हद तक सहमत है जिस हद तक उनकी व्यावहारिक आवश्यकता है।" निजीकरण के लिए वित्तीय सलाहकार का काम कर रही है बहुराष्ट्रीय कम्पनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स।

राज्य में कृषि आधारित उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की संभावना पर प. बंगाल के मुख्यमंत्री की मेज पर अमेरिकन कन्सल्टेंसी फर्म (जिसे कि उनकी सरकार ने अक्तूबर 2001 में तैनात किया था) मैकिंजी की रिपोर्ट पड़ी रहती है। मैकिंजी का प्रस्ताव है कि राज्य की सिंचित भूमि के 41 फीसदी हिस्से में धान की बजाय सब्जियों, फलों की नगदी फसलें उगाई जायें, कृषि पर आधारित बड़े निगमों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया जाना चाहिये; ठेका पद्धति पर कृषि की अनुमति देने के लिए कानूनों को बदला जाना चाहिये; और दशक की समाप्ति तक राज्य को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों को उतारने का लक्ष्य रखना चाहिये। यह पहलकदमी राज्य की तरफ राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेशकों को अकर्षित करने की तरफ लक्षित है। मैकिंजी ने पहले ही इस तरह के तमाम विनेशकों के साथ संपर्क स्थापित कर लिए हैं। हमें उनसे बेहतर प्रत्युत्तर हासिल हुआ है। अब हमारी योजनाएं और प्रयत्न उनकी जरूरतों और मांगों के अनुरूप होने चाहिये।

इस तरह से स्पष्ट है कि भारत में डब्ल्यूएसएफ के दोनों मुख्य आयोजकों एनजीओ और माकपा में से कोई भी मौजूदा साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ गंभीर प्रतिरोध आयोजित करने की स्थिति में नहीं हैं।

विश्व सामाजिक मंचसंघर्ष का औजार?

इस परिघटना के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं को प्रस्तुत करने के क्रम में डब्ल्यूएसएफ के चंदे और उसमें हिस्सा लेने वाले संगठनों की प्रकृति की बाबत हम पहले कुछ विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बहरहाल, अंतिम विश्लेषण में डब्ल्यूएसएफ का परीक्षण सिर्फ इस बात से नहीं होना है कि इसके पास धन कैसे आता है या इस बात से कि कतिपय अग्रणी प्रतिभागी संगठनों या व्यक्तियों का क्या चरित्र है, न ही इस बात से कि उसने विभिन्न ताकतों को शामिल होने से रोका है। आखिरकार, आज विश्व के तमाम मंचों की तरह-तरह की सीमाएं हैं और उनकी अपूर्णताओं के लिए सभी का परित्याग करने से परिवर्तन के लिए जूझ रही ताकतें कमजोर होंगीं। इस तरह के किसी फोरम का असली परीक्षण उसकी वास्तविक राजनीतिक भूमिका से, मौजूदा साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ जनसंघर्षों से उस रिश्ते से होती है कि उसने उन्हें आगे बढ़ाया है या फिर जुझारू ताकतों की दिशा मोड़ने का काम किया है।

डब्ल्यूएसएफ के हिमायती कहते हैं कि उसने संघर्ष को संवेग प्रदान किया है। बात ऐसी नहीं है। जैसा कि हमने दर्शाने की कोशिश की है। गतिशील विरोध आन्दोलन संघर्ष को गति प्रदान करते हैं। जनान्दोलनों और मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया और इक्वाडोर के जन उभारों ने संघर्ष को गति प्रदान की। डब्ल्यूएसएफ ने महज अगले डब्ल्यूएसएफ और फिर अगले के आयोजन को गति प्रदान की है।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष से डब्ल्यूएसएफ का वास्तविक सम्बन्ध जनवरी, 2003 में हैदराबाद में एशियन सोशल फोरम की बैठक में उसके आयोजकों के आचरण द्वारा जोरदार तरीके से प्रकट हो जाता है। हैदराबाद, आंध्रप्रदेश की राजधानी है, जो भारत में एनजीओ चंदे के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में एक होने के अलावा दो अन्य विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। पहली, राज्य सरकारा सम्भवतः देश में सर्वाधिक सक्रिय "ग्लोबलाइजर" है। 1998 में, राज्य सरकार ने 50 करोड़ डालर के विश्व बैंक के ऋण के लिए सीधे वार्ता की, जो आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम (एपीईआरपी) से जोड़कर दिया गया। एपीईआरपी ने राज्य बिजली बोर्ड को विघटित करने, ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने और बिजली की दरें बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने किसानों को मिलने वाले पानी पर शुल्कों, कालेज फीसों, बस किरायों और सरकारी अस्पतालों के शुल्कों में भी वृद्धि करने का निर्देश दिया। इसने चौतरफा निजीकरण का आदेश दिया। राज्य सरकार इसके चलते बरपा होने वाले जबर्दस्त कहर, भुखमरी की लहरों, कर्ज के बोझ तले दबे हजारों किसानों की आत्महत्याओं से विचलित हुए बिना इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाती रही है। जब जनसंगठनों ने बिजली की दरें बढ़ाने का विरोध किया तो हैदराबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ बरसाकर इसका जवाब दिया। वाकई दूसरी खासियत, जो कि पहली की आवश्यक अनुपूरक है, आंध्र प्रदेश में राज्य प्रायोजित आतंक है जो अपने चरम पर है। आंध्र प्रदेश पुलिस को सरकार के राजनीतिक विरोधियों की सैकड़ों की संख्या में फर्जी मुठभेड़ों में निर्दयतापूर्वक हत्या करने के लिए मोटे वित्तीय पुरस्कारों से नवाजा जाता है। निशाने, क्रान्तिकारी समूहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से उन सभी लोगों तक विस्तारित हुए हैं जो आतंक राज्य के आगे झुकते नहीं हैं। नागरिक स्वातंत्र्य कार्यकर्ता विशेष रूप से आतंकराज के निशाने पर होते हैं।

असंख्य पैनल चर्चाओं, पत्रकार सम्मेलनों और सार्वजनिक जुलूसों के साथ हैदराबाद में एशियन सोशल फोरम के जमावड़े ने चंद्रबाबू नायडू द्वारा लाये जा रहे इस सशस्त्र 'भूमण्डलीकरण' पर एक शब्द भी नहीं कहा। स्पष्ट तौर पर आयोजकों ने सरकार के साथ शर्तों पर बातचीत कर ली थी। दरअसल, एएसएफ की बैठक के समय ही नायडू और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी स्वयं हैदराबाद में ही निवेश सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। नायडू के कार्यक्रम के खिलाफ

क्या साफ होगी।

अनुवाद : कामता प्रसाद

डब्ल्यूएसएफ, एनजीओ और हमारा दृष्टिकोण

अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच (एआईपीआरएफ)

यह विस्तृत लेख वर्ल्ड सोशल फोरम और एनजीओ के असली चरित्र को बेनकाब करने के साथ ही डब्ल्यूएसएफ के प्रति सर्वहारा वर्ग का क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। डब्ल्यूएसएफ के प्रति सर्वहारा दृष्टिकोण के प्रतिपादन में अपनाये गये बुनियादी 'एप्रोच' के साथ सहमति के बावजूद कुछेक बिन्दुओं पर सम्पादक मण्डल की राय अलग है। उदाहरण के लिए, लेख के अन्तिम हिस्से में डब्ल्यूएसएफ के प्रति 'संकीर्ण' रुख से बचने और उनके प्रति 'एकता और संघर्ष' का रुख अपनाने की हिमायत की गयी है। हम इससे सहमत नहीं हैं। इसके साथ ही लेख में अनेक स्थानों पर भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना, शासक वर्ग के चरित्र एवं उसकी एक प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस के उद्‌भव तथा भारतीय क्रान्ति की मंजिल आदि के बारे में प्रसंगवश जो मूल्यांकन प्रस्तुत हुए हैं उनसे भी हमारी असहमति है। फिर भी, डब्ल्यूएसएफ पर समझ बनाने के नजरिए से लेख बेहद उपयोगी है। *सम्पादक*

भूमण्डलीकरण का विरोध करने के नाम पर जनवरी 2003 में हैदराबाद में दुनियाभर से भारी संख्या में संगठन एवं लोग जमा हुए थे। यह आयोजन वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यूएसएफ) द्वारा एशिया सोशल फोरम के तहत किया गया। स्थानीय स्तर पर इसके मुख्य आयोजक संशोधनवादी पार्टियां सीपीआई एवं सीपीआई (एम) थीं। एशिया सोशल फोरम (एएसएफ) के इस तमाशे में व्यापक मार्क्सवादी-लेनिनवादी खेमे से जुड़े कुछ संगठन भी शामिल थे।

किंतु कुछ क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील संगठनों एवं व्यक्तियों ने डब्ल्यूएसएफ एवं एएसएफ के आयोजन का बहिष्कार किया तथा "एक दूसरी दुनिया संभव है! एक दूसरा एशिया संभव है" जैसे उनके खोखले नारों का भंडाफोड़ किया। उसी सप्ताह (4 जनवरी) को साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण विरोधी मंच (फैग) ने हैदराबाद में एक रैली का आयोजन किया जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार साम्राज्यवाद का पूरी तरह खात्मा करके ही नयी दुनिया संभव है। इस रैली में साम्राज्यवादी देशों से मिलने वाले फंड और डब्ल्यूएसएफ के रिश्तों को, भूमण्डलीकरण के बारे में एएसएफ एवं इसकी मूल संस्था डब्ल्यूएसएफ के संदेहास्पद विचारों एवं एएसएफ के आयोजकों के पाखंड का पर्दाफाश किया गया।

प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी हलकों में इसको लेकर पुरजोर बहस हुई कि एएसएफ के बारे में क्या रवैया अपनाया जाए।

शुरुआत में सच्ची क्रांतिकारी शक्तियों के बीच भी इस सवाल पर विभ्रम मौजूद था। हालांकि, यह बात सबको स्पष्ट थी कि डब्ल्यूएसएफ एवं एएसएफ भूमण्डलीकरण और जनता के बुनियादी मुद्दों का कोई वास्तविक समाधान नहीं देगा, फिर भी कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि इसमें शामिल होकर हम व्यापक आबादी के बीच अपने विचारों को पहुंचा सकेंगे। कुछ अन्य लोगों ने महसूस किया कि ऐसे हालात में जबकि बड़ी संख्या में प्रगतिशील संगठन एवं व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हों, इसमें भाग नहीं लेने से वे अलग-थलग पड़ जाएंगे। कुछ लोगों का यह भी मत था कि डब्ल्यूएसएफ को एक मित्र शक्ति माना जाए, इसके साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, हमें इसका उपयोग आंध्रप्रदेश में हो रहे राजकीय दमन पर ध्यान खींचने के लिए करना चाहिए, इसमें भाग लेकर हम विविध संगठनों एवं व्यक्तियों से मिल-जुल सकते हैं, इत्यादि।

विभिन्न क्रांतिकारी और प्रगतिशील संगठनों एवं व्यक्तियों ने डब्ल्यूएसएफ की प्रकृति, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों, जनता के क्रांतिकारी आंदोलनों एवं वर्ग संघर्ष पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में जो रुख अपनाया उसमें समझदारी की अस्पष्टता जाहिर हुई। एनजीओ की भूमिका एवं विभिन्न साम्राज्यवादी एजेंसियों और विश्व बैंक-विश्व मुद्रा कोष एवं एनजीओ की वर्तमान भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से रिश्तों की यथेष्ट समझ न होने के कारण भी ऐसा हुआ। एएसएफ के आयोजन में सीपीआई एवं सीपीआई (एम) की सक्रिय भागीदारी ने भी डब्ल्यूएसएफ को "वामपंथी" चेहरा प्रदान किया और कुछ बुद्धिजीवियों और समाज के प्रगतिशील तबकों में भ्रम पैदा किया। डब्ल्यूएसएफ को राष्ट्रपारीय निगमों तथा साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा फंड मुहैया कराने के तथ्य को आयोजकों एवं संशोधनवादी पार्टियों ने न केवल नजरअंदाज किया बल्कि उसे दबाने का प्रयास तक किया गया।

चूंकि, डब्ल्यूएसएफ के ज्यादातर घटक एनजीओ हैं इसलिए एनजीओ की भूमिका, डब्ल्यूएसएफ का दर्शन, राजनीति एवं उद्देश्य की स्पष्ट समझदारी कायम करना तथा सही मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवस्थिति अपनाना जरूरी है। डब्ल्यूएसएफ जनवरी 2004 में पहली बार ब्राजील के बाहर मुंबई में अपना सम्मेलन करने जा रहा है। इसलिए क्रांतिकारियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि इसके लिए भारत का ही चुनाव क्यों किया गया।

भूमण्डलीकरण एवं एनजीओ

1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के मौजूदा दौर की शुरुआत से ही और खासकर 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में रूस एवं पूर्वी यूरोप में नौकरशाही पूंजीवादी राज्य के ध्वस्त होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय पूंजी ने बेहद शातिराना तरीके से एक फैशनेबुल एवं रैडिकल शब्दावली को जोर-शोर से प्रचारित किया है। इस नयी शब्दावली को प्रचारित करने का काम तथाकथित गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के जरिए किया गया है, जो व्यापक पैमाने पर दुनिया भर में पसर चुके हैं।

एनजीओ की नयी शब्दावली है वंचित तबकों का सशक्तीकरण, सभ्य समाज, राज्यवाद का विरोध, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पहचान आंदोलन, तबकों के समूहगत आंदोलन, स्वयं सहायता, सामुदायिक विकास, टिकाऊ विकास, भागीदारी आधारित जनतंत्र, पर्यावरण सुरक्षा, इत्यादि। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ठीक ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां एवं इसके द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलनों के दस्तावेजों में किया जाता है। यह एक विरोधाभास लग सकता है कि वही साम्राज्यवादी एजेंसियां जो दुनियाभर में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण को जोर-शोर से बढ़ावा दे रही हैं वही तृणमूल जनतंत्र, सशक्तीकरण, मानवाधिकार इत्यादि की अवधारणाओं को उछाल रही हैं।

लेकिन अगर शोषक वर्गों की रणनीति का विश्लेषण किया जाए, तो हमें पता चलता है कि दमन एवं सुधार को एक साथ चलाना एक आम चलन है। वही फासिस्ट सरकारें जो संघर्षरत जनता का जघन्यतम कत्लेआम करती है, कथित कल्याणकारी योजनाओं, विकास इत्यादि के लिए खैरात भी देती हैं, चाहे यह एक छोटी जनसंख्या के लिए ही होता हो। इससे भी बुरी बात है कि वे कभी-कभार अपने ही सुरक्षाबलों द्वारा मानवाधिकार हनन किए जाने की बातें करते हैं तथा मानवाधिकार आयोग बनाते हैं।

हमने हाल ही में देखा है कि किस तरह एक ही साथ एक तरफ अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने अफगानिस्तान और इराक में कत्लेआम मचाया और दूसरी तरफ अमानवीय बमबारी के शिकार लोगों में खाद्य पैकेट और मानवीय सहायता भी पहुंचा रहे हैं। वही संयुक्त राष्ट्र, जो अफगानिस्तान, कोसोवो एवं इराक में बर्बर बल प्रयोग एवं बमबारी का अधिकार देता है, बाद में अपनी सहायता एजेंसियों के जरिए मानवतावादी मिशन भेज कर जलापूर्ति, खाद्य सामग्री, दवाईयां इत्यादि मुहैया कराता है। वही विश्व बैंक जो बड़े-बड़े बांध बनाकर लाखों लोगों को विस्थापित कर बेघरबार एवं भूमिहीन बनाता है, विस्थापित लोगों को हर्जाना दिलाने एवं उनके लिए घर बनाने के लिए संगठन बनाकर संघर्ष करता है। वही साम्राज्यवादी एजेंसियां जो विभिन्न परियोजनाओं के दौरान जंगलों की कटाई कर पर्यावरण का विनाश करती हैं, जंगलों की रक्षा के लिए एनजीओ का निर्माण भी करती हैं। ठीक इसी प्रकार जो साम्राज्यवादी ताकतें उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की नीतियों द्वारा विश्व को लूट रही हैं, वही इन नीतियों से आहत जनता को राहत पहुंचाने के लिए एनजीओ बनाते हैं (इस प्रकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है-दबी-कुचली जनता को अराजनीतिक एवं जड़ बनाना) यहां तक कि संघर्षशील जनता के लिए राजनीतिक पार्टियां बना कर जनाक्रोश से बचने के लिए साम्राज्यवादी सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं, जैसा कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर किया। किंतु 1980 के दशक की शुरुआत से एनजीओ बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है, जो कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की अवधि भी है। इसका कारण समझना कठिन नहीं है।

जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, भूमण्डलीकरण साम्राज्यवादियों द्वारा विश्व की उत्पीड़ित जनता, खासकर एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका के देशों की जनता की लूट को अधिकाधिक बढ़ाते जाने की नीति है। यह 1970 के मध्य से उनके गहराते संकट से बाहर निकलने का रास्ता है। साम्राज्यवादियों को पता है कि भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के साथ अभूतपूर्व रफ्तार से व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भयानक बीमारियों का पैदा होना एवं पर्यावरण का विनाश होना लाजिमी है। इससे दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों एवं साम्राज्यवादी मार-काट के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का उभरना सुनिश्चित है। उत्पीड़ित वर्गों की यह एकता, जो निश्चित रूप से होनी है, भूमण्डलीकरण के सूत्रधारों का सर्वनाश कर देगी। साम्राज्यवादियों एवं तीसरी दुनिया के उनके दलाल चमचों का सर्वनाश कर देगी। जो माओवादी जनयुद्ध जारी है वह और तेज होगा और एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिकी देशों के नये क्षेत्रों में फैलेगा। साम्राज्यवादी देशों में मजदूर वर्गों का संघर्ष और गहरा होगा और इन देशों में एक क्रांतिकारी संकट विकसित होना निश्चित है। दुनिया भर की उत्पीड़ित जनता समाजवाद की ओर देखेगी, जो मनुष्य को बेगाना बनाने वाली और उन्हें दयनीय अस्तित्व की ओर धकेलने वाली पूंजीवादी लालच और शोषण की मौजूदा व्यवस्था का एकमात्र विकल्प है। यह उभरते हुए समाजवाद का हौवा है, जो पुराने सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में नौकरशाही पूंजीवादी शासन के ध्वस्त होने के बाद साम्राज्यवादियों को आतंकित कर रहा है।

वास्तव में पूरा साम्राज्यवादी खेमा इन सत्ताओं के ध्वस्त होने के बाद हर्षोन्मत्त हो उठा था और उनके नियंत्रण में प्रतिक्रियावादी मीडिया कम्युनिस्ट सरकारों के सर्वसत्तात्मक स्वरूप, स्तालिन के अपराधों और कम्युनिस्टों के अनगिनत अत्याचारों पर स्टोरी-दर-स्टोरी छाप रहा था। जिनका गुप्त अभिलेखागारों से उत्खनन किया गया था। क्रांतिकारी ताकतों के लिए जो स्थायी विपरीत परिस्थितियां आई हैं, उनका अधिकतम लाभ उठा कर कुप्रचार करने के लिए उपयोग किया जा रहा है कि कम्युनिज्म मर चुका है, मार्क्सवाद पुराना पड़ चुका है, मजदूर वर्गों के लिए एकता का कोई आधार नहीं है क्योंकि मजदूर तबकों, राष्ट्रों, लिंगों, धर्मों इत्यादि के आधार पर विभाजित और उप विभाजित है। बहुत से वामपंथी बुद्धिजीवी, जो वर्ग संघर्ष एवं सर्वहारा अधिकनायकत्व में आस्था खो बैठे थे, 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तर संरचनावाद, उत्तर-आधुनिकतावाद इत्यादि फैशनेबुल प्रवृत्तियों की चपेट में आ गए। समूचे 1990 के दशक में साम्राज्यवादी पूंजी का विचारधारात्मक आक्रमण चलता रहा, लेकिन दशक के अंत में यह दम तोड़ने लगा। जैसे-जैसे विश्व पूंजीवादी तंत्र के अंतर्निहित अंतर्विरोध भूमण्डलीकरण के क्रूर आक्रमणों से गहरे होते गए वैसे-वैसे पूंजीवाद की अंतिम विजय, "इतिहास का अंत", "मार्क्सवाद एवं कम्युनिज्म की मौत", "पहचान की राजनीति" (वर्ग संघर्ष की जगह) जैसे नये सिद्धांतों के सिद्धांतकार एवं विचारकों की प्रतिष्ठा में गिरावट आती गई।

एक तरफ साम्राज्यवादी पूंजी को नौकरशाही पूंजीवादी सत्ताओं

के ध्वस्त होने से कोई बहुमूल्य राहत नहीं मिली और दूसरी तरफ, लगभग इन सभी देशों में पुनः वही ठुकरा दी गयी संशोधनवादी पार्टियां पश्चिमी प्रकार की सत्ता के नये अवतारों को हटा कर वापस सत्ता में आयीं। बहुत से देशों में साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के विरोध में गहन संघर्ष जड़ जमाने लगे और विश्वव्यापी चरित्र प्राप्त करने लगे। नेपाल, फिलीपींस, पेरू, भारत, तुर्की, और अन्य स्थानों पर माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के विरोध में और अधिक प्रगति हुई। अपार जनसमूह की निगाहों में पूंजीवाद की साख और खराब हुई, किंतु समाजवाद फिर भी एक प्रभावी विचारधारा के रूप में विश्व के लोगों में स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि वे समाजवाद को लगे धक्के के परिणामों को अब भी नहीं समझ पाये हैं।

विश्व के कई देशों में मजदूर वर्ग की एकता एवं नयी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के जन्म ने इस मिथक को क्षत-विक्षत कर दिया है कि वर्तमान विश्व में पहचान आंदोलन ही एक प्रबल धारा है और साथ ही इस मिथक को भी कि मजदूर वर्ग की एकता की बात एक इतिहास है। इन सभी बातों में प्रतिक्रियावादी सत्ता वर्ग एवं साम्राज्यवादी देशों एवं तीसरी दुनिया के उनके दलाल पिछलग्गुओं को बौखला दिया है।

इस प्रकार साम्राज्यवाद के संपूर्ण संकट की इसी पृष्ठभूमि में विश्व में जनांदोलनों में वृद्धि तथा पूंजीवादी विचारधारा की साख में हुई क्षति के मद्देनजर साम्राज्यवादियों के लिए जनता को अराजनीतिक बनाने एवं उनके संघर्षों को गुमराह कर शांतिपूर्ण रास्तों की तरफ ले जाना अत्यंत आवश्यक हो गया ताकि भूमण्डलीकरण का आक्रमण निर्बाध हो सके। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एनजीओ की जरूरत एक सुगम उपकरण के रूप में महसूस की गई। इस प्रकार भूमण्डलीकरण ने एनजीओ के 1990 के दशक एवं नयी सहस्त्राब्दी की शुरुआत में कुकुरमुत्ते की तरह फैलाव का आधार प्रदान किया।

1980 के दशक में पहली बार लातिन अमेरिका के देशों में भूमण्डलीकरण को थोपा गया, जहां इसके खिलाफ जनांदोलन बहुत धारदार हो गया। इसीलिए वहां सबसे अधिक एनजीओ दिखाई देते हैं। चिले, ब्राजील, बोलीविया, वेनेजुएला, पेरू में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण एवं निजीकरण की नीतियों ने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। ज्यादातर परिसंपत्तियों के निजीकरण होने के कारण भारी बेरोजगारी एवं गरीबी फैली। 1990 के दशक के मध्य में सब्सिडियों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती के कारण सत्ताधारियों के खिलाफ जनविद्रोह का जन्म हुआ। वेनेजुएला में आईएमएफ विरोधी दंगों, बोलीविया में मजदूरों की हड़ताल, मेक्सिको में जपाटिस्टा ग्रामीण विद्रोह, ब्राजील में मूल निवासियों का विद्रोह, काराकस, ब्राजील एवं अर्जेंटीना में शहरी जनउभार से साम्राज्यवादी भयभीत हो गये। उन्होंने इन देशों को अपनी कथित सहायता में वृद्धि की और अधिक से अधिक एनजीओ की स्थापना को प्रोत्साहित किया। पर साथ ही विद्रोही जनसमूहों का घातक दमन भी शुरू किया। जैसा कि जेम्स पेत्रास ने दर्शाया है, 1980 में बोलीविया में लगभग 100 एनजीओ थे, जो 1992 में बढ़कर 530 हो गए। भूमण्डलीकरण के कारण डरावने स्तर तक बढ़ गयी गरीबी को दूर करने के नाम पर इन एनजीओ को विश्व बैंक एवं साम्राज्यवादी सरकारों ने 1991 में 738 मिलियन डालर की रकम मुहैया करायी।

ओईसीडी (दुनिया के चौबीस सर्वाधिक धनी देशों का संगठन, जिसमें बाद में टर्की एवं मेक्सिको को भी शामिल कर लिया गया) की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके सदस्य देशों में 1989 में चार हजार एनजीओ थे। ये प्रतिवर्ष लगभग तीन बिलियन डालर (लगभग पंद्रह हजार करोड़ डालर) खर्च करते हैं। एक अनुमान के अनुसार एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका में सन् 2000 में लगभग 50,000 एनजीओ थे। इनका वार्षिक बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपये का है। यह सभी अनुमान वास्तव में कम हैं। एनजीओ की संख्या लाखों में है।

अकेले भारत में मार्च 31, 2001 तक फेरा के अंतर्गत पंजीकृत एनजीओ की संख्या 22,924 थी, जो पुनः वास्तविकता से कम का आकलन है। इन्होंने इस साल 4535.23 करोड़ विदेशी वित्त प्राप्त किया, जो विगत वर्ष से पंद्रह प्रतिशत अधिक था। दिल्ली स्थित एनजीओ ने सर्वाधिक वित्त प्राप्त किया जिसके बाद तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के एन.जी.ओ. ने प्राप्त किया। इसमें सर्वाधिक वित्त अमेरिका सेआया, जिसके बाद ब्रिटेन एवं जर्मनी से आया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी उन एनजीओ को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुछ सौ करोड़ का वित्त प्रदान किया, जो सामाजिक सेवाओं एवं लघु स्तरीय योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। विभिन्न राज्य अपने कथित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एनजीओ का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण कुछ राज्यों में हजारों एनजीओ उभर कर सामने आए हैं जैसे झारखंड, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली इत्यादि। वास्तव में विश्व बैंक सरकारों को एनजीओ के जरिए कार्यकारी एवं विकास कार्यों को लागू करने का निर्देश देता है। तीसरी दुनिया में विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त अधिकांश परियोजनाओं में एनजीओ की भागीदारी है। यह तथ्य विश्व बैंक के ही एक प्रपत्र के द्वारा प्रकाश में आया। **विश्व बैंक एवं नागरिक समाज, सितंबर 2000, शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है, विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाओं में जो 1999 तक अनुमति प्रदत्त हैं, सत्तर प्रतिशत से अधिक में किसी न किसी प्रकार एनजीओ और नागरिक समाज संलग्न है।**

एनजीओ की संक्षिप्त रूपरेखा

गैर सरकारी संगठन या एनजीओ शब्दावली वास्तव में अनुपयुक्त है। एनजीओ को साम्राज्यवादी एजेंसियां, साम्राज्यवादी सरकारें एवं दलाल सत्ताएं वित्त प्रदान करती हैं और निर्देशित करती हैं। यह जनता एवं सरकार के बीच एक दलाल के रूप में काम करते हैं। ये संस्थाएं ही वह वाहक हैं जिसके माध्यम से शोषक 'नागरिक समाज' की धारणा प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। ये साम्राज्यवादी पूंजी के चाकर हैं। लगभग सभी एनजीओ उन अदृश्य साम्राज्यवादी हाथों से निर्देशित होते हैं जो इन्हें बनाते हैं या रणनीतिक उद्देश्यों के अनुसार रकम प्रदान करते हैं। इस प्रकार एनजीओ को विकास, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, तृणमूल प्रजातंत्र के नाम पर मोटी रकमें मुहैया करायी जाती हैं। पिछले दशक से विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ की एजेंसियां जोर दे रही हैं कि धनराशियां एनजीओ के माध्यम से खर्च की जाएं। ऐसा ही विभिन्न सरकारें भी कर रही हैं। इतनी मोटी रकमें ऐंठकर एनजीओ एक 'अभिजात्य संगठन' के रूप में काम करते हैं, जिनका जनता से कोई लगाव नहीं होता। फिर भी वे अपने को जनता के सेवक के रूप में दिखाते हैं। यह अनुमानित है कि साम्राज्यवादियों द्वारा

एनजीओ को प्राप्त वित्त का केवल दस-पंद्रह प्रतिशत ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाता है, जबकि इसका अधिकांश भाग एनजीओ के ढांचे के रख-रखाव पर और तथाकथित स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं पर खर्च होता है।

अपने कार्य के आधार पर तीन प्रकार के एनजीओ हैं। पहले प्रकार के एनजीओ वे हैं जो युद्ध, प्राकृतिक विपदा, दुर्घटनाओं आदि के शिकार लोगों को तात्कालिक राहत पहुंचाते हैं। ऐसे एनजीओ मुख्य रूप से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के समय पाये जाते थे।

दूसरी कोटि के एनजीओ वे हैं जो दीर्घ अवधि में सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर बल देते हैं। ये यूरोप में 1960 के दशक में अस्तित्व में आए। तीसरी दुनिया में ये एनजीओ तकनीकी प्रशिक्षण, विद्यालय, अस्पताल एवं शौचालय इत्यादि बनाने के कार्य में लगे हैं। उनका दावा है कि वे आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादक संसाधनों के विकास, ग्रामीण बाजारों के विकास व लोगों के विकास में भागीदारी इत्यादि को प्रोत्साहित करते हैं। वे स्वायत्त समूहों, लघु ऋण समाजों इत्यादि को प्रोत्साहन देते हैं।

तीसरे प्रकार के एनजीओ सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बात करते हैं लोगों की क्षमताओं को मजबूत करने की, उनकी आंतरिक संभावनाओं को मुक्त करने की, उनकी (जनता की) सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने की, उनके पूंजीवाद-पूर्व की सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव से उभरने की इत्यादि। ये एनजीओ विश्व बैंक, विश्व मुद्राकोष, डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करते हैं और सुधार की सलाह देते हैं, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से गोलबंद करते हैं और इन साम्राज्यवादी एजेंसियों एवं सरकारों पर दबाव बनाते हैं, ताकि सुधार एवं परिवर्तन हो सके।

पहली कोटि के एनजीओ मुख्यतः इसाई धार्मिक संस्थान हैं जैसे गिरजाघर, हालांकि ये एनजीओ के दूसरी एवं तीसरी कोटि में भी मौजूद हैं। मोटा-मोटी पहली कोटि के एनजीओ को चैरिटी संगठन कहा जा सकता है। दूसरी कोटि को विकास संगठनों के रूप में व तीसरी कोटि को भागीदारीमूलक एवं वैश्विक संगठनों के रूप में निरूपित किया जा सकता है। पहली कोटि के एनजीओ प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासन को परिलक्षित करते हैं, दूसरे प्रकार के एनजीओ शीतयुद्ध को, और तीसरे प्रकार के एनजीओ भूमण्डलीकरण के दौरान सक्रिय हुए हैं। कुछ एनजीओ के कार्य एक-दूसरे पर आरोपित हैं, उनका वर्गीकरण उनके प्रमुख कार्य के आधार पर किया जाता है।

यह ध्यान देने की बात है कि एनजीओ के कार्य अलग-अलग कालों में साम्राज्यवादियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं।

एनजीओ मुख्यतः बीसवीं सदी में परिदृश्य पर आए, हालांकि कुछ उन्नीसवीं सदी में भी अस्तित्व में थे। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चिम में कुल 344 एनजीओ थे। एनजीओ के मुख्य कार्य साम्राज्यवादी शक्तियों की संस्कृति एवं मूल्यों को उपनिवेशों में फैलाना एवं आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना और गुप्तचर गतिविधियां इत्यादि थे। इसलिये उन्हें उपनिवेशवादी सरकारों से समर्थन मिलता था। उस समय एनजीओ का मुख्य स्वरूप मिशनरी चर्चों का था। ये उपनिवेशवादी सरकारों को सभी प्रकार का समर्थन देते थे।

प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति के बाद, यानी नवउपनिवेशवाद के समय एक चरण आया जब दुनियाभर में एनजीओ की संख्या में वृद्धि हुई। इस अवधि में अमेरिकी एनजीओ की भूमिका यूरोपीय एनजीओ से अधिक हो गयी। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के लिए यह एक लाभप्रद स्थिति थी। उनकी ताकत यूरोपीय साम्राज्यवादियों के दूसरे विश्वयुद्ध में कमजोर हो जाने से बढ़ गई थी इस प्रकार अमेरिकी पूंजी के साथ एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देशों में एनजीओ की घुसपैठ हुई। अमेरिकी एनजीओ के दुनिया भर में फैलने के लिए जिस तत्व ने महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम किया वह था 'कम्युनिज्म के खतरे' को रोकना, जो बहुत से देशों के ऊपर मंडरा रहा था। अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने 'कम्युनिस्ट खतरे' के प्रतिरोध के लिए विचारधारात्मक, राजनीतिक एवं सैनिक नेतृत्व की बागडोर थामी। यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने 1921 के अकाल में सोवियत संघ में 0.5 बिलियन डॉलर के खाद्य, कपड़े, दवाइयां आदि की आपूर्ति के लिए एनजीओ भेजा था। अमेरिकी राहत प्रशासन (एआरए) क्रांति के बाद रूस में राहत के लिए सबसे सक्रिय था। यह तब किया गया जब प्रतिक्रांतिकारियों के समर्थन से रूसी क्रांति को विफल करने के अमेरिका के सारे प्रयास बुरी तरह असफल हो गये। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी एनजीओ ने ऑस्ट्रिया एवं हंगरी में भी खाद्य आपूर्ति की थी ताकि इन देशों में क्रांति के बढ़ाव को रोक सके और उन्हें बोल्शेविज्म से दूर रखा जा सके। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को एनजीओ के माध्यम से साम्राज्यवादियों की सहायता देने का लक्ष्य पूंजीवादी शक्तियों को मजबूत करना और इन अर्थव्यवस्थाओं को उदार आर्थिक नीतियों की तरफ ढकेलना और अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में अच्छी छवि बनाना था। हालांकि, इसके पीछे आर्थिक कारण भी थे। उदाहरण के लिए, रूस को अमेरिका से 'एआरए' के जरिए जो 540,000 टन खाद्यान्न भेजा गया, इससे अमेरिकी बाजार में मूल्यों में स्थायित्व की प्राप्ति हुई तथा साथ ही अमेरिका पर मानवतावादी होने का ठप्पा भी लगा। अमेरिकी एनजीओ ने, अमेरिका के अतिरिक्त खाद्यान्न को 'काम के लिए भोजन' तथा 'दोपहर का भोजन' जैसे कार्यक्रमों के जरिये तीसरी दुनिया के देशों में भेजने के माध्यम के रूप में भी काम किया।

दूसरे वर्ग के एनजीओ का अमेरिका में फैलाव खासकर जॉन एफ कैनेडी के समय से हुआ। उन्होंने उद्घोषणा की कि अमेरिकी सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राजनैतिक प्रजातंत्र अमेरिका की विदेश सहायता नीति के मुख्य संबल हैं क्योंकि वे इन्हें एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका में कम्युनिज्म के खिलाफ एक वास्तविक गारंटी मानते थे। इसलिये स्वयं सहायता (सेल्फ हेल्प), सामुदायिक विकास, युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, साक्षरता, कृषि विकास इत्यादि के लिए योजनाओं की शुरुआत की गयी। अमेरिका के पिछवाड़े में क्यूबा में 1959 में संपन्न क्रांति और लातिन अमेरिका में अमेरिकी दबदबे ने इस काम की फटाफट शुरुआत के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी शासक वर्ग ने लातिन अमेरिकी देशों में एक तरफ भूतपूर्व सैनिक तानाशाहों एवं निरंकुश शासनों (और जहां नहीं है वहां उन्हें स्थापित कर) के माध्यम से फासिस्ट दमन की लहर सी छोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न सुधार कार्य करने की शुरुआत की गयी। उस समय पोप ने यूरोप के चर्च से दस प्रतिशत मिशनरियों को लातिन अमेरिका भेजने का अनुरोध

किया ताकि **लोगों को गरीबी, दीनता से लड़ने में सहायता मिले जिससे कम्युनिज्म के भूत से निपटा जा सके।**

जिस प्रकार एनजीओ उन देशों में काम करते हैं जिन पर साम्राज्यवादी शक्तियों के हमले हुए हैं, वह मानवीय सहायता का मजाक ही है, जिससे हर किसी की आंखें खुल जानी चाहिये। वियतनाम में अमेरिका ने जहां बमबारी और नापाम बम द्वारा बड़े पैमाने पर मौत और विनाश का तांडव रचा वहीं इसने 'केयर' (कोऑपरेटिव असिस्टेंस फॉर रिलीफ, एवरीवेयर), सीआरएस (कैथोलिक सविर्सेज), डब्ल्यू वी (वर्ल्ड विजन), आईवीएस (इंटरनेशलन वोलेंटरी सर्विसेज), अमेरिकन रेड क्रास, वियतनाम क्रिश्चियन सर्विसेज एवं अन्य एनजीओ को युद्ध के शिकार लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए लगाया। हमने देखा है कि अफगानिस्तान एवं इराक में अमेरिका के नेतृत्व में किस प्रकार पाशविक जुनून के साथ बमबारी के बाद मानवीय सहायता दी गयी। बम और रोटी एक साथ गिराये गये। जैसे ही किसी देश पर तबाही का कहर बरपा होता है, लोग मार दिए जाते हैं, अपंग बना दिए जाते हैं, और अपने घरों से विस्थापित किर दिए जाते हैं, एनजीओ 'घाव भरने के लिए' पहुंच जाते हैं।

इससे भी अधिक विडंबनापूर्ण बात यह है कि अमेरिकी कांग्रेस ने विदेशी सहायता से संबंधित 1975 में बने कानून में संशोधन किया जिसमें ऐसे देशों को सहायता रोकने का प्रावधान किया गया था जहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो। यही वह समय था जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों को सभी महाद्वीपों में पाला-पोसा- चीले में पिनोश, फिलीपीन्स में मार्कोस, इंडोनेशिया में सुहार्तो, जैरे में मोबुतु इत्यादि उनमें से कुछ उदाहरण मात्र हैं। मानवाधिकार एनजीओ इन नयी नीतियों की प्रत्यक्ष पैदावार थे जो मानवाधिकार की बातें करते हैं, जबकि उनके आका फासिस्ट तानाशाही को थोपते चलते हैं।

अमेरिकी एनजीओ तीसरी दुनिया में सरकारी प्रोजेक्टों के लिए उप-ठेकेदार का काम करते हैं। यूरोप के एनजीओ की तुलना में अमेरिकी एनजीओ नीतियों के उपकरण के रूप में काम करते हैं, जिसका सीधा सा कारण है कि उन्हें बड़ी मात्रा में सरकार से धन मिलता है जो उनके कुल व्यय का अस्सी प्रतिशत है। एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिकी देशों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ये अमेरिका के प्रभाव, विश्व दृष्टिकोण एवं पश्चिमी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। दानशीलता ही वह छद्म है जिसके आवरण में फोर्ड, रॉकफेलर, कार्नेगी और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों का वित्त इन इलाकों में प्रवाहित होता है। जब एनजीओ की सरकारी वित्त पर निर्भरता बढ़ती गयी और उनकी विश्वसनीयता कम होने लगी तो अमेरिकी कांग्रेस ने समय-समय पर कानून बना कर सुनिश्चित किया कि एनजीओ को प्राप्त कुल वित्त का 1985 तक कम से कम 20 प्रतिशत निजी स्रोतों से प्राप्त किया जाए। बाद में 1985 की समय सीमा को कुछ और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इस कानून को भी तिलांजलि दे दी गयी क्योंकि ज्यादातर एनजीओ निजी स्रोतों से अपना बीस प्रतिशत वित्त प्राप्त करने में असफल रहे।

भूमण्डलीकरण के दौर में, खासकर सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप की सत्ताओं के ध्वस्त होने के बाद, एनजीओ ने भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के दुष्परिणामों की काट करने को अपना मुख्य कार्य बना लिया है। वे भूमण्डलीकरण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिकारी का कहना है कि इसे जनता की भागीदारी के साथ लागू किया जाए या "भागीदारी पर आधारित भूमण्डलीकरण" में तब्दील किया जाए। वे मानवीय चेहरे के साथ भूमण्डलीकरण करते हैं, वहनीय विकास (substantial development) इत्यादि के लिए अभियान चलाते हैं। वे जनता में यह भ्रम पैदा करते हैं कि साम्राज्यवादी एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक एवं ऐसी अन्य संस्थाओं का सुधार संभव है। इस प्रकार वे साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता के आक्रोश को कम करने की कोशिश करते हैं तथा उन्हें सुधारवादी विचारधारा की ओर ले जाते हैं।

एनजीओ के मुख्य लक्ष्य

इन्हें निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है

1. वे व्यापक जनअसंतोष को संवैधानिक, शांतिपूर्ण एवं हानि रहित रास्तों की ओर ले जाकर **'सुरक्षा कवच'** के रूप में कार्य करते हैं।

2. वे उत्पीड़ित जनता को तबकों एवं पहचानों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उत्पीड़ित जनता में वर्गीय एकता के विकास को रोका जा सके।

3. इससे भी बढ़कर वे सिर्फ लैंगिक (स्त्री), जातिगत (दलित), जनजातीय (आदिवासी) तथा राष्ट्रीयता इत्यादि पहचानों के आधार पर उत्पीड़ितों एवं उत्पीड़कों की एकता की वकालत कर विभिन्न तबकों एवं सामाजिक समूहों के बीच **वर्ग विभेद को धुंधला करना या उलझाना चाहते हैं**।

4. वे उत्पीड़ित जनता को यह मिथ्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है और इसकी अंतिम विजय हो चुकी है। वे ऐलान कर चुके हैं कि मार्क्सवाद पुराना पड़ चुका है और कम्युनिज्म मर चुका है, इसलिए हमें वर्तमान विश्व में नागरिक समाज के जनवादीकरण एवं **मानवीय चेहरे के साथ भूमण्डलीकरण** कर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

5. वे राज्य विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो बाहर से प्रगतिशील समूहों को भी आकर्षक लगता है। वे **सूक्ष्म स्तर पर भी निजीकरण करने की कोशिश करते हैं जो उनके आका वृहद पैमाने पर करते हैं।** कहने का तात्पर्य है कि जहां अंतरराष्ट्रीय पूंजी राज्य की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करने की भूमिका पर चोट करती है और चाहती है कि बाजार राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र कार्य करें (यह दूसरी बात है कि वास्तविकता में यह बात कितनी झूठी है) वहीं एनजीओ स्वयंसेवा, सहकारिता, सामुदायिक विकास इत्यादि की बाते करते हैं। इस प्रकार राज्य जनता के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है, जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य की देखरेख, पीने का साफ पानी, सफाई, सिंचाई, रोजगार इत्यादि व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओं को सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार निजीकरण को एनजीओ साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर एक समान लक्ष्य बना लेते हैं। साथ ही वे ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहर की गंदी बस्तियों में रहने वाली गरीब जनता पर खासकर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने तथाकथित दानशील एवं विकास योजनाओं के लिए पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता देते हैं जहां आदिवासी रहते हैं। इस प्रकार वे वंचित जनता के आक्रोश पर पानी के छींटे डाल देते हैं।

6. वे जनता से गैर पार्टी सक्रियता की शब्दावली में बात कर उसे अराजनीतिक बनाने का प्रयास करते हैं। वे दावा करते हैं कि उन्हें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है और जनता का भी आह्वान करते हैं कि वह सभी राजनीतिक पार्टियों से दूर रहें, कि वे अपनी समस्याओं का स्व-सहायता एवं सहकारिता के माध्यम से स्वयं समाधान करें। इस प्रकार अपनी अराजनीतिक लगने वाली रणनीति की हिमायत कर वे सत्ताधारी वर्ग की विचारधारा एवं राजनीति का जनता पर प्रभाव कायम करने के लिए कार्य करते हैं। वे स्वयं को राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। और स्वयं को गरीबों का मसीहा बता कर क्रांतिकारी पार्टियों को विस्थापित कर देते हैं।

7. वे जनता को संघर्ष के रास्ते से विमुख कर तथा उनके बीच के अच्छे तत्वों को व्यवस्था एवं सुधारवाद में शामिल कर अकर्मण्य बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी प्रगतिशील एवं रैडिकल छवि बनाकर वामपंथी बुद्धिजीवियों को अंतरराष्ट्रीय पूंजी के पक्ष में लाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। ये एनजीओ, जिनके पास बहुत सारा वित्त होता है, वामपंथी बुद्धिजीवियों को आकर्षित करने और अपने साथ लेने में विभिन्न कार्यों जैसे सेमिनार, कार्यशाला, कान्फ्रेंस इत्यादि में जाने के लिए, उन्हें प्रोजेक्ट में भागीदार बनाने के लिए तथा अनुसंधान एवं नीतिगत अध्ययनों के लिए वित्त प्रदान कर सफल हो जाते हैं। सैकड़ों प्रोजेक्ट एवं संस्थाएं साम्राज्यवादी पूंजी द्वारा दुनियाभर में स्थापित किए गए हैं। जो साम्राज्यवादियों की आवश्यकताओं के अनुरूप 'थीसिस' गढ़ते हैं। ये बुद्धिजीवी इन प्रोजेक्टों के साथ स्वयं को जोड़कर इन एनजीओ को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं और जनता में भ्रांति पैदा करते हैं।

8. एनजीओ पूंजीवादी शोषण को जारी रखने के लिए जरूरी विचारधारा एवं भ्रांतियों को जन्म देने के लिए जनता की राय गढ़ने के माध्यम के रूप में काम करते हैं। वे लोगों के दृष्टिकोण को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं जैसा राज्य एवं सत्ताधारी पार्टियां प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पातीं। अपने को स्वार्थ रहित, दानशील एवं जनकल्याणकारी दिखाकर, वे जनता की हमदर्दी बटोरते हैं। उनकी रैडिकल एवं साम्राज्य विरोधी लफ्फाजी और विकास, आधुनिकीकरण, तृणमूल प्रजातंत्र, नागरिक समाज का जनवादीकरण, सामाजिक न्याय, राज्य विरोधवाद, मानवतावाद एवं मानवाधिकार, सशक्तीकरण इत्यादि की बकवासें प्रगतिशील एवं कुछेक क्रांतिकारी तबकों को भी धोखा दे सकती हैं। इस प्रकार वे जनता के बीच एक विचारधारात्मक रहस्यीकरण का निर्माण करते हैं और साम्राज्यवादी पूंजी द्वारा बेलगाम लूट के रास्ते बनाते हैं।

9. वे अंतरराष्ट्रीय पूंजी के उपकरण के रूप में काम करते हैं ताकि एशिया, अफ्रीका एवं लातिन अमेरिका में उनका उपनिवेश स्थापित हो सके। वे इन देशों में साम्राज्यवादी पूंजी की घुसपैठ के लिए जमीन बनाते हैं और इस पूंजी के बेरोकटोक कार्यशील होने एवं बाजार के विस्तार के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। अपने काम के लिए सबसे पिछड़े इलाकों का चयन कर इन एनजीओ ने उन इलाकों में सामुदायिक विकास, स्वयंसेवी समूहों इत्यादि के नाम पर बाजार के संबंधों को शुरू करने में सफलता पायी है और साम्राज्यवादियों की मदद से चलने वाले विकास कार्यक्रमों को भी जोर-शोर से आगे बढ़ाया है।

10. वे सूक्ष्मतम तरीकों से क्रांतिकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं और जहां क्रांतियां सफल हो गयी हैं वहां मजदूर वर्ग की सत्ता को अस्थिर बनाते हैं तथा पूंजीवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए शहर के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बुनियादी वर्गों के अलावा एनजीओ सबसे पिछड़े एवं रणनीतिक महत्व के उन क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जहां क्रांतियों के तूफान उठने की संभावनाएं होती हैं।

तमाम उत्तर आधुनिक, जो सामुदायिक उद्यम की तुलना में व्यक्तिगत उद्यम में अधिक भरोसा रखते हैं, लिंग, जाति, जनजाति, राष्ट्रीयता जैसी पहचानों की बात करते हैं और वर्ग एकता की बात को ही खारिज करते हैं। राजनीतिक पराजयवाद का शिकार होकर, वे हिमायत करते हैं कि हम 'इतिहास के अंत' तक पहुंच गये हैं, कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, कि हमारे पास अब एक ही साधन है कि मौजूदा हालात में पूंजीवाद में, भीतर से सुधार किया जाए और इस प्रकार आधुनिक एनजीओ परिघटना के लिए विचारधारात्मक आधार प्रदान करते हैं। चूंकि बहुतेरे उत्तर आधुनिक चिंतक एक समय मार्क्सवादी थे, वे एनजीओ को एक प्रगतिशील और यहां तक कि रैडिकल संस्था के रूप में विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

निचोड़ के तौर पर एनजीओ साम्राज्यवाद के पैरोकार हैं जो आकर्षक भाषा में अपने असली चेहरे को छिपाते हैं। वे जनता की भयावह गरीबी का व्यापार करते हैं और तीसरी दुनिया की गरीबी की मारी जनता की नुमाइश कर साम्राज्यवादी दाताओं या विदेशों में बसे व्यक्तियों से फंड हासिल करते हैं। परजीवियों की तरह वे वंचित स्त्रियों, बच्चों और अपंग लोगों के नाम पर, विकास के नाम पर, सशक्तीकरण के नाम पर और इसी तरह की दूसरी चीजों के नाम पर ऐंठी गयी रकमों पर जीते हैं। वे तीसरी दुनिया के देशों में साम्राज्यवादी पूंजी की घुसपैठ के औचित्य प्रतिपादन द्वारा साम्राज्यवाद के सिद्धांतकार के रूप में सेवा करते हैं और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर साम्राज्यवादियों की सर्वग्रासी पकड़ को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि स्वार्थी, रक्तपिपासु साम्राज्यवादी इन संगठनों को खड़ा करने और उन्हें पालने पोसने के लिए भारी-भरकम धनराशि खर्च करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, कार्नेगी फाउंडेशन, हाइनरिख बोल फाउंडेशन और बड़ी संख्या में दूसरे साम्राज्यवादी संस्थान इन एनजीओ को बनाए रखने के लिए दसियों लाख डॉलर हर वर्ष खर्च करते हैं। वे हर तरह की परियोजना, संस्थान, अध्ययन इत्यादि को पैसा देते हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड फाउंडेशन ने कमोबेश दुनिया के हरेक देश में असंख्य संगठनों और परियोजनाओं को पैसा दिया है और उन्नीस सौ छत्तीस में उसके गठन के समय से लेकर यह धनराशि आठ अरब डॉलर (चालीस हजार करोड़ रुपये) के गगनचुंबी आंकड़े तक जा पहुंची है। उसने साम्राज्यवादियों के लिए प्रासंगिक विषयों पर अध्ययन करने के लिए शोधार्थियों और बुद्धिजीवियों को तैनात किया है। अलाभकारी संगठनों के रूप में भी माने जाने वाले ये एनजीओ वास्तव में साम्राज्यवादी लाभों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। साम्राज्यवाद के इन भेष बदले हुए एजेंटों और हिमायतियों के खिलाफ सुसंगत और निर्मम संघर्ष चलाए बगैर हम क्रांतिकारी जनता को सुधारवादी और संवैधानिक भ्रमों के बाहर नहीं ला सकते। इस मसले पर सतर्कता का अभाव क्रांतिकारी पार्टियों और आंदोलनों को कमजोर बनाने की तरफ ले जाएगा जैसा कि तमाम देशों खासकर लातिन अमेरिका में देखा गया है। इन एनजीओ ने पूर्व समाजवादी देशों में मजदूर वर्ग की तानाशाही को और कालांतर में सोवियत खेमे

के देशों की नौकरशाह पूंजीवादी सत्ताओं को पश्चिमी पूंजी, फंड और विचारधारा झोंक कर नष्ट करने में कोई कम भूमिका नहीं निभायी। हालांकि, जहां एनजीओ की बाबत हमारा मूलभूत आकलन ऊपर दिया जा चुका है वहीं हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एनजीओ बड़ी संख्या में प्रगतिशील एवं साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों को, जो कि सामाजिक परिवर्तन में वाकई दिलचस्पी रखते हैं, अपने आमूल परिवर्तनवादी (रैडिकल) शब्दाडंबर द्वारा और इसके अलावा क्रांतिकारी ताकतों की कमजोरियों के चलते भी आकर्षित करने में सफल रहते हैं।

समाज के वंचित तबकों के बीच जमीनी स्तर पर काम करने वाले कुछेक एनजीओ को आवश्यक रूप से जनता के मुद्दों को उठाने और संघर्षों की शुरुआत करनी पड़ती है। हालांकि, आखिर में इन संघर्षों पर पानी फेर दिया जाता है फिर भी इन संघर्षों को हमारे सक्रिय मार्गदर्शन के जरिए सही दिशा दिए जाने की संभावना बनती है। इस तरह के हस्तक्षेप के जरिए एनजीओ के नेतृत्व की सीमाओं और उसकी भूमिका को उजागर किया जाना चाहिए।

कुछ एनजीओ का खुल्लमखुल्ला साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वास्तव में साम्राज्यवाद के खिलाफ समग्रता में नहीं, वरन् खास साम्राज्यवादी शक्ति या शक्तियों के खिलाफ निर्देशित होता है। यूरोप के एनजीओ अमेरिकी साम्राज्यवाद की लुटेरी और आक्रामक नीतियों की तरफ रैडिकल भंगिमा अख्तियार करते हैं, अमेरिका के एनजीओ प्रायः यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ रुख अपनाते हैं, यूरोप के विभिन्न देशों से जुड़े हुए एनजीओ स्वयं अपने यहां की सरकारों का समर्थन करने वाला लेकिन यूरोपीय संघ के भीतर के दूसरे देशों का भंडाफोड़ करने वाला दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसी तरह की और बातें गिनाई जा सकती हैं। किसी देश के भीतर बहुराष्ट्रीय कंपनी विशेष भी उसी देश में अपनी प्रतिद्वंद्वी बहुराष्ट्रीय कंपनी की असलियत उजागर करने के लिए एनजीओ को नियुक्त कर सकती है या उसे पैसा दे सकती है। लिहाजा, एनजीओ के बारे में आकलन पेश करते समय हमें बेहद सचेत रहना चाहिए, शब्दाडंबर या घोषित उद्देश्यों पर नहीं जाना चाहिए जो कि प्रायः रैडिकल स्वर लिए होते हैं। अंतरसाम्राज्यवादी अंतर्विरोध अनिवार्य रूप से एनजीओ के अभियानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

वर्ल्ड सोशल फोरम का गठन

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि 1990 के दशक में साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के खिलाफ पहले लैटिन अमेरिका और फिर पूरे विश्व में एक जबर्दस्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। एक तरफ तो साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सभी देशों के दरवाजे खोलने के लिए कृत संकल्प थे वहीं उन्हें भूमण्डलीकरण के खिलाफ जनता के संघर्ष को सीमित कर उन्हें शांति के रास्ते पर लाने के लिए भी सोचना था। एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में 90 के दशक के अंत में उभरे जबर्दस्त प्रदर्शन जब साम्राज्यवादी देशों में फैलने लगे जैसा कि सिएटल व प्राग में देखा गया, तो साम्राज्यवादी इस आक्रोश को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर के मंच की स्थापना के लिए सोचने को मजबूर हो गये।

अटैक के बर्नार्ड काजेन ने 2000 में डब्ल्यूएसएफ की योजना प्रस्तुत की। इसी साल ब्राजील के आठ संगठनों ने मिलकर साओ पाउलो में एक मंच की स्थापना की। उन्होंने पोर्तो अलेग्रे में एक सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया, जिसमें मार्च 2000 में कुछ दूसरे संगठन भी शामिल हो गये। उसी साल जून में उन्होंने जेनेवा में कोपेनहेगेन विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहीं कई यूरोपीय संगठन प्रस्तावित डब्ल्यूएसएफ में शामिल होने पर राजी हो गए।

दरअसल उस समय पोर्तो अलेग्रे में पहले डब्ल्यूएसएफ में दो समानांतर सम्मेलन आयोजित हुए। जहां एनजीओ की भागीदारी वाले डब्ल्यूएसएफ के आधिकारिक सम्मेलन में सिर्फ दस हजार लोग शामिल हुए वहीं इसके समानांतर सम्मेलन में पचास हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि, इस वास्तविकता को डब्ल्यूएसएफ के आयोजकों ने दबा दिया, अंततः डब्ल्यूएसएफ के आधिकारिक सम्मेलन ने अट्ठारह सूत्री घोषणापत्र जारी कर दिया।

पोर्तो अलेग्रे का चयन सम्मेलन स्थल के लिए इसलिए किया गया चूंकि यह उस राज्य की राजधानी थी (जहां लूला की वर्कर्स पार्टी (एक सामाजिक जनवादी पार्टी) की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार का शासन था) बाद में लूला ब्राजील के राष्ट्रपति बने।

सीओबी (Organizing Brazilian Committee) डब्ल्यूएसएफ के अंतरराष्ट्रीय सचिवालय के रूप में काम करती है और इसमें वर्कर्स पार्टी की सामाजिक जनवादी धारा का वर्चस्व है और यह अपने यूरोपीय बिरादर अटैक (ATTAC-Action For Taxation Of Financial Transaction For The Aid Of The Citizens) से जुड़ी है। डब्ल्यूएसएफ की अंतरराष्ट्रीय परिषद में अटैक, जेनोवा सोशल फोरम, त्रात्सकीपंथी चौथे इंटरनेशनल का एक धड़ा (रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लीग), अमेरिकन कौंसिल ऑफ सोशल साइंसेज, सामिर अमीन का वर्ल्ड फोरम ऑफ आल्टरनेटिव और इटली के कम्युनिस्ट रीफांउडेशन समेत लगभग 80 संगठन शामिल हैं।

जनवरी 2002 में पोर्तो अलेग्रे में डब्ल्यूएसएफ के दूसरे सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक और प्रधानमंत्री लिओनल जॉस्पिन ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें सरकार के छह मंत्री और राष्ट्रपति के चार शीर्षस्थ सलाहकार शामिल थे। इसके साथ-साथ पेरिस के मेयर फ्रांस के राष्ट्रपति पद के तीन उम्मीदवार और मध्य-दक्षिणपंथी पार्टी आरपीआर के महासचिव भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। इसके अलावा इस सम्मेलन में बेल्जियम के प्रधानमंत्री और पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने नयी उदारीकरण नीतियों को अपने देश में मजदूर वर्ग के जबर्दस्त विरोध के बीच लागू करवाया था।

डब्ल्यूएसएफ में इस तरह के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से तीसरी दुनिया के कर्ज, निजीकरण, उदारीकरण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहस और इसके नतीजों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि ये प्रतिनिधिमंडल उन सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्होंने तीसरी दुनिया के लोगों को बेरहमी से लूटा और उनसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर बहस की उम्मीद करना बेवकूफी थी। उदाहरण के लिए फ्रांस के सहकारिता मंत्री चार्ल्स जोसेलिन अफ्रीकी देशों के विदेशी कर्जों की लेन-देन के लिए सीधे जवाबदेह हैं। फ्रांस उत्तरी अफ्रीका के पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों के राष्ट्रीय बजट का 60 प्रतिशत सूद के रूप में वसूल करता है और वहां की जनता को असह्य गरीबी और दुखदायक जीवन स्थितियों के लिए मजबूर करता

है।

भूमण्डलीकरण विरोधी इनकी तमाम जुमलेबाजियां भी एक प्रहसन के समान हैं चूंकि यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतें भी जोरशोर से भूमण्डलीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। इन नीतियों से वे खुद अपने देश में लाखों मजदूरों को बेरोजगार बना रहे हैं तथा पूंजी की बेलगाम लूट की खातिर तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए साम्राज्यवादी प्रवक्ता जिस भागीदारी जनवाद की बात करते हैं वह उनके खुद के देशों में जनवाद पर बर्बर प्रहार को छुपाने भर के लिए धुएं का पर्दा है।

डब्ल्यूएसएफ का चरित्र और उद्देश्य

सर्वप्रथम जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं; डब्ल्यूएसएफ विभिन्न एनजीओ, जन संगठनों, सामाजिक जनवादी मार्का ट्रेड यूनियनों, कुछ त्रात्सकीपंथी तत्वों और यहां तक कि मेयरों, प्रशासकों, मंत्रियों और मुख्यतः यूरोपीय संघ के साम्राज्यवादी लुटेरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशासकों का एक लुंज-पुंज जमावड़ा है। इस तरह की शिवजी की बारात उस राजनीति का तर्कसंगत नतीजा है जिस पर डब्ल्यूएसएफ का निर्माण हुआ है। और डब्ल्यूएसएफ के विभिन्न घटक अपने फायदों के लिए फोरम में जोड़-तोड़ करते हैं।

डब्ल्यूएसएफ का घोषित उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? इसकी घोषणा के अनुसार यह "नागरिक समाज के उन सभी समूहों और आंदोलनों, जो नवउदारवाद और पूंजी एवं साम्राज्यवाद के सभी रूपों द्वारा दुनिया पर वर्चस्व कयम करने के विरोधी हैं, को कारगर कार्रवाई के लिए आपस में जोड़ने... और विचारशील चिंतन , विचारों के बीच जनतांत्रिक बहस, का खुला मंच है। ... और यह केवल दुनिया के सभी देशों के नागरिक समाज के संगठनों एवं आंदोलनों को एक साथ लाता और आपस में जोड़ता है।"

वास्तविक जाल तो 'नागरिक समाज' की मुख्य अवधारणा में है जो सभी वर्ग विभेदों से परे है और पूंजी तथा श्रम, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, साम्राज्यवाद पोषित एनजीओ तथा सच्चे राष्ट्रीय आंदोलनों को गड्डमड्ड कर देता है। यह अवधारणा, विशेष रूप से समाजवाद को धक्का लगने के बाद बेहद आकर्षक, लोकप्रिय तथा फैशनेबल हो गयी है। यह उदार बुर्जुआ वर्ग तथा साम्राज्यवादी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रोत्साहित की जा रही है। नागरिक समाज की अवधारणा वर्गों के अस्तित्व, वर्ग-अंतरविरोध तथा वर्गीय शोषण पर पर्दा डालने में मदद करती है। डब्ल्यूएसएफ उत्पीड़कों तथा उत्पीड़ितों के बीच बातचीत शुरू करके तथा परस्पर शत्रुतापूर्ण अंतरविरोधों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का उपदेश देता है, जिसका मतलब है कि मजदूर अपने बुनियादी वर्ग हितों को कुछ सुधारों के बदले त्याग दें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएसएफ दोनो पक्षों को वाद-विवाद और चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराएगा। इसी कारणवश डब्ल्यूएसएफ सरकारों के प्रतिनिधियों तथा उद्योगपतियों के साथ ट्रेड यूनियनों और आंदोलनों से जुड़े संगठनों को आमंत्रित किया करता है। लेकिन इस मुद्दे पर भी डब्ल्यूएसएफ गंभीर नहीं है। इसका पाखंड इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि एक ओर यह सरकार के प्रतिनिधियों, बुर्जुआ राजनीतिक दलों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आमंत्रित करता है, वहीं क्रांतिकारी विचारधारा वाली शक्तियों को फोरम में भागीदारी करने से ही रोक देता है। इसने कोलंबिया के एफएआरसी (जिसने डब्ल्यूएसएफ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी) और Mother of Plaza de Mayo (अर्जेंटीना में गायब कर दिये गये लोगों की मांएं)को आमंत्रित करने से इंकार कर दिया।

घोषणापत्र का नवां बिंदु कहता है कि **फोरम में न तो पार्टियों के प्रतिनिधि और न ही सशस्त्र संगठन भाग ले सकते हैं। सरकारों के मुखिया और विधायिकाओं के सदस्य, जो घोषणापत्र की वचनबद्धताओं को स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किये जा सकते हैं।"** इस प्रकार शासक वर्गों और साम्राज्यवादियों की भागीदारी के लिए तो जगह बना दी गयी जबकि क्रांतिकारी पार्टियों एवं सैन्य समूहों को फोरम में शामिल होने से रोक दिया गया है।

स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि डब्ल्यूएसएफ विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच होने का दावा कैसे कर सकता है जब सशस्त्र संघर्ष संचालित करने वाले संजीदा एवं प्रतिबद्ध संगठनों को फोरम में जगह तक नहीं दी जा रही है। डब्ल्यूएसएफ नवउदारीकरण, युद्ध वर्चस्व और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को पराधीन बनाने के सभी रूपों के खिलाफ संघर्ष करने वाला निकाय कैसे बना रह सकता है जब यह उन शक्तियों की भागीदारी को ही ठुकरा देता है जो इन सबके खिलाफ पूरी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। (पूंजी द्वारा) वर्चस्व कायम करने का प्रतिरोध करने एवं उस पर विजय हासिल करने के तरीकों एवं कार्रवाइयों की बातें करना पर सशस्त्र प्रतिरोध करने वाली ताकतों के लिए दरवाजे बंद कर देना डब्ल्यूएसएफ के असली चरित्र को ही उजागर करता है। दरअसल यह जनता को निःशस्त्र करना और यथास्थिति बरकरार रखना चाहता है। घोषणापत्र का 13वां बिंदु इस बात का बिल्कुल साफ कर देता है जब यह जोर देकर कहता है कि **"डब्ल्यूएसएफ संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के बीच नया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्क बनाने और इसे मजबूत करने की इच्छा रखता हैयह सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के जीवन में दुनिया में जारी अमानवीयकरण की प्रक्रिया और राज्य द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ अहिंसात्मक सामाजिक प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाएगा और इस तरह के आंदोलनों और संगठनों की कार्रवाइयों द्वारा अपनाए जा रहे मानवीय तरीकों को पुनर्स्थापित करेगा।"**

इस तरह से डब्ल्यूएसएफ राज्य द्वारा की जा रही क्रूर हिंसा और दुनिया में जारी अमानवीयकरण की प्रक्रिया के अहिंसात्मक सामाजिक प्रतिरोध को मजबूत करने की इच्छा रखता हैइससे बढ़कर यूटोपिया दूसरा नहीं हो सकता। डब्ल्यूएसएफ के घोषणापत्र के सिद्धांतों को लिखने वालों की निर्भीकता पर आश्चर्य होता है। इस्राइल अधिकृत फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान या इराक के कत्लगाहों में लड़ने वालों के बीच डब्ल्यूएसएफ अहिंसात्मक सामाजिक प्रतिरोध का प्रचार करने की बात करता है। इरादे कुछ भी हों उनके साधन इस्राइली जियनवादियों, भारतीय शासकों और खून के प्यासे अमेरिकी भाड़े के हत्यारों की बर्बर हिंसा और लूट की मदद करने में ही काम आएंगे।

डब्ल्यूएसएफ घोषणा करता है, *"डब्ल्यूएसएफ के सम्मेलन डब्ल्यूएसएफ को एक निकाय मानकर उसकी तरफ से विचार-विमर्श नहीं करते। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह डब्ल्यूएसएफ के किसी भी संस्करण की तरफ से यह व्यक्त करे कि यह सभी भागीदारों की अवस्थिति है। फोरम के किसी भागीदार को,*

चाहे मतदान के जरिये या हाथ उठाकर अनुमोदन करके, सभी भागीदारों को, या बहुमत को वचनबद्ध बनाने वाली घोषणाओं या प्रस्तावों पर एक निकाय के रूप में निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जा सकता, जिसे एक निकाय के रूप में फोरम की अवस्थिति के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार यह (फोरम) शक्तियों का कोई ऐसा केंद्र नहीं है, जहां मीटिंगों के दौरान भागीदार विवाद करें, न ही यह (फोरम) इसमें भागीदारी करने वाले संगठनों तथा आंदोलनों द्वारा कोई कार्रवाई करने या आपस में संबंध कायम करने वाला एकमात्र विकल्प है।"

ऊपर वर्णित बातें एक संस्था के रूप में डब्ल्यूएसएफ की प्रभावहीनता को ही दर्शाती है क्योंकि यह ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता है जो भागीदारों के लिए बाध्यकारी हो। यह एक वाद-विवाद का मंच है जो मुद्दों पर विचार करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता।

डब्ल्यूएसएफ के घोषणापत्र का एक अन्य बिंदु मार्क्सीय राजनीतिक अर्थशास्त्र, सामाजिक विकास की मार्क्सवादी अवधारणा पर परोक्ष हमला करता है, यह कहकर कि **"डब्ल्यूएसएफ अर्थव्यवस्था विकास और इतिहास के सभी तरह के सर्वसत्तावादी और अपचयनवादी (रिडक्शनिस्ट) तथा सामाजिक नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा हिंसा के प्रयोग का विरोध करता है।"** (जाहिर है इसका आशय समाजवादी राज्य से है) इसके बाद डब्ल्यूएसएफ **"मानवाधिकार के सम्मान, सच्चे लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र आदि के समर्थक होने की बात करता है।"** भागीदारी लोकतंत्र आदि के रूप में इसका उदाहरण दक्षिणी ब्राजील के एक राज्य रियो ग्रांदे दो सुल और खासकर इसकी राजधानी पोर्तो अलेग्रे में अमली रूप में दिखायी देता है।

डब्ल्यूएसएफ के आधे संगठन एनजीओ हैं जिनको साम्राज्यवादी देश धन मुहैया कराते हैं। फोर्ड फाउंडेशन ने वर्ष 2001-2002 में ब्राजील के एनजीओ संघ को डब्ल्यूएसएफ सम्मेलन कराने और डब्ल्यूएसएफ के अंतरराष्ट्रीय परिषद को एक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में मजबूत करने के लिए 2,38,000 डॉलर का अनुदान दिया। (इस धनराशि में से 65,000 डालर फेमिनिस्ट स्टडीज और असिस्टेंस सेंटर को दिये गये।) यह धन फोर्ड फाउंडेशन ने 'शांति और सामाजिक न्याय' के नाम पर मुहैया कराया। इस तरफ फोर्ड की नजरों में डब्ल्यूएसएफ शांति और सामाजिक न्याय बहाल करने वाला मंच है जबकि उसकी तरह के बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रपारीय कंपनियां बेरोकटोक दुनिया को लूट रही हैं।

फोर्ड फाउंडेशन के धन देने की बात कुछ लोगों ने उठायी तो एशिया सोशल फोरम, हैदराबाद के आयोजकों ने इसकी खिल्ली उड़ायी। यह सरासर झूठ था और एक आलोचक ने फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट से तथ्य जुटाकर इसे साबित कर दिया। वास्तव में हैदराबाद के एएसएफ सम्मेलन के बाद फोर्ड फाउंडेशन ने फिर 50,0000 डॉलर ब्राजील के एनजीओ के संघ को दिया और कहा कि यह डब्ल्यूएसएफ सम्मेलन, 2003 के लिए था। फाउण्डेशन की वेबसाइट में साफ तौर पर यह कहा गया है। इस तरह कुछ आलोचकों द्वारा यह कहना कि फोर्ड फाउंडेशन डब्ल्यूएसएफ को पैसा नही देता, लोगों को धोखा देने वाली बात है।

डब्ल्यूएसएफ के एक अन्य मुख्य घटकऑक्सफेम को विभिन्न साम्राज्यवादी संगठनों द्वारा पैसा देने का एक लंबा इतिहास है। ऑक्सफेम (Oxford Committe for Famine Relief) की स्थापना ब्रिटेन में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी। 1960 और 1970 के दशक में यह कई देशों में फैल गया। आक्सफेम इंटरनेशनल, 12 आक्सफेम संगठनों से मिलकर बना है और विश्व के प्रायः सभी देशों में यह कार्यरत है। इराक में अमेरिकी बमबारी के बाद यह इराकियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने में संलग्न है। यह सर्वविदित है कि आक्सफेम विभिन्न सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों को लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनवाने के लिए प्रभावित करने की चेष्टा करता है। आक्सफेम दावा करता है कि एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों में काम करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात से अवगत हो गया है कि "गरीबी के मूलभूत कारणों को संबोधित करने की जरूरत है।" नतीजतन, विकास कार्यक्रमों को स्व-कार्यान्वयन (self realisation) और सामुदायिक कार्रवाई (community action) की दिशा में निर्देशित किया गया। आक्सफेम गरीबी, सामाजिक अन्याय और असमानता के मूलभूत कारणों को दूर करने की कोशिश करने का भी दावा करता है! हाइनरिख बोल फाउंडेशन, डब्ल्यूएसएफ का एक अन्य पार्टनर है। यह एनजीओ सामाजिक न्याय, पर्यावरण, निरंतर विकास और लैंगिक जनवाद के लिए संघर्ष करने का दावा करता है। यह ग्रीन पार्टी (जो जर्मनी की साझा सरकार में पार्टनर है) से संबद्ध है। विभिन्न देशों में इसके कार्यालय और नेटवर्क हैं। यह कई संस्थान चलाता है, जिसमें फेमिनिस्ट इंस्टीट्यूट भी है।

आईसीसीओ (इण्टर चर्च कोआर्डिनेशन कमेटी फार डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट्स) डब्ल्यूएसएफ का एक और पार्टनर है। यह एक प्रोटेस्टेंट एनजीओ है तथा इसे नीदरलैंड सरकार सारा धन मुहैया कराती है।

'अटैक' डब्ल्यूएसएफ का मुख्य संस्थापक और आयोजक है। इसकी स्थापना 1998 में फ्रांस में नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और कारपोरेट "मुक्त व्यापार" के मुखर समर्थकजेम्स टोबिन के नाम पर हुई थी। अटैक बाद में अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर विकसित किया गया। इसका एक मुख्य लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर 0.05-0.1 प्रतिशत तक टोबिन टैक्स स्थापित करना है और इससे प्राप्त धनराशि को एक अंतरराष्ट्रीय फंड के रूप में 'विकास' और 'गरीबी से संपर्क' की सहायता में उपयोग करना है। अटैक का विचार है कि भूमण्डलीकरण पर बेहतर नियंत्रण से "एक दूसरी दुनिया संभव है"। अटैक को यूरोपीय आयोग, फ्रांस सरकार के सामाजिक अर्थव्यवस्था विभाग व शिक्षा एवं संस्कृति के राष्ट्रीय मंत्रलय से मदद मिलती रहती है।

दैनिक ल मोंद के अनुसार **"अटैक और ल मोंद डिप्लोमतीक को डब्ल्यूएसएफ को संगठित करने के लिए फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय की ओर से 80,000 यूरो दिए गए।"**

और देखिये कि साथ ही साथ वही फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय पूरे दिल से जार्ज बुश जूनियर के तथाकथित "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" के लिए मदद कर रहा था। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सूसन जार्ज जैसे अटैक के प्रवक्ता बड़े प्रदर्शनों के रूप में सीधी कार्रवाई करने का न केवल जोरदार विरोध कर रहे थे वरन ऐसी कार्रवाइयों में शामिल लोगों को निकाल बाहर करने के लिए मुहिम भी चला रहे थे।

इन एनजीओ को प्राप्त वित्तीय सहायता का ही यह परिणाम है कि एएसएफ ने हैदराबाद में अपने तमाशे के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च किये।

डब्ल्यूएसएफ का एक चेहरा साम्राज्यवादियों से धन पाने वाले एनजीओ का है, वहीं उसका दूसरा चेहरा सामाजिक जनवादियों का है। ये सभी संगठन जैसे अटैक (फ्रांस), जर्मनी का ग्रीन पीस, ब्राजील की वर्कर्स पार्टी, भारत की सीपीआई और सीपीआई (एम) भूमण्डलीकरण के प्रबल समर्थक हैं। ये जनता पर भूमण्डलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावहीन करने की बात करते हैं या मानवीय चेहरे वाले भूमण्डलीकरण की वकालत करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दावोस के अंतरराष्ट्रीय परभक्षी पूंजी का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और पोर्तो अलेग्रे (डब्ल्यूएसएफ) के बीच दूरियां पाटने का दावा करते हैं। इसीलिए वह जनवरी 2003 में डब्ल्यूएसएफ मीटिंग से सीधे दावोस रवाना हो गये ताकि वह साम्राज्यवादियों को इस बात के लिए कायल कर सकें कि भूमण्डलीकरण को अधिक मानवीय बनाया जाए और संरक्षणवाद को छोड़कर 'मुक्त व्यापार' को बढ़ावा दिया जाए। वह तथाकथित 'मुक्त व्यापार' के प्रवक्ता बन गये जिससे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे साम्राज्यवादियों के नुमाइंदे काफी गदगद हुए। साम्राज्यवादी प्रतिनिधि काफी खुश हुए। इराक पर अमेरिका के बर्बर हमले और हजारों की तादाद में इराकी अवाम के कत्लेआम के बाद हाल ही में बुश के साथ किया गया सौदा लूला के दलाल चरित्र को और भी बेनकाब कर देता है।

सीपीआई (एम) जो लूला की वर्कर्स पार्टी का भारतीय संस्करण है, विश्व बैंक निर्देशित नीतियों को पश्चिम बंगाल में तत्परता से लागू कर रही है।

अतः डब्ल्यूएसएफ सामाजिक जनवाद और एनजीओ के सोशल एक्टिविज्म का समेकन है। यह साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ संघर्ष की हवा निकाल देना चाहता है; यथास्थिति कायम रखते हुए, यानी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए विकल्प के लिए हाथ-पैर मारता है, वर्ग संघर्ष को दरकिनार करता है और क्रांतिकारी हिंसा का विरोध करता है तथा जनता के क्रोध को शांतिपूर्ण तरीकों से निकालने के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है।

यही कारण है कि हैदराबाद में संपन्न एएसएफ सम्मेलन ने भारत में विश्व बैंक-विश्व मुद्रा कोष-विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के कारण हुए विनाश पर चुप्पी साध रखी थी। काश्मीर में बर्बर दमन और मानवाधिकार हनन की कोई चर्चा तक नहीं की। भारत में विश्व बैंक की सबसे वफादार कठपुतली, चंद्रबाबू नायडू द्वारा आंध्रप्रदेश के लोगों पर बर्बर अत्याचार और क्रांतिकारियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों की रोज हो रही हत्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आयोजक भूमण्डलीकरण और राज्य द्वारा फैलाये गये आतंक के बीच रिश्ते को नहीं समझ सके, दरअसल यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसने उन्हें सच बोलने से रोक दिया। इसका नारा कि "दूसरा एशिया संभव है" या डब्ल्यूएसएफ का नारा कि "दूसरी दुनिया संभव है" अस्पष्ट और अमूर्त है। यह उस सवाल को संबोधित नहीं करता कि दूसरे विश्व का स्वरूप कैसा है, इसे प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, और साम्राज्यवादियों को खत्म किए बिना दूसरी दुनिया की प्राप्ति कैसे संभव है? लेकिन डब्ल्यूएसएफ और एएसएफ की लफ्फाजी और नारे उदारवादी बुद्धिजीवियों, निम्न-बुर्जुआ रैडिकल तत्वों और समाज के अभिजात्य वर्ग को लुभा रहे हैं जो पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं देख पाते और इसी को अंदर से सुधारने की बात सोचते हैं। यह इसलिए भी लुभा रहा है चूंकि जनता का राजनीतिक पार्टियों से मोहभंग हो चुका है और डब्ल्यूएसएफ खुद को राजनीतिक पार्टियों के एक विकल्प के रूप में पेश करता है।

विश्व सामाजिक मंच में अंतरसाम्राज्यवादी अंतरविरोध का प्रतिबिंबन

डब्ल्यूएसएफ द्वारा अमेरिका के खिलाफ कठोर शब्दों के इस्तेमाल पर किसी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में इसकी खामोशी अंतरसाम्राज्यवादी अंतरविरोध का एक प्रतिबिंबन है। यहां तक कि अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण भी साम्राज्यवाद विरोधी नहीं है, बस अमेरिका की कुछ नीतियों के खिलाफ है। यूरोप कई दशकों से सामाजिक जनवादी पार्टियों का मजबूत गढ़ रहा है। ये पार्टियां द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद काफी समय से कई देशों में राजसत्ता पर काबिज हैं। यूरोप में मजदूरों के संघर्ष के लंबे इतिहास के परिणामस्वरूप और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देशों के नजदीक आने के कारण समाजवाद के हौवे ने यूरोप के देशों को मजदूर वर्ग की कई मांगें मानने को बाध्य किया था और कई समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इसलिए यूरोप के काफी देशों में मजदूर अमेरिकी मजदूरों की तुलना में बेहतर कार्य परिस्थितियों जैसे छोटे कार्य सप्ताह, अधिक वेतन और बेहतर समाज कल्याण सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मजदूरों के प्रबल प्रतिरोध के कारण यूरोप के शासक वर्ग अमेरिका की तुलना में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियां लागू करने में काफी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। इसलिए 'टिकाऊ विकास', पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता की सुरक्षा आदि की बातें करते हैं।

इन जुमलों की जुगाली किसी दयाभाव या ईमानदारी, लोकोपकार के कारण नहीं, बल्कि सीमित बाजार के लिए गलाकाटू होड़ में अमेरिका के ऊपर बढ़त लेने के लिए है। इसी कारणवश ये सरकारें एनजीओ को पैसा देती रही हैं और फ्रांस ने डब्ल्यूएसएफ को अपना सहयोग दिया है। अधिकतर यूरोपीय एनजीओ अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं लेकिन अपनी ही सरकार द्वारा किए गए शोषण और उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेते हैं। इसी कारक ने इसी व्यवस्था के भीतर डब्ल्यूएसएफ के सुधार के कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया है। सामाजिक जनवाद की राजनीति जो कि यूरोपीय राजनीति का महत्वपूर्ण उपादान है, डब्ल्यूएसएफ में भी प्रभावी धारा बन चुकी है। एनजीओ द्वारा अमेरिकी मजदूरों की बदतर होती कार्य-स्थितियों और जीवन स्तर, अमेरिकी शासक वर्ग के संरक्षणवाद की नीति, और अमेरिकी अगुवाई में जारी आक्रमणकारी युद्ध के खिलाफ प्रचार यूरोपीय देशों के हितों और दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है। इसलिए 'नागरिक समाज' के इन समूहों और उनकी सरकारों के बीच सहयोग-सहकार कायम है।

डब्ल्यूएसएफ की राजनीति वर्ग सहयोग की राजनीति है। 'नागरिक समाज' के नाम पर डब्ल्यूएसएफ उत्पीड़ितों एवं उत्पीड़कों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश करता है। भूमण्डलीकरण और युद्ध के मुद्दों को उत्पीड़ितों के दृष्टिकोण से उठाने के बजाय डब्ल्यूएसएफ शांतिवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने और पूंजीवादी वर्ग द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण को 'मानवीय चेहरा' देने की कोशिश करता है। ये तथ्य ब्राजील के विभिन्न ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा पोर्तो अलेग्रे में,

डब्ल्यूएसएफ 2002 में भाग ले रही ट्रेड यूनियनों और कार्यकर्ताओं को संबोधित अपने खुले पत्र में प्रकाश में लाये गये हैं। पत्र की शुरुआत इस विचारोत्तेजक प्रश्न से होती हैक्या भूमण्डलीकरण और युद्ध को मानवीय चेहरा प्रदान "करना संभव है"?

इस खुले पत्र के अनुसार, अपनी शुरुआत से लेकर आज तक डब्ल्यूएसएफ ने खुद को 'नागरिक समाज' के एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया है। 'नागरिक समाज' की अवधारणा जो आज इतनी लोकप्रिय है, समाज में मौजूद विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच विभाजनों को मिटा देती है। उदाहरण के लिए, 'नागरिक समाज' की एक ही श्रेणी में शोषक और शोषित, अधिकारी और कर्मचारी, उत्पीड़ित और उत्पीड़िक को कैसे रखा जा सकता है, चर्चों, एनजीओ, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों की तो बात ही छोड़िये? आगे भी 'नागरिक समाज' की राजनीति आज आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक की राजनीति है। इन राजनीतियों की अंतर्वस्तु क्या है? खुद फैसला कीजिए। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2000/2001 में इस सच्चाई को यूं कहा गया हैः "वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने साधनों का इस्तेमाल करना जायज है, परिष्कृत समाज के संगठनों के साथ एक खुली और नियमित बातचीत, खासकर उनके साथ जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं।... विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मंचों पर इन समूहों को एक साथ लाकर और खुले संघर्षों के बदले उनकी क्षमता को राजनीतिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल कर सामाजिक विभाजन को कम किया जा सकता है।"

क्या यह संयोग है कि डब्ल्यूएसएफ के वित्तीय स्रोतों में फोर्ड फाउंडेशन का नाम है, या कि विश्व बैंक की वेबसाइट पोर्तो अलेग्रे फोरम को प्रोत्साहित करती है?

तथाकथित 'भागीदारी लोकतंत्र', जिसे डब्ल्यूएसएफ के जमावड़ों और मीडिया द्वारा जोरदार ढंग से प्रचारित किया गया, एक धोखा है, इसको भी खुले पत्र में उजागर किया गया हैः *"विश्व बैंक ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय विभाग गठित किया है जो 26 देशों में 'भागीदारी लोकतंत्र' के इस्तेमाल पर नजर रखेगा। इसने 'भागीदारी बजट : पोर्तो अलेग्रे का अनुभव' नामक पुस्तक, जिसे तार्सो जनरो (पार्तो अलेग्रे के भूतपूर्व मेयर) और उबिराता डि सूजा ने लिखा है, का अनुवाद, प्रकाशन और वितरण भी किया है।"*

क्या यह विश्व बैंक का अनिच्छित प्रचार है? या, इसके विपरीत, क्या 'भागीदारी लोकतंत्र' और 'भागीदारी बजट' की प्रक्रियाएं 'क्षमताओं के इस्तेमाल' और फिर 'टकराव टालने' की नीति को अभिव्यक्त नहीं करती हैं?

खुला पत्र तथाकथित 'भागीदारी लोकतंत्र' और 'भागीदारी बजट' को एक प्रहसन के रूप में व्यक्त करता है। यह दिखाता है कि म्युनिसिपल बजट का एक छोटा हिस्सा जो पोर्तो अलेग्रे के मामले में 17 प्रतिशत है, लोकप्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों की सभाओं द्वारा बंटवारे और विचार-विमर्श के लिए निश्चित किया गया है, जबकि एक बड़ा हिस्सा विदेशी कर्ज चुकाने और अन्य मदों में खर्च किया जाता है। इस छोटी सी रकम, जो कि लोकप्रिय संगठनों (नागरिक समाज!) के बीच बांटी जानी है, का भी गलत हिसाब तैयार किया जाता है और इस गड़बड़झाले में अंततः कौन फायदे में रहता है इसका खुलासा भी खुले पत्र में किया गया है।

पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी बताया है कि वे डब्ल्यूएसएफ में क्यों शामिल नहीं हो सकते

"हम वहां नहीं होंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि संगठित मजदूरों ने पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए जो सुरक्षा रणनीति तैयार की है वह 'नागरिक समाज' की नीति के विपरीत है, जो सामाजिक वर्गों के विभाजनों को धूमिल करती है। यह 'भूमण्डलीकरण को मानवीय चेहरा' देने की राजनीति के भी विपरीत है, जो कि, जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि विश्व पूंजीवाद की उत्पत्ति है। भूमण्डलीकरण हमारे कार्यस्थलों, नौकरियों, अधिकारों को नष्ट करना अनिवार्य बना देता है। पूंजीवादी भूमण्डलीकरण ने राष्ट्रों, लोकतंत्र और गरीबों की संप्रभुता को नष्ट किया है। इसे मानवीय रूप नहीं दिया जा सकता है।

"हम, जो ट्रेड यूनियनों को मजदूरों के संघर्ष का एक उपकरण मानते हैं, एनजीओ द्वारा शोषितों और उत्पीड़ितों के एवज में बोलने को नकारते हैं।"

दूसरे डब्ल्यूएसएफ ने 'युद्धों के बिना दुनिया संभव है' के नाम से एक विशेष सत्र भी रखा। लेकिन इसकी कार्यसूची में अफगानिस्तान पर बमबारी का नाम भी नहीं था और इस तरह डब्ल्यूएसएफ ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों के बर्बर कृत्य को नजरअंदाज कर दिया और साम्राज्यवादियों, खासकर अमेरिका द्वारा दुनिया के पुनर्उपनिवेशीकरण की दुष्टतापूर्ण योजना के बारे में दुनिया के लोगों को निष्क्रियता की ओर धकेल दिया। फलस्तीनी मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन मूलभूत कारणों जियनवादी विस्तारवाद और इस्राइल के शासक वर्ग को साम्राज्यवादियों के समर्थनकी अनदेखी की गयी, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित 'शांति योजना' पर पूरा जोर दिया गया। डब्ल्यूएसएफ युद्ध से मुक्त दुनिया कायम करने की इच्छा रखता है, लेकिन साम्राज्यवादियों से लड़कर नहीं बल्कि उन्हें उपदेश देकर और उन पर दबाव डालकर।

अर्जेंटीना के एक संगठन ला हैने ने पोर्तो अलेग्रे में जनवरी 2003 में संपन्न तीसरे डब्ल्यूएसएफ सम्मेलन के निमंत्रण का माकूल जवाब दिया **"हम पोर्तो अलेग्रे के डब्ल्यूएसएफ में भाग नहीं ले सकते क्योंकि हम नहीं मानते कि पूंजीवाद को नष्ट किए बिना दूसरा विश्व संभव है।"** ला हैने ने डब्ल्यूएसएफ के वर्ग सहयोग की राजनीति पर तीखा प्रहार इन शब्दों में कियाः

"पूंजीवादियों से हमारे संबंध भूखे भेड़ियों के झुंड और आज्ञापरायण भेड़ों से मिलते-जुलते हैं। डब्ल्यूएसएफ हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार हम इन रिश्तों को सहयोग और समानता में बदल सकते हैं, जैसे कि एक भेड़िया एक भेड़ की तरह व्यवहार करे। हममें से जो यह मानते हैं कि, भेड़िया एक भेड़िए की तरह ही व्यवहार करेगा, वह मांसभक्षी है और अपने स्वाभाविक शिकार को खाना नहीं छोड़ेगा, वे डब्ल्यूएसएफ में हिस्सा नहीं ले सकते, जानबूझकर या अनजाने उत्पीड़न को जारी रखने में मददगार नहीं बन सकते।... "

इस संगठन ने डब्ल्यूएसएफ के बारे में निष्कर्ष देते हुए लिखा कि, *"डब्ल्यूएसएफ की भूमिका, जिसे अब बखूबी पहचाना जा चुका है, प्रतिरोध को निष्क्रिय करने की है। उसके द्वारा किये जा रहे बदलाव के वादे चाहे जितने प्रभावी नजर आयें, यहां तक कि उत्कृष्टतम वादे भी, उन बुनियादी नाइंसाफियों को रत्ती भर भी दूर नहीं कर सकते,*

जिनके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं।"

इस तरह, साम्राज्यवादियों के भूमण्डलीकरण की मौजूदा व्यवस्था, युद्ध और नवउदारवाद के कथित विकल्प के उभरने के बाद सामाजिक जनवादी, एनजीओ व्यवस्था पोषित मीडिया द्वारा पैदा किये गये हर्षोन्माद, जिसकी चपेट में कुछेक क्रांतिकारी संगठन भी आ गये, के बाद भी हम पाते हैं कि विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी संगठन डब्ल्यूएसएफ के असली चरित्र और उद्देश्यों को अच्छी तरह जान-समझ रहे हैं।

डब्ल्यूएसएफ के प्रति सर्वहारा वर्ग की नीति क्या होनी चाहिए?

हम पूर्व के विश्लेषण में यह देख चुके हैं कि डब्ल्यूएसएफ, एनजीओ और सामाजिक जनवादी संगठनों का एक घालमेल है, जिसका लक्ष्य रैडिकल लफ्फाजी के जरिए यथास्थिति को बनाए रखना है। यह समाज और पूंजीवादी व्यवस्था में मौजूद वर्ग-अंतरविरोधों को छुपाना चाहता है और 'नागरिक समाज' के नाम पर समकालीन विश्व के सामने खड़ी समस्याओं के प्रति एक गैर वर्गीय पहुंच का प्रचार करता है। यह व्यवस्था के खिलाफ लोगों के आक्रोश और मोहभंग को शांतिपूर्ण रास्तों की ओर मोड़कर जुझारू क्रांतिकारी संघर्षों से उनका ध्यान हटाना चाहता है। यह बुर्जुआ जनवाद के बारे में विभ्रम पैदा करता है और कहता है कि समाज को प्रभावित करने वाली इसकी बुराइयों को 'भागीदारी लोकतंत्र' के जरिए दूर किया जा सकता है। यह विभिन्न स्तरों पर हजारों सामाजिक मंचों की स्थापना कर अस्पष्ट कार्यक्रमों द्वारा क्रांतिकारी राजनीतिक पार्टियों को विस्थापित करना चाहता है और इस तरह जनता को नेतृत्वविहीन और असंगठित कर देना चाहता है। विद्रोही मजदूरों, छात्रें-युवाओं, औरतों, बुद्धिजीवियों और दूसरे उत्पीड़ित वर्गों की एक पूरी पीढ़ी को शांतिपूर्ण रास्तों पर ले जाकर शांत, निष्क्रिय और नपुंसक बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता के असंतोष को संस्थाबद्ध करके उसका अराजनीतिकरण किया जा रहा है और उसे गोलबंद होने से रोका जा रहा है और इस तरह साम्राज्यवादियों और स्थानीय प्रतिक्रियावादियों के बढ़ते आक्रमणों के सामने उन्हें शस्त्ररहित और शक्तिहीन बनाना ही डब्ल्यूएसएफ की नीतियों का अवश्यंभावी नतीजा है। यह समाजवाद और मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चलाये जा रहे आंदोलनों और संघर्षों के लिए एक जबर्दस्त खतरा है। इन सबका पूरी तरह से जनता के बीच भंडाफोड़ किया जाना चाहिए।

सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण तथा मार्क्सवाद और कम्युनिज्म की विचारधारा को विभिन्न शोषित वर्गों में स्वीकार्य बनाना क्रांतिकारियों के लिए पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। हमें उत्पीड़ितों पर एनजीओ और डब्ल्यूएसएफ द्वारा डाली गई सैद्धांतिक बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करनी होगी, उन्हें साम्राज्यवाद के असली चरित्र के बारे में शिक्षित करना होगा और उन्हें जुझारू क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की ओर ले जाना होगा ताकि साम्राज्यवाद, सामंतवाद और प्रतिक्रियावादी कचरे का सफाया किया जा सके, जिन्होंने समाज के विकास को रोक रखा है। उत्तर-संरचनावाद, उत्तर-आधुनिकतावाद और इनके विभिन्न वैकल्पिक रूप जैसे फैशनेबल सिद्धांतों का, जो बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं, विचारधारात्मक रूप से भंडाफोड़ करना चाहिए। हमें खासकर विचारधारात्मक और राजनीतिक रूप से सामाजिक जनवादियों, विभिन्न रंग के संशोधनवादियों और तथाकथित क्रांतिकारियों, जो डब्ल्यूएसएफ के हिस्से हैं और एनजीओ मार्का कार्रवाइयों के बारे में भ्रम पैदा करते हैं, को निशाना बनाया जाना चाहिए। और यह कार्यभार पूरा करने के लिए हमें उन सभी ताकतों के साथ एकजुट होना पड़ेगा जो अडिग साम्राज्यवाद विरोधी पहुंच और डब्ल्यूएसएफ के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं।

साथ ही, हमें डब्ल्यूएसएफ के प्रति संकीर्ण नजरिया रखने से बचना चाहिए। **हमारी पहुंच एकता और संघर्ष की होनी चाहिए, जिस हद तक वे साम्राज्यवाद विरोधी पहुंच अपनाते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उस हद तक एकता कायम करनी होगी और विचारधारात्मक राजनीतिक दायरे में उनके गैर वर्गीय या अधि-वर्गीय (non class or supra class) दृष्टिकोण से लड़ने में उनके सुधारवादी दृष्टिकोण के खिलाफ संघर्ष चलाना होगा।** हमें खुले तौर पर डब्ल्यूएसएफ के भीतर की उन ताकतों के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जाहिर करनी चाहिए अगर वे जनता के जुझारू संघर्षों में शामिल होते हैं। हमें यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि डब्ल्यूएसएफ ने कई प्रगतिशील संगठनों और व्यक्तियों को आकर्षित किया है जो अमानवीय पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुए अलगाव और अमानवीयता से दुखी हैं और साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खिलाफ ईमानदारी से खड़े हैं तथा वर्तमान शोषक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के पक्षधर हैं। हमें डब्ल्यूएसएफ के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हर किसी की भर्त्सना करने की पहुंच नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय हमें इन लोगों को डब्ल्यूएसएफ की राजनीति से दूर करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खिलाफ संघर्ष में तथा रूपांतरण के संघर्ष में साथ लाना चाहिए।

डब्ल्यूएसएफ सम्मेलन में सीधे हिस्सा लेने से इसका विचारधारात्मक और राजनीतिक रूप से भंडाफोड़ करने में मदद नहीं मिलेगी। और हमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारी ताकतों के हिस्सा लेने से डब्ल्यूएसएफ को बदला जा सकता है। डब्ल्यूएसएफ के सिद्धान्तों का चार्टर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस तरह की संभावना को नकारता है। इसके विपरीत, इसमें भागीदारी डब्ल्यूएसएफ की परियोजनाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाना है, जनता और क्रान्तिकारी शुभचिन्तकों को दिग्भ्रमित करना है और डब्ल्यूएसएफ के चार्टर एवं लक्ष्यों के बारे में भ्रान्ति पैदा करता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम डब्ल्यूएसएफ की परियोजनाओं-कार्यों से अपना सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक अन्तर स्पष्टता से दर्शायें और क्रान्तिकारी लोगों एवं आम जनता को बाहर से शिक्षित करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी तत्वों तक पहुंचे जो डब्ल्यूएसएफ के अंग बन गये हैं और हमें ऐसे तरीकों का ईजाद करना होगा जिससे हमारी राजनीति इन वास्तविक तत्वों तक पहुंचे।

हमें सम्मेलन एवं संघर्ष के अंतर को समझना चाहिए। एक तरफ जहां हम संघर्ष में सभी शक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वहीं हम ऐसे सम्मेलनों में नहीं जाते जो ऐसे दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं जो मौलिक रूप से हमारे दृष्टिकोण के विपरीत हो और इस प्रकार उन संस्थाओं एवं फोरम की साख बढ़ाते हैं जो ऐसे दृष्टिकोण रखते हों। हमें अपना दृष्टिकोण स्वतंत्र रूप से घोषित करना चाहिए और अपनी वास्तविक विचारधारात्मक एवं राजनीति के अंतरों को स्पष्ट करना चाहिए व उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

अनुवाद : शेखर हिमांशु

वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा प्रस्तुत भूमण्डलीकरण के 'नानाविध विकल्प'

पी.जे. जेम्स

प्रस्तुत लेख 'रेड स्टार, प्लेटफार्म ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज' (जनवरी, 2003) से लिया गया है। लेख जब लिखा गया था तब हैदराबाद के एशिया सोशल फोरम की तैयारियां चल रही थीं। इसलिए लेख में उस समय के हवाले हैं। यह कम्युनिस्ट आन्दोलन की एक धारा का दृष्टिकोण है जो भारत को एक नवऔपनिवेशिक समाज मानती है। वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा प्रस्तुत भूमण्डलीकरण के अनेकानेक विकल्पों की असलियत को लेख में अच्छी तरह उजागर किया गया है। लेख की इस मुख्य विषयवस्तु को केन्द्र में रखते हुए जगह-जगह लेखक ने भारतीय शासक वर्ग के चरित्र, आज के साम्राज्यवाद और उसके साथ भारतीय शासक वर्ग के रिश्ते आदि पर प्रसंगवश जो टिप्पणियां की हैं, सम्पादक मण्डल उनसे सहमत नहीं है। भूमण्डलीकरण के खिलाफ दुनियाभर में उठी आवाजों, खासकर भारत में विभिन्न वर्गों-तबकों के संघर्ष के बारे में भी जगह-जगह जो संदर्भ आये हैं, सम्पादक मण्डल की राय में वे अतिरंजनाओं के शिकार हैं। फिर भी लेख की मुख्य विषयवस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसलिये विचारोत्तेजक और पठनीय भी। *सम्पादक*

अभी हाल तक TINA (कोई विकल्प नहीं है) का विमर्श नवउदारवादी भूमण्डलीकरण पर मुख्यधारा की चर्चाओं में प्रमुख हुआ करता था, मगर आजकल TAMA (बहुत से विकल्प मौजूद हैं) का प्रचलन जोरों पर है। इस लोकरंजक नारे के तात्कालिक उभार का कारण है डब्ल्यूएसएफ का गठन एवं इसके वेबसाइट्स द्वारा किया जाने वाला प्रोपेगैंडा। काफी हद तक गुजरे जमाने के कल्पनावादी और ईसाई समाजवादियों की याद दिलाते हुए डब्ल्यूएसएफ अब भूमण्डलीकरण के "अनेक विकल्पों" और यहां तक कि अनेक विश्वों की कल्पना करने लगा है। इस परिप्रेक्ष्य के साथ डब्ल्यूएसएफ स्वयं को महाद्वीपीय और राष्ट्रीय स्तर के संस्करणों जैसे यूरोपीय सोशल फोरम, अफ्रीकी सोशल फोरम, एशियाई सोशल फोरम आदि-आदि तथा डब्ल्यूएसएफ ब्राजील, डब्ल्यूएसएफ अर्जेंटीना, डब्ल्यूएसएफ फलस्तीन, डब्ल्यूएसएफ इंडिया आदि के रूप में पुनः अवतरित कर रहा है। यहां तक कि देशों के भीतर डब्ल्यूएसएफ की क्षेत्रीय संस्करणों जैसे केरल सोशल फोरम (केएसएफ), जिसका नारा है "दूसरा केरल संभव है" के प्रयास हो रहे हैं। इसी दरम्यान डब्ल्यूएसएफ इंडिया के तत्वावधान में 2-7 जनवरी, 2003 को निर्धारित है, हैदराबाद का आयोजन, जो एशियाई "स्वरूप और अंतर्वस्तु" वाले एशिया सोशल फोरम का गठन करने वाला है, का सूत्र वाक्य है "दूसरा एशिया संभव है।"

डब्ल्यूएसएफ का आविर्भाव पोर्तो अलेग्रे उद्घोषणा "दूसरा विश्व संभव है" के साथ पोर्तो अलेग्रे, ब्राजील में जनवरी 25-30, 2001 के दौरान हुआ। पोर्तो अलेग्रे आयोजन का विचार आठ ब्राजीली नागरिक समाज व वाम स्वेच्छातंत्रवादी (Libretarian) संगठनों को आया, जिन्हें इसकी प्रेरणा यूएएमपीए (यूनियन ऑफ नेबरहुड एसोसिएशन ऑफ पोर्तो अलेग्रे) द्वारा 1990 में सर्वप्रथम प्रस्तावित एक भागीदारी बजट कार्यक्रम, जो समाज प्रशासन में एक प्रयोग था, से प्राप्त हुई। डब्ल्यूएसएफ के वैधानिक गठन के ठीक एक साल पहले जनवरी 2001 में पोर्तो अलेग्रे भागीदारी प्रयोग और संबंधित अन्य प्रयोगों के सशक्तिकरण आयाम को नियमबद्ध करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'वास्तविक कल्पनावादी परियोजना : सशक्तीकृत जनवाद में प्रयोग' का यूनिवर्सिटी आफ विस्कान्सिन, मेडिसन, अमेरिका में आयोजन हुआ। पोर्तो अलेग्रे की भागीदारी म्यूनिसिपल बजट निर्माण के साथ ही सम्मेलन ने पड़ोस प्रशासन परिषद और शिकागो की सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, अमेरिका की आवास सुरक्षा योजना और केरल की भागीदारी जनयोजना का निरीक्षण वास्तविक विश्व यूटोपिया या सशक्तीकृत भागीदारी प्रशासन के उदाहरण की तरह किया।

"अनेक विकल्पों" और "अनेक विश्वों" के नारों के साथ डब्ल्यूएसएफ के गठन तक पहुंचाने वाली अवधारणाओं के विकास समेत इसके बौद्धिक स्रोतों के सिरे को अमेरिका में सम्पन्न इस "यूटापियाई सम्मेलन" में ढूंढ़ा जा सकता है। दरअसल, डब्ल्यूएसएफ और इससे जुड़े विश्व भर के एनजीओ ने अफ्रीकी-एशियाई-लातिन अमेरिकी देशों में नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के विभिन्न स्वरूपों और कुप्रभावों पर अनगिनत साहित्य प्रकाशित किया है। गरीबी, भूख, उत्पीड़न, राजकीय दमन, पर्यावरणीय विनाश आदि पर डब्ल्यूएसएफ के विशेषज्ञ बुद्धिजीवियों द्वारा किए गए ढांचागत विश्लेषण ने साम्राज्यवादी लूट के बारे में दुनियाभर के लोगों की समझ को निश्चय ही उन्नत किया है।

हालांकि, नवउदारवाद की अपनी मुखर आलोचना और भूमण्डलीकरण के बहुविकल्पों की कवायद के बावजूद इस समस्या के प्रति डब्ल्यूएसएफ का रुख, नवउदारवादी भूमण्डलीकरण, जिसकी जड़ें साम्राज्यवादी पूंजी की गति के नियमों में निहित है, की वैज्ञानिक समझदारी में बाधक है। यह भूमण्डलीकरण पर विस्तृत समझ नहीं पेश करता। भूमण्डलीकरण की अपनी आलोचना में, यद्यपि डब्ल्यूएसएफ रैडिकल रुख रखता है, इसके नित-नये संस्करण व अवतार पूंजी के विश्व स्तरीय क्रियाकलापों के पीछे के राजनीतिक अर्थशास्त्र पर केंद्रित नहीं है। डब्ल्यूएसएफ के विश्लेषणात्मक और अकादमिक कवायदों का अंतिम नतीजा मेहनतकश जनता के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को आज के बेहद जरूरी राजनीतिक विकल्प से विमुख करना है। दूसरे शब्दों में, नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के बुनियादी कुंजीभूत राजनीतिक अर्थशास्त्र को रेखांकित करने की बजाय डब्ल्यूएसएफ के तथाकथित "आयोजनों" में संचालित अनेक सम्मेलनों, सेमिनारों, वर्कशॉप आदि द्वारा इस पूरे मुद्दे को विघटित और विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, हैदराबाद में होने वाला डब्ल्यूएसएफ इंडिया का "आयोजन" जो एक साथ सैकड़ों मंचों पर आयोजित होगा, का कोई भागीदार भूमण्डलीकरण का खंडित स्वरूप अंधों के हाथी के अनुभव की तरह ही देख पायेगा। यह एक बेहद जरूरी राजनीतिक रुख का निषेध कर देगा। कोई भ्रम नहीं, कि एक हद तक सामाजिक सच्चाई का यह विखंडीकरण अंततोगत्वा साम्राज्यवादी पूंजी की ऐतिहासिक गति की और भूमण्डलीय कार्यप्रणाली की समझ को मुश्किल बनाने की नवउदारवादी चाल की सहायता करता है।

डब्ल्यूएसएफ द्वारा प्रस्तुत "बहु-विकल्पों" के सूत्रीकरण में यह अच्छी तरह चरितार्थ होता है। इसकी वेबसाइट्स के अनुसार, जैसा पहले ही देखा जा चुका है, डब्ल्यूएसएफ के हर "संस्करण" या "आयोजन" का नतीजा इसके द्वारा प्रस्तुत भूमण्डलीकरण के विकल्प के संकरण (hybridisation) या स्थानीयकरण जैसे 'दूसरा एशिया', 'दूसरा अफ्रीका', 'दूसरा लातिन अमेरिका', 'दूसरा भारत' और यहां तक कि दूसरा केरल इत्यादि में होता हैयह फेहरिस्त बढ़ती ही जाती है, जैसे 'हरि अनंत हरि कथा अनंता'। हालांकि, यह लुभावना जान पड़ता है, इस लोकरंजक रुख में विचारधाराविहीन करना और अराजनीतिकरण निहित है, जो नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के बारे में अत्यंत आवश्यक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को खत्म कर देता है। यह अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सभी देशों की मेहनतकश आबादी की एकजुटता और एकता पर आधारित एक साम्राज्यवाद विरोधी विकल्प की मांग करता है, जिसमें राष्ट्रीय भूभाग की सीमाओं में भूमण्डलीकरण विरोधी लड़ाई को पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। यह क्षरणशील पूंजीवादी साम्राज्यवादी तंत्र के एक समाजवादी विकल्प की प्रासंगिकता को भी उभारता है। बहरहाल, डब्ल्यूएसएफ का केवल राष्ट्रीय एवं स्थानीय विशिष्टताओं पर जोर विचारधाराविहीन करने और मेहनतकश अवाम को वर्ग आधारित राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद से भटकाने की बदनीयती भरी चाल हैयह डब्ल्यूएसएफ द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी समाजवादी विकल्प की पूर्ण अवमानना में और अलग-अलग देशों के स्तर पर अलग-अलग विकल्प प्रस्तुत करने की निरपेक्षतावादी सोच में दिखायी देता है। इस विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में जिसमें 'चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद' जैसे विकल्प अंधराष्ट्रवाद और संकीर्ण आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में पतित हो गये हैं, डब्ल्यूएसएफ की तुरही बजाने वाले हर देश के लिए विशेष किस्म के "अनेक विकल्पों" की हांक लगा रहे हैं। ये विकल्प साफ तौर पर वैश्विक पूंजी के साथ विचारधारात्मक-राजनीतिक टकराव से मुंह मोड़ रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने अपने सामने दुनियाभर में मजबूत हो रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को विचारधाराविहीन करने का एजेंडा रखा है।

निस्संदेह, डब्ल्यूएसएफ की यह अवस्थिति राजनीतिक आंदोलनों और राजनीतिक दलों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। एक तरफ यह कहते हुए कि "डब्ल्यूएसएफ हमेशा ही एक ऐसा मंच रहेगा जो इसमें भागीदारी करने वाले संगठनों और आंदोलनों के बहुलवाद और विभिन्न क्रियाकलापों तथा काम करने के तरीकों पर खुला रुख अपनाएगा", दूसरी तरफ डब्ल्यूएसएफ चार्टर का 9वां बिंदु कहता है, "न तो दलीय प्रतिनिधित्व और न ही सैन्य संगठन इस फोरम में भागीदारी कर सकते हैं।" (वही) इस तरह डब्ल्यूएसएफ न सिर्फ राजनीतिक दलों को अपने आयोजनों से दूर रखता है, बल्कि खुले तौर पर उनको सैन्य संगठनों के वर्ग में रख देता है। यह घोर अनुदारवादी और इसी कारण सच्ची नवउदारवादी अवस्थिति न तो नयी है न अपने आप में अलग है। यह मेहनतकश आबादी और उसकी पार्टी को मुख्य धारा की बहसों से दूर रखने की कट्टरपंथियों और नवदक्षिणपंथियों द्वारा ईजाद एक जांचा-परखा भटकाने वाला रवैया है। रजनी कोठारी जैसे कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्तकार, जो कि अब डब्ल्यूएसएफ के हैदराबाद आयोजन के साथ साझा मंचों पर आसीन होते हैं, आम जनता के विकल्पों के अपने संस्करणों में लम्बे समय से एक गैर-पार्टी प्रक्रिया के जबर्दस्त पैरोकार रहे हैं। इन्हें वह "मध्यवर्ग के प्रेरित किये गये पेशेवर लोगों" की अगुवाई वाला जन-विकल्प कहते रहे हैं।

सच्चाई यह है कि तथाकथित "बहुलवाद" जिसकी वकालत डब्ल्यूएसएफ करता है, तथा जैसा कि हम आगे की चर्चा में देखेंगे, नये सामाजिक आन्दोलनों (एनएसएम-न्यू सोशल मूवमेण्ट्स) से इसकी घनिष्ठता और वर्ग-आन्दोलनों के प्रति इसकी घृणा खुले रूप में प्रकट होती है। इन सब का विभिन्न विचारधारात्मक शाखाओं में व्यापक बंटवारा है, जिनकी जड़ें एक क्रान्तिकारी ताकत के रूप में सर्वहारा वर्ग के पराभव या लोप और "इतिहास के नये क्रान्तिकारी विषय" के रूप में 'एनएसएएम' और एनजीओ के उभरने के उत्तर-मार्क्सवादी विश्लेषण शास्त्र में गहराई से पैठी हुई हैं।

इसी प्रकार डब्ल्यूएसएफ का चार्टर "अर्थशास्त्र, विकास और इतिहास के सभी सर्वसत्तावादी और अपचयनवादी नजरियों" के प्रति अपने विरोध की बात भी करता है। (पैरा-10) अगर बेलागलपेट ढंग से कहा जाये तो "सर्वसत्तावादी" और अपचयनवादी शब्दावली साम्राज्यवादी थिंक टैंकों द्वारा कम्युनिस्टों की वर्गीय पहुंच पर कीचड़ उछालने की करतूतों का एक हिस्सा हैं। डब्ल्यूएसएफ तो इस घिनौने कुत्सा प्रचार की सिर्फ तोते की तरह रट लगा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि, इसका पूरा रुख ही पूँजीवाद के आक्रमण का राजनीतिक दिशा के साथ विरोध करने वाली मजदूरों, शोषितों और अन्य मेहनतकश आबादी के वर्ग हितों के विपरीत है। उदाहरण के लिए विकास के प्रति डब्ल्यूएसएफ के गैर अपचयनवादी नजरिये को ही लें। बिल्कुल तर्कसंगत ढंग से, इस नजरिये का एक गैर-वर्गीय, गैर-राजनीतिक, और गैर-राज्य

कोटि के रूप में विकास की विशेषताएं बताने वाले नवउदार-उत्तरआधुनिक नजरिये के साथ मेल भिड़ जाता है। यह नजरिया विकास और विचारधारा के अंतर्निहित रिश्ते को नहीं मानता है। अगर सार रूप में कहें तो, यद्यपि विकास के प्रति डब्ल्यूएसएफ का रुख लोकरंजक उद्देश्यों की सेवा करता है, पर यह इस मुख्य मुद्दे को स्वीकार करने में बुरी तरह मात खाता है कि नवउदारवाद के अंतर्गत साम्राज्यवादी पूँजी एफ्रो-एशियाई-लातिन अमेरिकी देशों में किसी प्रकार का आत्मनिर्भर राष्ट्रवादी विकास नहीं होने देती, जिससे कि नतीजा अ-विकास हो जाता है, जैसा कि प्रचारित किया जाता है।

विकल्प सिर्फ एक है न कि अनगिनत, और यही भूमण्डलीय पूँजी की गति के सिद्धान्त से बुनियादी तौर पर अलग होना है। सम्भवतः, सर्वाधिक बहस का मुद्दा स्वयं डब्ल्यूएसएफ का सैद्धान्तिक आधार ही है। इसके प्रकाशित दस्तावेजों पर नजर डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि डब्ल्यूएसएफ, 'एनएसएम' और एनजीओ के प्रति रुझान वाला वैश्विक नागरिक समाज का मंच है। डब्ल्यूएसएफ "दुनियाभर के देशों में केवल नागरिक समाज के संगठनों और आन्दोलनों को जोड़ता और एक मंच पर लाता है" (सिद्धान्तों का चार्टर, पैरा-5) और "नागरिक समाज के संगठनों और आन्दोलनों के बीच नये राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध बनाने और सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिए प्रयास करता है।" (वर्ल्ड सोशल फोरम इंडिया-पॉलिसी गाइडलाइन्स, पैरा-18) इस प्रकार डब्ल्यूएसएफ चार्टर और सम्बन्धित दस्तावेजों को राजनीतिक रुझान वाले "पुराने आन्दोलनों" और नागरिक रुझान वाले "नये आन्दोलनों" के बीच विभाजक रेखा के रूप में देखा जा सकता है (उदाहरण के लिए देखें एशियन सोशल फोरम 2003, हैदराबाद, भारत, प्रोग्राम नोट, पृष्ठ-9)। स्पष्टतः, डब्ल्यूएसएफ का जोर "नये आन्दोलनों", जो एनजीओ, स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के नागरिक एवं सामुदायिक संगठनों से संघटित होते हैं, से निर्देशित 'नागरिक समाज' पर है। राजनीतिक पार्टियों और "राज्य-नियन्त्रणवादी" राजनीति के प्रति इसकी बेरुखी और तथाकथित नागरिक समाज आन्दोलनों के प्रति लगाव, निस्सन्देह, राज्य के विरोध में नागरिक समाज की उत्तर आधुनिक अवधारणाओं से उत्पन्न होता है। यहाँ इस बात पर गौर किया जा सकता है कि नागरिक समाज के प्रति यह नया विमर्श उस सामान्य प्रवृत्ति का अंग है जिसने 1970 के दशक में कल्याणकारी राज्यों के खात्मे के सन्दर्भ में नवउदारवादी-उत्तर आधुनिक चिन्तन में महत्ता प्राप्त की। आज नागरिक समाज को केंद्र में रखने पर उत्तर आधुनिक चिन्तन का जोर, विकास के क्षेत्र से राज्य के हाथ खींचने से पैदा हुई खाली जगह को भरने के लिए है। उत्तर-मार्क्सवादी और उत्तर आधुनिकतावादी दोनों ही यह कल्पना करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के विखंडन और नतीजतन वाम व दक्षिण दोनों ध्रुवों द्वारा एक-दूसरे को निष्प्रभावी बना देने के कारण नागरिक समाज नये सिरे से उभर कर सामने आ रहा है।

इस तरह, नागरिक समाज के प्रति डब्ल्यूएसएफ के व्यामोह में, आजकल नवउदारवाद से लेकर पतित वाम तक व्यापक दायरा सिमटा हुआ है। नव-उदारवादी भूमंडलीकरण के लिए नागरिक समाज की अवधारणा का निर्माण सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बदले प्राइवेट सेक्टर लाने में ही नहीं बल्कि सहभागिता पर आधारित जनता के विकल्पों के आवरण के अन्तर्गत सामाजिक सेवा प्रावधानों की जिम्मेदारी स्वयं जनता के कंधों पर स्थानान्तरित करने में भी उपयोगी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज नागरिक समाज के सबसे बड़े समर्थक और कोई नहीं बल्कि विश्व बैंक, यूएसएड, यूएनडीपी व फोर्ड फाउण्डेशन जैसी संस्थाएं हैं। नागरिक समाज के आदर्शीकरण के सम्बन्ध में नव-उदारवादी एजेंसियां और डब्ल्यूएसएफ एक साथ कार्यरत हैं। विश्व बैंक नागरिक समाज को एनजीओ निर्देशित संपूर्ण प्राइवेट सेक्टर के रूप में व्याख्यायित करता है और इसे निभाने के लिए इसने पहले ही विश्व बैंक/एनजीओ समिति नाम से एक कार्यकारी विंग बना रखा है। विश्व बैंक के लिए बाजार और नागरिक समाज समानार्थी हैं। विश्व बैंक का साहित्य बाजारों के विश्वव्यापी विस्तार और नागरिक समाज के विकास को एक मानकर ही व्याख्यायित करताा है; यह एफ्रो-एशियन-लातिन अमेरिकी देशों में जनतंत्र के विकास और "सुशासन" को पारम्परिक राजनीतिक क्षेत्र से नागरिक कार्रवाई में स्थानान्तरण की श्रेणी के रूप में व्याख्यायित करता है।

इस सन्दर्भ में, बिना किसी अधिक विवरण के, यह समझा जा सकता है कि नवउदारवादी एजेंसियों का नागरिक समाज के प्रति एकाएक उमड़ा प्यार सीधे-सीधे वर्ग-समाज और वर्ग-संघर्ष के अस्तित्व को मानने की उनकी अनिच्छा से पैदा होता है। वास्तव में, मेहनतकश वर्ग की अवस्थिति, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक भौतिकवाद में हैं, के अनुसार तथाकथित नागरिक समाज एक वर्ग-समाज है। मार्क्सवाद के आगमन के बहुत पहले ही, फ्रांसीसी क्रान्ति के अग्रदूत रूसो ने बताया था कि सभी नागरिक समाजों का उद्देश्य "मूल रूप से बल पर आधारित असमानताओं को कानूनी मान्यता और स्थायित्व प्रदान करना" है। ग्राम्शी इसे केवल दुहराते हैं जब वह नागरिक समाज को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं जहाँ "एक सामाजिक समूह का वर्चस्व या राजनीतिक सत्ता समूचे राष्ट्र पर सूक्ष्म, अमूर्त और अदृश्य रूपों में स्थापित हो।" दूसरे शब्दों में, नागरिक समाज में ताकतवर समूहों को राज्य सदैव ही कानूनी मान्यता और आश्रय देता है। संक्षेप में, राज्य और राजनीतिक सत्ता को तथाकथित नागरिक समाज का विस्तार मानने के बजाय, उत्तर-मार्क्सवादियों, उत्तर-आधुनिकतावादियों और नवउदारवादियों ने राज्य और नागरिक समाज को अलग-अलग खानों में कैद कर दिया है। वास्तव में, ग्राम्शी द्वारा वर्ग पर दिये गये मुख्य जोर का निषेध करते हुए और उनके द्वारा रेखांकित राज्य और नागरिक समाज के आवश्यक द्वन्द्वात्मक और सतत सम्बन्धों को अस्वीकृत करते हुए उत्तर-मार्क्सवादी, उत्तर-आधुनिकतावादी और नवउदारवादी एजेंसियों ने नागरिक समाज की नवग्राम्शीवादी व्याख्या (जो ग्राम्शी को उत्तर-मार्क्सवादी नजरिए से देखते हैं) का आश्रय लिया है, जिसके अन्तर्गत नागरिक समाज को राज्य के दमन के विरुद्ध उग्र एवं विविध संघर्षों के रूप में निरूपित किया गया है। दुर्भाग्यवश, डब्ल्यूएसएफ के दस्तावेजों पर एक नजर डालने से वही चित्र उभरता है। समूचा प्राइवेट सेक्टर बहुराष्ट्रीय निगमों सहित नागरिक समाज का अंग है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण खतरा है कि स्वयं वैश्विक नागरिक कार्रवाई ही नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के खतरों को फिर से पैदा कर सकती हैइस पहलू को डब्ल्यूएसएफ नहीं समझ सकता क्योंकि वह वर्गों और वर्ग संघर्षों का निषेध करता है।

निश्चित रूप से, डब्ल्यूएसएफ के प्लेटफॉर्म पर सहभागिता करने वाले अनेक संगठन हैं जो संगठित मजदूर वर्ग और प्रगतिशील ताकतों के साथ मिलकर भूमण्डलीकरण और आईएमएफ-विश्व बैंक-डब्ल्यूटीओ

जैसी एजेंसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ इस तरह की एकजुट कार्रवाईयों को ऊँचे स्तर तक उठाने के लिए उन्हें फलने-फूलने देना और आगे विकसित करना बेहद जरूरी है। साथ ही भूमण्डलीकरण के खिलाफ विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर लड़ने वाले विभिन्न तबकों से अधिकतम सम्भव एकता कायत करने के लिए प्रगतिशील ताकतों की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये। इसके साथ ही, इन संघर्षों को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है कि समझौताविहीन विचारधारात्मक संघर्ष छेड़ा जाये। भूमण्डलीकरण के अन्तर्निहित तर्क की वस्तुपरक व्याख्या पर आधारित इस तरह की सही दिशा भूमण्डलीकरण विरोधी संघर्षों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीतिक विकल्प तक ले जाने के लिए आवश्यक है। अन्यथा, ये संघर्ष व्यवस्था के अन्दर नागरिक विकल्प तक सीमित रहेंगे, जैसा कि डब्ल्यूएसएफ द्वारा प्रस्तुत "नानाविध विकल्पों" के रूप में प्रकट होता है। उस अर्थ में, संगठित मजदूर वर्ग, किसानों और अन्य मेहनतकश अवाम द्वारा पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के भौतिक आधार के खिलाफ छेड़े गए राजनीतिक संघर्ष जनकार्रवाई के मुख्य भाग का निर्माण करते हैं। इस तरह के संघर्ष चूँकि, "पुराने आन्दोलनों" के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसलिए डब्ल्यूएसएफ उनका समर्थन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, भारत के मामले को ही लें। संगठित मजदूर वर्ग के नेतृत्व में देश में भूमण्डलीकरण विरोधी अभूतपूर्व संघर्ष, जिनमें अखिल भारतीय बन्द भी शामिल हैं, विकसित हुए हैं। एक समय तो इन हड़तालों में भाग लेने वालों की संख्या विस्मयकारी आँकड़े-चार सौ पचास लाख तक बढ़ी, जो कि लिखित इतिहास में सर्वाधिक है। निश्चित रूप से, यह समय की माँग है कि राजनीतिक क्षेत्र में सदैव बढ़ने वाले इन संघर्षों को साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा और राजनीतिक रुझान से लैस किया जाये। इस निर्णायक समय में "नानाविध विकल्पों" और स्वप्नलोकों के साथ डब्ल्यूएसएफ का आगमन उन संघर्षों को सही साम्राज्यवाद विरोधी दिशा प्रदान करने में कत्तई सहायक सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इन विकल्पों की जड़ें नागरिक समाज की विचारधारा और नये सामाजिक आन्दोलनों में हैं तथा ये भूमण्डलीकरण के निर्णायक राजनीतिक अर्थशास्त्र को सम्बोधित करने से हिचकते हैं। डब्ल्यूएसएफ द्वारा प्रस्तुत विकल्प यूटोपिया ही हो सकता है क्योंकि यह भूमण्डलीकरण की संचालक शक्ति के रूप में पूँजी की गति के नियमों को उजागर करने में अक्षम है। इस तरह, डब्ल्यूएसएफ के आगमन और इसके अवतारों या "संस्करणों", जिसमें अकादमिक प्रयोग या "आयोजन" शामिल हैं, का जनसंघर्षों को साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक दिशा से विचलित करने का गुप्त एजेण्डा भी हो सकता है।

रेड स्टार, प्लेटफार्म ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज

(जनवरी 2003) से साभार

हजारों भागीदार, पर दुश्मन कौन?

युनाइटेड ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन आफ ब्राजील (सीयूटी) की ओर से डब्ल्यूएसएफ, पोर्तो अलेग्रे में एक खुला पत्र व्यापक रूप से बांटा गया जिसका शीर्षक था "क्या भूमण्डलीकरण और युद्ध को मानवीय चेहरा देना संभव है?" 26 यूनियन नेताओं को हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में वर्ल्ड सोशल फोरम और 'सिविल सोसायटी' की इसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की गयी थी।

पत्र पढ़ने के बाद बहुत से कार्यकर्ता इसे बांटने वालों को ढूंढ़कर मिले और अपनी सहमति व्यक्त की। एक कार्यकर्ता ने कहा, "मैं यहां देखने आया था कि यह सब क्या है और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक कहते हैं। **हजारों लोग भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन अंततः निर्णय कौन करेगा?"**

...

"ग्लोबल यूनियनिस्ट ग्रुप" की ओर से न्यूयार्क में वर्ल्ड इकोनामी फोरम में एक घोषणा पत्र बांटा गया जिसमें कहा गया था : "दुनिया को सीधे-सीधे ऐसे दो खेमों में नहीं बांटा जा सकता जो भूमण्डलीकरण के पक्ष और विरोध में हों।... हम वर्ल्ड इकोनामी फोरम पर दबाव डालेंगे ताकि वह सामाजिक न्याय का भूमण्डलीकरण करने की जरूरत पर विचार करे। साथ ही डब्ल्यूएसएफ के भीतर हम ऐसी रचनात्मक रणनीतियां स्पष्ट करने में योगदान देते रहेंगे जिनसे भूमण्डलीकरण को मेहनतकशों के हित में लोकतांत्रिक बनाया जा सके।"

रियो ग्रांदे दो सुल के अखबार *जीरो होरा* में लिखा कि डब्ल्यूएसएफ के दूसरे सम्मेलन में एक "उल्लेखनीय अवधारणात्मक प्रगति" हुई है। "भूमण्डलीकरण अब एक शैतानी दुश्मन नहीं रहा जिसकी समझौताविहीन और अतर्कपरक ढंग से आलोचना की जाये। ... जो भूमण्डलीकरण वांछनीय है उसे एक नया नाम भी मिल गयानैतिक भूमण्डलीकरण।" यह नई परिभाषा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त और आयरलैण्ड के पूर्व राष्ट्रपति मैरी राबिन्सन ने दी जो पोर्तो अलेग्रे में मौजूद थी।

हमें किस दुश्मन से लड़ना है?

पोर्तो अलेग्रे फोरम के समापन सत्र में प्रमुख हस्तियों के भाषणों का आम स्वर यह था : "आखिरकार, हमारी आवाजें न्यूयार्क में सुनी जाने लगी हैं""दुनिया की मेज पर हमें भी एक जगह मिल गयी है""यह फोरम पिछले वाले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सोद्देश्य था" वगैरह-वगैरह। मुट्ठी भर लोगों के आयोजक समूह द्वारा पास किया गया घोषणा पत्र सम्मेलन के अंत में वितरित किया गया। इसमें "नव उदारवाद, सैन्यवाद और युद्ध" की निंदा की गयी। लेकिन सवाल तो बना रहा कि वह दुश्मन कौन है जिससे हमें लड़ना हैदुनिया की इस भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?

डब्ल्यूएसएफ के घोषणापत्र के अनुसार "पितृसत्ता, नस्लवाद और हिंसा पर टिकी व्यवस्था ही लोगों की आवश्यकताओं और आशाओं के ऊपर पूंजी के हितों को विशेषाधिकार देती है।" तो हमने ठीक समझा कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था दुश्मन नहीं है (इसका तो जिक्र भी नहीं किया गया है) जबकि पूंजी के सारे विशेषाधिकार इसी पर आधारित हैं।

जूलियो टुरा

युनाइटेड ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन आफ ब्राजील (सीयूटी) की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य

विश्व सामाजिक मंच के सम्बन्ध में कुछ सवाल

प्रतिरोध का स्वर

क्या डब्ल्यूएसएफ भूमण्डलीकरण विरोधी या साम्राज्यवादी युद्ध विरोधी आन्दोलनों का संगठनकर्ता हो सकता है? भाकपा-माकपा जैसी सामाजिक जनवादी पार्टियों की डब्ल्यूएसएफ में भागीदारी की असलियत क्या है, डब्ल्यूएसएफ से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने की यह टिप्पणी कोशिश करती है। प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गयी यह टिप्पणी 'प्रतिरोध का स्वर' पत्रिका (जनवरी 2003) से साभार ली गयी है। *सम्पादक*

पहली बार विश्व सामाजिक मंच पोर्तो अलेग्रे से बाहर निकलकर अरब महासागर के गरम तट पर आ रहा है। भारत की वित्तीय राजधानी मुम्बई में सन् 2004 के जनवरी के मध्य में इसका छह दिवसीय लम्बा कार्यक्रम चलेगा।

वर्तमान व्यवस्था की सत्ता से अपनी निकटता के कारण विश्व सामाजिक मंच का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार हुआ है। इससे इस मंच ने विस्तृत शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है और इन कारणों से मीडिया में भी इसकी व्यापक पहुंच बनी है। इस संगठन को नजरअंदाज करना न तो सम्भव है न ही ऐसा किया जाना चाहिए। विश्व सामाजिक मंच के विभिन्न पहलुओं पर हमारे पाठकों व साथियों ने हमसे कई प्रश्न किये हैं, हमारे सम्पादक ने संक्षेप में कुछ सवालों का उत्तर दिया है।

प्रश्न : विश्व सामाजिक मंच को विश्व आर्थिक मंच की प्रतिक्रिया के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, 1999 में सिएटल तथा सन् 2000 में चले भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यक्रमों की जारी प्रक्रिया बताया जा रहा है तथा पश्चिमी देशों में इसे भूमण्डलीकरण विरोधी तथा युद्ध विरोधी आंदोलनों का संगठनकर्ता बताया जा रहा है। यह कहां तक सही है?

उत्तर : यह सही बात है कि विश्व सामाजिक मंच के आयोजक तथा इसके प्रति सहानुभूति रखने वाली अन्तरराष्ट्रीय मीडिया का ऐसा ही प्रचार है। परंतु यह कथन सही नहीं है। विश्व आर्थिक मंच की बैठकें स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 1971 से हर वर्ष एक बार आयोजित की जाती रही हैं। इसमें पूंजीवादी दुनिया की सरकारें तथा व्यवसायिक नेता भाग लेते हैं। अब सन् 2001 में ली गयी इस पहलकदमी को विश्व आर्थिक मंच की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। यह तीन दशक विलम्ब से हो रही है। ऐसा नकाब ओढ़कर ये लोग व्यर्थ ही भूमण्डलीकरण के विरुद्ध जारी जनता के आंदोलनों के समक्ष आ रहे प्रश्नों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह मंच विश्व आर्थिक मंच के विरुद्ध भी नहीं है जैसा कि हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साबित किया। सन् 2003 में उन्होंने विश्व आर्थिक मंच तथा सामाजिक मंच दोनों की सभाओं को संबोधित किया। विश्व सामाजिक मंच की बैठक में वह केवल औपचारिकतावश नहीं गये थे क्योंकि इसकी बैठक ब्राजील में हो रही थी बल्कि उनकी पार्टी विश्व सामाजिक मंच की एक प्रमुख संगठनकर्ता है।

जहां तक पश्चिमी देशों में भूमण्डलीकरण विरोधी तथा युद्ध विरोधी कार्यक्रमों का सवाल है, इन विरोध कार्यक्रमों का आयोजन विश्व सामाजिक मंच ने नहीं किया। जहां एक ओर विश्व सामाजिक मंच और उसके घटकों ने इन अभियानों में भागीदारी की वहीं कई अन्य संगठनों ने भी इनमें भाग लिया और इन्हें संगठित किया। यही नहीं ये विरोध कार्यक्रम पहले से चले आ रहे उन विरोध कार्यक्रमों का जारी रूप थे जो विश्व सामाजिक मंच के शुरू होने से पहले से हो रहे थे।

विश्व सामाजिक मंच निश्चित तौर पर सिएटल में 1999 में हुई विश्व व्यापार संगठन की बैठकों को बाधित करने वाले भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यक्रम तथा विश्व सामाजिक मंच के गठन से पूर्व सन् 2000 में पश्चिमी देशों में पूरे वर्ष चले भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यक्रम का जारी रूप नहीं है, बल्कि विश्व सामाजिक मंच उन सामाजिक शिखर सम्मेलनों का जारी रूप है जो विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष तथा यूरोपीय समुदायों की बैठकों के साथ-साथ आयोजित किए जा रहे थे। ऐसा एक सम्मेलन 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक की शुरूआत से एक दिन पूर्व भी आयोजित किया गया था।

लेकिन विश्व सामाजिक मंच का सिएटल तथा अन्य स्थलों पर भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यक्रमों के साथ एक निश्चित संबंध हैयह अन्तरराष्ट्रीय मैदान में कुछ बड़े खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया है जो इन विरोधों को विकसित होकर उन धाराओं में बहने से रोकना चाहती है जिनका जिक्र महानिदेशक रेनाटो रुगिएरो ने चेतावनी देते हुए किया था कि ये "वैकल्पिक समाधानों की ओर मुड़ सकते हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण आधारशिला को हिला भी सकती है।"

सिएटल तथा अन्य भूमण्डलीकरण विरोधी अभियान तीसरी दुनिया की जनता तथा अपने यहां की मेहनतकश जनता पर साम्राज्यवादी पूंजी के वर्तमान हमले के विरुद्ध विकसित देशों के मजदूरों तथा तबकों के विरोध तथा अविश्वास को प्रतिबिम्बित करते हैं। ये लोग बड़ी संख्या में विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष,

नाटो तथा साम्राज्यवादियों की बैठकों के विरोध में सड़कों पर उतरे। दूसरी ओर अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक द्वारा निर्देशित अपनी अर्थव्यवस्थाओं के भूमण्डलीकरण, यानी अर्थव्यवस्थाओं की बेरोकटोक लूट के लिए साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने के विरुद्ध तीसरी दुनिया के देशों की जनता लड़ती आ रही है। भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यक्रमों ने संघर्ष की इन दोनों धाराओं, राष्ट्रीय मुक्ति के लिए तीसरी दुनिया के देशों की जनता के संघर्ष तथा पूंजी के हमले के विरुद्ध साम्राज्यवादी देशों की जनता के संघर्षों की एकता की सम्भावनाओं को खोल दिया। चीन के एक पूंजीवादी देश के रूप में पतन के बाद ये साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष पहली बार एक अन्तरराष्ट्रीय राजनैतिक व सांगठनिक रूप अख्तियार कर सकते थे। इसे रोका जाना जरूरी था। भूमण्डलीकरण के टेढ़े-मेढ़े रास्ते को सीधा करना जरूरी था और साम्राज्यवादी पूंजी के इस हमले के रास्ते से गड्ढे हटाये जाने जरूरी थे। भूमण्डलीकरण विरोध को सख्ती के साथ एक दायरे में सीमित किया जाना जरूरी था ताकि यह साम्राज्यवाद का विरोध न कर बैठे और इस विरोध को वर्तमान वैश्विक आर्थिक ढांचे में दिखावटी तथा लेशमात्र परिवर्तनों तक सीमित किया जा सके। सबसे जरूरी था कि दुनिया भर में चल रहे विरोध कार्यक्रमों को इसी रूपरेखा में शामिल किया जाये। वास्तविक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों का एकताबद्ध होना धीरे-धीरे ही सम्भव था और वह भी अपने संघर्षों को तेज करने के क्रम में अपने अन्तरविरोधों को हल करके ही हो सकता था। पर उन्हें ऐसे अवसर से वंचित किया जाना जरूरी था।

साम्राज्यवाद के दोनों वफादार नौकरों, यूरोपीय सामाजिक जनवादियों तथा गैर सरकारी संगठनों को इस काम में सक्रिय कर दिया गया। भारी पैमाने पर पैसे और व्यक्तियों के रूप में साधनों को सक्रिय किया गया ताकि वे भूमण्डलीकरण विरोध के कार्यक्रमों द्वारा बनाये गये राजनैतिक दृश्य पर छा जायें और साम्राज्यवाद, विशेषकर उसके वर्तमान हमले के विरुद्ध व्यापक संघर्ष के लिए खुले अवसरों को रोका जा सके। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को, विशेषतः प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को इसमें लगाया जा रहा है। पूरे के पूरे आंदोलनों को इसमें शामिल किया जा रहा है, विशेषकर उनको जो साम्राज्यवाद के प्रभुत्व वाली अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्देशित नीतियों के लागू होने से हो रहे परिणामों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। एक और टीना (देयर इज नो अल्टरनेटिवकोई विकल्प नहीं है) का निर्माण किया जा रहा है कि जिस तरह के भूमण्डलीकरण विरोधी आंदोलन की रूपरेखा विश्व सामाजिक मंच बना रहा है, यानी "मानवीय चेहरे के साथ" भूमण्डलीकरण के लिए संघर्ष, इसका कोई विकल्प नहीं है। यह नया टीना (कोई विकल्प नहीं है) साम्राज्यवादी शक्तियों के उस पहले अभियान के सहयोग के लिए है कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का कोई विकल्प नहीं है।

प्रश्न : क्या साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों का समन्वय करने के लिए विश्व सामाजिक मंच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया की जनता के बढ़ते साम्राज्यवाद विरोधी तथा भूमण्डलीकरण विरोधी संघर्षों में इसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती?

उत्तर : यहां पर यह समझना जरूरी है कि विश्व सामाजिक मंच संघर्ष का मंच नहीं हो सकता। यह खुद ही ऐसी संभावना को प्रतिबंधित करता है। इसका घोषणापत्र समान घोषणाओं को ही प्रतिबंधित करता है, साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध समान कार्यभार तय करने का तो सवाल ही नहीं उठता। विश्व सामाजिक मंच का घोषणापत्र कहता हैः

"विश्व सामाजिक मंच की बैठकें, एक संगठन के रूप में इस मंच की ओर से चर्चा नहीं करती। मंच के किसी भी संस्करण की ओर से किसी को भी यह अधिकार नहीं होगा कि वह तमाम भागीदार घटकों की ओर से राय व्यक्त करे। भाग लेने वालों की ओर से या उनके किसी बहुमत की ओर से, ऐसा कोई निर्णय, जो इन भागीदारों को प्रतिबद्ध करे या मंच की प्रस्थापनाओं को एक संगठन के रूप में रेखांकित करे, वोटों के माध्यम से अथवा सर्वसम्मत रूप से मंच में भाग लेने वालों को एक संगठन के रूप में नहीं लेना होगा।" अतः यह काफी स्पष्ट है कि विश्व सामाजिक मंच को एक संघर्ष के मंच के रूप में नहीं बनाया गया है।

दूसरी बात यह है कि यह विभिन्न शक्तियों के खुले रूप से मिल-बैठ कर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने का भी मंच नहीं है जैसा कि उसका अपने बारे में दावा है। विश्व सामाजिक मंच का दस्तावेज कहता है, "विश्व सामाजिक मंच सोचने-विचारने का, विचारों पर जनवादी बहस का, प्रस्ताव तय करने का तथा अनुभवों का खुला आदान प्रदान करने का मंच है... ।"

साथ ही यह दस्तावेज लिखता है कि "विश्व सामाजिक मंच इतिहास के एकाधिकारवादी और संकीर्ण रुख रखने वाले दृष्टिकोण को नकारता है। ..." एक ऐसा मंच जो खुली बहस के लिए बना हो और अपनी घोषणा में ही मजबूती से इन पहलुओं को नकार दे, तो उसमें बहस कितनी खुली हो सकती है। यह प्रावधान केवल दिखावटी नहीं है, यह सभी को स्पष्ट होना चाहिए।

यह खुली बहस का मंच नहीं है यह इसी बात से स्पष्ट है कि यह साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के विरुद्ध लड़ने वाली सभी शक्तियों को स्थान नहीं देता। इसका घोषणापत्र "राजनीतिक दलों" और "सैन्य संगठनों" की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। यह प्रतिबंध साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रही लोकप्रिय शक्तियों पर लागू करने के लिए है यह बात इनके घोषणापत्र से भी स्पष्ट है और इसे लागू करने के इनके व्यवहार से भी। घोषणापत्र लिखता है कि "उनको बहस में भाग लेने से न रोका जाए जो अपनी जनता द्वारा अधिकृत होकर जिम्मेदार राजनीतिक पदों पर हैं।..." इस मंच को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि "जनता द्वारा अधिकृत" बहुत से "जिम्मेदार पदों के राजनीतिज्ञ" अपने देशों के सैनिक तंत्र के नेता भी हैं। विश्व सामाजिक मंच का प्रतिबंध इन पर लागू नहीं है।

यह प्रतिबंध किन पर लागू है यह 2002 तथा 2003 में हुई विश्व सामाजिक मंच की बैठकों में भागीदारी पर लगे प्रतिबंध से स्पष्ट हो जाता है। फार्क (एफ.ए.आर.सी.रिवोल्यूशनरी आर्मड फोर्सेस आफ कोलम्बिया), मैक्सिको की जपाटिस्टा के प्रतिनिधियों को भाग लेने से रोका गया और अर्जेन्टीना की माद्रेस दे प्लाजा दे मायो (मदर्स आफ द डिसअपियर्डसैनिक शासन के दौरान लापता हुए लोगों की माताएं) को भी जो न तो एक "राजनीतिक दल" है और न ही "सैनिक संगठन"।

भाग लेने वालों की सूची, जिसमें विशाल बहुमत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का है, से ही यह स्पष्ट है कि यह मंच बहस का खुला मंच नहीं है जैसा होने का यह दावा करता है। स्वाभाविक रूप से दिमाग में प्रश्न उठता है कि फिर यह मंच क्या है और किस उद्देश्य

की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। विश्व सामाजिक मंच, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और नीतियों के कारण फल रही दरिद्रता तथा विनाश के विरुद्ध जनता के गुस्से को इसी व्यवस्था के अन्दर की सुरक्षित सीमाओं तक केन्द्रित करने और "जनता की भागीदारी" द्वारा इसी व्यवस्था को सुधारने का भ्रम फैलाने के लिए है। इसका मकसद ही इन शक्तियों को अपने इस अभियान में शामिल करने का है। यह जनता के आन्दोलन को "मानवीय चेहरे के साथ भूमण्डलीकरण" के जाल में आकर्षित करके फंसाना चाहता है।

यह मंच, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के असर के विरुद्ध दुनिया भर में विकसित हो रहे उन आन्दोलनों व शक्तियों को, जिनका साम्राज्यवादी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम नहीं है, एकताबद्ध करके ऐसा कर रहा है। इसका मकसद ऐसी शक्तियों को वर्तमान व्यवस्था सुधारने के लक्ष्य के अन्तर्गत सीमित रखना है। इसका प्रयास है कि ऐसा करके साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रही शक्तियों को उलझाकर उन पर दबाव बनाकर उन्हें अपने उद्देश्यों व लक्ष्य बदलने के लिए मजबूर करे, यानी विश्व सामाजिक मंच के व्यवस्था को सुधारने का घोषणापत्र के अनुसार ढालने के लिए मजबूर करे। जैसे पूंजीवादी संसदों में 'वफादार' विपक्ष होना जरूरी है और होता है, साम्राज्यवाद चाहता है कि साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन भी 'वफादार' हो। दूसरी ओर यह उन शक्तियों को अलग-थलग करना चाहते हैं जो अपनी साम्राज्यवाद विरोधी दिशा के प्रति अविचल तथा दृढ़ हैं। ये इन शक्तियों को अपने उद्देश्यों व लक्ष्य के पक्ष में अभियान चलाने से रोकना तो चाहते ही हैं, साथ-साथ इनकी इच्छा है कि वे विश्व सामाजिक मंच की दिशा को अपना लें।

विश्व सामाजिक मंच साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का समन्वय करने का न तो दावा कर सकता है और न ही वो ऐसा कर रहा है, बल्कि यह तीसरी दुनिया के देशों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं, साम्राज्यवादी सरकारों और साम्राज्यवादी धन देने वाली संस्थाओं से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन की सच्ची शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करके यह ऐसा कर रहा है। यह सभी जानते हैं कि ऐसे संगठन, यानी एनजीओ भारत समेत सभी तीसरी दुनिया के देशों में बड़े पैमाने पर विकसित हो रहे है। ये एनजीओ जिनका अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी संस्थाओं, और स्थानीय सरकारों के साथ गहरा सम्बन्ध है और जिन्हें साम्राज्यवाद से बड़े पैमाने पर पैसा मिल रहा है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई के संगठन नहीं है। विश्व सामाजिक मंच न केवल इनकी वैधता स्थापित करता है, ये संगठन उसका मुख्य हिस्सा भी हैं।

यह एक चिंता की बात है कि जनता के कई संगठन और कुछ क्रांतिकारी शक्तियां भी इस बिन्दु पर उचित सतर्कता नहीं दिखा रही हैं और सामान्य ढंग से इन एनजीओ से उत्पन्न खतरों की बात कर रही हैं और दूसरी ओर विभिन्न कारण गिनाकर यह उन्हीं से हाथ मिलाने को तैयार हैं। उन्हे समझना चाहिए कि उनके अनगिनत लेखों को कोई लाभ नहीं होगा अगर वह इसे अमल में लागू नहीं करेंगे। जब भारत की आम जनता हर रोज साम्राज्यवादी शक्तियों की नीतियों के नीचे कराह रही है तो उन्हें साम्राज्यवाद का यंत्र बताकर उन्हीं के साथ सहयोग करने से क्या लाभ होगा ? यह अच्छी स्थिति नहीं है और दिखाती है कि जनता के आन्दोलन के बीच, विशेषकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच एन0जी0ओ0 के प्रति आकर्षण को तोड़ने के लिए काफी काम करना बाकी है।

प्रश्न : ऐसे कई संगठन जिनके साथ हम संयुक्त कार्यवाइयां करते हैं विश्व सामाजिक मंच में हैं। ऐसे में विश्व सामाजिक मंच संयुक्त कार्रवाइयों का मंच क्यों नहीं बन सकता ?

उत्तर : यह बात सही है कि ऐसे कई संगठन जिनके साथ जनता के सवालों पर हम संयुक्त कार्रवाइयां करते हैं, विश्व सामाजिक मंच में भाग ले रहे हैं। ये हैदराबाद में हो रहे एशिया सोशल फोरम के भी हिस्सा थे। संयुक्त कार्यवाही का मकसद् जनता के ठोस सवालों पर संघर्ष का विकास करना है। हमारा राजनैतिक प्रस्ताव कहता है ;

"हम शासक वर्गों के विपक्षी दलों और संशोधनवादी पार्टियों के साथ जनता के विशेष सवालों पर संयुक्त संघर्षों का निर्माण कर सकते हैं, उन राज्यों को छोड़कर जिनमें यह दल राज्य कर रहे हैं। हमें जनता के सवालों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए क्योंकि इनके साथ संयुक्त कार्यवाही का मकसद ही जनता को संघर्ष में उतारना है। ऐसे मुद्दों पर जिनमें यह सम्भावना न हो, हमें इनके साथ संयुक्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

यहां संयुक्त कार्रवाइयों की दिशा संघर्षों के विकास के लिए और वे भी जनता के विशेष सवालों पर। विश्व सामाजिक मंच को ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी समझ ही संघर्ष करने की नहीं है जैसा कि हमने पहले देखा है।

दूसरी आर विश्व सामाजिक मंच ने "एक अलग दुनिया संभव है" का नारा दिया है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विश्व सामाजिक मंच एक अलग विश्व व्यवस्था की बात नहीं कर रहा बल्कि केवल एक अलग दुनिया की बात कर रहा है जो कि काफी अस्पष्ट व धुंधला है। जहां एक ओर यह नारा साम्राज्यवाद द्वारा विश्व जनता के शोषण व भयावह स्थिति के प्रति गुस्से को गोलबंद करता है, यह उस साम्राज्यवादी व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव तक प्रस्तुत नहीं करता।

यही नहीं, विश्व सामाजिक मंच एक स्थायी ङ्क्रिया है जैसा कि इसकी भारतीय इकाई द्वारा जारी नीति-निर्देशों से स्पष्ट है;

'पोर्ते एलग्रे' में "अलग दुनिया संभव की घोषणा के बाद यह विकल्पों को तलाशने व उनका निर्माण करने की एक स्थायी प्रक्रिया बन जाती है, इस प्रक्रिया को समर्थन देने वाली कार्यवाहियों को निष्कर्षों तक सीमित नहीं किया जा सकता। (विश्व सामाजिक मंच-भारत, भोपाल, 19-20 अङ्क्रैल 2002)

उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि हम साम्राज्यवाद द्वारा शोषित जनता के ठोस व विशिष्ट सवालों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक अलग दुनिया की कल्पना की बात कर रहे हैं जो वास्तव में कोई कल्पना ही नहीं।

अतः ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसका बयान रेनाटो रुगिएरो ने किया था, यानी, "व्यापार उदारीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु पर्याप्त समर्थन" प्राप्त करने के लिए "सभी राजनैतिक नायकों का आपसी सहयोग व समर्थन प्राप्त किया जा सके।"

क्योंकि यह मंच साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का मंच नहीं है। इसलिए इसे इस हेतु इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रश्न : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में विश्व सामाजिक मंच की सबसे मजबूत पैरोकारों में से एक है और इसकी आयोजक भी हैं। क्या, गैर-सरकारी संगठनों के प्रति उन्होंने अपना रवैया बदल दिया है और क्यों ?

उत्तर : यह सही बात है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भारत में विश्व सामाजिक मंच के सबसे मजबूत पैरोकरों में है। इसका कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। यह भूमण्डलीकरण के प्रति उनके रवैये पर आधारित है। वह भी मानवीय चेहरे के साथ भूमण्डलीकरण के पक्षधर रहे हैं और यह उनके द्वारा अमल की जा रही वर्ग सहयोग की राजनीति का हिस्सा है, खास तौर से नक्सलबाड़ी के क्रांतिकारी सशस्त्र किसान विद्रोह का उनके द्वारा किए गये दमन के बाद।

आपने गैर-सरकारी संगठनों के प्रति उनके बदले हुए रवैये का सवाल ठीक उठाया है। 1988 में प्रकाश कारत ने एक लेख लिखा था जिसका विषय था 'स्वयंसेवी संगठनों का दर्शन और विदेशी फन्डिंग'। यह *मार्क्सिस्ट* नामक पत्रिका में छपा था। इस लेख में उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों (अब इन्हे गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है) और साम्राज्यवाद के बीच संम्बन्धों के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि "इन्हें उदारतापूर्वक ढंग से धन देकर साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज के जीवनदायक तबकों के बीच प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने के रास्ते खो दिए हैं और साथ-साथ वह वामपंथी आन्दोलन की सम्भावनाओं को तहस-नहस तथा उसका विरोध करने के लिए वह इस आन्दोलन को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल करता है।" उन्होंने आगे लिखा, "मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम शक्तियों को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के इस हथियार का गम्भीरतापूर्वक गौर करना पड़ेगा।"

श्री प्रकाश कारत ने तब गैर सरकारी संगठनों की साम्राज्यवाद परस्त भूमिका पर लम्बे वक्तव्य दिये। और अब उसी माकपा को विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया के अर्न्तगत गैर सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर है, उनके रवैये में एक निश्चित परिवर्तन आया है। उनके एक प्रमुख नेता ने बयान दिया कि "आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी सामाजिक ढांचे के आवश्यक अंगों में गैर सरकारी संगठन भी है और बहुत से उसी तरह के नागरिक समाज संगठन भी हैं। अतः साम्राज्यवादी साजिशों के प्रति सतर्क रहते हुए हमें साम्राज्यवाद तथा भूमण्डलीकरण की पक्षधर नागरिक समाज संगठनों और ऐसे संगठनों के बीच, जिनका यह चरित्र नहीं है, अन्तर करना पड़ेगा"। (माकपा विधायक और पूर्व राज्य योजना आयोग के सदस्य डा. थामस इसाक, आस्पेक्ट्स ऑफ इन्डियाज इकोनामी अंक 35)।

या जैसे सीटू सचिव वरदराजन ने हाल में गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपने सहयोग के पक्ष में लिखा, "आपने देखा होगा कि एक नया रूझान उभर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और आर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी, जहां 'नागरिक समाज' के प्रतिनिधि होने वाले गैर सरकारी संगठन राजनैतिक संगठनों की तथा पारम्परिक जन आन्दोलनों व संगठनों की आलोचना करते रहे हैं। भारत में भी जहां 'जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच' पर (एनपीएमओ) संयुक्त कार्यवाही के लिए कई जन-संगठन साथ आए, एक अन्य मंच 'जन-आन्दोलनों के राष्ट्रीय गठजोड़' (एनएपीएम) भी देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय था। विश्व सामाजिक मंच जो सभी को शामिल करता है, विस्तृत है और कई दिशाओं के प्रति खुला है, में ऐसे गैर-सरकारी संगठन भी भाग ले रहे हैं। नागरिक समाज, सामाजिक आन्दोलन, आदि नामों का मूल्यांकन इस पृष्ठभूमि में हमें करना होगा।"

यह स्पष्ट है कि मा.क.पा. ने गैर सरकारी संगठनों के प्रति अपनी समझ को बदल दिया है, या कहा जाए कि स्थिति अनुसार परिवर्तित कर दिया है जैसा कि तिरुवनन्तपुरम सम्मेलन में उन्होंने अपने कार्यक्रम के साथ किया था। इस परिवर्तन को करने के पीछे असली बात है सोवियत संघ के गिरने और सामाजिक साम्राज्यवाद के खेमें के विघटन के बाद उनके द्वारा किया गया संशोधन। माकपा ने पहले दोनों अतिमहाशक्तियों अमेरिका व सोवियत संघ के बीच विश्व प्रभुत्व की होड़ के दौर में दिशा तय की थी। प्रकाश कारत का लेख इस समझ को सूत्रबद्ध करता है। माकपा भारत में सोवियत प्रभुत्व की पक्षधर थी और उसके द्वारा भारत में किए जा रहे शोषणकारी निवेशों का समर्थन करती थी। माकपा कुल मिलाकर साम्राज्यवाद की विरोधी नहीं थी बल्कि तब पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की विरोधी थी। कारत ने उस लेख में लिखा था "स्वयंसेवी संस्थाओं/एक्शन ग्रुपों का जाल पश्चिमी पूंजीवादी देशों से आ रहे धन से पोषित व बिछाया हुआ है।"

सामाजिक साम्राज्यवाद के खेमे के विघटन के बाद दुनिया में दो मंडियां नहीं है और रूसी पूंजी पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व वाले साम्राज्यवादी विश्व-बाजार का हिस्सा है और उसकी दावेदारी इसी में बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितयों में माकपा को पश्चिमी साम्राज्यवादी पूंजी के प्रति अपने रवैये को बदलना पड़ा है और वह अब इसे नई तकनीक व उत्पादन तरीकों के वाहक के रूप में देखती है। इसी तरह यह इसके द्वारा पोषित संस्थाओं को भूमण्डलीकरण विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी संगठनों के रूप में देखती है जो जनता की सेवा कर रहे हैं। यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि माकपा को अब विदेशियों द्वारा पोषित गैर सरकारी संगठनों से कोई आपत्ति नहीं है। (प्रोजेक्ट/स्कीम के लिए यह धन भले ही उन्हीं विदेशी पूंजीवादी देशों से आया हो) और उनकी कतारें इनके साथ सक्रिय घनिष्ठता बढ़ा रही हैं।

माकपा के इस बदले हुए रवैये पर गौर करते समय हमें स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों द्वारा पोषित गैर सरकारी संगठनों के प्रति उनका पुराना रवैया वास्तव में विश्व-प्रभुत्व के लिए दोनों अतिमहाशक्तियों के आपसी संघर्ष का ही प्रतिनिधित्व करता था और गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध उनका कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं था। साम्राज्यवाद और घरेलू प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध जन-संघर्षों के लिए इन संस्थाओं से उत्पन्न खतरे पर भी इनका कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं था। यह स्पष्ट है कि जहां आज गैर-सरकारी संगठनों से उत्पन्न खतरा कई गुना बढ़ गया है, माकपा ने इनके साथ सहयोग करने का फैसला किया है, हालांकि एक समय वह इन्हें "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का माध्यम" कहती थी। उन्हें जानना चाहिए और इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि धन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ी है... और इतनी गुना क्यों बढ़ गई है? फिर भी माकपा उन्हीं के साथ है। क्या यह बढ़ते विदेशी धन और गैर-सरकारी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का असर है।

मदर्स ऑफ प्लाजा डि मेयो

"हम लोगों से उम्मीद की जा रही है कि हम भूमण्डलीकरण पर 'एक मानवीय चेहरा लगाने' के बारे में बातें करें!"

(मदर्स ऑफ प्लाजा डि मेयो की अध्यक्ष हेबे डि बोनाफिनी, द्वितीय वर्ल्ड सोशल फोरम में बोलते हुए...)

मदर्स ऑफ प्लाजा डि मेयो की अध्यक्ष हेबे डि बोनाफिनी द्वारा अर्जेंटीना के ब्यूनो आयर्स में एक विशाल रैली में 7 फरवरी 2002 को दिए गए भाषण के मुख्य अंश यहां प्रस्तुत हैं। मदर्स ऑफ प्लाजा डि मेयो अर्जेंटीना में 1976-83 की फौजी तानाशाही के दौर में गायब हुए हजारों-हजार यूनियन कार्यकर्त्ताओं और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की मांओं का संगठन है। यह इन लोगों के गायब होने के लिए जिम्मेदार लोगो को सजा दिलाने और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है।)

"साथियो, हम द्वितीय डब्ल्यूएसएफ के मौके पर पोर्तो अलग्रे में थे। सप्ताह भर चले इस आयोजन में 50 हजार से अधिक लोगों ने शिरकत की। वहां पर हजारों युवाओं समेत दुनिया के कोने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

''इस डब्ल्यूएसएफ के तीन भिन्न स्तर थे। पहला स्तर उन लोगों का छोटा जमावड़ा था जो कि चीजों को नियंत्रित करने वाले प्रभारी थे। उनका नेतृत्व फ्रांसीसियों द्वारा खासकर 'अटैक' के लोगों और कुछ दूसरे देशों से आये अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा था।

''और इसके बाद कमीशनों और सेमिनारों का स्थान था जहां पर सभी बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों और विचारकों ने हिस्सेदारी निभायी। और इसके बाद आम कार्यकर्ता आते थे। हमने इसी स्तर पर भागीदारी की और हमने सभी तरह के लोगों से चर्चा की। अलबत्ता, सच्चाई तो यह है कि हमें डब्ल्यूएसएफ में लाया ही इसलिए गया था कि हम चुपचाप सुनेंइसलिए नहीं कि हम इसमें भागीदारी करें।

''फिदेल कास्त्रो को भागीदारी करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और न ही एफएआरसी को।

यह शर्म की बात है। और न ही मदर्स आफ प्लाजा डि मेयो को आमंत्रित किया गया था।

''मैं पोर्तो अलग्रे पहुंची क्योंकि एमएसटी की तरफ से निजी तौर पर मुझे आमंत्रित किया गया था। और यह महत्वपूर्ण था कि मैं वहां थी क्योंकि मैं कुछ अन्य लोगों के साथ इस विश्व सामाजिक मंच की अपनी तीखी आलोचना को आगे बढ़ाने वाले पहले कुछ लोगों में से थी।

''हमने कहा कि सामाजिक जनवाद और समाजवाद एक ही चीज नहीं है। हमने कहा कि यूरोपीय सामाजिक जनवाद ने इस डब्ल्यूएसएफ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसका औचित्य प्रतिपादित किया। हमने कहा कि फ्रांसीसी आयोजक (अर्थात एटीटीएसी) और उनके बिरादर इस प्रक्रिया में निस्संदेह सहभागी हो सकते थे लेकिन उन्हें इसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए था।

''हमने कहा कि हमारे दृष्टिकोण से लोग इस डब्ल्यूएसएफ में भूमण्डलीकरण के खिलाफ लड़ने और संगठित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आयोजकों ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया कि पहले से ही यह मान लिया गया था कि हम भूमण्डलीकरण को 'मानवीय चेहरा' देने के बारे में बात करने वाले हैं।

''जिन लोगों से मैंने बात की एक भिन्न संदेश सुनने को मिला : अर्जेंटीना के सम्बन्ध में मैंने उन्हें बताया कि मदर्स प्लाजा डि मेयो ने 25 साल पहले प्लाजा डि मेयो को अपने अधिकार में ले लिया था जो कि ब्यूनस आयर्स में राष्ट्रपति के महल के ठीक सामने है।

''और मैंने कहा कि उस जगह पर जहां हमें छोड़ा गया था लाखों की संख्या में लोग नियमित रूप से जमा हो रहे हैं और देश बेचने वाले राष्ट्रपतियों की नए सिरे से लानत-मलामत कर रहे हैं।"

डब्ल्यूएसएफ : साम्राज्यवाद का नया मोहरा

युवाभारत

युवाभारत की ओर से जारी यह लेख बहुत सीधे-सरल ढंग से डब्ल्यूएसएफ के गठन, साम्राज्यवाद से इसके सम्बन्ध, इसके मार्गदर्शक सिद्धान्तों की वास्तविकता, एनजीओ की राजनीति और भारत में डब्ल्यूएसएफ की भूमिका तथा इसके आधार का भण्डाफोड़ करता है। *सम्पादक*

भारत में फोरम का आधार

यह साम्राज्यवाद की आर्थिक शक्ति का कमाल ही कहा जायेगा कि वह एक ही छत के नीचे साम्राज्यवादी हित साधने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा भारत की कई कम्युनिस्ट पार्टियों, सर्वोदयी-गांधीवादियों तथा अन्य परिवर्तनकारी संगठनों को एक साथ ले आया है। यह कमाल उसने वर्ल्ड सोशल फोरम बनाकर किया है।

वर्ल्ड सोशल फोरम (अब से फोरम) विभिन्न जन संगठनों, ट्रेड यूनियनों तथा विशिष्ट सामुदायिक संगठनों तथा ग्रुपों का ढीला-ढाला मंच है जिसके कोई लिखित नियम तो नहीं है, परंतु निश्चित लक्ष्य जरूर है।

फोरम के आधे से ज्यादा संगठन साम्राज्यवादी पैसे से संचालित एन.जी.ओ. हैं। इसके खुले वित्त पोषकों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दाता 'फोर्ड फाउन्डेशन' है।

'फोर्ड फाउन्डेशन' ने ब्राजील के गैर सरकारी संगठनों को पहली तथा दूसरी फोरम की बैठकें संगठित करने के लिए 3,28,000 डालर (1 डालर यानि 45 रूपये या 1 करोड़, 47 लाख, 60 हजार रूपये) दिये थे।

यह पैसा इस फाउन्डेशन ने "शांति तथा सामाजिक न्याय' स्थापित करने के लिए दिया था। फोर्ड ने 5 लाख डालर ब्राजील के गैर सरकारी संगठनों को 2003 की फोरम के सालाना जलसे के लिए दिये। फोरम का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक "आक्सफैम" है। इस संगठन को लंबे समय से साम्राज्यवादी पैसा मिल रहा है। इसका प्रसार समूचे विश्व में है। ब्रिटिश सरकार से एक समय में इसका 90 प्रतिशत व्यय, अनुदान के रूप में मिलता था। इसके अन्य कई स्रोत हैं। आजकल इसका काम ध्वस्त इराक में साम्राज्यवादियों की ओर से मरहमपट्टी करना है। 'आक्सफैम' की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिणी अमरीका में कार्य के पश्चात् इसे यह ज्ञान हुआ कि प्राथमिक कार्य इन देशों में गरीबी दूर करना है। यह गरीबी साम्राज्यवादी शोषण को समाप्त करके नहीं, बल्कि विकासोन्मुख योजनाओं का लक्ष्य, आत्म-जागरण तथा सामुदायिक कार्रवाई की ओर मोड़कर होगा। इसका दावा है कि यह "निर्धनता, सामाजिक अन्याय तथा असमानता के बुनियादी कारणों को दूर करने में लगा हुआ है।"

जर्मनी की 'हाइनरिख बोल फाउन्डेशन', फोरम की एक और महत्वपूर्ण साझीदार है। इस गैर सरकारी संगठन का दावा है कि वह सामाजिक न्याय, लिंग अधिकारों, पर्यावरण तथा वहनीय विकास का पक्षधर है। इसका संबंध जर्मनी की ग्रीन पार्टी से है।

साम्राज्यवादी देशों के इन गैर सरकारी संगठनों के साथ भारत के बहुत से परिवर्तनकारी संगठन, कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े जन संगठन, समाजवादी तथा सर्वोदय मूल के संगठन और भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों ने कई मोर्चे बनाये हैं। ये मोर्चे जनता के अलग-अलग हिस्सों में कार्यरत हैं। इनकी लम्बी सूची नीचे दी गई है।

फोरम का राष्ट्रीय विचार-विमर्श भोपाल में अप्रैल 19 तथा 20, 2002 को संपन्न हुआ था। उसमें भागीदार संगठन इस प्रकार थे :-

1. अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन (माकपा) 2. ट्रेड यूनियनों का अखिल भारतीय फेडरेशन (ए.आई.एफ.टी.यू.) 3. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक, भाकपा) 4. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (ए.आई.ए. के. एस.एस.) 5. आल इंडिया सेन्ट्रल काउन्सिल फार ट्रेड यूनियन्स (एक्टू) (भाकपा-माले, लिबरेशन) 6. आल इंडिया पीपुल्स साइन्स नेटवर्क (ए.आई.पी.एस.एन.) 7. आल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमन्स एसोसियेशन (सी.पी.आई.) 8. आल इंडिया स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (आइसा) (भाकपा-माले) 9. आल इंडिया युनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क 10. एलाएन्स फार ए रिस्पान्सिबल एण्ड प्लूरल युनाइटेड वर्ल्ड (एशिया पैसिफिक) 11. एशियन यूथ नेटवर्क 12. भारत ज्ञान विज्ञान समिति (माकपा) 13. सेन्टर फार इंडिया ट्रेड यूनियन्स (सीटू) (माकपा) 14. फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव आफ इंडिया (एफ.एम.आर.आई.) (माकपा) 15. फोकस आन द ग्लोबल साउथ इंडिया प्रोग्राम 16. इंडियन पीपुल्स कैम्पेन अगेन्स्ट डब्ल्यू. टी.ओ. 17. इंकलाबी यूथ फोरम 18. जन स्वास्थ्य अभियान 19. नेशनल एलायन्स फार पीपल्स मूवमेन्ट (एनएपीएम) 20. नेशनल कैम्पेन कमेटी फार पीपल्स राइट टू इन्फोर्मेशन 21. नेशनल कैम्पेन कमेटी फार रूरल वर्क्स 22. नेशनल कैम्पेन फार ट्राइबल सेल्फ रूल। 23. नेशनल कैम्पेन आन दलित ह्यूमन राइट्स 24. नेशनल सेंटर फार लेबर 25. नेशनल दलित फोरम 26. नेशनल दलित वूमन्स फेडरेशन 27. नेटवर्क फार माइन्स, मिनरल्स एण्ड पीपुल्स 28. राष्ट्रीय युवा संगठन 29. सर्व सेवा संघ 30. साउथ इंडिया फोरम फार पीस 31. जस्टिस वासुदेव कुटुम्बकम्।

उपरोक्त संगठनों तथा नेटवर्क के प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति गठिन की गयी, जिसके सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:-

अमरजीत कौर, अमित सेन गुप्ता, अरूणा राय/नीलाभ मिश्रा, वृन्दा कारात/सुभाषिनी अली, चक्रपानी घण्टा, चार्ल्स वेस्त्री मीसा, डेविड सेल्फराज, दिनेश अबरोल/श्री दीपंकर भट्टाचार्य, जय सेन, मार्टिन माकवान/पाल दिवाकर, मीना मेनन, एन.पी. सामी, पी.के. मूर्ति, प्रबीर

पुरकायस्थ, रूथ मनोरमा, एम.जी. संजय, सिद्धार्थ, श्रीलता स्वामीनाथन, सुभाष लोमटे, उषा पंडित/सवाई सिंह, बसावी/जानू, विजय प्रताप, विनोद रैना/टी.सुन्दरम, डब्लू वरदराजन।

इस बड़ी कमेटी के तहत एक छोटी कमेटी बनाई गई थी, जिसे एशियाई फोरम की बैठक आयोजित करनी थी तथा फोरम के अन्तरराष्ट्रीय संबंधों तथा बाहरी संगठनों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार था। इस कमेटी के सदस्य थे :- अजीत झा, जयसेन, मीनार पिम्पले, सिद्धार्थ, श्रीलता स्वामीनाथन।

फोरम की भारतीय शाखा में नया इतिहास रचने वाला घटनाक्रम देखा जा सकता है। एक ही कमेटी में भाकपा, माकपा, भाकपा-माले, मेधा पाटकर, गांधीवादी सर्वसेवा संघ तथा साम्राज्यवादी पैसे से संचालित गैर सरकारी संगठन सब मिल जुलकर एक ही कमेटी के सदस्य हैं तथा एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं।

साम्राज्यवाद की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है कि ये सब पार्टियों/विचार/व्यक्ति जो पिछली अर्द्ध शताब्दी से आपस में ही सिर फुटौव्वल करते आ रहे हैं, वे सब के सब फोरम के झण्डे तले बड़ी खुशी-खुशी एकजुट हो गये हैं।

फोरम के मार्फत साम्राज्यवाद को भारत में बहुत सशक्त राजनैतिक आधार प्राप्त हो गया है। साथ ही, उन समस्त पार्टियों, व्यक्तियों की असलियत भी सबके सामने साफ हो गई है कि वे अन्ततः साम्राज्यवाद की छतरी के नीचे आ गये हैं और उनके दस्तावेज/कार्यक्रम/कार्यनीति सब महत्वहीन तथा छलावा हैं।

ये पार्टियां बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद से सहयोगी संबंध बनाने में जुट गयी हैं। अभी यह कार्य उनके जनसंगठनों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। समय तथा परिस्थिति के अनुसार, सहयोग करने के तौर-तरीके बदलते रहेंगे, परन्तु जो स्थायी है वह है इन समस्त पार्टियों, व्यक्तियों इत्यादि का साम्राज्यवाद से गठजोड़। यह साम्राज्यवाद की आर्थिक, राजनीतिक तथा हाल की वैचारिक विजय का ही द्योतक है कि वैसे साम्राज्यवाद विरोध की चर्चा करने वाले, दर्जनों संगठन, अपने समर्पण को तरह-तरह के तर्को से न्यायोचित ठहराकर वर्ल्ड सोशल फोरम में भागीदार बन गये हैं। इस प्रकार का समर्पण विश्व के अन्य देशों में भी देखा जा सकता है, परंतु भारत में यह सर्वाधिक है। भारत के दलाल वर्गो की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। देश भक्तों तथा परिवर्तनवादी शक्तियों का कार्य पहले से अधिक कठिन हुआ प्रतीत होता है।

फोरम की असलियत जैसे-जैसे खुल रही है, तो इसमें शामिल शक्तियों में से कुछ में बेचैनी भी पैदा हो रही है। अनेक गांधीवादी संगइनों व सर्वसेवा संघ के नेतागण इसलिए हैदराबाद सम्मेलन से भी अलग हट गए। कई समाजवादियों में भी बेचैनी बढ़ गई है। परंतु फिर भी हमें जागरूक रहना होगा।

फोरम और साम्राज्यवाद

फोरम के पहले तीन वार्षिक सम्मेलन ब्राजील में पोर्तो एलेग्री में किये गये, जहां उसमें तरह-तरह के संगठनों/व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। ब्राजील तथा अन्य दक्षिणी अमरीका के देश भारी कर्जे में डूबे हुए हैं तथा सभी सरकारें इसी कर्जे को वापस करने के लिए साम्राज्यवादी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पैसा लेने जाती हैं तथा कोष उन पर अपना चिरपरिचित संरचना/समायोजन की योजना लागू करता है जिससे सरकारी खर्चे में कमी, निजीकरण तथा जन कल्याण की योजनाओं में कटौती को लागू करना पड़ता है। इन सभी देशों में आम जनता के शोषण की धार बहुत तेज हो गयी है जिससे पूरे महाद्वीप में विरोध आंदोलन तेज हो गये हैं। विश्व साम्राज्यवाद को इस महाद्वीप में खतरा उत्पन्न हो गया है। फोरम के ब्राजील में सम्पन्न तीसरे सालाना अधिवेशन में 35 लाख डालर व्यय होने का अनुमान था। केवल 8 लाख डालर भागीदारों के रजिस्ट्रेशन फीस से प्राप्त हुआ। ब्राजील की दो प्रादेशिक सरकारों ने कुल मिलाकर 6 लाख डालर दिये। फोर्ड फाउन्डेशन ने 5 लाख डालर, ब्राजील सरकार के स्वामित्व वाले बैंक आफ ब्राजील तथा पेट्रोबास तेल कम्पनी ने 7 लाख डालर दिये।

कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि समूची बैठक में ब्राजील के गैर सरकारी संगठन छाये रहे तथा वहां के संसदीय वामपंथ ने इसका प्रयोग अपनी नई नीतियां प्रसारित करने के लिए किया।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, जिनके चुनाव पर यह सोचकर खुशियां मनाई गई थीं कि यह जनता के राष्ट्रपति हैं, फोरम की बैठक का उद्घाटन करने के तुरन्त बाद ही विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के लिए कूच कर गये।

'विश्व आर्थिक फोरम' विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों, उनके सिद्धांतकारों संक्षेप में विश्व की नई साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया है जिसकी सालाना बैठक स्विट्जरलैण्ड देश के दवोस नाम के नगर में हर वर्ष होती है। यहां विभिन्न राजनेताओं को आमंत्रित किया जाता है, प्रत्येक देश पर किसी वर्ष सघन चर्चा होती है। उस देश के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों से भी चर्चा होती है।

प्रत्येक बारी-बारी से जाकर अपने विचार रखता है और आमतौर पर यह घोषणा करता है कि वह वर्तमान आर्थिक पद्धतियों तथा नीतियों से सहमत है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने फोरम के उद्घाटन के तुरन्त बाद दावोस के फोरम में जाकर भाषण दिया। साम्राज्यवाद के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। फोरम की तीसरी बैठक में फ्रांस के कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। आम तौर पर यह समझा जा रहा है कि फोरम के बढ़ते प्रभावों के कारण छोटे साम्राज्यवादी देश भी इसका उपयोग अमरीका जैसे बड़े साम्राज्यवादी देशों के विपरीत नीतियों के प्रचार के लिए कर सकते हैं।

ब्राजील के अन्य पर्यवेक्षक सिण्डी मिल्स्टीन ने फोरम की तीसरी बैठक के बाद यह लिखा कि, "फोरम एक अनौपचारिक तरल प्रक्रिया है इसमें विश्व के प्रभावशाली गैर सरकारी संगठन, जिन्हें 'गैर सरकारी' तथा आंदोलनरत माना जाता है, उन्हें आपसी तालमेल के लिए फोरम संगठित मंच प्रस्तुत करता है।"

विश्व मंच पर इनके एकत्रित होने से यह साफ है कि इनकी शक्ति शीघ्र ही किसी भी राष्ट्र-राज्य से अधिक हो जायेगी। जैसा कि पिछले दो वर्षो में स्पष्ट हो गया है कि इसके विचार-विमार्श का व्यापक असर है तथा इसी से नीति निर्धारण को मार्ग-दिशा भी मिलेगी। अतः बड़े नौकरशाह और गैर सरकारी संगठन फोरम में निरंतर बड़ी तादाद में जाते रहेगें। सामान्य सामाजिक कार्यकलापों की तुलना में इनके पास समुचित पैसा है जिससे ये हर वर्ष इन बैठकों में भाग ले सकेंगे, तथा बैठकों के बीच सांगठनिक कमेटियों के सदस्य की तरह काम कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि एन.जी.ओ. ही फोरम की चर्चाओं के विषयों

को तय करेंगे। वे ही विषय वहां उठाये जा सकेगें जिसमें एन.जी.ओ. की दिलचस्पी हो। इसके अलावा इन गैर सरकारी संगठनों की समुचित आर्थिक सामर्थ्य है जिससे वे सरकारों/निगमों में लगातार अपनी बात प्रचारित कर सकते हैं। बहुधा इन सरकारों/निगमों से ही उनका वित्त पोषण होता है। उनके प्रचार का असर यह होगा कि जो भी परिवर्तन की सोच होगी, वह यथास्थिति को बनाये रखने के लिए ही होगा।

आज के युग में "पानी, शिक्षा तथा यातायात के साधनों की कमी से आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है क्योंकि ये बुनियादी आवश्यकताएं आर्थिक विकास का बुनियादी ढांचा खड़ा करती हैं।"

यह गौर करने योग्य है साम्राज्यवादी निगमों को उत्पाद बेचने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त देश में समुचित आर्थिक विकास हो चुका हो, क्योंकि दिवालिया देश तथा लोग, अच्छे बाजार का कार्य कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्रय शक्ति नगण्य होती है तथा वे विद्रोही भी बन सकते हैं।

इसके विपरीत वर्ल्ड सोशल फोरम सामाजिक न्याय, रोजगार, भोजन तथा मकान की बात करता है जो 'विश्व आर्थिक फोरम' यानि वर्तमान की साम्राज्यवादी नीतियों, से समाप्तप्राय हो जाते हैं। अतः देखने में दोनों फोरम परस्पर विरोधी कार्य कर रहे हैं, परंतु गौर करें तो यह वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। सोशल फोरम वर्तमान सामाजिक-आर्थिक दायरे में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। यह कार्य बिना सामाजिक संबंधों के बदले हुए करना चाहता है अर्थात वर्तमान व्यवस्था के दायरे में। अतः 'अन्य दुनिया भी संभव है' का नारा पहले से ही सीमित कर दिया गया है। यह किसी दूसरी व्यवस्था में बनी अन्य दुनिया नहीं है बल्कि वर्तमान पूंजीवादी शोषणवादी ढांचे के भीतर की दुनिया ही है।

अतः फोरम इसमें व्यापक भागीदारी का इच्छुक है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गठजोड़ का भी, ताकि भागीदारी को व्यापकतम बनाया जाय। इससे लोगों में हिस्सेदारी का भाव जागेगा। जनता की जरूरतों वाली मांगों के इसमें सम्मिलित करने से उनका असंतोष घटेगा तथा भागीदारी से जन-आंदोलन बनने की गुंजाइश घटेगी। और साम्राज्यवादी शोषण का बुनियादी ढांचा ज्यों का त्यों बना रहेगा।

इस समूचे उद्यम में हमारे देश की दिग्गज कम्युनिस्ट पार्टियां, गांधीवादी संगठन, जाने-माने जनसंगठन सभी एक तरफ शामिल हैं।

फोरम के मार्गदर्शक सिद्धांतों की वास्तविकता

वर्ल्ड सोशल फोरम इंडिया-पालिसी गाइड लाइन्स (विश्व सामाजिक मंच भारत-नीतिगत मार्गदर्शन) नामक अंग्रेजी में लिखा दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। नीचे लिखी विवेचना उसी पर आधारित है।

मार्ग दर्शन के प्रावधानों में यह कहा गया है कि :

1. यह फोरम विचारात्मक सोच, लोकतांत्रिक वाद विवाद, अनुभवों के खुले आदान-प्रदान और प्रभावी कार्रवाई के लिए नागर समाज (सिविल सोसायटी) में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों तथा समूहों में तालमेल स्थापित करेगा जो वर्तमान में स्थापित नव-उदारीकरण, साम्राज्यवाद तथा विश्व पर पूंजी के प्रभुत्व के विरोधी है तथा मानव केंद्रित विश्व की संरचना के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

अर्थात्, यह मंच मात्र है, संगठन नहीं, इसका कार्य सामूहिक कार्रवाई करना नहीं है। यह केवल उपरोक्त नीतियों के विरोधी समूहों तथा व्यक्तियों में सम्पर्क स्थापित करेगा। इसके संगठनकर्ता इसे एक ऐसी स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका लक्ष्य निरंतर नये विकल्पों को खोजना है। इसमें पूंजीवाद को खत्म करने का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात यह वैश्विक पूंजीवाद के तहत चलने वाली स्थायी प्रक्रिया है।

2. यह एक विश्व प्रक्रिया के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है। (WSF is a World Process)

उपरोक्त दोनों बिंदुओं से यह झलकता है कि इसमें शामिल लोग, विश्व व्यापार संगठन को स्वीकार करते हैं या करने के लिए बाध्य हैं। विश्व व्यापार संगठन का खुला विरोध कहीं नहीं किया गया है।

3. फोरम यद्यपि यह कहता है कि इसमें दिये प्रस्ताव वैश्विक पूंजीवाद की प्रक्रिया जिसमें चालक शक्ति बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तथा वे सरकारें तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जो इनकी सेवा में लिप्त हैं, के विकल्प प्रस्तुत करेंगे जो इस प्रक्रिया के विरोध में हैं। परंतु अगली लाइन में इसका मायने, यह कह कर स्पष्ट किया गया है कि ये विकल्प इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वैश्विक एकता विश्व इतिहास के नये चरण के रूप में स्थापित होगी, उसकी सीमाएं भी यह कह कर बांध दी गयी हैं कि ऐसे विश्व में यह व्यवस्था वैश्विक मानव अधिकारों तथा समस्त राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करेगी, पर्यावरण का ध्यान रखेगी। सामाजिक न्याय, जन की सार्वभौमिकता, तथा समता के सेवार्थ, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथापि संस्थाएं लोकतांत्रिक आधार पर कार्य करेंगी। अर्थात वर्तमान विश्व व्यवस्था को स्वीकारने, इसी के तहत ऊपर लिखे अक्षरों को प्राप्त करने का प्रयास फोरम करेगा। कृपया गौर करें इसमें राष्ट्रों की सार्वभौमिकता की बात नहीं की गई है बल्कि व्यक्तियों की।

4. फोरम केवल समन्वय का कार्य करेगा तथा नागर समाज (सिविल सोसाइटी) के विभिन्न संगठनों को साथ लाकर उनमें सामंजस्य स्थापित करेगा। परंतु यह अपने आप में संगठन नहीं है न ही इसके स्वयं की किसी विषय पर कोई अलग राय होगी। फोरम की चर्चा में भाग लेने वाले संगठन एक इकाई या संगठन के रूप में न वोट से न ही हर्ष ध्वनि से किसी घोषणा या प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। इससे अंतर नहीं पड़ता कि यदि इस घोषणा के प्रस्ताव से सभी प्रतिबद्ध हों तो भी यह फोरम के निर्णय के बतौर नहीं माना जायेगा।

यद्यपि भागीदार संगठन आपस में तालमेल करने अथवा किसी कार्रवाई पर यदि सहमत हों तो उनके फैसलों को फोरम वितरित करेगा। यह वितरण उन संगठनों के नाम से ही होगा।

उपरोक्त से तात्पर्य है कि फोरम केवल एक विचार-विमर्श का संगठन है न कि सामूहिक रूप से कार्रवाई करने का। संस्थापकों ने इसका ध्यान रखा है। इसका कोई अपना मत या विचार घोषित रूप से नहीं है।

6. फोरम का दावा है कि वह शक्ति का केंद्र नहीं है जिसके नियंत्रण के लिए संघर्ष किया जाय।

7. लेकिन फोरम इसकी घोषणा अवश्य करता है कि वह गैर-पार्टी, गैर सरकारी, बहु वैचारिक विविधता वाला फोरम है जो स्थानीय से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्य करने वाले संगठनों में सामंजस्य को गैर केन्द्रीकृत आधार पर संगठित करता है।

8. अपने अलग विचार न रखने का दावा करने के बावजूद, उसका यह मानना है कि समाज की समस्याओं का लोकतांत्रिक तरीके से राजनैतिक हल ढूढंना ही फोरम का कार्य है।

इसी तरह एक अन्य विरोधाभास फोरम का यह है कि वह इतिहास के समस्त निरंकुशतावादी तथा अव्याख्यावादी (Reductionist) विचारों का विरोधी है, राज्य पर सामाजिक नियंत्रण के लिए हिंसा के प्रयोग यानि क्रांति करने वाली पार्टियों, का भी वह विरोध करता है।

वह मानवीय अधिकारों के सम्मान, शांतिपूर्ण संबंधों, जनता, नस्लों, लिंग तथा लोगों में समता तथा एकता का समर्थक है और सभी प्रकार के आधिपत्यवाद और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दबाने का विरोधी है।

9. उसका एक अन्य विचार यह भी है कि वैसे तो उसकी बैठकें सभी के लिए खुली हैं सिवाय उन संगठनों के जो हिंसा को एक राजनैतिक कार्रवाई मानते हैं अथवा नस्ल, धर्म तथा जाति पर आधारित संगठन हैं।

10. एक अन्य प्रावधान के अनुसार, फोरम में उन सभी तबकों के लिए स्थान बताया जाना चाहिए जो साम्राज्यवाद तथा नव-उदारवादी नीतियों से संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे साथ-साथ आकर अपनी सोच और संघर्षों की अभिव्यक्ति कर सकें। इसमें किसानों, मजदूरों, विद्यार्थी, शिक्षाविदों, अधिकारी, दलितों, स्त्रियों, खोमचेवालों, स्थानीय व्यवसायी, बेहतर नौकरशाह इत्यादि राज्य के भीतर तथा बाहर दोनों स्थानों से लिए जाने चाहिए। विशेषरूप से उन सभी हिस्सों को हिस्सेदार बनाना चाहिए, जिनकी मौजूदगी समाज में दर्ज नहीं होती, सीमान्त, अप्रतिष्ठित तथा शोषित।

11. फोरम ने अपने आपको साम्प्रदायिक फासीवाद तथा कट्टरपंथ विरोधी भी बताया है। यह अत्यंत चिन्तित है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिवर्तनकारी शक्तियों को साम्प्रदायिकों से मिल रही चुनौती के मुकाबले के लिए इस प्रकार के संगठनों की इस विषय में चर्चा करवाकर, उन्हें एक इकट्ठे तथा विदेशी अनुभवों (साम्राज्यवादी हथकंडों?) से सीखने की सलाह दी है।

12. फोरम का दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि यह क्रिया केवल घटनाओं पर नहीं बल्कि देश भर में अलग-अलग होने वाली गतिविधियों पर भी लागू होती है। ये सभी प्रक्रियाएं खुली, सबको सम्मिलित करने वाली तथा लचीली होंगी और इनका उद्देश्य स्थानीय संगठनों तथा आंदोलनों को मजबूर करना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह कार्य कैसे किया जायेगा।

फोरम का इस बात पर जोर है कि इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों का वर्तमान में लागू आर्थिक नीतियों पर विचार जानना बहुत आवश्यक है तथा यह भी कि साम्राज्यवादी नीतियों का जनता के दैनिक जीवन पर क्या असर है तथा लोगों की इस विषय में सोच को सामने लाना आवश्यक है।

13. फोरम यद्यपि स्थानीय संसाधनों से गतिविधियों के संचालन की बात करता है परंतु वैश्विक एकता के लिए बाहरी संसाधानों को मुहैया कराने पर भी जोर देता है। इसलिए कार्पोरेट सेक्टर से भी अनुदान लेने से नहीं हिचकता।

इसका अंतिम तथा 19वां प्रावधान महत्वपूर्ण है। फोरम भागीदार संगठनों को अपने कार्यो तथा मुद्दों को वैश्विक नागरिकता के आधार पर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। फोरम का यह भी प्रयास है कि इन संगठनों द्वारा नये विश्व का निर्माण करने के लिए खोजे गये परिवर्तनवादी तौर तरीकों को वैश्विक स्तर पर विचार के लिए प्रस्तुत करें।

दो फोरमएक लक्ष्य

फोरम ने प्रारंभ से ही अपने को 'नागर समाज (सिविल सोसाइटी) के फोरम के रूप में प्रस्तुत किया है। परंतु 'नागर समाज' की सोच समाज में वर्गो के बुनियादी भेद, वर्गो की सीमाओं, उनके पारस्परिक हितों के टकराव, परस्पर विरोधी अभिव्यक्तियों को दरकिनार कर देती है जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं है। सवाल है कि एक ही 'नागर समाज' में शोषक तथा शोषित, स्वामी तथा श्रमिक, उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित को एक वर्ग में कैसे रखा जा सकता है?

यह प्रचार है कि दोनों परस्पर विरोधी तत्वों को एक ही खेमे का सदस्य बना दें।

'नागर समाज' की राजनीति आज विश्व बैंक की अधिकृत राजनीति है। विश्व बैंक 2000/2001 की विश्व विकास रपट में कहा गया है :

"वित्तीय संस्थाओं को अपने साधनों का प्रयोग 'नागर समाज' के विभिन्न संगठनों विशेषकर निर्धनों के प्रतिनिधि संगठनों से खुले, नियमित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिये। विभिन्न समूहों को औपचारिक तथा अनौपचारिक मंचों से साथ-साथ लाकर, उनकी ऊर्जा को खुले संघर्षों के स्थान पर, राजनैतिक प्रक्रियाओं की ओर मोड़ना चाहिये। इससे सामाजिक विखराव घटाने में सहायता मिलेगी।

संक्षेप में विश्व पटल पर आज दो संगठन कार्यरत है 'विश्व आर्थिक फोरम' तथा 'विश्व सामाजिक फोरम'।

पहला आज से 15 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था जो साम्राज्यवाद के वर्तमान दौर की नीतियों के विचार विमर्श का केन्द्र है। जहां हर वर्ष इस व्यवस्था के सिद्धांतकार एकत्रित होते हैं, विचार-विमर्श करते हैं तथा हर वर्ष किसी न किसी देश पर, उनके शासकों के राजनयिकों, सिद्धांतकारों को बुलाकर, चर्चा करते हैं। इस फोरम का भारत जैसे सभी देशों के नीति निर्माण पर सहज असर होता है क्योंकि यहां साम्राज्यवाद के वर्तमान दौर की नीतियों पर बृहत् चर्चा होती है। यहां विश्व के स्वामी मौजूद होते हैं।

दूसरी ओर सोशल (सामाजिक) फोरम है जो उपरोक्त फोरम द्वारा बनायी नीतियों को लागू होने से जन्मी बदहाली की परिस्थितियों को घटाने को प्रयत्नशील रहता है। इसके मुख्य कलाकार एन.जी.ओ. हैं। जो साम्राज्यवादी पैसे से चलते है। इस लिहाज से देखने में ये अलग-अलग तबकों में कार्यरत हैं लेकिन एक साथ मिलकर एक पूरक की तरह समूची विश्व व्यवस्था का संतुलन कर रहे हैं।

विश्व बैंक ने हाल ही में 'भागीदारी लोकतंत्र' का नारा दिया है। बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय विभाग खोला है जिसकी देख-रेख में इस कार्यक्रम को 26 देशों में लागू किया जा रहा है।

'भागीदारी लोकतंत्र' का भी यही लक्ष्य है कि लोगों की ऊर्जा को ऐसे रास्तों में लगाया जाय जिससे खुला संघर्ष रोका जा सके।

इसी पर 'भागीदारी बजट' को भी बैंक ने मान्यता दी है। यह तरीका ब्राजील के एक शहर में लागू किया जा चुका है। यह बजट

किस प्रकार का है? पोर्टोएलीग्री-जहां फोरम के पहले तीन अधिवेशन हो चुके हैं, के म्युनिसिपल बजट के 17 प्रतिशत पर विभिन्न संगठन अपनी राय रखते हैं। इन सीमित राशियों पर विभिन्न संगठन अपने अपने दावे रखते हैं तथा आपस में निरंतर बहस करते हैं। इस प्रकार आम जनता की मांगों को मानने की जिम्मेदारी अपने स्वयं से हटाकर शासक वर्ग दूसरों पर डाल देते हैं तथा जन आलोचना से मुक्त हो जाते हैं। व्यवस्था की जन आक्रोश से रक्षा हो जाती है।

इन सभी लुभावने नारों का सार तत्व केवल इतना है कि इन कार्रवाइयों से जनता को यह लगे कि स्थिति सुधारने का मौका मिल रहा है, ताकि वह विद्रोही न बने।

सभी प्रावधान कुल मिलाकर भूमण्डलीकरण के स्रोत की ओर ले जाते हैं, असंतोष शांतिपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त हो तथा साथ मिलकर कोई कार्य न हो, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है।

एक लक्ष्य के नए वाहकएन.जी.ओ.

इस समूचे कार्य को सम्पन्न करने का वाहक हैगैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)।

साम्राज्यवाद के वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी ने एक नया प्रचार अभियान, जो देखने में बहुत संस्कारित परंतु वास्तव में गुमराह करने वाला है को अपनाया है।

इसमें परिवर्तनवादी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तथा इसे लागू करने का वाहन गैर सरकारी संगठन हैं।

इन संगठनों की नई शब्दावली है जनता के वंचित हिस्सों का 'सशक्तिकरण', 'नागर समाज', राज्य विरोध, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, पहचान के आंदोलन, भागीय (जैसे जाति सम्प्रदाय) आन्दोलन, स्वयंसेवा, सामुदायिक विकास, भागीदारी लोकतंत्र, पर्यावरण ह्रास इत्यादि। यही शब्दावली आज विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों की भी हो चुकी है।

साम्राज्यवादी देशों के निगम तथा संगठन, जो भूमण्डलीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं वे ही इस फोरम तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

इतिहास इस बात का गवाह है कि उत्पीड़न तथा सुधार यानी उत्पीड़ित को मरहम पट्टी लगाना, एक साथ किया जाता है। एक ओर जबर्दस्त नरसंहार, शोषण तथा आतंक लादा जाता है तथा दूसरी ओर जन हितैषी कार्यक्रम भी परोसे जाते हैं। ईराक में यही किया जा रहा है। अन्य देशों के अंदर भी यही किया जाता है। विश्व बैंक के अनुदान से बड़े-बड़े बांध बनाये जाते हैं, तथा वही बैंक ऐसे संगठनों की सहायता करता है जो पुर्नवास तथा मुआवजे की लड़ाई लड़ते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम एक ओर तो पेड़ों की जबर्दस्त कटाई करते हैं तथा दूसरी ओर पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठन को खड़ा करते हैं।

भूमण्डलीकरण को दक्षिणी अमरीका के देशों पर सबसे पहले लादा गया था, जिससे सबसे पहले इन्हीं देशों में इसके विरोध में संघर्ष प्रारंभ हुए। इसके बाद ही वहां एन.जी.ओ. की संख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई।

बोलिविया में 1980 तक 100 एन.जी.ओ. थे, 1992 तक इनकी संख्या बढ़कर 530 हो गई। 1991 में इन्हें 7380 लाख डालर (1 डालर-50 रू.) विश्व बैंक तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों से मिले। विश्व के 24 सबसे समृद्ध देशों के संगठन, ओ.ई.सी.डी. के आंकड़ों के अनुसार सदस्य देशों में लगभग 4000 एन.जी.ओ. कार्यरत थे जो प्रतिवर्ष रू. 1500 करोड़ खर्चा कर रहे थे। उस समय एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका में, सन् 2000 के अनुमानों से 50,000 एन.जी.ओ. कार्यरत थे। इनका वार्षिक बजट रू. 40,000 करोड़ है।

परन्तु यह बहुत कम करके आंका गया है क्योंकि केवल भारत में, मार्च 31,2001 के आंकड़ों के अनुसार, 22,924 गैर सरकारी संगठन थे जिन्हें विदेश से पैसा मिल रहा था। उन्हें रू. 4535.23 करोड़ इस वर्ष मिले थे जो, उसके पूर्व वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक था। भारत सरकार ने भी सातवीं योजना में रू. 380 करोड़ गैर सरकारी संगठन के लिए आबंटित किये थे।

इन संगठनों को गैर सरकारी संगठन कहना सरासर गलत है। वास्तव में इनका समस्त वित्त पोषण साम्राज्यवादी सरकारें तथा उनकी एजेंसियों द्वारा ही होता है। ये साम्राज्यी पूंजी के चाकर हैं इनके द्वारा साम्राज्यवाद समाज को अपनी ओर मोड़ना चाहता है।

भूमण्डलीकरण के दौर में गैर सरकारी संगठन का मुख्य कार्य सामाजिक हस्तक्षेप है। वे जनता की क्षमता में वृद्धि, उनकी क्षमताओं के विकास, सामाजिक जागरूकता, पूंजीवाद से पूर्व के अवशेषों से संघर्ष करना, आदि से लेकर विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष, डब्ल्यू. टी.ओ. तथा अन्य एजेन्सियों से वार्ता करते हैं और उनको सुधार का कार्यक्रम मानने के लिए प्रेरित करते हैं।

आज ये भूमण्डलीकरण तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभुत्व के पूंजीवाद, के विपरीत असर यानि प्रतिक्रिया को घटाना चाहते हैं। लादा हुआ नहीं बल्कि 'भागीदारी भूमण्डलीकरण' यानि लोगों को इस प्रक्रिया को स्वीकार्य करवाना चाहते हैं, जिससे जनता का साम्राज्यवाद के विरोध में क्रोध घट जाये।

संक्षेप में एन. जी. ओ. के लक्ष्य इस प्रकार हैः-

1. गैर सरकारी संगठन लोगों का गुस्सा संवैधानिक, शान्तिपूर्ण तथा अशक्त या नपुंसक रास्तों की ओर मोड़ता है। इस प्रकार सुरक्षा कवच का काम करते हैं।

2. उत्पीड़ित जन को ये कई हिस्से में बांट देते है जैसे लिंग पहचान, इत्यादि, जिससे उत्पीड़ित की वर्गीय एकता नहीं बन पाती है।

3. इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक अवयवों (भागों) को जैसे लिंग (महिला), जाति (दलित), नस्ल (अदिवासी), राष्ट्रीयता इत्यादि को इन्हीं के भीतर के उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित के साथ जोड़ कर, उनके वर्गीय विभाजन को अस्वीकार कर देते हैं।

4. वे उत्पीड़तों में यह भावना पैदा करते हैं कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है तथा उसकी अन्तिम जीत हो चुकी है। परिवर्तनवादी दर्शन ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिये वर्तमान को अन्तिम मानकर उसी में सुधार करने का प्रयास करना चाहिये। 'मानवीय चेहरे वाला भूमण्डलीकरण' को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5. वे राज्य विरोधी सोच को प्रचारित करते हैं, अन्तरराष्ट्रीय पूंजी के व्यापक तथा ऊँचे स्तर पर राजकीय उद्योगों के निजीकरण चाहते हैं तथा ये स्वयं सेवा, सहयोग, सामुदायिक विकास इत्यादि की बात करते हैं। इस प्रकार राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के प्रति जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है तथा इन सबको निजी व्यक्तियों के हाथों सौंप दिया जाता है। इसे आन्ध्र प्रदेश में साफ देखा जा सकता

है जहाँ चन्द्र बाबू नायडू, गैर सरकारी संगठन की भाषा बोल रहे हैं तथा उन्हें बुलाकर इस कार्य को सम्पन्न करा रहे हैं।

6. वे जनता को अराजनैतिक बनाने का प्रयास यह कह कर करते हैं कि हमें गैर पार्टी कार्यकर्ता बनना है। गैर पार्टी-गैर राजनीति की सोच द्वारा, गैर सरकारी संगठन वर्तमान की यथास्थिति को बनाये रखने का काम करते हैं।

7. अपनी परिवर्तनवादी शब्दावली तथा वाकपटुता से वे जन में वैचारिक रहस्य का ताना-बाना बुन देते हैं जिससे सच जानना अत्यन्त कठिन हो जाता है और साम्राज्यवादी पूंजी की लूट का रास्ता सुगम हो जाता है।

8. गैर सरकारी संगठन अपने को पार्टियों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपनी जनहित की शब्दावली को अपने स्वयं को परिवर्तनकामी संगठनों के विपरीत, शोषितों के हिमायती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आखिर वर्ल्ड सोशल फोरम बनाने की क्या आवश्यकता है?

इसे जानने के लिए वर्तमान में साम्राज्यवाद के तौर तरीकों को समझना आवश्यक है।

वर्ल्ड सोशल फोरम क्यों ?

साम्राज्यवाद का वर्तमान नारा है भूमण्डलीकरण। भूमण्डलीकरण के मायने हैंसाम्राज्यवादी पूंजी (तथा अन्य पूंजी भी) को दुनिया भर में निवेश करने का अधिकार होना चाहिये। उत्पादों के आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिये। कोई भी देश इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है कि वह अपना कच्चा माल निर्यात नहीं करेगा तथा केवल तैयार माल का ही निर्यात करेगा।

प्रत्येक देश तटकरों को लगातार घटाएगा और किसी भी उत्पाद के आयात-निर्यात पर रोक नहीं लगायी जायेगी। चूंकि अमरीका, जापान, यूरोप सरीखे देशों में उत्पादन और उत्पादकता का तेज विकास हुआ है, हर कारखाने में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है जो बेकार जा रही है। इन सभी देशों को भारत, चीन तथा एशिया, अफ्रीका के अन्य देशों द्वारा विभिन्न उत्पादों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है तथा काफी क्षेत्रों से पीछे हटना पड़ा है। धीरे-धीरे इन देशों ने तकनीक का विकास भी किया है। मोटर कार, मशीन उद्योग, अन्तरिक्ष मेंउपग्रह भेजना इत्यादि में महारत प्राप्त कर ली है। यदि यह विकास इसी प्रकार होता रहता तो ये देश कालान्तर में आज के विकसित देशों के बराबर आ जाते।

इसीलिये तीसरी दुनिया के देशों में विकास को रोकने तथा अपने उत्पादों को स्थापित कर लाभ कमाने के लिए यह जरूरी है कि ये देश इस प्राविधान को कि उत्पादों का व्यापार बेरोकटोक हो, लागू करे। इस प्राविधान को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा लागू किया जा चुका है।

इसलिये आस्ट्रेलिया का सेब, फ्रान्स का फर्नीचर, न्यूजीलैण्ड की क्रीम तथा मक्खन, वहां के कच्छे-बनियान, अमरीका के बने जूते, स्विजरलैण्ड का दूध इत्यादि बड़ी मात्रा में भारत में आयातित हो रहे हैं। डब्ल्यू. टी. ओ. के तहत किसी माल के उत्पादन का आयात प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता तथा तटकर लगातार घटाया जाना है, इसलिये विदेशों में निर्मित सामान, जो फेंक दिये जाते या उत्पादित नहीं किये जाते थे वह अब भारत सरीखे देशों में निर्यात किये जा रहे हैं। भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ता जा रहा है। साफ्टवेयर निर्यात से जो पैसा कमाया जाता है, वह आयात के खर्चे उठाने में वापस चला जाता है। इसके बावजूद भारत का व्यापारिक घाटा पूरा नहीं हो पाता है।

कई बहुदेशीय कम्पनियां जो भारत में कई उत्पाद बनाती थीं, अब उन्हें भारत में बनाना बंद कर रही है और सीधा अन्य देशों में स्थापित कारखानों से ला रही हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया, अनेक देशों में हो रही है। भारत में कई प्रकार की विदेशी मोटरों तथा अन्य साज सामान पुनः बड़े-बड़े हिस्सों में लाकर यहां जोड़कर बेचा जा रहा है, इससे भारत में औद्योगिक निर्माण घटना शुरू हो रहा है और निर्यात के देश जो अधिकांश यूरोप, अमेरिका तथा जापान जैसे हैं, में औद्योगीकरण बढ़ रहा है। यह इसीलिये संभव हो रहा है क्योंकि आयात पर कर बहुत कम हो गया है भारत में आयात करना यहां निर्माण करने से अधिक सस्ता पड़ता है।

भूमण्डलीकरण का यह एक लक्ष्य विकसित देशों ने प्राप्त कर लिया है। साम्राज्यवादी देशों में उत्पादक पूंजी निवेश, यानि जिसमें अत्यधिक लाभ हो, की संभावना बहुत घट चुकी है। कुछ विद्वानों की गणना के अनुसार कुल उपलब्ध पूंजी का केवल 1-2 प्रतिशत ही उत्पादक तरीके से निवेशित हो पाता है, बाकी सब खाली है। ये पूंजी मुनाफे के तरीके ढूंढती रहती है, इस सट्टा पूंजी की मांग है कि वह जहां कहीं चाहे वहां निवेशित करे तथा मुनाफा कमा अपने देश वापस लौटे या केवल मुनाफे को, बिना कर दिये बाहर ले जाये। इस प्रावधान के तहत विदेशी वित्तीय संस्थाओं तथा प्रकार के फण्डों ने भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी लगानी प्रारंभ कर दी है। इस मांग को भी डब्ल्यू. टी. ओ. के तहत भारत जैसे देशों ने स्वीकार कर लिया है। परिणामस्वरूप भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों के अधिकांश ऐसे शेयर जो किसी बड़े हिस्सेदार के पास नहीं है, का स्वामित्व विदेशी वित्तीय संस्थानों के पास है।

यह पूंजी कभी भी अपने हिस्से बेचकर देश के बाहर पलायन कर सकती है। यह पलायन केवल आर्थिक कारणों से हो सकता है और जरूरत पड़ने पर राजनैतिक दबाव डालने हेतु भी। इसी से मिलता जुलता एक अन्य तरीका यह भी है कि विदेशी कम्पनियां जिन्हें एक समय भारत में अपनी अंश पूंजी बेचकर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराना पड़ा था, उन्हें अब इस बात की रट है कि वे बाजार में बचे हुए अन्य अंश खरीद सकते हैं तथा अपनी कम्पनी को सूचीबद्ध करा सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इससे न भारतवासियों को कम्पनी के कार्यकलाप वार्षिक रिपोर्ट देने की जरूरत है तथा न ही लाभ में उन्हें हिस्सा। समूचा लाभ विदेशी कम्पनियां बाहर ले जायेंगी।

उनकी देखा देखी भारत के पूंजीपति वर्ग के उस हिस्से ने जो सारा पैसा स्वयं जेब में डालने में विश्वास रखता है, उसने भी यही रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप भारत में पूंजीवाद का आधार संकुचित होता जा रहा है। अस्सी के दशक में भारत में अंश पूंजी खरीदने वालों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गयी थी। अब यह घटकर 50 लाख से भी कम रह गई है। पूंजीवादी दायरे में लोगों की संख्या घट गई है। इसका सामाजिक आधार संकीर्ण हो गया है।

इस प्रक्रिया के परिणामों परन हम बाद में विचार करेंगे। अभी अपने विषय से न भटकते हुए, यह बताना आवश्यक है कि भूमण्डलीकरण

का सारतत्व यही खाली पूंजी है, जो सट्टा करने के लिये समूचे सौर मण्डल में विचरण करना चाहती है। उसे यह छूट डब्ल्यू. टी. ओ. के द्वारा पूरे तौर पर मिल चुकी है तथा विभिन्न देश, उनकी अर्थव्यवस्था तथा राजनीति, इसी पूंजी के नियंत्रण में आती जा रही है।

खेतिहर क्षेत्र में देखें तो भूमण्डलीकरण से तात्पर्य है खेती के समस्त उत्पादों का स्वतंत्र व्यापार। लेकिन व्यापार तभी स्वतंत्र हो सकता है जब वह तमाम प्रोत्साहनों-अनुदानों से रहित हो जाय। विश्व व्यापार संगठन और अमरीका से संधि के द्वारा भारत ने अपने कृषि को दिये प्रोत्साहन तथा अनुदानों को घटाना शुरू कर दिया है। परन्तु यूरोप तथा अमरीका ने कुछ वर्ष पूर्व, कृषि पर समझौते पर हस्ताक्षर से पहले ही अपने किसानों को प्रोत्साहन तथा अनुदानों की मात्रा बढ़ा दी थी, इससे उनके कृषि उत्पादों का मूल्य काफी कम हो जाता है तथा वे आसानी से भारत जैसे देशों को गेहूं, चावल इत्यादि सभी प्रकार के अनाज सभी प्रकार के अनाज भारतीय किसान के लागत मूल्य से कम में बेच सकते हैं। भारत में यह होना शुरू हो गया है। भारतीय किसान को उचित दाम कृषि उत्पादों के नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत मजबूर किये जाने पर भारत के शासकों को बुद्धि आयी है तथा चीन इत्यादि देशों के साथ मिलकर वे इसका विरोध करने को तैयार हो गये है। जैसे कानकुन सम्मेलन में किया गया।

यह भी भूमण्डलीकरण का ही हिस्सा है। अतः भूमण्डलीकरण से भारत सरीखे देशों की औद्योगिक प्रगति समाप्त होने की ओर अग्रसर है। इसकी पूंजी निरन्तर बाहर जा रही है। सस्ते में निर्यात करना पड़ रहा है तथा कृषि लाभकारी होने के स्थान पर, विनाश की ओर अग्रसर है। स्वाभाविक है कि भारत जैसे देशों की आर्थिक दशा खराब होती जायेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बरबादी होगी। भारत की दुर्दशा एक बार फिर दोहरायी जायेगी। इससे विद्रोही आंदोलन फूटेगा जो इस व्यवस्था को चुनौती देगा।

साम्राज्यवाद का सेफ्टी वाल्ववर्ल्ड सोशल फोरम

यहाँ वर्ल्ड सोशल फोरम की भूमिका प्रारंभ होती है।

भारत की सभी राजनैतिक पार्टियों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी.ओ.) द्वारा स्थापित व्यवस्था को स्वीकृति दे दी है। पूंजीपति वर्ग की दो प्रमुख पार्टियांकांग्रेस तथा भाजपा इसे लागू करने में जुटी हुई हैं। मार्क्सवादी पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ना-नुकुर करते हुए यह मानती हैं कि इससे बाहर नहीं आना चाहिये, बल्कि अंदर रहते हुए इससे ही संघर्ष कर, बेहतर शर्तें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

समाजवादी पार्टी ने यद्यपि अपने उत्तर प्रदेश के 2002 के चुनाव घोषणापत्र में डब्ल्यू.टी.ओ. की कटु आलोचना की थी, परन्तु व्यवहार में उसने उसके विपरीत कोई कदम नहीं उठाया है। अभी तक केवल जबानी जमाखर्च है। क्षेत्रीय पार्टियों में तेलुगू देशम तथा उनके नेता, चन्द्रबाबू नायडू अमरीका के अत्यन्त प्रिय हैं। दोनों द्रविण मुनेत्र कषगम पार्टियां, शिव सेना, अकाली दल इत्यादि नयी आर्थिक योजनाओं को लागू करने तथा डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुसार कार्य करने में जुट गये है। सभी स्थानों पर डब्ल्यू.टी.ओ. की काली छाया देखी जा सकती है। कारखाने बड़ी तादाद में बंद हो गये हैं। उनका स्थान दूसरे उद्योगों ने नहीं लिया है। बेरोजगारी में दिन दूनी-रात चौगुनी वृद्धि हुई है।

इसको विदेशी पूंजी निवेश, तथा कृषि उत्पादों की खरीद से फौरी तौर पर पर कुछ स्थानों पर, थोड़ा कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इसका विपरीत असर इतना है कि इस प्रकार के प्रयासों का प्रचारात्मक असर ही है। और युवाओं की विदेश तृष्णा बढ़ाने का ही कार्य कर रहा है।

भारत में दुर्दशा से उपजी समस्याओं के कारण स्वयंस्फूर्त आंदोलन सभी स्थानों पर खड़े हो रहे हैं। सभी वर्ग जहाँ-जहाँ मौका मिल रहा है तथा देखने में छोटी मांग पर ही संघर्ष कर, बुनियादी असंतोष की अभिव्यक्ति कर रहे हैं।

इन संघर्षों से बड़ी पार्टियां तथा उनसे सम्बद्ध जन संगठन आम तौर पर लापता हैं। कभी कभार स्थानीय स्तर पर कोई संगठन मजबूरीवश बोल पड़ता है। यदि ये आंदोलन भी करते हैं तो केवल अपना जन समर्थन बचाने के लिए, न कि व्यवस्था विरोधी आंदोलन की तैयारी करने के उद्देश्य से।

जैसी कि आशा थी उसी के अनुरूप ये पार्टियां अपना जन समर्थन खोती जा रही हैं। जनता नये नेता, संगठन, विचारों को तलाश रही है और ये उसे मिलने भी शुरू हो गये हैं।

यही विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्थापित विश्व व्यवस्था को सर्वाधिक खतरा है।

इस प्रकार के खतरे को बहुत पहले साम्राज्यवादियों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन, बिहार आंदोलन इत्यादि और उसके बाद के घटनाक्रम में देख लिया था। इसका मुकाबला करने के लिए विदेशी सहायता से चलने वाले गैर-सरकारी संगठनों की स्थापना शुरू कर दी थी तथा सत्तर के दशक के अन्त में ही देश के विभिन्न विशेषकर पिछड़े तथा अविकसित इलाकों में व्यापक रूप से धन आना प्रारंभ हो गया था। बम्बई शहर को भी इसका प्रमुख केंद्र बनाया गया था।

अस्सी तथा नब्बे के दशक में ही ये संगठन समूचे देश में फैल गये थे इन सभी प्रकार के कार्यो में हिस्सा ले रहे थे। उनकी रणनीति बहुत सरल तथा साफ थी।

सुधार के कार्य एनजीओ की प्राथमिकता है। सुधार का तरीका परजीवी बनाने का था। वे किसी को भी, विशेषरूप से पहले से स्थापित सामाजिक कार्यकर्ताओं यदि नक्सल विचार का है या रहा हो, तो उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी भी 'वामपंथी' नारे, भाषण, बातचीत का स्वागत करते हैं। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रौढ़ शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, भूमि सुधार इत्यादि जहाँ जैसी आवश्ययकता हो उसी के अनुसार कार्यक्रम तथा पैसा देने का प्रावधान इन गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) का रहा है। बड़े-बड़े सेमिनार कराना, बौद्धिकों को उसमें आमन्त्रित करना भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा है; वे सभी कार्य जिसमें कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, वह समाज में सिर उठाकर चले, उसके पास कम से कम मध्यमवर्गीय स्तर का जीवन जीने लायक पैसा हो। यह सब एक लिखित परियोजना से बंधा हो।

प्रगतिशील सोच के कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार के संगठनों में जाना आसान होता है, जिनमें देखने में कार्य जनता की भलाई का हो। जहाँ एन.जी.ओ. ही कार्यरत हो वहाँ की जनता को बुनियादी संघर्षो में उतारना कठिन हो जाता है। कार्यकर्ताओं की आदतें तथा तौर तरीके आसान जीवन के हो जाते हैं तथा कार्यकर्त्ताओं की खुद की आदतें, तौर तरीके और सोच सुविधाभोगी मध्यम वर्ग जैसी हो जाती है।

संक्षेप में, आज भारत में विशाल पैमाने पर हजारों करोड़ रुपया

प्रति वर्ष इन्हीं संगठनों में निवेशित किया जा रहा है। ताकि (1) जनआंदोलन सीमित किया जा सके, विस्फोट तक न पहुँचे, (2) सुविधाभोगी सुधारवादी कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या तैयार की जायें, जो आड़े वक्त में ताश के पत्तों की तरह ढह जायें।

आज एन.जी.ओ. से जुड़े कार्यकर्ताओं की संख्या सम्भवतः किसी भी देशभक्त/समाजवादी/कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से कहीं अधिक है। गत तीस वर्षों में इन संगठनों ने शान्तिपूर्ण तरीके से अनेक प्रतिभाशाली संभावनाओं से ओत प्रोत नवयुवकों को बुनियादी परिवर्तन के रास्ते से हटाने का कार्य किया है और उन्हें सुधारवादी सुविधाभोगी जीवन का आसान रास्ता दिखाया है। वर्तमान परिवर्तनकारी संगठनों में केवल बहुत निष्ठा तथा दृढ़ता वाले कार्यकर्ता ही इस प्रकोप से बच सके है।

आज बरसों से पाले पोसे गये इन कार्यकर्ताओं को एक नयी भूमिका अदा करनी है। आज इनकी यह जिम्मेदारी है कि वे भारत देश में बढ़ता असंतोष तथा उससे फूटने वाले स्वयंस्फूर्त आंदोलन कहीं संगठित विद्रोह न बन जाये, इसको रोकने का कार्य करना है। ये कार्य राजनैतिक पार्टियों केवल एक सीमा तक ही कर पायेंगी, क्योंकि वे पहले से विश्व व्यापार संगठन से प्रतिबद्ध हैं। अतः आंदोलन में बदलने का कार्य नई गैर-संसदीय परिवर्तनवादी शक्तियां करेंगी। इन्हीं से भारत में संचालित वर्तमान विश्व व्यवस्था को खतरा है।

फोरम की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ऐसे तबकों पार्टियों, संगठनों, व्यक्तियों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, जो परिवर्तनवादी हैं, जिनको जनता में आदर से देखा जाता है। वे शासकों के विरोध में विशिष्ट मुद्दों पर खड़े होते हैं जैसे मेधा पाटकर अथवा वे वामपंथी पार्टियां जो संसदीय रास्ते पर चलती हैं। आज भी कई वामपंथी पार्टियां इसी प्रकार की हैं। वे व्यक्ति जिनकी बौद्धिक क्षमता की जनता में धाक है और सबसे महत्वपूर्ण है, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) जो इस उद्यम की रीढ़ की हड्डी है।

इस प्रयास में फोरम को पर्याप्त सफलता मिली है। हैदराबाद में गत वर्ष सम्पन्न एशिया सोशल फारेम में एन.जी.ओ. के अलावा पार्टी का बिना नाम लिये मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा नेता शामिल थे। अन्तिम सत्र को भाकपा (माले) लिबरेशन ग्रुप के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सम्बोधित किया। मेधा पाटकर तथा शासकों के सामाजिक न्याय का नारा देने वाले वी.पी. सिंह और उन्हीं किस्म के तमाम लोग वहां मौजूद थे।

वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा इस प्रकार समस्त तत्वों को एकत्रित कर, उन्हें मंच बनाकर प्रस्तुत करने से, एक बड़ा तबका एकत्रित हो जाता है जिसकी जनता में समुचित पैठ है, आदर की नजर से देखे जाते हैं तथा अपनी वजहों से वे इस प्रकार के फोरम को मान्यता दे रहे हैं।

इस फोरम को भी पर्याप्त सीमित, यह प्रावधान रख कर किया गया है कि इसका कोई अपना मत नहीं होगा, वैसे यह बात अलग है इस प्रकार का प्रावधान अपने आप में एक मत है, एक बड़ी राजनीति है। लेकिन यह सब इसी घोषणा के तहत किया जा रहा है कि इसका कोई अपना मत/विचार/नीति/संगठन नहीं होगा, ताकि यह संगठन बनाने की प्रक्रिया को रोके। भागीदार संगठन प्रत्येक विषय पर विश्व नागरिक समझ कर अपने विचार रखें। इस प्रावधान से स्वतः ही देश तथा राष्ट्र-राज्य की सोच समाप्त हो जायेगी जो डब्लू.टी.ओ. का लक्ष्य है।

साम्राज्यवादी प्रभाव का देश की आन्तरिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है। लोकत्रांत्रिक अधिकार, चुनाव प्रणाली, संसद इत्यादि तभी सफल होते हैं, जब स्थानीय शासक वर्गों में समुचित सामर्थ्य हो; परन्तु साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप के बाद यह सामर्थ्य क्षीण होती चली जाती है तथा वहां आम तौर पर पर तानाशाही स्थापित हो जाती है। जनता के अधिकार, चाहे पहले भी सीमित थे अब नाम मात्र के रह जाते हैं।

साम्राज्यवादी शोषण, उसका राजनैतिक हस्तक्षेप, स्थानीय शासक वर्गों और उस देश की आम दशा को खराब कर देता है। स्थानीय शासक कठपुतली की भूमिका अदा करते हैं। 1950 से 1980 तक तीसरी दुनिया के जिन देशों से इससे पुराना लोकतांत्रिक ढांचा बना नहीं रह पाता है और साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय जन का शोषण तेज हो जाने, लोकतंत्र का आवरण भी शासक उतार देते हैं। जिन देशों की अमरीका से पूर्व में फौजी सन्धियां रही हैं वे सब तानाशाही राज थे। साम्राज्यवाद के शोषण की तीव्रता जिस हद तक बढ़ेगी, उसी हद तक तानाशाही भी कायम रहेगी। फोरम में एकत्रित संगठन तथा व्यक्ति, यथास्थिति को बनये रखने का साधन मात्र है। इसीलिए यह सब तैयारी की जा रही है ताकि जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार फोरम का उपयोग किया जा सके।

भारत में फोरम की भूमिका

भारत की वर्तमान स्थिति में इस फोरम का कार्य 1. भारत में प्रगतिशील विचारों, परिवर्तनवादी सोच, इत्यादि को सामने लाना है। 2. वर्तमान व्यवस्था से संघर्ष कर रहे समाजवादी या मार्क्सवादी, गांधीवादी सोच के संगठनों को, जो इसके खिलाफ हैं, उनको भी फोरम के पक्ष के प्रगतिशीलों के द्वारा इस फोरम में लाने का प्रयास करना, 3. सभी को वैचारिक स्तर पर सोचने का तथा उन्हें साधन मुहैया कराना; संभव हो तो विदेश यात्रा इत्यादि के प्रलोभनों द्वारा उन्हें 'शिक्षित' करना, 4. यथास्थिति को बनाये रखने के लिए आंशिक प्रगतिशील आंदोलनों का सहायक तत्व बनना। इसमें संसदीय रास्ते पर चलने वाले वामपंथी संगठन तुरंत ही आकर्षित हो गये हैं। कानू सान्याल के नेतृत्व में हाल ही में गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा.ले.) ने यह फैसला किया है कि वे भी इस सम्मेलन में जाकर उसका अन्दर से विरोध करेंगे।

वे सभी संगठन जो रास्ते पर 'प्रगतिशील' समझौतावादी बने रहकर चलना चाहते हैं उनके लिए यह आदर्श मंच बन गया है, 'एक अन्य दुनिया संभव है' के आकर्षक नारे के तहत कई अच्छे संघर्षशील कार्यकर्त्ता/संगठन भी पहुंच सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि फोरम की वास्तविकता सभी को मालूम हो।

अंत में साम्राज्यवाद के वर्तमान दौर में जिसमें विश्व व्यापार संगठन के द्वारा साम्राज्यवादी देशों ने विश्व की भौतिक सम्पदा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास तेज कर दिया गया है, वहां जनता के प्रत्याशित असंतोष/विक्षोभ विद्रोह बनकर न फूट सकें तथा ऐसा होने पर, उसे दबाने के लिए, नाना प्रकार के तौर तरीके तथा संगठन बनाये जायेंगे। इन सबका लक्ष्य साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था की रक्षा करना है।

वर्ल्ड सोशल फोरम भी एक ऐसा ही संगठन बनाया गया है जिसका अर्थ है विश्व व्यापार संगठन के कार्य कलापों के लिए राजनैतिक समर्थन जुटाना। ऐसे उद्यमों से युवा भारत न केवल दूर रहेगा बल्कि उसका विरोध करेगा तथा सभी देशभक्तों से अपील करता है कि इस फोरम का बायकाट करे तथा भागीदारों और संगठनकर्ताओं का जन के समक्ष

भण्डाफोड़ करे।

भारत देश और भारत जनता की विश्व साम्राज्यवाद से लड़ाई आज तेज हो रही है।

सर्व सेवा संघ के 1991 के वर्धा निर्णय के बाद से इस लड़ाई ने संगठित रूप लेना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद से ही समस्त राजनैतिक धाराओं को इस बारे में अपना मत साफ करना पड़ रहा है। गत 12 वर्षों में यह मत साफ उभर कर आ चुका है। समस्त स्थापित पार्टियां साम्राज्यवाद के साथ हैं। साम्राज्यवाद के वर्तमान दौर में जनता को बेहतर जीवन देने का लक्ष्य हासिल करना, इन पार्टियों के लिए असंभव हो गया है। इस दौर के तेज तथा गहरे शोषण में ये पार्टियां जनता को कोई राहत दिलाने की स्थिति में नहीं है। बल्कि उल्टे साम्राज्यवाद के चाकर की भूमिका अदा कर रही हैं।

इन पार्टियों की सोच की सीमाएं हैं। ये वर्तमान व्यवस्था के अंदर जनता को खुशहाल बनाना चाहती हैं। परंतु 1990 के बाद, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान जैसे-जैसे लागू होते गये, वैसे-वैसे, साम्राज्यवादी शोषण बढ़ता गया। इन पार्टियों के समक्ष यह चुनौती कि वे इस गहराते शोषण का मुकाबला करें तथा जनता को राहत दिलायें, इसके लिए चाहे उन्हें अपनी समझ के दायरे को विस्तृत करना पड़े।

जैसा अब साफ है कि वे अपनी स्रोत तथा नीति के दायरे में ही रहकर कार्य करना चाहते हैं। चूंकि राहत दिलाने का रास्ता समाप्त हो गया, पुनः उन्होंने साम्राज्यवाद से ही यारी करने तथा उसमें कुछ गुंजाइश मिलने का रास्ता चुना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एशिया सोशल फोरम और वर्ल्ड सोशल फोरम का रास्ता चुना।

देश में कारखाना बंदी से उत्पन्न स्थिति निरंतर छंटनी, वेतन कटौती, किसानों को उचित मूल्य न मिलना, इत्यादि सभी क्षेत्रों से ये समस्त पार्टियां पीछे हट गई हैं। यह सारा मैदान उन्होंने खाली छोड़ दिया है। जनता को साम्राज्यवाद के हवाले कर दिया है। स्वयं उन्होंने साम्राज्यवाद द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठनों से समझौता कर लिया है।

अतः जन अधिकारों का कुचला जाना, हड़ताल पर पाबंदी का अदालतों का फैसला, उ.प्र. में कारखानों के निरीक्षण का समापन इत्यादि एक सिरे से पहले से प्राप्त जन अधिकारों को सीमित तथा समाप्त करने की नीति का कहीं विरोधी नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी ओर इन्हीं पार्टियों के आम कार्यकर्ता, व्यापक जन तथा नाना प्रकार के जन संगठन, जिनका किसी पार्टी से जुड़ाव नही है, वे सब इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं तथा इस लड़ाई में भारतीय जनता के साथ खड़े हैं। देशी तथा वैश्विक सभी मुद्दों पर ये दोनों पक्ष इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।

इस समय इस संघर्ष का केन्द्र बिंदु वर्ल्ड सोशल फोरम की मुंबई में 9 से 14 जनवरी, 2004 को आहूत फोरम की चौथी सालाना बैठक है।

सवाल है कि साम्राज्यवादियों तथा उनके स्थानीय सर्मथकों द्वारा तैयार मंच भारत का विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, अपनी बैठक में किन जन प्रतिनिधियों को आकर्षित कर सकेगा? क्या भारत की जनता के प्रतिनिधि व जनता के संगठनों के नेता अपनी बिक्री के लिए तैयार हैं?

इस बात का निर्णय इस फोरम की बैठक में होगा। आइये हम सब समूचे देश में फैल कर इसकी असलियत समस्त जनता को बतायें ताकि साम्राज्यवाद और उसके स्थानीय समर्थकों के खिलाफ प्रबल जनमत तैयार हो।

युवा भारत आप सबको इस कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता है।

दायित्वबोध यहां से प्राप्त करें

उत्तर प्रदेश • संस्कृति कुटीर, कल्याणपुर, **गोरखपुर** • जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर** • अक्षरा स्टेशनर्स, स्टशेन रोड, **गोरखपुर** • जनचेतना स्टाल, निकट काफी हाउस, हजरतगंज, **लखनऊ** (शाम पांच से साढ़े आठ) • जनचेतना, डी-68, निराला नगर, आई.टी. चौराहा, **लखनऊ** • विश्वनाथ मिश्र, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग, नेशनल पी.जी.कालेज, **बड़हलगंज**, **गोरखपुर** • शहीद पुस्तकालय, द्वारा, डा. दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर, मऊ** • जनचेतना, 989, पुराना कटरा, युनिवर्सिटी रोड, मनमोहन पार्क, **इलाहाबाद** • सबद, 171, कर्नलगंज (स्वराज भवन के सामने) **इलाहाबाद** • श्री मुचकुंद, प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट,बीएचयू, **वाराणसी** • • करेंट बुक डिपो, 18/53, माल रोड, (फूलबाग के सामने), **कानपुर** • प्रतिभा प्रकाशन, (पेप्सी होटल के नीचे), स्टेशन रोड, **बलिया** • राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, रेणुकूट, **सोनभद्र** • डा. पी.एस. कुशवाहा, ओल्ड हास्टल, सेंट जॉन्स कालेज, **आगरा** • गार्गी विक्रय पटल, 127, न्यू आवास विकास कालोनी, **सहारनपुर**

उत्तरांचल • जनचेतना, ग्राम भदईपुरा, किच्छा रोड, रुद्रपुर, **ऊधमसिंहनगर** • प्रो. प्यारेलाल, 139, फूलबाग कालोनी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, **पंतनगर** • बुक वर्ल्ड, एस्ले हाल, गांधी पार्क के सामने, **देहरादून**

दिल्ली • सत्यम वर्मा, 29, यू.एन.आई. अपार्टमेंट, जीएच-2, सेक्टर-11, वसुंधरा, गाजियाबाद • बुक कार्नर, श्रीराम सेंटर, मण्डी हाउस • गीता बुक सेण्टर, शापिंग काम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय • पत्रिका मण्डप, आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय • पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, मरीना आर्केड, कनाट प्लेस ***नोएडा*** • जनचेतना ठेला, चौड़ा मोड़ (शाम 5 से 8.30), नोएडा

बिहार • समकालीन प्रकाशन, पुस्तक बिक्री केन्द्र, आजाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** • विद्यानन्द सिंह, वार्ड न. 4, **सुपौल**

पंजाब • सुखविन्दर, द्वारा का. दशरथ लाल, म.नं.-14, लेबर कालोनी, गिल रोड, **लुधियाना** • नवा जमाना बुक शाप, नेहरू गार्डन रोड, **जालंधर**

हरियाणा • नरभिन्दर सिंह, शहीद भगतसिंह विचार मंच, हरियाणा, ग्रा.-पो.-संतनगर, जि.-**सिरसा** • पंकज, प्लॉट नं. 33, सेक्टर-15, **सोनीपत**

राजस्थान • चन्द्रशेखर, लोकायत प्रकाशन, 883, लोधों की गली, एम.डी. रोड, **जयपुर** • बुक्स एंड न्यूज मार्ट, एम.आई.रोड, **जयपुर**

महाराष्ट्र • पीपुल्स बुक हाउस, मेहर हाउस, 15, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, **मुम्बई** • वसुन्धरा, 602, हीरानंदानी गार्डन, गेट वे प्लाजा, **पवई** • वि.रा. साथीदार, **नागपुर**

प. बंगाल • पुस्तक केन्द्र, भारतीय भाषा परिषद, शेक्सपियर सरणी, **कोलकाता** • राकेश गोरखा, पाथिभरा पुस्तक पसल, प्रधाननगर, सिलीगुड़ी, **दार्जीलिंग** • जनार्दन थापा, लुकसान बाजार, पो. आ. केरन, जि.-**जलपाईगुड़ी**

आन्ध्र प्रदेश • गोविन्द अक्षय, 'सारस्वत सदन', 13/6/411/2, रामसिंहपुरा, कारवान, **हैदराबाद**

मध्यप्रदेश • जयप्रकाश जायसवाल, 'पितृछाया,' अमृत सागर कालोनी, एम.आई.जी. 96-97, **रतलाम**

छत्तीसगढ़ • चिंचोलकर बुक हाउस, बस स्टैण्ड, **जगदलपुर**, **बस्तर**

वर्ल्ड सोशल फोरम : व्यवस्था की सेवा में जुटा सामाजिक जनवाद

वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में यह टिप्पणी 20-28 फरवरी, 2002 के 'एन मार्चा' से ली गयी है, जो इक्वाडोर की मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी का केन्द्रीय मुखपत्र है। सम्पादक

डब्ल्यूएसएफ में क्रान्तिकारियों और सुधारवादियों के बीच का विभाजन अधिकाधिक प्रकट होता जा रहा है और यह दो अलग-अलग एवं विरोधी लाइनों को प्रस्तुत कर रहा है।

फरवरी के शुरुआती दिनों में, ब्राजीली शहर पोर्तो अलेग्रे में पचास हजार से भी अधिक लोग उस वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए इकट्ठा हुए जो निश्चित रूप से साम्राज्यवाद से लड़कर उसे सुधारने और मानवीय चेहरा प्रदान करने वालों और उसे परास्त कर समाजवाद का निर्माण करने वाले हम जैसे लोगों में स्पष्ट विभेद करता था। यह भूमण्डलीकरण विरोधी आन्दोलनों की जटिलताओं और उन तरीकों को, जिनसे सामाजिक जनवादी धाराएं इसे पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, प्रकट करता है।

सुधार

डब्ल्यूएसएफ स्पष्ट रूप से सामाजिक जनवादियों और यूरोप केन्द्रित समूहों, खासतौर से ब्राजील की वर्कर्स पार्टी, फ्रांस के 'अटैक' और 'एसोसिएशन ऑफ ब्राजीलियन बिजनेसमेन फार द सिटिजन्स' के नेतृत्व के मातहत था। उन्होंने सावधानी से चुने गये संचालक मंडल के साथ आयोजनों और फोरम का वृहद आयोजन किया। वे उनमें 'विविधता के सम्मान' की अपनी डींगों को ताक पर रखते हुए दूसरे विचारों को व्यक्त किये जाने का विरोध करते थे। यह शर्मनाक था कि उन्होंने एफएआरसी (रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस आफ कोलंबिया), फिदेल कास्त्रो, द मदर्स आफ प्लाजा डी मेयो (अर्जेंटीना में गायब कर दिये गये लोगों की मांएं) जैसी महाद्वीप की प्रातिनिधिक शक्तियों को इन आयोजनों में निमंत्रित नहीं किया।

इस तर्क का इस्तेमाल करते हुए कि यह सम्मेलन 'सामाजिक आन्दोलनों और नागरिक समाज का है' उन्होंने इसमें सामाजिक प्रभाव वाले क्रान्तिकारी संगठन के बजाय एक छोटे एनजीओ को आमंत्रित किया। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास तो तब उभरा जब आमंत्रित लोगों की सूची में सरकारों की नवउदारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करने वाले, खास तौर से यूरोपीय राजनीतिज्ञों, विधायकों, मेयरों की उपस्थिति देखी गयी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले फ्रांस, बेल्जियम व पुर्तगाल के मंत्रियों का विरोध स्वयं उनके देशों के प्रतिनिधियों ने किया।

बाद में आलोचनाएं और बढ़ीं क्योंकि आयोजनों पर ब्राजीली सरकार और अंतरराष्ट्रीय (यूरोपीय) फंडिंग वाले एनजीओ का एकछत्र अधिकार था। और यही वजह थी कि स्वयं को वाम का प्रतिनिधि बताने वाले सामाजिक जनवादियों ने मरियल और यहां तक कि लोक लुभावन बयान दिये। उनके बीच लूला और वर्कर्स पार्टी ने अमरीकियों को खुश करने के लिए, जिनकी खूब आलोचना हुई थी, अंतिम वक्तव्य को हलका बनाने के सचेत प्रयास किये। इससे भी अधिक नाजुक मामला तब सामने आया जब वर्कर्स पार्टी और अटैक के नेतृत्व में सीयूटी (ब्राजीलियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन) ने 'दो शैतानों' के सिद्धान्त का, फोरम से बाहर निकल जाने की धमकी देते हुए, समर्थन करना चाहा। इनकी दलील यह थी कि अमेरिका तो "सबसे बड़ा आतंकवादी" है ही, लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ने वाली जनता और ऐसे आन्दोलन भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इस तरह डब्ल्यूएसएफ का अंतिम वक्तव्य न्याय मांगों की सूची है, लेकिन इसमें समाजवाद के लिए संघर्ष का कोई जिक्र नहीं है जो भूमण्डलीकरण और साम्राज्यवाद के प्रतिरोध का एकमात्र रास्ता है। इन जातीय, लैंगिक, पर्यावरण सम्बन्धी, आर्थिक और युगीन (generational) मांगों को कुछ क्रान्तिकारियों का भी समर्थन प्राप्त है, परन्तु जैसा कि हम जानते हैं यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नये समाज के निर्माण की खातिर सत्ता हासिल करने के लिए क्रान्तिकारी संघर्ष आवश्यक है।

यह अन्तर बताता है कि किस वजह से डब्ल्यूएसएफ का अंतिम वक्तव्य अमेरिकी, यूरोपीय, जापानी या अन्य किसी साम्राज्यवाद से लड़ रही जनता के समर्थन में कुछ नहीं कहता। यह केवल 'कार्निवाल' जैसे आयोजनों में भागीदारी करने वालों का नहीं, बल्कि सच्चे संघर्षों में सक्रिय रूप से जुड़े लोगों का गंभीर कर्तव्य है।

आगे बढ़ने के लिए

साम्राज्यवादी वर्चस्व की क्रूर अभिव्यक्तियों का विरोध करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की एकता आवश्यक एवं प्रभावकारी है। इसलिए ऐसे आयोजन जिनमें संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान हो सकता है, हमेशा ही फायदेमंद होंगे। लेकिन तभी जब उनसे क्रान्तिकारी

(पृष्ठ 73 पर जारी)

केवल मजदूर वर्ग ही पूंजीवाद के पिशाच का खात्मा कर सकता है

दि इण्टरनेशनल ब्यूरो फॉर दि रिवोल्यूशनरी पार्टी

इण्टरनेशनल ब्यूरो फॉर दि रिवोल्यूशनरी पार्टी (आईबीआरपी) का 1 मार्च 2001 को जारी किया गया यह वक्तव्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वितरित किया गया था। यह उन्हीं दिनों सम्पन्न 'समिट आफ अमेरिकाज' की एक विस्तृत आलोचना पर आधारित है। वक्तव्य साम्राज्यवादी 'भूमण्डलीकरण' की प्रक्रिया को जन्म देने वाले विश्व पूंजीवाद के अन्तर्निहित संकटों पर रोशनी डालते हुए इसके विरोध के प्रपंच का पर्दाफाश करने का एक प्रयास है।
इस वक्तव्य में, एक स्थान पर चलताऊ ढंग से 'स्तालिनवादी और त्रात्स्कीवादी मिथ्या धारणाओं' से बचने की बात की गयी है जो आईबीआरपी के विचारधारात्मक धुंधलके पर रोशनी डालता है। विश्व सर्वहारा के महान नेता स्तालिन और सर्वहारा क्रान्ति के एक गद्दार त्रात्स्की को एक ही खाने में रख देने की इस सोच से हम कतई सहमत नहीं हैं। कहने की जरूरत नहीं कि पाठक वक्तव्य की इस विचारधारामक सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ेंगे। सम्पादक

इस बदतर दुनिया में पूंजीवाद सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था नहीं है। दरअसल, यह तो दुनिया के कष्टों का अकेला, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 1945 तक चले पिछले साम्राज्यवादी संघर्ष के खात्मे से लेकर अब तक पांच करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग, टाले जा सकने वाले अकालों और तथाकथित "प्राकृतिक आपदाओं" में मारे गए। पिछले दशक में पश्चिम द्वारा इराक की जनसंहारक नाकेबंदी के कारण वहां बीस लाख लोगों को मौत निगल गई है। इस्राइल, फलस्तीन से बाल्कन तक, चेचेन्या, इंडोनेशिया या अफ्रीका तक हम जहां कहीं भी देखते हैं, कत्लेआम जारी है। धर्म और राष्ट्रवाद इस मारकाट के नाममात्र के कारण हैं। असली कारण तो पूंजीवादी शक्तियों के बीच संसाधनों को लेकर मची होड़ है। समृद्धतम पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की दखलंदाजी के कारण ही स्थानीय संघर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल दहला देने वाले नरसंहार बन जाते हैं।

फिर भी, येन केन प्रकारेण, इस सचाई को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि युद्ध क्षेत्रों से बाहर रोजमर्रा की जिंदगी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। वे हमें बताते हैं कि हमने हाल ही में विश्व अर्थव्यवस्था में एक दशक लंबी उछाल दर्ज की है। यह ऐसी उछाल है जिसका अस्सी प्रतिशत जनसंख्या के लिए कोई मायने नहीं है। सच यह है कि उसके जीवन स्तर में इसी अवधि में कटौती कर दी गई है। इसे सरकारी आंकड़ों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यह उस नयी "भूमण्डलीकृत" अर्थव्यवस्था के परिणामों में से एक है, जिसमें निवेश इस या उस भौगोलिक क्षेत्र से मजबूती से बंधा नहीं रहता है। पांच या छह बड़े औद्योगिक केंद्र जो कुल विश्व उत्पादन का पचहत्तर प्रतिशत नियंत्रित करते हैं, बड़ी आसानी से एक प्लांट के नुकसान को बट्टे-खाते में डाल सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे आंतरिक निवेश अनुदान, कर छूट तथा पूंजी की मर्जी की गुलाम एवं असुरक्षित श्रम शक्ति का लाभ उठाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। जहां तक उछाल का संबंध है तो कुछ लोगों ने, जिनका परजीवी वित्तीय बाजारों से संबंध है, पिछले दशक के दौरान बहुत अच्छी उन्नति की है, किंतु उनके और उन्नत पूंजीवादी विश्व के निचले बीस प्रतिशत हिस्से के आम जीवन स्तर के बीच की खाई चौड़ी हुई है।

बहरहाल अमेरिकी शेयर बाजार का बुलबुला अब फट चुका है जिसकी लंबे समय से आशंका थी। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आधा प्रतिशत की कटौती अमेरिका और दुनिया में पनप रही मंदी को कम करने का एक प्रयास है। जापानी बैंकिंग व्यवस्था पहले से ही ढहने की ओर अग्रसर है और पूरी दुनिया के स्तर पर वे हमें एक अगले दौर की बर्बादी व पगारों में कटौती के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। हाईटेक फर्मों में भारी संख्या में छंटनी की घोषणा की गई है (पूरी दुनिया के स्तर पर केवल दस सप्ताह के अंदर अकेले दूरसंचार की कंपनियों में एक लाख रोजगार समाप्त हो गये हैं) और अन्य भी ऐसा ही करेंगी। भूमण्डलीकरण हमें केवल यह याद दिलाता है कि दुनिया भर के उजरती मजदूर एक ही नियति के शिकार हैं और पूंजीवाद के उतार-चढ़ावों की दया पर निर्भर हैं।

'भूमण्डलीकरण' पूंजीवादी साम्राज्यवाद है

आज के भूमण्डलीकरण में वस्तुतः कुछ भी नया नहीं है। यह मार्क्स द्वारा अभिचिह्नित पूंजी के संकेंद्रण की प्रवृत्ति की निरंतरता है, जो बड़े साम्राज्यवादी इजारेदारियों को जन्म देती है। इसी कारण हम आज भी इस युग को साम्राज्यवाद के युग का नाम देते हैं। यानी, साम्राज्यवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी प्रतियोगिता का युग है।

इसमें सिर्फ नया है तो आज के इजारेदार संगठनों के नियंत्रण में पूंजी का अबाध विस्तार। अब सबसे बड़ी राष्ट्रपारीय कंपनियां औद्योगिक पूंजी के बजाय वित्तीय पूंजी के वर्चस्व में हैं। वे दुनिया के लगभग सभी देशों की तुलना में अधिक संपदा का नियंत्रण करती हैं। इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था पर एक नया अंतर्विरोध आरोपित कर दिया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था सारतः राष्ट्र-राज्यों के इर्द-गिर्द संगठित है किंतु इन राष्ट्रों और विशेषकर जो परिधि पर हैं उनका, देश की सीमाओं के अंदर होने वाली घटनाओं पर बहुत ही कम नियंत्रण है। इसी कारण तरह-तरह के सुधारवादी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की लंबी उछाल वाले पुराने भले पूंजीवाद, जिसके अंत का संकेत 1971 में ब्रेट्टनवुड्स समझौते के टूटने पर मिला था, की ओर लौटना पसंद करेंगे। यही सुधारवादी 'अमेरिकाज इन क्यूबेक' की हाल ही में संपन्न शिखर वार्ता, जिसे 'जन शिखरवार्ता' का नाम दिया गया और विगत फरवरी 2003 में पोर्तो अलेग्रे में संपन्न 'दावोस विरोधी' वर्ल्ड सोशल फोरम में भारी संख्या में जुटे थे। किंतु संचय के संकट द्वारा अपने आंतरिक ढांचे तक झकझोरा जा चुका वह पूंजीवाद, जिसे हमने पिछले तीस वर्षों से देख है, अब चुक गया है। अब वह समय निकल चुका है, जबकि शासक वर्ग सापेक्षिक रूप से 'स्वीकार्य' जनसेवाओं और कानूनी सामाजिक सुरक्षाओं को प्रदान करने का (कम से कम धनी देशो में) भार उठा सके। "भूमण्डलीकरण" पूंजीवाद के आम संकट की देन है।

सुधारवादी, जो दावा करते हैं कि वर्तमान उत्पादन प्रणाली का परित्याग किए बिना भी "दूसरी दुनिया संभव है", भलीभांति बहका दिये गए हैं अथवा नागरिकता की अवधारणा पर अधिकाधिक केंद्रित पूंजीवादी मिथ्या प्रचार अभियान के निकृष्टतम "प्रगतिशील" सहयोगी हैं। इस विचार के हिमायती हमेशा से मौजूद रहे हैं कि पूंजीवाद के पुराने ढांचे के जस का तस रहते हुए भी पूंजीवाद के विनाशकारी प्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया जा सकता है। उनकी बासी पड़ चुकी राजनीतिक लाइन यह है कि "नागरिक" कार्रवाई (पूर्णतया हास्यास्पद विचार पर आधारित यह कार्रवाई कि चूंकि हम सभी 'सिविल सोसायटी' में रहते हैं, इसलिए पूंजीवाद में हम सभी बराबर हैं), द्वारा हमारी "एक सभ्य नगर" तक पहुंच हो सकती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह "नगर" केवल अपने सीवर और नालियां हमारे लिए आरक्षित रखता है।

ये नीतियां, जो *ल मोंद डिप्लोमतीक* के अमेरिका विरोधी उदारवादियों तथा 'अटैक' द्वारा जुटाई गई भीड़ द्वारा बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही हैं, समूचे पूंजीवादी वामट्रेड यूनियनों, एनजीओ वालों, नारीवादियों, अकादमिशियनों, सुधारवादी पार्टियों एवं पंथों की विचारधारात्मक ईंट-गारा बन चुकी हैं। यह पोर्तो अलेग्रे में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम से निकली नए सुधारवादी इंटरनेशनल की लाइन है। यह इतनी प्रभावी है कि बुर्जुआ पार्टियां इसका अधिकाधिक प्रयोग कर रही हैं। इस विचारधारा का असली चरित्र 'पीपुल समिट' के उद्घाटन के दौरान देखा गया था जब ये सभी "ईमानदार नागरिक" क्यूबेक की राष्ट्रीय असेंबली के आरामदायक ड्राइंगरूमों में जाम टकराने के लिए इकट्ठे हुए थे। मेजबान कोई और नहीं उन्हीं के "कॉमरेड", क्यूबेक के प्रधानमंत्री बर्नार्ड लांड्री, एक वामपंथी थे जो शासक वर्ग के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। विश्वास मानिये कि उसी लांड्री ने 'रॉकफोर्ट चीज' के अपने शानदार बचाव के लिए "कॉमरेड" बोवे से एकता का हाथ बढ़ाया था। किंतु सारे भाषणों के पीछे से वास्तविकता झांकती रही। इसका खुलासा सस्ती राजनीति करने वाले पोर्तो अलेग्रे के मेयर टार्सो फर्नांडो हर्ज जेनरो की प्रभावशाली घोषणा में किया जा सकता है। उसने कहा था, "न तो पोर्तो अलेग्रे बाजारों के उदारीकरण का विरोध करता है और न ही डब्ल्यूएसएफ।" दरअसल, पूंजीवादी वामपंथी जो चाहते हैं वह हैवार्ता की मेज पर आमंत्रित किया जाना। वे मजदूर वर्ग तथा वर्ग सहयोग को सीमाबद्ध करने में भूमिका अदा करने के काबिल बनना चाहते हैं। यानी कि पूरी मानवता को इस बात का कायल बनाने के लिए कि पूंजीवाद उन पर जो भी अत्याचार करता है, उसकी निंदा की जाती है। सुधारवाद, प्रबुद्ध बर्बरता से अधिक की आशा नहीं करता। यह और अधिक कष्टों और शोषण के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता।

भूमण्डलीकरण विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा किये गये प्रदर्शन उन अवसरों पर आयोजित होते रहे हैं, जहां बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें आपस में उठापटक करती रहती हैं। चूंकि वे संकट प्रबंधन पर बातचीत के लिए एक-दूसरे के पास आते हैं इसलिए वे सभी व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए ऐसे नियम बनते देखना चाहते हैं, जो उन्हें वित्तीय लूट का माल सबसे ज्यादा दे सकें। इस प्रकार प्रचलित मिथकों के विपरीत एमएआई (निवेश पर बहुपक्षीय समझौता), जो राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं के अधिक से अधिक क्षेत्रों को "मुक्त बाजार" की खातिर खोलने के लिए बाध्य करेगा, को कुछ एक कमजोर सुधारवादी संगठनों के पिलपिले घुटनाटेकू विरोध के कारण खारिज नहीं किया गया। वास्तव में, कुछ एक महाशक्तियों, विशेषतया यूरोपीय महाशक्ति की सहमति के कारण समझौते को रद्द किया गया था।

पूर्व सोवियत साम्राज्य के ढह जाने के साथ ही पुराने खेमों का शक्ति-संतुलन बिगड़ चुका है और नई साम्राज्यवादी शक्तियां उनका स्थान लेने के लिए उभर रही हैं। इन शक्तियों में एक यूरोपीय संघ है जो कि 1992 से विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में है। एक दूसरी शक्ति सुदूर-पूर्व, चीन, जापान, कोरिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संस्था (आसियान) के अन्य सदस्यों के इर्द-गिर्द खड़ी हो रही है। सिएटल और प्राग की बैठकें सभी साम्राज्यवादी खेमों और देशों के लिए रणक्षेत्र थीं जबकि 'क्यूबेक समिट' तीसरी दुनिया को एकजुट करने की तैयारी के लिए थी। क्यूबेक बैठक को संचालित करने वाले मुख्य देश (कनाडा, अमेरिका) एक नये "मुनरो सिद्धांत"अमेरिकी मामलों में यूरोपीय संघ की दखलंदाजी का निषेध, जो उन्हें क्षेत्र के राष्ट्रीय बाजारों में अधिकतम पैठ जमाने की और इस प्रकार विश्व-स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्द्धात्मक होने एवं शक्ति की गारंटी देगी, की आशा करते हैं।

क्या करें?

एक बार फिर जनसाधारण की उन ताकतों की आवाजों को असंख्य पगली घंटियां बजाकर खामोश करने की कोशिशें जारी हैं जो इतिहास के लाल डोरों को सहेजने-समेटने में जुटी हुई हैं और मानवता की सच्ची आजादी के मार्ग पर अग्रसर हैं। सभी स्तालिनवादियों और त्रत्स्कीपंथियों के वैचारिक छलावों के विरुद्ध हम आने वाले समाज को कम्युनिस्ट समाज के रूप में परिभाषित करने का काम जारी रखते हैं चूंकि वह वैसा ही होगा। वहां तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत सा

कार्य किया जाना बाकी है। यही वह समय है जब मजदूर वर्ग को अपने औजारों को चमका लेना चाहिए। हमें उस ट्रेड यूनियन वर्ग के भ्रमजाल को तोड़ने की आवश्यकता है जो मजदूरों के हितों और हमारा खून चूस कर पलने वाले पिशाचों के बीच सामंजस्य बनाने का दावा करता है। हमें कारखानों के मजदूरों तथा रिहाइशी इलाकों के लोगों के ही पूर्ण नियंत्रण में उनके संघर्षों से उभरने वाले जुझारू जनसंगठन भी बनाने की आवश्यकता है। अंत में, मजदूर वर्ग को अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना होगा। यानी एक सच्ची कम्युनिस्ट एवं अंतरराष्ट्रीयतावादी पार्टी बनानी होगी। एक ऐसी पार्टी नहीं जो मजदूरों के ऊपर और उनकी ओर से नेतृत्व करेगी, बल्कि एक ऐसी पार्टी जो अपने वर्ग के बीच क्रांति के पूर्व तथा बाद में संघर्ष करेगी और सच्चे कम्युनिज्म के ऐतिहासिक मिशन को सामने रखेगी ।

हम उनके सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हां, एक रास्ता है, इस अंधेरनगरी से बाहर निकलने का"समानता की पुकार पर सुख और न्याय की शक्तियां संगठित हों।"

कम्युनिज्म अमर रहे!

दि इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर दि रिवोल्यूशनरी पार्टी (आईबीआरपी)
1 मार्च, 2001

सीडब्ल्यूओ (कम्युनिस्ट वर्कर्स आर्गनाइजेशन), ब्रिटेन
इंटरनेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इटली
बिलान एत पर्सपेक्टिव्स, फ्रांस
इंटरनेशलिस्ट नोट्स, कनाडा
इंटरनेशलिस्ट नोट्स, अमेरिका
इंटरनेशनलिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, लातिन अमेरिका

व्यवस्था की सेवा में जुटा सामाजिक जनवाद

(पृष्ठ 59 का शेष)

ताकतों की अवधारणाओं को बाहर नहीं रखा जायेगा। इसके अलावा, एक सुस्पष्ट साम्राज्यवाद विरोधी अवस्थिति प्रकट होनी चाहिये, जो एक साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करने के नाम पर दूसरी शक्ति का पक्ष लेने की अवस्थिति से, जैसा कि इस साल डब्ल्यूएसएफ में हुआ, स्पष्ट तौर पर अलग हो। अफगानिस्तान और यूगोस्लाविया के युद्धों में और इराक की आर्थिक नाकेबंदी के दौरान यूरोपीय साम्राज्यवादियों की भूमिका को भुलाते हुए उनके खिलाफ डब्ल्यूएसएफ के अंतिम वक्तव्य में ढूंढने पर एक शब्द भी नहीं मिलता। वक्तव्य इस तथ्य की भी उपेक्षा करता है कि ये साम्राज्यवादी देश विदेशी ऋणों और दूसरे देशों, खास तौर से अफ्रीका पर, अपने आपराधिक वर्चस्व से मालामाल हो रहे हैं। इस सच्चाई की अनदेखी नहीं की जा सकती कि फोरम की शुरुआती स्पिरिट यह थी कि पूँजीवाद पर विजय प्राप्त करने, कर्जों को वापस न करने, संघर्षरत जनगणों के साथ एकजुटता कायम करने के वास्ते समाजवाद के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है।

यह व्यवस्था की बर्बरताओं के कुछ उदाहरणों के खिलाफ संघर्ष करने का नहीं, बल्कि उनके कारणों के खिलाफ संघर्ष करने का मसला है, जिन पर पूँजीवाद का अस्तित्व टिका हुआ है। इसलिए साम्राज्यवाद के प्रति वर्गीय पहुँच और स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाये रखते हुये लोगों और उनके संगठनों की ईमानदार एकजुटता के लिये काम करना जरूरी है। हम इस महाद्वीप और पूरी दुनिया के दूसरे बहुत से संगठनों के साथ मिलकर यह संघर्ष जारी रखेंगे, जो इस व्यवस्था और साम्राज्यवाद के सभी रूपों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हैं।

एनजीओ : एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र

तीसरी दुनिया के देशों में विकास और जनकल्याण के नाम पर एन.जी.ओ. की गतिविधियों के पीछे की साम्राज्यवादी साजिश। लुटेरे साम्राज्यवादी कारपोरेशनों का हित साधने और पूंजीवाद के दामन पर लगे खून के धब्बों को ढांकने-छुपाने का काम करते हुए स्वयंसेवी संगठन व्यापक जनता में भ्रम पैदा करने के साथ ही, उसके हर विरोध को व्यवस्था की चौहद्दी में कैद करने के लिए छद्म व्यवस्था-विरोध का कुचक्र रच रहे हैं और क्रान्तिकारी विरोध के संगठित होने की प्रक्रिया पर प्रभावी चोट कर रहे हैं। इनकी खतरनाक भूमिका के सभी आयामों के बारे में आम जनता और बुद्धिजीवियों में गलत समझदारी या भ्रम बना हुआ है।

आधिकारिक विद्वानों और जमीनी कार्यकर्ताओं की कलम से एन.जी.ओ. कुचक्र के सभी पहलुओं को उजागर करने वाली एक बेहद जरूरी किताब।
पृष्ठ : 104 मूल्य : रु. 25.00
प्राप्त करें
जनचेतना के सभी केन्द्रों से

"जहां संकल्पों के बैरिकेड खड़े हो रहे हैं
जहां समझ की बंकरें खुद रही हैं
जहां चुनौतियों के परचम लहराये जा रहे हैं
वहां तुम्हारी तैनाती है
अगर तुम युवा हो!"

इंकलाबी छात्रों-युवाओं की त्रैमासिक पत्रिका

आह्वान

कैम्पस टाइम्स

सम्पादकीय कार्यालय : 'आह्वान कार्यालय', कल्याणपुर, गोरखपुर-273 001
एक प्रति : आठ रुपए, वार्षिक : 32 रुपए (डाकव्यय सहित 40 रुपए)
email : ahwancampustimes@rediffmail.com

अनुत्तरित प्रश्न

फर्मिन गोंजालेज

पोर्तो अलेग्रे में दूसरे डब्ल्यूएसएफ में मतभेद का एक मुद्दा आयोजकों द्वारा लिया गया यह निर्णय था कि साओ पाउलो फोरम की राजनीतिक पार्टियों को फोरम से बाहर रखा जाए। इसका कारण यह बताया गया कि यह जमावड़ा राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि, सामाजिक आंदोलनों का है। साओ पाउलो फोरम ने पिछले एक दशक से समूचे लातिन अमरीका में वाम और मध्य-वाम दलों के व्यापक दायरे को एकजुट किया है। हाल के वर्षों में उसके गुरुत्व का केंद्र दक्षिणपंथ की तरफ चला गया है। इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्किंग ग्रुप के प्रमुख सदस्यों के बीच विशेषकर ब्राजीलियाई वर्कर्स पार्टी के नेतृत्व के बड़े हिस्से में इसी तरह का विचलन प्रतिबिम्बित हो रहा है। लेकिन इसमें अभी भी कोलम्बियाई ग्रुप 'प्रेजेंट्स पोर एल सोशलिज्मो' समेत क्रांतिकारी मार्क्सवाद से स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले कई छोटे संगठन शामिल हैं। आखिर में पोर्तो अलेग्रे में समझौता हुआ। फर्मिन गोंजालेज उस बैठक का ब्योरा दे रहे हैं जिसमें यह समझौता हुआ, और साथ ही उसमें अनुत्तरित छोड़ दिये गये राजनीतिक सवालों के बारे में बताते हैं। *सम्पादक*

सामाजिक जनवाद के साथ पोलेमिक्स

डब्ल्यूएसएफ कार्यक्रम की एक थीम "राजनीति को संचालित करने के दूसरे उपाय संभव हैं" शीर्षक से सामाजिक एवं राजनीतिक मामले के बीच संबंध पर कार्यशाला थी। सत्र का आयोजन साओ पाउलो फोरम वर्किंग ग्रुप का संयोजन करने वाले निकाय की ओर से किया गया था। साओ पाउलो फोरम ऐसा संगठन है जो समूचे लातिन अमरीका और कैरेबियाई द्वीप समूह की व्यापक वाम घेरे की अग्रणी पार्टियों को एक साथ लाता है। लगभग एक हजार प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत तौर पर या राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में हिस्सा लिया।

मुख्य वक्ता अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए ब्राजीलियाई वर्कर्स पार्टी (पीटी) का प्रतिनिधि और वर्किंग ग्रुप के कार्यकारी सचिव एलोइसियो मर्केदांते थे। उन्होंने साओ पाउलो फोरम के अपने दृष्टिकोण और नवउदारवादी शिविर के बाहर की पार्टियों और राज्य प्रमुखों की वैश्विक बैठक को तीसरे डब्ल्यूएसएफ के संयोजन में प्रायोजित करने के लिए 'पीटी' की बहुसंख्यक धारा के प्रस्ताव को पेश किया।

सोशलिस्ट इंटरनेशनल से संबद्ध लातिन अमेरिकी पार्टियों के उन सदस्यों के बीच संयुक्त कार्य का यह विचार उभर कर आया जो स्वयं को सामाजिक यूरोप (Social Europe) के स्थानीय अवतार के रूप में देखते हैं। यह यूरोपीय सामाजिक जनवादी पार्टियों के भीतर वाम धाराओं का समूह है जोकि उस 'तीसरे रास्ते' की नीतियों का विकल्प पेश करने की तैयारी कर रही हैं जो टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में मानवीय चेहरे के साथ नवउदारवाद के विकल्प को आगे बढ़ाती है। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि सोशल रिपब्लिक धड़े समेत सभी सामाजिक जनवादियों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद और अग्रणी बहुपक्षीय निकायों की मांग पर सभी तरह की सैनिक और अलोकप्रिय कार्रवाइयों के समर्थन में मत दिया था।

दूसरे डब्ल्यूएसएफ के दौरान बैठक करने वाले वर्ल्ड पार्लियामेंटरी फोरम में पार्टियों की बैठक के लिए प्रस्ताव उभर कर आया। यह ऐसा आयोजन था जिसमें सोशल रिपब्लिक के साथ पहचाने गए फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपीय सांसद वाम शाखा के यूरोपीय कम्युनिस्टों, विशेषकर व्यापक इतालवी शिष्टमंडल और दुनिया भर के दूसरे विधान निर्माताओं की तरफ से यूरोपीय संसद में अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में मत देने के लिए तीखी आलोचना का निशाना बने। जहां, बैठक में अफगानिस्तान पर मतदान पर वक्तव्य आया वहीं पर स्पष्ट था कि बहस तो केवल शुरुआत भर है।

पार्टियों और दूसरे राजनीतिक संगठनों की भूमिका को बहाल करना

वर्किंग ग्रुप की तरफ से 'प्रेजेंट्स पोर एल सोशलिस्मो' ऑफ कोलंबिया के प्रतिनिधि ने साओ पाउलो फोरम के उभार की व्याख्या की और बताया कि यह राजनीतिक दलों की अनुकूल अवस्थिति से सामाजिक आंदोलनों को एक साथ लाने के तमाम प्रयत्नों में से एक है। इस प्रस्तुति में जिस बात पर जोर दिया गया उसने साओ पाउलो फोरम के भीतर की क्रांतिकारी वाम धारा के दृष्टिकोण की व्याख्या करने में मदद पहुंचायी। यह धारा पुरानी कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर क्रांतिकारी वाम संगठनों की विस्तृत शृंखला तक फैली हुई थी, जिनके उद्‌भव और संघर्ष के रूप पूरी तरह से भिन्न थे।

डब्ल्यूएसएफ के भीतर सक्रिय पार्टी विरोधी और मध्यमार्गी अवस्थितियों और इस आयोजन के पहले चलने वाली बहसों और तनावों के मद्देनजर यह बात बुनियादी महत्व की थी कि शुरुआत राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की रणनीतिक भूमिका का पक्ष पोषण करते हुए की जाए जबकि उनके व्यवहारों, विशेषकर सामाजिक आंदोलनों के संबंध में, के विशिष्ट पहलुओं की आलोचनाओं को मान्यता प्रदान की जाए। ऊपर वर्णित प्रस्तुति और चर्चा में भाग लेने वालों के हस्तक्षेप चिंतन के दो ध्रुवों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहला ध्रुव वह जो सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टियों की आवश्यक क्रांतिकारी भूमिका की फिर से पुष्टि करना चाहता है। यह अवस्थिति ऐसी है जिसे डब्ल्यूएसएफ की नौकरशाहियों के भीतर नकारा जाता है या पूंजीवादी राज्य के भीतर निर्वाचित पद की अवस्थितियों समेत इसकी संस्थाबद्ध अवस्थितियों तक घटा दिया जाता है। इसके साथ-साथ चिंतन का वह दूसरा ध्रुव भी आता है जो सामाजिक एवं राजनीतिक अनुकूल अवस्थिति से डब्ल्यूएसएफ को एक प्रकार के संयुक्त राष्ट्र में या उनकी स्वयं की "यथार्थवादी" राजनीति के बावर्चीखाने में तब्दील कर देना चाहता है।

हम उस विचारधारात्मक बहस को याद कर लेना जरूरी समझते हैं जो साढ़े ग्यारह वर्ष पहले प्रथम साओ पाउलो फोरम के समय अपनी साम्राज्यवाद विरोधी और नवउदारवाद विरोधी चरित्र की पुष्टि करते हुए सम्पन्न हुई थी। इस अवस्थिति को विश्व के अन्य हिस्सों में इस तरह की व्यापक और विविध ताकतों के बीच अभी हासिल किया जाना है। यह ऐसी अवस्थिति है जो अभी तक यूरोपीय सामाजिक गणराज्य के चिंतन से दूर थी। यह विचार जहां फोरम में उस समय मजबूती की ओर प्रवृत्त होते हैं जब उन्हें क्यूबा की सीपी, ब्राजील की पीटी या फ्रेंटे एंपलिओ आफ उरुग्वे जैसी सर्वाधिक प्रतिनिधि राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। जबकि राजनीतिक आम सहमति ऐसे पूर्णाधिवेशनों में उभर कर आती है जिसमें कोई भी संगठन, फिर वह चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो या उसका संघर्ष का तरीका कोई भी हो, चर्चा या निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। यह ऐसा विचार है जिसे यूरोपीय सामाजिक जनवादी गले नहीं लगाएंगे।

सनद रहे कि वह बहस जो कि साओ पाउलो फोरम में वर्षों पहले वैधता के मसले पर या संघर्ष के विविध रूपों के अभाव में शुरू हुई डब्ल्यूएसएफ में उभर कर सामने आने लगी है। सशस्त्र संगठन को बाहर रखे जाने को लेकर शुरू हुई बहस सिर्फ उन विरोधी संगठनों पर ध्यान केंद्रित कर नहीं संचालित की जानी चाहिए जो कि राजनीतिक संगठन के स्तर पर साफ-साफ सक्रिय हैं, बल्कि इसके बजाय सामाजिक संगठनों के उस ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो कि व्यवस्था के हमले से बाध्य होकर सशस्त्र आत्मरक्षा के स्वरूपों को अपना रहे हैं जबकि फलस्तीन, फिलीपीन्स, बोलीविया, इक्वाडोर और यहां तक की अर्जेंटीना जैसे तमाम देशों में लोकसत्ता की अभिव्यक्ति के तौर पर गोलबंद करने के उनके अधिकार को छीना जा रहा है।

यह वह सवाल है जिसे उठाने में डब्ल्यूएसएफ विफल रहा है। भला हो अंतरराष्ट्रीय एनजीओ वालों का जो कि ऐसे एनजीओ बनाए रखना चाहते हैं जिसमें सामाजिक मुद्दों को वर्ग से पृथक उन्हें बहुत कम क्रांतिकारी, आर्थिक और राजनीतिक सरोकारों वाला बना दिया जाता है।

भावी चुनौतियां

जहां यह सवाल डब्ल्यूएसएफ के संदर्भ में हुए तमाम सेमिनारों में से बस एक था वहीं वहां शुरू हुई बहस डब्ल्यूएसएफ के भविष्य को निश्चित करेगी। इस बार फोरम के भीतर बीच-बचाव के रास्ते की व्यापक हिमायत की गयी और बहस से बचने के प्रयत्नों के साथ-साथ भिन्न प्रकृति के विचारधारात्मक दृष्टिकोणों को बहुत अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया। प्रतिभागी सामाजिक संगठनों, अकादमीशियनों, बुद्धिजीवियों और लोकप्रिय संघर्षों के नेताओं का योगदान उल्लेखनीय रहा। चार समानांतर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें से सर्वाधिक जुझारू और सुसंगत कार्यशालाएं 'कैम्पेसिनोस ऑफ दी मोविमिएंटो सिन टिएर्रा' और 'वाया कैम्पेसिना' की थीं, जिन्हें बाहर कर देने के लिए डब्ल्यूएसएफ के भीतर रुझान जोर पकड़ रहा था। दूसरी कार्यशाला उन पंद्रह हजार युवाओं की थी जिन्होंने हमारे शामियाने गाड़े थे, जिन्होंने खास कर अर्जेंटीना को केंद्रित करते हुए गहन-गंभीर, व्यापक और गर्मागर्म बहसों में हिस्सा लिया। तीसरी एनजीओ वालों और सामाजिक संगठनों की थीं, जिसमें मतभेदों के सवालों पर बातचीत हुई। चौथी उन बुद्धिजीवियों और राजनीतिक लड़ाकुओं की थी जिन्होंने दुनियाभर में चल रही समकालीन बहसों को ठोस रूप देने की कोशिश की।

डब्ल्यूएसएफ के भीतर एक रुझान यह उभर कर सामने आया जिसने विचारों के टकराव की जगह सामंजस्य को प्राथमिकता देने की कोशिश की। इसने गोलबंदी की जगह मध्यस्थता और सामंजस्य पर जोर दिया। इस प्रवृत्ति ने किसी नवजात आंदोलन की निष्कपटता के साथ उन लोगों के पीढ़ियों पुराने विद्वेष का तालमेल भिड़ाने की कोशिश की जो वर्ग संघर्ष और वर्ग टकरावों के बाहर राजनीतिक पाप मुक्ति के लिए गंगा स्नान करने के रूप में इसकी भर्त्सना करते हैं।

दुनियाभर की राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग पर चली बहस अभी निपटाई जानी है और साथ ही डब्ल्यूएसएफ की मांगों पर सहमति की मोहर लगाने के लिए राज्यों के प्रमुखों की भागीदारी का प्रस्ताव भी लटका पड़ा है। इन पाखंडपूर्ण भंगिमाओं को पुण्यात्माओं पर दुष्टात्माओं की श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा सकता है। चौथे इंटरनेशनल और कम्युनिस्ट रिफाउंडेशन के एक नेता लिवियो मैतान ने उसी समय इस ओर इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि यह समझने में असफल रहना नितांत भोलापन होगा कि दुष्टात्माओं के गुणगान के पीछे पुण्यात्माओं को भ्रष्ट करने का खतरा मुंह बायें खड़ा है।

भूमण्डलीकरण का विरोध करने वाले आंदोलनों और जनसंघर्षों के दमन को रोकने के लिए संघर्ष जारी है, वह संघर्ष जो पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ इस बात से जुड़ा है कि कहीं उन्हें सहयोजित और संस्थाबद्ध न कर लिया जाए।

(फर्मिन गोंजालेज एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी संगठन प्रेजेंटेस पोर एल सोशलिज्मो के सदस्य हैं जो फ्रेंते सोशल वाई पोलितिको ऑफ कोलम्बिया (Frente Social Y Politico of Columbia) और साओ पाउलो फोरम से ताल्लुक रखता है।)

यूरोपीय सोशल फोरम का नियंता कौन?

पाल ट्रीनर

इस लेख में दिखाये गये यूरोपीय सोशल फोरम के आईने में भारत में हो रहे डब्ल्यूएसएफ को देखा जा सकता है। लेखक का कहना है कि मीडिया में पेश छवि के बावजूद ईएसएफ कोई रैडिकल जुटान नहीं बल्कि बड़े एनजीओ, राजनीतिक दलों और उद्योग जगत का एक औजार है और इसका एजेण्डा नव-कारपोरेट एजेण्डा है। इटली के फ्लारेंस में हुए पहले ईएसएफ को इतालवी आयोजकों ने मनमाने ढंग से चलाया। 2003 में पेरिस के ईएसएफ को फ्रांसीसी आयोजक पर्दे के पीछे से संचालित कर रहे थे। 2004 में लन्दन में होने वाले फोरम का बड़ा खर्च कौन उठायेगा और डोरियां किसके हाथों में होगी यह अभी से साफ हैमेयर केन लिविंगस्टन। *सम्पादक*

प्रथम यूरोपीय सोशल फोरम (ईएसएफ) मुख्यतः इतालवी सम्मेलन था जिसमें 80 से 90 फीसदी प्रतिनिधि इटली से थे और सम्मेलन के एजेंडे का निर्धारण अधिकांशतः इटली की राजनीतिक पार्टियों ने ही किया था। फ्लोरेंस में संपन्न ईएसएफ के इस सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा इराक युद्ध था और मीडिया द्वारा उसकी कवरेज में इसमें संभावित भारी हिंसा पर ही मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया। लेकिन ईएसएफ एक उग्र परिवर्तनकारी संगठन नहीं है। इसके सरकारों और उद्योगों से वित्तीय संबंध हैं और वह नव निगमवाद को बढ़ावा देता रहा है। विश्व व्यापार संगठन की ही भांति यूरोपीय सोशल फोरम में भी परिवर्तन संभव नहीं है और इसका खात्मा कर देना होगा।

वर्ल्ड सोशल फोरम से यूरोपीय सोशल फोरम तक की यात्रा

पोर्तो अलेग्रे के वर्ल्ड सोशल फोरम में डब्ल्यूएसएफ की अंतरराष्ट्रीय परिषद ने प्रत्येक महाद्वीप के लिए अलग से एक सोशल फोरम के आयोजन का निर्णय लिया था। यह स्पष्ट नहीं है कि इस अंतरराष्ट्रीय परिषद का निर्माण कौन करता है, इसके वर्तमान सदस्यों की कोई निश्चित सूची इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। एशियाई और पैन अमेरिकन महाद्वीपीय सोशल फोरमों के गठन की योजनाएं भी हैं पर यूरोपीय सम्मेलन को आयोजित करने का काम पहले शुरू हुआ। छह महीने की तैयारी के बाद यूरोपीय सोशल फोरम फ्लोरेंस (इटली) में छह से दस नवंबर 2002 तक आयोजित किया गया।

सामाजिक आंदोलनों के इस भारी जमावड़े का कारण क्या है? दावोस फोरम की ही तरह इनका आयोजन भी विशेष रूप से वैश्विक व्यापार और राजनीतिक अभिजात्यों के लिए बैठकों का एक विकल्प प्रदान करना था। हालांकि ये 'शिखर सम्मेलन विरोधी प्रदर्शन' मात्र नहीं हैं। इनके कुछ विशिष्ट कार्य हैं।

सबसे पहले ये आयोजक खुद को सामाजिक आंदोलनों के नेताओं के रूप में स्थापित करने की आशा रखते हैं। वैश्विक व्यापार मंचों से इनकी समानता से भी यही पता चलता है कि ये वैश्विक व्यापारियों के बराबर के हिस्सेदार हैं। 'वैश्विक नागरिक समाज' और 'वैश्विक प्रशासन' के नाम पर आयोजकों के बीच वैश्विक कारपोरेटवाद के भी कुछ समर्थक हैं। यह मॉडल दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति के तीन प्रमुख खिलाड़ी हैंवैश्विक व्यापार, राष्ट्रीय सरकारें और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। इनके वैश्विक प्रशासन के मॉडल के अनुसार इन्हें विश्व को एक साथ मिल कर संचालित करना चाहिए। खरे शब्दों में यदि परिभाषित किया जाए तो वर्ल्ड सोशल फोरम 'ग्रीनपीस-शेल विश्व सरकार' की ओर ही एक कदम है।

दूसरे, सामान्यतः आयोजक अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इस **'आंदोलन'** को **जारी रखने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम का खाका** भी बनाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोजक अखंडित हैं। सच्चाई यह है कि विशाल अंतरराष्ट्रीय बैठकों में कुशल रूप से संगठित और अनुदान प्राप्त समूहों का ही वर्चस्व रहता है। चूंकि ये स्थापित समूह सम्मेलन और उसकी संरचना को नियंत्रित करते हैं इसलिए ये सम्मेलन के किसी भी नीतिगत प्रस्ताव को प्रभावित कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि सोशल फोरम आधिकारिक संस्थाओं को अपनी '**कोऑप्ट करने की रणनीति**' के तहत उनके विरोधियों को प्रभावित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। और उनके तथाकथित विरोधी कोऑप्ट कर लिए जाने से काफी गदगद रहते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम को फोर्ड फाउंडेशन, कनाडा के विदेश मंत्रालय और जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने प्रायोजित और प्रभावित किया था। भविष्य के संयुक्त कार्यक्रमों के लिए इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय वर्तमान विश्व संसदीय फोरम और स्थानीय अधिकारियों के फोरम के साथ समझौते कर रहा है।

...यूरोपीय सोशल फोरम के मामले में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इसके आयोजक खुद को 'यूरोप के सामाजिक आंदोलनों के अगुवा' के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। संभवतः वे अपनी इस हैसियत को आधिकारिक मान्यता दिलाना और यूरोपीय संघ से सब्सिडी पाने की आशा रखते हैं। (गौरतलब है कि 1997-98 में 'यूरोपीय सोशल फोरम' नामक एक निकाय पहले ही मौजूद था। यह यूरोपीय

कमीशन को रिपोर्ट करने वाला एक वाणिज्य दूतावासीय निकाय था।) इस तरह जो विचारधारा उभर कर आती है वह है नव-निगमवाद (neo-corporatism), अर्थात यह विचार कि यूरोप को उद्योग, एनजीओ और सरकारों की भागीदारी वाली एक त्रिपक्षीय संरचना द्वारा नियंत्रित करना चाहिए।

यूरोपीय सोशल फोरम का इतालवी संदर्भ

मीडिया की नजरों में एक अराजकतावादी भीड़ की धारणा के बावजूद यूरोपीय सोशल फोरम वास्तव में टस्कनी और फ्लोरेंस शहर का एक अर्द्ध सरकारी सम्मेलन ही था। इसकी पहल क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख जनवादी वामपंथी पार्टी के क्लाडियो मार्टिनी ने की थी। वह पोर्तो अलेग्रे में वर्ल्ड सोशल फोरम में मौजूद थे और एक आधिकारिक शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह अन्य राष्ट्रों के नेताओं से चार कदम आगे एक ऐसे चतुर व्यक्ति थे जिन्होंने वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन को वोट पाने के मुद्दे रूप में ताड़ लिया था। फ्लोरेंस के जनवादी वामपंथी मेयर लियानार्दो दी मेनिसी ने भी ईएसएफ का समर्थन किया था।

ईएसएफ के आयोजन स्थल के रूप में फ्रांस और इटली ही संभावित थे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किसने पहला ईएसएफ फ्रांस के बजाय इटली में कराने का निर्णय लिया था। कुछ रिपोर्टों में बताया गया था कि यह निर्णय 'पोर्तो अलेग्रे में यूरोपीय सामाजिक आंदोलनों के एक शिष्टमंडल का था।' हालांकि, इस बैठक और इसमें हिस्सा लेने वालों का कोई सार्वजनिक रिकार्ड मौजूद नहीं है। संभव है मार्तिनी ने फ्लोरेंस को आयोजन स्थल के रूप में प्रस्तावित किया हो। इटली में वेनिस और नेपल्स से ज्यादा उपयुक्त स्थल टस्कनी का क्षेत्र और फ्लोरेंस शहर थे। फ्लोरेंस में होने के कारण ईएसएफ को वित्तीय सहायता भी मिली, मसलन 8000 लोगों के ठहरने का मुफ्त इंतजाम और अनुवाद सेवाएं। टस्कनी में कांफ्रेंस स्थल था और इसके लिए कोई अग्रिम राशि की मांग नहीं की गयी, यह जानते हुए भी कि बिल कभी चुकता नहीं किया जाएगा। ईएसएफ के अनुमान के मुताबिक क्षेत्रीय अनुदान 40000 डालर का था। आयोजन स्थल के रूप में फ्लोरेंस के चुनाव के कारण यूरोपीय सोशल फोरम इटली की घरेलू राजनीति का हिस्सा बन कर रह गया और उसने इटली की पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकली हुई दो पार्टियों के साथ अपना राजनीतिक गठजोड़ कर लिया। वे दो पार्टियां हैं :

डेमोक्रेटिक लेफ्ट, डीएस
कम्युनिस्ट रिफाउंडेशन, पीआरसी

प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इतालिया के शहर पार्षदों ने ईएसएफ का विरोध किया था लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर विपक्ष इस मामले में सबसे आगे रहा। बर्लुस्कोनी द्वारा अक्टूबर तक ईएसएफ में अड़चन पैदा करने अथवा उसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। बर्लुस्कोनी ने अपेक्षाकृत देर से ईएसएफ को महत्व दिया। लेकिन यह जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर का राजनैतिक मुद्दा बन गया और अंत में सम्मेलन बगैर किसी अप्रत्याशित घटना के शांति से गुजर गया।

फ्लोरेंस ईएसएफ को कौन नियंत्रित कर रहा था?

अन्य देशों में ईएसएफ के लिए हुई आयोजन बैठकें दिखावा मात्र थीं और उन्हें ईएसएफ की संरचना के बारे में कोई सलाह-सुझाव नहीं देना था। इटली में बैठी आयोजन समिति ने ही ईएसएफ के बारे में सारे निर्णय लिए थे जिसमें किसे शामिल करना है और किसे नहीं, प्रायोजकों के साथ सहयोग, उनकी शर्तों को मंजूरी दिया जाना, ईएसएफ की संरचना और उसका एजेंडा आदि प्रमुख मुद्दे शामिल थे। पीआरसी की रिमिनी कांग्रेस में छह लोगों के समूह ने ये निर्णय सबसे पहले मिल कर लिया था।

इटली से बाहर हुई बैठकों में कुछ लोगों के समूह का प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पड़ सकाउदाहरण के लिए 'अटैक' फ्रांस के क्रिस्टोफ एगिटन, एआरसीआई के रोफेला बोलीनी और एंजेला क्लीन। यह तो अपरिहार्य है कि अखिल यूरोपीय स्तर के किसी संगठन के पूर्व अनुभवों से लैस संगठित समूहों का ही ईएसएफ पर वर्चस्व रहेगा। बहरहाल, इसकी हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती हैएजेंडे का नियंत्रण उनके हाथ में होगा और संभवतः ईएसएफ की अंतिम राजनीतिक दिशा को भी वही निर्धारित करें।

ईएसएफ का एक नारा है, "एक और यूरोप संभव है"। लेकिन अंततः ईएसएफ के आयोजक एक ही यूरोप को स्वीकार करते हैं, वह यूरोप जो अस्तित्व में है। अपनी वामपंथी वाक्पटुता के बावजूद ये लोग उदारवादी बाजार लोकतंत्र, बहुलतावादी संसदीय सरकार, कानून और संपत्ति के अधिकारों में विश्वास करते हैं। ये समतावादी व्यवस्था और धन के बलपूर्वक विभाजन को नकारते हैं। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ बलप्रयोग को नकारते हैं चाहे ये सरकारें कितनी ही नस्लवादी और अन्यायी हों। ये लोकतंत्र में असमानता और अन्याय को तब तक वैध ठहराने पर बल देते हैं जब तक उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से दूर किया जा सके। वे आंदोलन को अपनी बपौती समझते हैं और इन्हें लगता है कि उग्र परिवर्तनकारी ताकतें आंदोलन को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये इन परिवर्तनकारियों को बाहर निकाल फेंकना ही अपना कर्तव्य समझते हैं ताकि ईएसएफ को यूरोपीय संघ के एक साझीदार के रूप में बचाए रखा जा सके।

उनके नजरिए से देखा जाए तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि ईएसएफ के आयोजक क्यों उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाते हैं और उसका अपने हितों के लिए उपयोग करते हैं। इसी संदर्भ में बर्लुस्कोनी की सरकार अथवा विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के प्रति इनका नजरिया भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इनके अलग-अलग मत हो सकते हैं लेकिन बर्लुस्कोनी और डब्ल्यूटीओ इनके साझेदार ही हैं, दुश्मन नहीं।

पोर्तो अलेग्रे 2002 : दो सम्मेलनों का सच

जेम्स पेत्रास

17 फरवरी 2002 को लिखी गयी यह टिप्पणी जेम्स पेत्रास की वेबसाइट से ली गयी है। इसमें डब्ल्यूएसएफ के दूसरे सम्मेलन में भागीदार एनजीओ मार्का सुधारवादी और 'रैडिकल' धाराओं के बीच वैचारिक टकराहट और आयोजकों के पक्षपातपूर्ण रवैये का अच्छा ब्योरा दर्ज है। टिप्पणी लिखे जाने के समय उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद तीसरे सम्मेलन में डब्ल्यूएसएफ "उभरते ऐतिहासिक यथार्थ के साथ मेल बनाते हुए अपने एजेण्डे को रेडिकलाइज करे और गहराई" दे सके। ऐसा नहीं होने पर एक नये नारे के उभरने की सम्भावना व्यक्त करते हुए वह लिखते हैं कि "एक दूसरा सोशल फोरम सम्भव है।" जाहिर है कि पेत्रास खुद डब्ल्यूएसएफ के बारे में उदारवादी विभ्रमों के शिकार हैं। फिर भी डब्ल्यूएसएफ के "जनवादी" पाखण्ड को समझने के लिए टिप्पणी गौरतलब है। *सम्पादक*

पोर्तो अलेग्रे में एक से पांच जनवरी 2002 के बीच चले वर्ल्ड सोशल फोरम के दूसरे सम्मेलन ने 70,000 प्रतिभागियों को आकर्षित किया जिसमें करीब 5000 संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। 150 देशों के प्रतिनिधि 28 गोष्ठियों, 100 सेमिनार और 70 कार्यशालाओं में हिस्सा लेने आये थे। रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के तीन हजार से अधिक पत्रकारों ने पूरे आयोजन को कवर किया।

11 सितंबर/7 अक्तूबर के बाद की सबसे प्रमुख घटना के रूप में सोशल फोरम ने बुश-रम्सफेल्ड के दुष्प्रचार की इस लाइन का खंडन किया कि विश्व की जनता को अमरीकी साम्राज्यवाद और इसलामी आतंकवाद के बीच चुनाव करना है। पोर्तो अलेग्रे ने प्रदर्शित किया कि विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण विरोधी आंदोलन जीवित है और यह बढ़ रहा है। 2002 के सोशल फोरम में भागीदारी करने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना थी; अमरीकी मीडिया को छोड़कर विश्व मीडिया में इस वर्ष के सम्मेलन को अधिक कवरेज मिला; पिछले किसी भी मंच से अधिक यहां संगठनों और लोगों ने हिस्सा लिया; और अंततः पचास हजार प्रतिभागियों का एफटीएए विरोधी प्रदर्शन अभी तक उत्तरी अथवा दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल प्रदर्शन रहा। भारी संख्या में लोगों और संगठनों की भौतिक उपस्थिति जितनी महत्वपूर्ण थी, संभवतः उतनी ही सम्मेलन की भावना। यह उभरती हुई उम्मीद और आशावाद ही था जो सम्मेलन के प्रमुख नारे में प्रतिबिंबित होता था, "यहां एक दूसरी दुनिया संभव है"।

अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बौद्धिक हलकों में 9/11 के बाद पराजयवाद और हतोत्साह बहुत कम मात्रा में परिलक्षित हुआ। अमेरिका के सैन्य आक्रमण और उसकी एकपक्षीय मुद्रा से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के मार्ग के अवरोध और सुदृढ़ ही होंगे, इस तथ्य की स्वीकार्यता से एक वैकल्पिक विश्व की आशा को बल मिला। अधिकतर जनसंचार माध्यमों में (केवल अमेरिका को छोड़कर) कवरेज में वृद्धि और वस्तुपरक रिपोर्टों के आने का कारण सम्मेलन में मध्यमार्गी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति थी (फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के प्रतिनिधि, ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के मध्यमार्गी/सामाजिक जनवादी नेता इत्यादि)।

सोशल फोरम 2002 की राजनीतिक उपलब्धियों और प्रगति पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग में दर्ज किया गया लेकिन इसमें एक खास तरह का पक्षपात भी देखने को मिला। अधिकतर पत्रकारों और संपादकों ने कैथोलिक विश्वविद्यालय में आयोजित एक बैठक में सम्मिलित मध्यमार्गी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं के 'गंभीर विचारों' का ही हवाला दिया और उन्हें रेखांकित किया। जनांदोलनों से जुड़े राजनीतिक कार्यकताओं और नेताओं के वक्तव्यों का बहुत कम प्रकाशन हुआ, और उनके फोटो भी बहुत कम ही प्रकाशित हुए। उदाहरणस्वरूप फाइनेंशियल टाइम्स (5 फरवरी, 2002; पृ.8) ने रैडिकलों और सुधारवादियों के बीच के अंतर को हास्यास्पद रूप दे दिया। "सम्मेलन में विरोध की मंचीय अभिव्यक्तियों के पार्श्व में मुख्य बिंदु विचारों और प्रस्तावों का गंभीर आदान-प्रदान रहा, उदाहरण के तौर पर विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा के अधिकार संबंधी समझौतों में सुधार। अधिकतर प्रतिभागियों का कहना था कि वे भूमण्डलीकरण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि निर्णय के अधिकार में विस्तृत भागीदारी के एक समानांतर रूप के पक्ष में थे।

आंदोलनकारी संगठनों द्वारा आयोजित सैकड़ों समानांतर बैठकों और मालिक व क्रांतिकारी महिलाओं, युवाओं, किसानों तथा भारतीय संगठनों द्वारा शिविर स्थल पर आयोजित किए गए औपचारिक व अनौपचारिक विमर्शों को जनसंचार माध्यमों ने कमोबेश अनदेखा कर दिया। एक ओर जहां जनसंचार माध्यमों ने विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति को "सम्मेलन की वैधता" के रूप में दर्ज किया, वहीं दूसरी ओर तीसरी दुनिया के अधिकतर कार्यकर्ताओं के लिए वह अर्जेंटीना से नवउदारवादी सत्ता का तख्ता पलट कर आए लड़ाकू समूह की उपस्थिति थी, जो मंच को वैधता प्रदान करती थी। हालांकि, कई नेताओं ने सम्मेलन में प्रतिभागिता के स्तर पर विविधता की बात कही, लेकिन कुल प्रतिभागियों में 90 फीसदी ब्राजीली, (67 प्रतिशत), इतालवी, स्पानी, फ्रेंच और अर्जेंटीनियाई (23 प्रतिशत) रहे, जो इस विविधता का सच बयान करता है।"

राष्ट्रीयताओं की विविधता (जैसा कि उपर्युक्त आंकड़े बताते हैंकाफी सीमित थी) से अधिक महत्वपूर्ण ब्राजीली और यूरोपीय प्रतिभागियों के बीच के सामाजिक-राजनीतिक मतभेद थे। अधिसंख्य सामाजिक संगठनों द्वारा जारी किए गए अंतिम एकीकृत वक्तव्य में विदेशी ऋण अदायगी, अफगानिस्तान में अमरीकी युद्ध का विरोध और फिलस्तीनी हितों के साथ एकजुटता पर एक स्तर तक आम सहमति थी। कार्यक्रम के स्तर पर मांगों में सुधारवादियों और गैर सरकारी संगठनों की छोटी-छोटी मांगें प्रतिबिंबित होती थीं, वहीं 2002 की गोलबन्दी सम्बन्धी कार्यसूची में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था।

वास्तव में, सोशल फोरल 2002 सुधारवादियों और रैडिकलों में विभाजित था, जिसकी अभिव्यक्ति वहां उपस्थित विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के बीच देखी जा सकती थी। यह विभाजन विमर्शों के लिए तय स्थितियों तक में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था, साथ ही साथ प्रस्तुति के तौर-तरीकों और श्रोताओं की संरचना में भी उपस्थित था। सोशल फोरम के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है अधिकांश वह कैथोलिक विश्वविद्यालय (पीयूसी) की घटनाओं पर आधारित है। कम से कम कई आंदोलनकारियों की दृष्टि में तो पीयूसी की घटनाएं वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रतिनिधि नहीं थीं। आयोजकों ने इस बात को इंगित किया कि सम्मेलन के प्रतिभागियों का तकरीबन पांचवां हिस्सा (10000) पीयूसी में उपस्थित था जिनमें विशेषतः चालीस वर्ष की आयु से अधिक के मध्यवर्गीय व्यवसायी थे। पीयूसी से इतर तकरीबन 50000 लोग एक व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया में संलग्न थे जिसमें समाजवाद के संघर्षों से संबंधित वाद-विाद और विमर्श शामिल था। कैथोलिक विश्वविद्यालय पीयूसी में अधिकतर अकादमिक, बुद्धिजीवी और गैर सरकारी संगठनों ने अपने बीच विमर्श चलाया। उसमें किसान नेता, शहरी कार्यकर्ताओं और मजूदर संगठनों की संख्या सीमित थी। यही नहीं, अकादमियों ने थोड़ी ही संख्या में उपस्थित जमीनी कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत कम प्रयास किया। उनकी अधिकांश प्रस्तुतियां रैडिकलों के राजनीतिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ पाने में असफल रहीं।

समानांतर बैठकों और कार्यशालाओं में कार्यकताओं व वक्ताओं के बीच विचारों का ज्यादा तरल, द्विपक्षीय और व्यापक आदान-प्रदान हुआ, और जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुभवों से जोड़ने का अधिक प्रयास हुआ। सम्मेलन में ध्रुवीकरण स्पष्ट था। एक ओर सभी सुधारवादी गैर सरकारी संगठन, अकादमिक, सम्मेलन के आयोजक, फ्रांस अटैक (एटीटीएसी)-टोबिन टैक्स के समर्थक और ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के सामाजिक-उदारवादी नेता थे। दूसरी ओर ब्राजील के भूमिहीन मजदूर आंदोलन के क्रांतिकारी-बुद्धिजीवी, अर्जेंटीना के पिकेतेरोस, वामपंथी पार्टियों के प्रतिनिधि मजदूर संगठन, शहरी आंदोलन और सॉलिडरिटी समूह थे। बैठकों की सामाजिक संरचना और जनप्रदर्शनों में काफी स्पष्ट अंतर थे।

सुधारवादी अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई उद्घाटन रैली में प्रदर्शनकारी विभिन्न संगठनों से आए थे। लातिन अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ पचास हजार लोगों की आधिकारिक रैली का आयोजन कुछ रैडिकल संगठनों ने किया था जिसमें भारी संख्या में ब्राजील के मजदूर किसान, और बेघर थे, साथ ही अर्जेंटीना, बोलीविया और अन्य देशों में चल रहे संघर्षों के अंतरराष्ट्रीयतावादी लड़ाकू सम्मिलित थे। दोनों ही प्रदर्शनों के बारे में अद्भुत बात यह रही कि उनमें बैनरों और वामपंथी और रैडिकल आंदोलनों का प्रतिनिधितित्व करते सैन्य समूहों दलों, झंडों की बहुलता रही, जबकि सुधारवादी और गैर सरकारी समूह बहुत कम दिखे। उदाहरण के रूप में वर्कर्स पार्टी, ब्राजील के केंद्रीय श्रमिक संघ (सीयूटी) वैश्विक "अटैक" समूह इत्यादि के बैनर बहुत कम दिखाई दिए।

सम्मेलन में वक्ताओं को दिये गये बोलने के मौकों में भी अन्तर स्पष्ट था। दोनों ही आयोजनों में जो वक्ता बोले उनमें ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के नेता प्रमुख थे जो उस वर्ष चुनाव में खड़े हो रहे थे। सम्मेलन विभाजित था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ जहां सुधारवादी सोशल फोरम के संविधान की धाराओं का हवाला देकर जपातिस्तों, फार्क (एफएआरसी) और अन्य जनविद्रोहों के राजनैतिक आंदोलन होने की पुष्टि कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की वर्कर्स पार्टी और फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख राजनैतिक चेहरों को प्रकाशित कर रहे थे। यही नहीं अर्जेंटीना के प्रमुख सामाजिक आंदोलन मेद्रेस दि प्लाजा दि मेयो के सोशल फोरम 2002 के अधिकारियों द्वारा निष्कासन का ब्राजील के एमएसटी विरोध कर रहे थे। एमएसटी ने मेद्रेस को आमंत्रण और हीब वोनाफिनी को हवाई टिकट भेजा था।

प्रमुख संघर्षों और प्रस्तावों की उनकी परिभाषाओं में सुधारवादियों और सोशल फोरम के बीच के मतभेद स्पष्ट थे। सुधारवादी अभी भी भूमण्डलीकरण के विरोध की भाषा बोल रहे थे, जिनमें अमेरिकी सैन्यीकरण का विरोध भी था। जबकि रैडिकल तत्व बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को लगातार साम्राज्यवाद से जोड़ते हुए साम्राज्यवाद विरोधी भाषा बोल रहे थे। यह मतभेद कोई आलंकारिक मतभेद नहीं है बल्कि प्रतिद्वंद्वी रुझानों में रणनीति और दिशा के स्तर पर काफी गहरे जड़ित हैं। सुधारवादी जहां गोलबन्दी की निरंतरता की बात करते हैं, उनका मुख्य जोर भूमण्डलीकरण को मानवीय चेहरा प्रदान करने के वायदों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक व अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ अभिजात्य समझौतों व गुटीकरण पर होता है। कई सुधारवादी एक अन्य प्रकार के भूमण्डलीकरण के बारे में बोलते व लिखते हैं जिसका अर्थ मानवाधिकारों की अधिक धाराओं को साम्राज्यवादी ताकतों, उनके बैंकरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच मेज पर लाना, जोड़ना और स्थान सुनिश्चित करना है।

रैडिकलों का मानना है कि यह गोलबन्दी लोकप्रिय सत्ता के नए संगठनों के निर्माण की ओर ले जायेगी, जिनका आधार शहरी आबादी, मजदूर, बेरोजगार किसान, वर्ग आधारित स्त्रियां, रेड इंडियन और अश्वेत आंदोलन का जनसंगठनों के स्तर पर एकीकरण है। Via Campesina की तरह ही इनका रुझान एक वर्ग आधारित अंतरराष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है जिसका उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों और उत्पादन के सामाजिक संबंधों का मौलिक रूपांतरण है। नागरिक समाज के संदर्भों में सुधारवादियों की राजसत्ता में रुचि नहीं होती है। वे बेहतर व्यवस्था के नियामकों, सीमित टोबिन टैक्स, और तीसरी दुनिया के अभिजात कृषि निर्यातकों के लिए विकसित पूंजीवादी देशों में बड़े बाजारों को सुरक्षित करने हेतु व्यापार को और उदार बनाने के लिए साम्राज्यवादी ताकतों पर दबाव बना कर ही संतुष्ट रहते हैं। रैडिकल ठोस रूप से लिंग, नस्ल, और पारिस्थितिकी को साथ में लेते हुए वर्ग संगठनों की

बात करते हैं, और वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जबकि सुधार अपनी जगह अनिवार्य है, वह टिकाऊ नहीं है और न ही साम्राज्यवादी देश या क्षेत्रीय राज्य इन्हें क्रियान्वित करते हैं। वे एक नयी राजसत्ता की आवश्यकता की बात करते हैं, जो उत्पादन के साधनों के समाजीकरण और सामाजिक संबंधों के जनतांत्रिकरण में सक्षम जमीनी समूहों पर आधारित हो, और जो वर्तमान कारपोरेट अभिजातों और उनके आईएफआई सहायकों को पूर्णरूपेण प्रतिस्थापित कर ले। वे विश्व बैंक की मेज पर स्थान बांटने की समानांतर रणनीति को खारिज करते हैं, जिसमें साम्राज्यवादी देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वित्तीय और संरचनात्मक गठबंधनों पर नियंत्रण सहभागिता की नीति को एक ऐसी अंधी खाई में धकेल देता है जहां जनता की कीमत पर गैर सरकारी संगठन समृद्ध होते हैं।

"भूमण्डलीकरण विरोधी एकता" के लिए एक साझा जमीन की खोज में सुधारवादियों ने उन नामित हस्तियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया था जिनकी राजनीतिक पार्टियां अफगानिस्तान में अमेरिकी नरसंहार और बुश के सैन्य आक्रमण का (कुछ बचते-बचाते) समर्थन करती हैं। रैडिकलों ने उनकी उपस्थिति को सम्मेलन के मूल सिद्धांतों से बेमेल बताया। (और कुछ अराजकतादियों ने अपनी बात 'नरो वा कुंजरो' की भाषा में रखी।)

रैडिकल शिविर के अंदर विशेषकर एमएसटी जैसे अनुशासित सामाजिक आंदोलन ने उकसावेबाजों और अराजकतावादियों को अव्यवस्था फैलाने से रोकने में, और हजारों की तादाद में लड़ाकू कार्यकर्ताओं को व्यापक किंतु शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन के लिए गोलबन्द करने में प्रभावी भूमिका निभायी।

हालांकि कई टिप्पणीकारों ने समूहों और उनकी मांगों की भिन्नता को रेखांकित किया, उनमें से कुछ ने ही उपस्थित समूहों के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न उठाए। वहां उपस्थित कई यूरोपीय और अमेरिकी गैर सरकारी संगठन सिर्फ कागजी हैं और तीसरी दुनिया के अधिकांश 'एनजीओ पेशेवरों के छोटे से समूह के सदस्य हैं, जिनमें से कुछ के पास ही संगठित समर्थक बल और संगठनात्मक शक्ति है। दूसरी ओर, अफ्रीका, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका और एशिया से जन आंदोलनों के कुछ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे जो सैंकड़ों-हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके बावजूद गैर सरकारी संगठनों के नामचीन बुद्धिजीवी ही मंचों पर भीड़ एकत्रित कर पाए और जिन्होंने जनता को उनके क्षेत्रों में चल रहे आंदोलनों की जानकारी दी। नामचीन हस्तियों की कीमत पर छोटे-छोटे समूहों और नामित व्यक्तियों ने भले ही मीडिया को आकृष्ट किया, लेकिन इससे संघर्ष की प्रथम पंक्ति में खड़े लोगों को अनुभवों के संचार और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा नहीं मिला। आधिकारिक पूर्णधिवेशन पूरी तरह एनजीओ वालों और बुद्धिजीवियों के पक्ष में रहे जबकि समानांतर कार्यशालाएं और बैठकें ही ऐसे दृष्टांत थे जहां साम्राज्यवाद (भूमण्डलीकरण) के विरुद्ध संलग्न महत्वपूर्ण आंदोलनकारियों के कार्यकर्ताओं के बीच सार्थक आदान-प्रदान देखने को मिला। 'विकल्पों' के विमर्श में जहां आधिकारिक आयोजनकर्ताओं ने साम्राज्यवाद में सुधार और अनुशासित पूंजीवाद पर बल दिया, वहीं रैडिकल सामाजिक आंदोलनों ने एक खुली बहस चलाते हुए समाजवाद के बारे में विमर्श को मुद्दा बनाया।

एक ओर, जहां वैश्विक समस्याओं की चीर-फाड़ की गई और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का खाका बनाया गया वहीं दूसरी ओर, अंतिम मांगों में सुधारवादियों की आंशिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण परिवर्तनों का सुधारवादी मंत्रोच्चार प्रतिबिंबित हुआ जिसमें साम्राज्यवाद की पराजय और भागीदारी समाजवाद के लिए किसी भी मांग की गुंजाइश नहीं थी।

निष्कर्ष यह निकला कि क्षितिज पर साम्राज्यवादी युद्ध के बादल, वैश्विक मंदी के गहराते संकट और लातिन अमेरिका से दक्षिण मध्य एशिया तक फैले तेल के क्षेत्रों पर वाशिंगटन के नववाणिज्यिक साम्राज्य निर्माण के दौर में सुधारवादी राजनीति के लिए बहुत कम स्थान है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि या तो यह साम्राज्य में ढल जाना है या समाप्त हो जाना है।

सोशल फोरम 2002 के आयोजकों द्वारा दक्षिणपंथी पैंतरापलट, न्यूनतम कार्यक्रम और सम्मेलन में उदारवादी हस्तियों को अहमियत दिये जाने से ऐसा लगता है कि यह अमरीकी साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण नहीं कर सकेगा। नवसाम्राज्यवाद जो विश्व का ध्रुवीकरण कर रहा है रैडिकलों के विश्लेषण से सटीक मेल खाता है। अमरीकी सैन्यीकरण की संभावनाओं और गहराइयों का सामना संगठित जनसमर्थन के बगैर एनजीओ नेटवर्क के छिटपुट विरोधों से नहीं किया जा सकता है। विश्व भर में ठुमकते फिर रहे एनजीओ वालों के मुकाबले रैडिकल क्रान्तिकारी सामाजिक आंदोलनों द्वारा स्थानीय, राष्ट्र ीय और क्षेत्रीय स्तरों पर शक्तिशाली पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों का निर्माण और राजसत्ता के केंद्रों पर सीधी कार्रवाई अधिक कारगर होगी। सोशल फोरम 2002 के पास नयी वास्तविकताओं के विषय में चिंतन-मनन करने के लिए एक वर्ष है और आशा है कि सोशल फोरम 2002 में मिले भारी समर्थन के आधार पर सामने आ रहे ऐतिहासिक यथार्थ के अनुरूप समाज सम्मेलन 2003 और गहराई में जाकर एजेंडे को रैडिकल बनाएगा।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक नारा उभरेगा, "एक और सोशल फोरम संभव है"।

नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मेहनतकशों का इंकलाबी मासिक अखबार

एक अंक : 3 रु. वार्षिक : 36 रु.
(डाकव्यय सहित 40 रुपए)

प्राप्त करने के लिए लिखें :

जनचेतना, डी-68, निरालानगर
लखनऊ-226020

पोर्तो अलेग्रे2 के प्रतिनिधियों की एक बानगी

फ्रेंच वर्कर्स पार्टी

मजदूर और कार्यकर्ता, "भूमण्डलीकरण" से जूझने वाली किसी भी पहलकदमी का मूल्यांकन करते समय, यह तर्कसंगत प्रश्न पूछेंगे : क्या वह कार्रवाई या आयोजन किसी ऐसे विकल्प की ओर इशारा करता है जो मेहनतकश जनता को रोज-रोज के कष्ट, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने में सहायक हो?

पोर्तो अलेग्रे के दूसरे वर्ल्ड सोशल फोरम के फ्रेंच प्रतिनिधियों पर एक नजर डालने से स्पष्ट हो जायेगा कि यह ऐसा आयोजन नहीं था। प्रतिनिधियों में फ्रेंच राष्ट्रपति जॉक शिराक और प्रधानमंत्री लियोनेल जोस्पिन द्वारा भेजा गया छह सरकारी मंत्रियों (अमरीका के सरकारी विभागों के सचिवों के समकक्ष) और राष्ट्रपति के चार वरिष्ठ सहायकों वाला उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में पेरिस के मेयर, राष्ट्रपति पद के तीन उम्मीदवार और प्रमुख दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी आरपीआर के महासचिव भी शामिल थे।

डब्ल्यूएसएफ-2 में तीसरी दुनिया के देशों के विदेशी कर्जों के बारे में, जिसने अभी हाल में अर्जेंटीना को बर्बाद कर दिया, काफी कुछ कहा गया। फ्रांस का सहकार मंत्री, चार्ल्स जोसेलिन, वह शख्स है जो अफ्रीकी देशोंखासकर पूर्व फ्रेंच उपनिवेशोंके कर्जे के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

इन कर्जों की, जैसा कि Information Ouverier के पाठक वर्षों से जानते हैं, सालाना ब्याज अदायगी अक्सर दिन-प्रतिदिन छोते होते जाते राष्ट्रीय बजटों के लगभग 60 फीसदी के बराबर होता है; यह तमाम अफ्रीकी जनता के लिए विनाशकारी है।

क्या जोसेलिन महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस कर्जों की वजह से जनसंहारी परिस्थितियाँ झेल रहे अफ्रीकी देशों का कर्जा माफ कर देगा? कदापि नहीं। जोसेलिन ने भी, दूसरे बहुतेरे लोगों की तरह "नवउदारवादी भूमण्डलीकरण" की बुराइयों पर लंबे हवाई भाषण दिये। लेकिन अंत में उसने स्वयं को, आगे विचार-विमर्श के लिए फ्रांसीसी सरकार, अफ्रीकी देशों में फ्रांसीसी राजदूतों और "नागरिक समाज" के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय आयोग के गठन के प्रस्ताव तक सीमित कर लिया।

फ्रांस की गृह-निर्माण मंत्री, मेरी-नोएल लिनेमान अपने ब्राजील प्रवास के दौरान कई अिमसें.घ्घ्झुग्गी-बस्तियों में गयीं और उन्होंने "उदारवादी भूमण्डलीकरण" के बारे में कुछेक बेहद कड़वे शब्द कहे। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को विनियमित करने की आवश्यकता की बात की।

लेकिन इस समय, फ्रांस में उनकी सरकार ने लोई गेसोत नाम का एक नया आवासीय कानून पास किया। *'जनरल आफीशियल'* के 30 जनवरी के अंक में मूल रूप में प्रकाशित यह कानून फ्रेंच आवासीय विधान के सभी प्रावधानों से मीलों पीछे हटना थाउस सीमा तक जहां इसके कुछ मूलभूत प्रावधान ऑफीशियल हाऊसिंग कोड के विरोधी भी हो जाते हैं।

फ्रांस के शिक्षामंत्री जैक लैंग पोर्तो अलेग्रे में शामिल नहीं हो पाये थे। लेकिन उन्होंने डब्ल्यूएसएफ-2 के साथ "गहरी सहानुभूति और बिरादराना एकजुटता" का वक्तव्य भेजा, जिसमें "सार्वजनिक शिक्षा के बाजार और अनियंत्रित उदारवाद के नियमों से निर्देशित होने के बढ़ते खतरों" की निंदा की गयी थी। आज भी फ्रांस में मंत्री लैंग ही सार्वजनिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक निधि को कम करने के कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। वह निजीकरण के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। वास्तव में, वह लाखों हाईस्कूली लड़कों को समूचे फ्रांस में फैक्टरियों और कार्यालयों में "अप्रेंटिसशिप" कार्यक्रमों के बहाने ले ऑफ करने के लिए सीधे-सीधे उत्तरदायी है। और यह मुफ्त श्रम, वास्तव में कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं है बल्कि यह तो मालिकों के श्रम की लागत घटाने की कवायद है।

इसलिये प्रश्न यह उठता है : क्या किसी ऐसे आदमी की बात को गंभीरता से लिया जा सकता है जो डब्ल्यूएसएफ-2 जैसे मंचों पर तो भूमण्डलीकरण, निजीकरण, विनियमन, युद्ध और दुनिया की उत्पीड़ित जनता के सत्यानाशी कर्जे का विरोध करने का दावा करे और दूसरी ओर अपने देश में उन्हीं विनाशकारी नीतियों को लागू करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो?

फ्रेंच वर्कर्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, डेनियल ग्लकस्टीन हाल में ही फ्रांस इनफो रेडियो को दिये सक्षात्कार में इसे सबसे बढ़िया ढंग से बताते हैं : "जब मैं सुनता हूँ कि फ्रांस के सभी पारम्परिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जोस्पिन सरकार के चार मंत्री और जॉक शिराक के चार प्रमुख सहायक भी पोर्तो अलेग्रे में "भागीदारी जनवाद" पर बोलने के लिए जायेंगे, मैं सोच सकता हूँ कि यह उनके द्वारा उनके अपने देश में जनवाद पर किये जा रहे सर्वाधिक बर्बर हमलों को ढँकने के लिए धूम्रावरण है। फ्रांस की मजदूर जनता अधिकाधिक संख्या में शिराक-जोस्पिन सरकार की छँटनी नीति को रोने की माँग को लेकर संगठित हो रही है। उन्होंने सरकार से फ्रांस में निजीकरण और विनियमन की विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाली सरकार ने हर क्षण जनता की इच्छा का पालन करने और उनकी न्यायसंगत माँगों को मानने से इन्कार किया है। इस तरह पोर्तो अलेग्रे जाने वाले हमारे ये अच्छे मंत्रीगण सबके द्वारा अंतरराष्ट्रीयतावाद और भूमण्डलीकरण विरोध के नये मतावलम्बी घोषित किये जा रहे हैं। कितना जबर्दस्त झाँसा है!"

सच्चा अंतरराष्ट्रीयतावाद ले-ऑफ और छँटनी जैसी महाविपत्तियों को पहले अपने देश में रोकने और बाद में दुनिया के पैमाने पर इनके खात्मे के लिए संघर्ष करने से आता है।

(यह फ्रेंच वर्कर्स पार्टी के साप्ताहिक पत्र 'Information Ouverier' के 12 फरवरी, 2002 के अंक में छपे लेख का संक्षिप्त रूप है।)

भागीदारी बजट : राज्यतंत्र का हिस्सा बना लेने की प्रक्रिया

एलन बेंजामिन

ब्राजील के 'द ऑर्गनाइजर नामक द्वैमासिक पत्रिका से जुड़े एलन बेंजामिन की टिप्पणी 'भागीदारी बजट' की असलियत को बेनकाब करती है। इसमें ब्राजील के रियो ग्राण्डे डो सुल राज्य (पोर्तो अलेग्रे जिसकी राजधानी है) के भागीदारी बजट की परिषद में शामिल एक पार्षद के अनुभवों का दिलचस्प ब्योरा दर्ज है। टिप्पणीकार ने खुद पार्षद के निष्कर्षों को उसी के शब्दों में इस प्रकार रेखांकित किया है : "इस अनुभव से हम सीख चुके हैं कि स्वतंत्र संघर्ष संगठित किये बिना, हम कहीं नहीं पहुंचेगे।" सम्पादक

11 मार्च को मार्क कूपर का एक लेख नेशन नामक पत्रिका में आवरण कथा के रूप में, पोर्तो अलेग्रे में आयोजित डब्ल्यूएसएफ के बारे में, "प्रतिरोध से राजनीति तक" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस लेख में लेखक यह दिखाना चाहता है कि क्यों वह ऐसा महसूस करता है कि यह डब्ल्यूएसएफ वैश्विक निगमों की मंशाओं के विरुद्ध लड़ने के तरीकों के सवाल पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये कूपर स्थानीय प्रशासन में नेतृत्व प्रदान कर रही पोर्तो अलेग्रे की वर्कर्स पार्टी के तेरह सालों के प्रयासों से उभरे "बजट को जनवादी बनाने" के अनुभव को बारम्बार बतौर उदाहरण अपने लेख में प्रस्तुत करते हैं।

कूपर के अनुसार, पोर्तो अलेग्रे में वर्कर्स पार्टी का प्रयास, उस किस्म की पार्टी का है जो वैश्विक न्याय के उन्हीं समझौतों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जो डब्ल्यूएसएफ की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।" पर क्या भागीदारी बजट वास्तव में उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसाकि कूपर और बहुत से लोग दावा करते हैं? क्या यह वैश्विक पूँजीवाद की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष की एक दिशा की ओर है। ... एक नये समाज, एक अलग दुनिया की दिशा में, चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, एक कदम है?

या फिर, यह "पुरानी व्यवस्था" की कठोरता को अमली जामा पहनाने के लिए यूनियनों और कार्यकर्ताओं को उसमें समाहित करने का एक साधन है? 'द आर्गनाइजर', नवंबर-दिसंबर, 2001 अंक में हमने इस तथाकथित "सहभागी बजट" के घातक चरित्र को दर्शन के लिए पर्याप्त जगह दी है। तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर, और साथ ही पोर्तो अलेग्रे में यूनियनवादियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर हमने इस "भागीदारी बजट" के तेरह सालों के इतिहास की कलई खोली थी और यह भी उद्घाटित किया था कि क्यों दुनियाभर में , विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूँजीवादी संस्थान एक उदाहरण के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं और इसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं।

हाल ही में व जतंइंसीव अखबार में रियो ग्रांडे डो सुल राज्य के, जिसकी राजधानी पोर्तो अलेग्रे है, सहभागी बजट की परिषद के पार्षद का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ और यह साक्षात्कार भी हमारी इस "भागीदारीपूर्ण कठोरता" युक्त प्रक्रिया की आलोचना को सही ठहराता है। ऑटो वेरेमचुक, जो खुद एक वर्ष के लिए 'भागीदारी बजट' परिषद में पार्षद रहे हैं, का तर्कयुक्त दावा है कि "भागीदारी बजट का तो उद्देश्य ही लोकप्रिय आन्दोलनों के नेतृत्व को

कैसे-कैसे भागीदार

"डब्ल्यूएसएफ की बैठक (2002) में सामाजिक जनवाद और ग्रीन कैम्प के कई राजनीतिज्ञ हावी रहे। यह स्वाभाविक ही है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में शामिल लोगों की बढ़ती हुई संख्या आंदोलन का दोहन करने की कोशिश कर रही है। डब्ल्यूएसएफ के इतालवी संयोजक, जोस लुईस डेल रोजो ने यह आलोचना की : ''हमारी एक समस्या है। यहां पर कई हजार राजनीतिज्ञ उपस्थित हैं, जिनमें से कई संसद सदस्य हैं, मुख्यतः यूरोप से, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी युद्ध के पक्ष में मत दिया था। इनमें से कइयों ने अपने आपको हमारे आंदोलन के खिलाफ घोषित किया है। और अब वे सब यहां पर हैं, और अंतरराष्ट्रीय प्रेस को साक्षात्कार दे रहे हैं...। हमें समस्या है खास तौर पर फ्रांसीसी और इटली के संसद सदस्यों से। उदाहरण के लिए यहां पर इटली की वाम जनवादी पार्टी के सचिव पियरे फेसिनो हैं, जो इटली के युद्ध में शामिल होने के पक्ष में बहुत जोरदार ढंग से बोले थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेनोआ में, जब पुलिस हमें पीट रही थी, लोगों से प्रदर्शनों में शामिल न होने के लिए कहा था, ताकि हम अकेले पड़ जाएं और राज्यतंत्र के दमनकारी हाथों में हमें छोड़ दिया जाए। .... यहां पर यूरोप के प्रशासक भाग ले रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अपनी नगरपालिकाओं और क्षेत्रों से आप्रवासियों को बाहर कर दिया है। इस सबका हमारे सिद्धांतों से कुछ भी लेना-देना नहीं हैं।

यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप भी ध्यान देने योग्य है, उदाहरण के लिए जर्मन प्रतिनिधि। सिर्फ कुछ सच्चे सामाजिक आंदोलनों ने ही भाग लिया। प्रोटेस्टेंट वालंटियरी सर्विस ओवरसीज जैसे एनजीओ भरे पड़े थे। बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े फाउंडेशनों द्वारा चुने गए थे, जैसे कि हाईड्रिक ऐबर्ट फाउंडेशन के साथ 19 प्रतिनिधि, रोजा लक्जमबर्ग फाउंडेशन के साथ 9 प्रतिनिधि, हाइनरिख बोल फाउंडेशन के साथ 2 प्रतिनिधि और डीजीबी (ट्रेड यूनियनों का जर्मन फेडरेशन) के साथ 7 प्रतिनिधि थे।

सुदूर इलाकों के और क्षेत्रीय सामाजिक आंदोलन, फोरम के स्थान से बहुत दूरी पर थे, और वे जिन्हें प्रभावी संस्थाओं से वित्तीय सहायता न मिली हो या छोटे गैर-सरकारी संगठन यात्रा-व्यय वहन नहीं कर सकते थे। जो संगठन इन खर्चों को उठा सकते थे वे अपने साथ राजनीतिक पर्यटकों की भीड़ ले आए, जिन्हें स्थानीय आंदोलनों से कुछ लेना देना नहीं था।

आस्ट्रियाई पत्रिका *डेर फुंके* से अनूदित

राज्यतंत्र चौहद्दी से एकीकृत करना है।" वेरेमचुक आजकल नगरपालिका की कार्यकारी कमेटी के सदस्य हैं, जहां वे कूड़ा-करकट इकट्ठा करने वाली कोर्जन नामक कम्पनी में कार्यरत हैं।

एक दिल दहलाने वाली कहानी

वेरेमचुक की कहानी दिल दहलाने वाली है। यह ग्वाइबा (पोर्तो अलेग्रे से विस्तृत म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र) नामक नगरपालिका की भागीदारी परिषद के लिए चुने गये थे। चूँकि वह अपने जिले कोहब के पचास हजार लोगों केलिये एक हेल्थ केयर क्लीनिक चाहते थे। "हमें कुछ करना होगा।" वेरेमचुक ने कहा, "पर हालात भयावह थे।" इसके बाद का एक साल तो लगाता सहभागी बजट परिषद की मीटिंगों का था। ये मीटिंगें भी तीन स्तरों पर हो रही थीं उनकी जिला परिषद के स्तरपर, क्षेत्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर। यह मीटिंगों का अनंत सिलसिला था। और वेरेमचुक ने आगे बताया कि "मुझे यह समझनेमें जरा भी देर नहीं लगी कि यह प्रतिनिधियों को थका डालने और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से दूर फंसाकर रखा जा सके।"

परिषद की ये मीटिंगे "सहभागी" होने के अलावा और सबकुछ थीं। यह कुछ इस प्रकार से था कि हम इनमें "भागीदार" होते थे और वे निर्णय लेते थे। वेरेमचुक आगे कहते हैं कि हर स्तर पर ये मीटिंगें सख्ती से, मुट्ठी भर निर्वाचित अधिकारियों के हाथों में नियंत्रित रहती थीं और इनका मुख्य उद्देश्य रहता था कि उन 'कठिन विकल्पों' कोसमझाना, जो कि उन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों के बतौर चुने थे और दरअसल, हमारी मीटिंगें, मूलतः चुने हुए अधिकारियों द्वारा तयशुदा फैसलों को सुनाने वाली बन गयी थीं।

इस बजट को आवंटित पैसा क्या वास्तव में भागीदारी बजट के नियंत्रण में था और यह पैसा आता कहां से है?

वेरेमचुक इसका जवाब इस तरह देते हैं : "कुछ पैसा तो राज्य और शहर के बजट से मिलता था। पर सच्चाई यह थी कि यह पैसा हमारे अनुमान से बेहद कम था और इसका कारण था कि, अधिकांश पैसा तो विदेशी कर्जे को चुकाने में बहा दिया जाता था" (सम्पादक : पोर्तो अलेग्रे के मामले में तो भागीदारी बजट परिषद के लिए केवल सत्तर प्रतिशत शहरी बजट ही आवंटित था।) पर धीरे-धीरे इस प्रक्रिया में वेरेमचुक ने खुद के नियमों से बाहर निकलना शुरू किया। वह बताते हैं कि "शुरू-शुरू में भागीदारी स्वतःस्फूर्त थी। लगता था कि वर्कर्स पार्टी के प्रशासन में लम्बे समय से लम्बित मांगें पूरी होंगी और कुछ बदलाव आयेगा।" पर धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग यह महसूस करने लगे कि इस भागीदारी बजट प्रक्रिया के मूल उद्देश्य कुछ और भी हैं। इसका एक सीधा उद्देश्य तो यह भी था कि हम बजट के बारे में दूसरों के द्वारा किये गये फैसलों को मान लें और वह भी इस आवरण में जैसे वास्तव में हमने इसमें भागीदारी की हो, जबकि ऐसा कुछ भी न था।

"भूलभुलैया से बाहर निकलने का समय"

आखिरकार वेरेमचुक ने इन भागीदारी बजट परिषदों को छोड़ दिया। "कोहब के वह तमाम लोग, जो स्वास्थ्य केन्द्र से आशान्वित थे, इस प्रक्रिया से पूरी तरह निराश हो गये।" वेरेमचुक कहते हैं कि, "मैंने उन्हें कहा कि धैर्य रखो! यह भागीदारी बजट कुछ तो करेगा।" पर सच यह है कि कुछ निकल कर आया नहीं। और अप्रैल 2000 में मैनें तय किया कि यही वह समय है जब मुझे भागीदारी बजट की भुलभुलैया से छुटकारा पा लेना चाहिये।" "वेरेमचुक अपनी बात जारी रखते हैं, समय बीतता रहा पर स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित करने में कोई भी मदद नहीं की गयी। और यह सब तब हो रहा था जब कोहेब की जनता में ऐसे केन्द्र को लेकर भावनाएं उफान पर थीं और मैं खुदको लुटा पिटा महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि इससे तो अच्छा यह होता कि मैं स्वास्थ्य केन्द्र की खातिर सड़कों पर उतरने के लिए लोगों को गोलबन्द करता।" अन्त में वेरेमचुक अपनी बात को समाप्त करते हुए कहते हैं कि : "लोकप्रिय संगठनों का नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह भागीदारी बजट कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस नेतृत्व को राज्यतंत्र से एकीकृत किया जा सके। इसका एकतात्र उद्देश्य इस लोकप्रिय नेतृत्व को समाप्त करना है। इसलिए कोहेब में हमने निर्णय लिया कि हम सब वापिस जनता के पास जायें और उसे मुहल्ला मीटिंगों द्वारा एकत्र और संगठित करें ताकि हम अपने स्वास्थ्य केन्द्र की मांग को सशक्त रूप से उठा सकें। और इस अनुभव से हमने यह सीखा है कि संगठित और स्वतंत्र संघर्ष के बगैर हम कुछ नहीं पा सकते और कहीं नहीं पहुँच सकते हैं।"

अनुराग
बाल पत्रिका

पता : **डी-68, निरालानगर, लखनऊ**
एक प्रति : 10 रु.
वार्षिक : 40 रु. (डाक व्यय अतिरिक्त)

'परिकल्पना' का नया प्रकाशन

इराक : साम्राज्यवादी कब्ज़ा और प्रतिरोध

यह किताब इराक पर हमले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने के साथ ही खाड़ी युद्ध के बाद इराकी जनता पर टूटे कहर के आंखें खोल देने वाले ब्यौरे देती है और साम्राज्यवादी आधिपत्य के खिलाफ वहां जारी जन प्रतिरोध की जीत में भरोसा पैदा करती है। साथ ही यह दुनिया में अनेक युद्धों के लिए जिम्मेदार तेल की राजनीति और अर्थशास्त्र को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण सामग्री मुहैया कराती है।

लेखक : हरपाल बराड़
पृ. 160, मूल्य : 40 रुपये
'जनचेतना' के सभी केन्द्रों पर उपलब्ध

ट्रेड यूनियन सोलिडेरिटी कमेटी, मुंबई द्वारा डब्ल्यूएसएफ के भारतीय आयोजकों को भेजा पत्र

प्रति,
भारत की आयोजन समिति
वर्ल्ड सोशल फोरम, भारत
24 जून, 2003

एन. वासुदेवन
संयुक्त संयोजक
ट्रेड यूनियन सोलिडेरिटी कमेटी, मुंबई

पिछले कुछ समय से हमें वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में खबरें मिलती रही हैं। दरअसल, हमारी घटक यूनियनों के कुछ साथियों ने हैदराबाद में एशिया सोशल फोरम में और मुंबई की शुरुआती बैठक, जिसे भारत में वर्ल्ड सोशल फोरम को आयोजित करने की प्रक्रिया हेतु विचार-विमर्श के लिए कहा गया था, में शिरकत की थी। कुछ मित्र सुझाव देते रहे हैं कि डब्ल्यूएसएफ द्वारा जनवरी 2004 में अगला सम्मेलन मुंबई में करने के फैसले के मद्देनजर हरेक को डब्ल्यूएसएफ प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए।

हम डब्ल्यूएसएफ के बारे में मित्रों से चर्चा और सूचनाएं इकट्ठा करते रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ बिन्दु ऐसे हैं, जिन पर इण्डिया ऑर्गनाइजिंग कमेटी और/या इण्डिया वर्किंग कमेटी जिसे हम भारत में डब्ल्यूएसएफ 2004 के लिए सर्वोत्तम निर्णायक समिति मानते हैं, का स्पष्टीकरण जरूरी है।

हम डब्ल्यूएसएफ इण्डिया के दस्तावेज और गाइडलाइन्स का अवलोकन कर चुके हैं। हम पाते हैं कि ढेर सारे सवाल अनुत्तरित रह गये हैं। हम आपसे निम्न सूचनाएं इस उम्मीद के साथ चाह रहे हैं कि आपका जवाब हमें इस प्रक्रिया के प्रति अपना मन बनाने में मदद करेगा।

पहले तो हम स्पष्ट होना चाहेंगे कि क्या डब्ल्यूएसएफ खुद को भूमण्डलीय साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखता है। क्या यह स्वयं को साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ आंदोलन की निरन्तरता के रूप में देखता है, ऐसा आंदोलन जिसने 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक और तत्पश्चात अन्य अमेरिकी, यूरोपीय और आस्ट्रेलियाई शहरों में साम्राज्यवादी सरकारों और मुख्य नीति निर्माता निकायों की बैठकों के दौरान लड़ाकू प्रदर्शनों के बाद एक नया विश्वव्यापी संवेग प्राप्त कर लिया। यदि ऐसा है तो हमारे लिए यह आश्चर्यजनक है कि डब्ल्यूएसएफ पिछले कुछ वर्षों में कोई भी सार्थक आंदोलन संगठित करने में क्यों असमर्थ रहा है, वरन यह तो साम्राज्यवादी एजेन्सियों की सीधी मुखालफत का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित किये बिना अपने सारे संसाधनों को ऐसे विश्वव्यापी विशाल सम्मेलनों में लगा रहा है।

हम कुछ ऐसी रिपोर्टों से भी परेशान हैं कि यद्यपि डब्ल्यूएसएफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति आलोचनात्मक है, पर यह कुछ अन्य साम्राज्यवादी सरकारों और एजेंसियों से विभिन्न रास्तों से मदद लेता है। ऐसी सरकारों के कुछ प्रतिनिधि तो वास्तव में डब्ल्यूएसएफ प्रक्रिया के भागीदार हैं।

इसीलिए हम एक स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे, क्या डब्ल्यूएसएफ किसी भी स्रोत, शक्ति या वित्तीय एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रास्ते से ऐसी संस्थाओं या सरकारों से जुड़ा है जो स्वयं भूमण्डलीकरण समर्थक हैं और इसके बावजूद कि वे विभिन्न मौकों पर अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की खास कार्रवाईयों का विरोध कर सकते हैं, उनके अपने साम्राज्यवादी हित फिर भी हैं।

प्रसंगवश, चूंकि भारत की ट्रेड यूनियनों में ज्यादातर ने डब्ल्यूटीओ कार्यसूची के सामाजिक उपबंध का विरोध किया था, यह मानते हुए कि इस मांग के पीछे साम्राज्यवादी हित हैं, और चूंकि भागीदारी करने वालों के लिए एक कसौटी यह है कि उन्हें साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का विरोध करना चाहिए, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि डब्ल्यूएसएफ की सामाजिक उपबंध पर क्या अवस्थिति है।

हम वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम और इसकी दावोस बैठक के प्रति डब्ल्यूएसएफ के रुख को भी जानना चाहेंगे, विशेष तौर पर उन सुझावों की रोशनी में जिनके अनुसार इन दो निकायों के बीच पुलों के निर्माण का प्रयास हो। सूचनाओं के आलोक में इसका महत्व बढ़ जाता है कि ब्राजील की वर्कर्स पार्टी के नेता लूला, जो डब्ल्यूएसएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और पोर्तो अलेग्रे में डब्ल्यूएसएफ 2003 के एक महत्वपूर्ण वक्ता रहे हैं, ने इस वर्ष वर्ल्ड इकानामिक फोरम की बैठक में भागीदारी की। क्या यही सच्चा 'सेतु निर्माण' है?

आगे हम जानना चाहेंगे कि डब्ल्यूएसएफ के दस्तावेजों में आने वाली "सामाजिक आन्दोलन" शब्दावली का क्या निहितार्थ है। एक सामाजिक आंदोलन होने का दावा कर डब्ल्यूएसएफ समाज की सभी अन्तरविरोधी ताकतों को जगह मुहैया कराना चाहता है। यद्यपि यह करते हुए डब्ल्यूएसएफ कहता है कि यह एक गंठजोड़ मंच, छाता संगठन इत्यादि नहीं है। तब यह क्या है? और किसके लिए?

हम यह भी समझते हैं कि डब्ल्यूएसएफ बहस-मुबाहसे लिए एक निकाय है, लेकिन साझा कार्रवाई विकसित करने की ओर आगे बढ़ने को प्रस्तावित नहीं करता है। हालांकि यह व्यक्ति, संगठनों या संगठनों के समूहों द्वारा ऐसी योजनाएं लिए जाने का विरोध नहीं करता। सच्चाई यह है कि भूमण्डलीकरण ने दुनिया के लोगों और संसाधनों को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। अतः, हमारा विश्वास है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ समन्वित वैश्विक कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

हमें डर है कि यदि विचार-विमर्शों और विवादों का निचोड़ न्यूनतम साझा सहमति के कार्यक्रम की किसी कार्रवाई में नहीं होता है तो ये एक निष्फल प्रयास होगा (चाहे उनका अर्थ कितना ही भला क्यों न हो)। यह जन आंदोलनों और संगठनों के मूल्यवान समय, ऊर्जा और संसाधनों को ठोस कार्रवाई से विमुख करना होगा, जिनसे ठोस कार्रवाई की मांग समय कर रहा है।

हम स्पष्ट परिभाषा प्राप्त करना चाहेंगे कि 'नागरिक समाज' का अर्थ क्या है। क्या डब्ल्यूएसएफ का उद्देश्य ऐसा "अलग विश्व" बनाना है जहां मजदूर, उद्योगपति चाहे छोटे हों या बड़े और यहां तक कि साम्राज्यवादी सरकार के प्रतिनिधि (जो डब्ल्यूएसएफ में निजी हैसियत में भागीदारी करेंगे) अन्तरविरोधी और अलग-अलग हितों को छोड़कर एक साथ बने रहेंगे? चूंकि सिद्धान्तों का चार्टर डब्ल्यूएसएफ के भागीदार संगठनों तथा आंदोलनों और भागीदारों तथा आंदोलनों के बीच "आपसी" मेल-जोल बनाने की वकालत करता है इसलिये इस दिशानिर्देश के दायरे में एक पाले में खड़े मजदूर और दूसरों में खड़े व्यवसायी और उद्योगपति भी आ जाते हैं। इनके बीच "आपसी" मेल जोल बनाने का अर्थ है मजदूर मौजूदा शोषण-प्रणाली को जस का तरस स्वीकार कर लेना। क्या यह सही है?

अब तक भूमण्डलीकरण के खिलाफ संघर्ष भूमण्डलीकरण के कहर के शिकार लोगों का संघर्ष रहा है। लेकिन यह नीति संबंधी दिशानिर्देश मजदूरों-किसानों और ऐसे ही अन्य वर्गों-तबकों के साथ स्थानीय व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए भी जगह बनाने की हिमायत करता है। हमारे ख्याल से भारत में स्थानीय व्यवसायी और उद्योगपति समाज के ऐसे तबके नहीं हैं जो अंधेरों में खोये हैं, हाशिये पर ठेल दिये गये हैं, जिन्हें तवज्जो नहीं दी जाती और जो उत्पीड़ित हैं और जिनके लिए जगह बनायी जानी चाहिए। ये वही तबके हैं जो भूमण्डलीकरण के लाभ बटोर रहे हैंकेवल कुछ छोटे उद्यमियों को छोड़कर जो सरकार की साम्राज्यवादपरस्त नीतियों से प्रभावित हुए हैं। क्या डब्ल्यूएसएफ का सुझाव यह है कि मजदूरों और किसानों को व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों से सहयोग करना चाहिए? डब्ल्यूएसएफ का नारा है"एक दूसरी दुनिया संभव है"। क्या इसका अर्थ यह निकाला जाये कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के फ्रेमवर्क के भीतर "एक दूसरी दुनिया संभव है" या यह कि इसके बाहर। यह स्पष्ट नहीं है।

डब्ल्यूएसएफ का चार्टर दावा करता है कि यह एक सामाजिक आंदोलन है और यह जताता है कि यह राजनीति से कोसों दूर है। लेकिन दस्तावेज एक स्थान पर 'मतभेदों के बीच संवाद का राजनीतिक वातावरण' बनाने की बात करता है। वे कौन से मतभेद हैं जिन्हें डब्ल्यूएसएफ कम करना और दूर करना चाहता है।

हम चार्टर में उस धारा को शामिल करने की जरूरत समझने में असमर्थ हैं जो "राजनीतिक कार्रवाई के तरीके के तौर पर लोगों की जान लेने वाले संगठनों" को डब्ल्यूएसएफ में शामिल होने से रोकता है। क्या इसका तात्पर्य आत्म-रक्षा के लिए किये जाने वाले सशस्त्र संघर्ष से है? एक ट्रेडयूनियन से जुड़े होने के नाते हम स्वयं ऐसे तरीकों का न तो सहारा लेते हैं और न ही इसका प्रचार करते हैं, और जनता के मुद्दों के नाम पर या संकीर्ण उद्देश्यों की लिए निरर्थक हिंसा की कार्रवाइयों के विरोधी हैं। लेकिन इतिहास को एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखने पर हम पाते हैं कि विभिन्न कालों में इस तरह के दर्शनों पर आधारित आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और कुछ आज भी निभा रहे हैं। यह हमारी समझ से बाहर है कि जनान्दोलनों पर दिनोंदिन बढ़ते फासिस्ट हमलों और साम्राज्यवाद परस्त राजकीय हिंसा के मद्देनजर किस तरह कोई साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष राजनीतिक कार्रवाई के इन रूपों को पूरी तरह खारिज कर सकता है।

क्योंकि हम सभी डब्ल्यूएसएफ को आयोजित करने में भारी परिमाण में संसाधन और समय खर्च करेंगे, इसलिए ट्रेड यूनियनों से जुड़े होने के नाते यह जानने में हमारी दिलचस्पी है कि डब्ल्यूएसएफ की प्रक्रिया किस तरह श्रम की मुक्ति के अपने संघर्ष में ट्रेड यूनियन आंदोलन को ऊपर उठायेगी, खासकर हाल के वर्षों में मजदूरों के अधिकारों और सुविधाओं पर बढ़ते हमलों के संदर्भ में, और यह किस तरह एक वर्ग विहीन समाज बनाने की दिशा में वर्ग संघर्षों को आगे बढ़ायेगी। उदाहरण के लिए, यह जानकर हमें खुशी होगी, कि समग्रता में डब्ल्यूएसएफ ने किस तरह उन मांगों को हासिल करने में योगदान दिया है या योगदान देने वाले हैं जिसके लिए हमने भारत में 21 मई 2003 की सफल आम हड़ताल की थी? (हम समिति के भीतर के अलग-अलग संगठनों से नहीं पूछ रहे हैं, जिनमें से कई संगठनों ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।)

ऊपर के बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हमें फैसले लेने में मदद करेगा, क्योंकि डब्ल्यूएसएफ आयोजित करने की प्रक्रिया में मदद करने का अर्थ है जरूरी सांगठनिक गतिविधियों की कीमत पर समय, संसाधनों और कार्यकर्ताओं को मुहैया कराना। बहरहाल, हमारा निर्णय जो भी हो, हम यह दुहराना चाहेंगे कि हमारे देश और जनता का शोषण करने वाले साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ ठोस संघर्ष में शामिल होने के लिए हम हमेशा तैयार है।

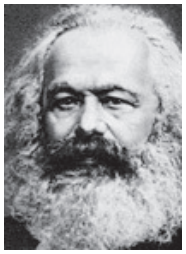

An Introduction to Marx's Capital

By **Ranganayakamma**

(Price: Rs. 90.00/ for Vol. I, Rs. 110.00 for Vol. II, and Rs. 80.00 for Vol. III)

A Book on 'Caste' question

For the solution of the 'Caste' question
Buddha is not enough,
Ambedkar is not enough either,
Marx is a Must

By **Ranganayakamma**
Pages 430. Paper back. Rs. 80

Published by Sweet Home Publications, Hyderabad
Availbale from : JANCHETNA
• D-68, Nirala Nagar, Lucknow-226020
• 29, UNI Aptts, GH-2, Sec-11, Vasundhara, Ghaziabad-201010

उपन्यास अंश

एक तयशुदा मौत

मोहित राय

बंगला से अनुवाद : रामकृष्ण पाण्डेय

मुम्बई। इंडियन एक्सप्रेस की दो लाइन की खबर से ही मुझे पता चल गया कि दीपू का खून कर दिया गया है। दीपू मर चुका है। खदान क्षेत्र के उस फैले हुए गैरिक प्रांतर में अब उसे नहीं देखा जा सकेगा। अचानक चाय की किसी दुकान पर भी उसे देख पाने का मौका अब नहीं मिलेगा। हफ्ताभर पहले की खबर है। दिल्ली संस्करण से मुम्बई संस्करण तक पहुंचने में शायद इतनी देर हो गयी। दीपू मर गया। किन्तु ...सीड (सोसायटी फार एजुकेशन एण्ड डेवलपमेण्ट) को क्या कुछ मालूम नहीं होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी का पन्ना पलटकर उसका फोन नम्बर और पता खोजा। दोपहर में चलकर मिला जाये।

ग्यारहवीं मंजिल पर आफिस है। कार्निश से चकचक चमकती हुई लकड़ी पर पीतल से लिखा था : SEED। भीतर रिसेप्शन पर एक खूबसूरत महिला बैठी थी। मि. कारलेकर अभी आयेंगे। बाहर शीशे की खिड़की से आकाश नजर आ रहा है। चमकती हुई धूप है। यहां से शहर सुंदर दिखता है। बत्तियों की खूबसूरती उदात्त है। आकाश छूती इमारते हैं। बायीं ओर मालाबार पहाड़ की नीलिमा युक्त हरियाली, एक ओर समुद्र।

दो पुस्तिकाएं उठा लीं। लगता है उन्हें दीपू के घर पर भी देखा था। एक ओर साफ-सुथरी दीवार पर दुनिया का नक्शा टंगा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस पर यहां-वहां अनेक लाल बिंदियां चमक रही हैं। अच्छा तो ये इनके कार्य क्षेत्र हैं। बंगलादेश, बोलीविया, कांगो, सूडान इत्यादि। और सबसे बड़ी बिंदी एम्सटर्डम है। मतलब सीड का हेडआफिस। दूसरी दीवार पर एक क्रास और गांधी की तस्वीर टंगी है। दो-एक पोस्टर भी टंगे हैं जिन पर सेवा परियोजनाओं, लोगों की सेवा प्रगति आदि के बारे में नारे लिखे हैं...।

कारलेकर आ गये। हल्के रंग का सूट पहन रखा है। मुंह में पाइप है। काले-सफेद बाल। थोड़ा-सा सिर झुकाकर उन्होंने गुड मार्निंग कहा और हाथ बढ़ाया। परिचय के बाद थोड़ा मुस्कुराकर बोलेहम भी दुखी हैं। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर के लिए व्यस्त हूं। उसके बाद कुछ क्षण रुककर कहाऐसा करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। हमारे कांफ्रेंस रूम में वीडियो पर एक डाक्युमेंटरी दिखायी जा रही है। हमारे कामकाज के बारे में एक फिल्म।

उस कमरे में आठ-दस लोग थे। तीन आदमी गौरांग थे। फिल्म आधी हो चुकी थी। टी.वी के पर्दे पर किसी जगह कारीगर कपड़े पर डिजाइन बना रहे थे। कैमरा एक कारीगर के चेहरे पर टिका है। आधी घूंघट में एक महिला कुछ असहज नजर आ रही है। पर रंग में तूलिका डुबाकर काम में व्यस्त है। साथ में हल्का अवरोही संगीत। नपी-तुली अंग्रेजी में लक्ष्मीगढ़ के हस्तशिल्पियों की जानकारी दी जा रही है। कैमरा एक बड़े हाल के नीम अंधेरे में बैठकर काम कर रहे शताधिक कारीगरों का दर्शकों से परिचय करा रहा है। अब एक गरीब कारीगर अपनी बात रख रहा है। टी.वी. के पर्दे पर अंग्रेजी में उसका अनुवाद लिखा है। पता चला कि सीड ने यह संगठित किया है। इनकी समस्याएं हैं सस्ते में कच्चा माल प्राप्त करना, बिचौलियों द्वारा दिये गये एडवांस पर ऊंची दर पर ब्याज, बाजार में तैयार माल सीधे बेचने की सुविधा का अभाव आदि। सीड इनकी एक सहकारी समिति बना रहा है। कम ब्याज पर बैंक से ऋण की व्यवस्था कर रहा है। बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है आदि, आदि। फिल्म अंग्रेजी में है। लगता है विदेशों में अच्छा चलेगी। और अधिक विदेशी सहायता मिलेगी। पता चला कि सीड के प्रतिनिधि तीन-चार शहरी लड़के-लड़कियों को, जो इन कारीगरों को संगठित कर रहे हैं, अच्छा वेतन दिया जायेगा। यह पता नहीं चला कि उच्च प्रौद्योगिकी के साथ इन कारीगरों की जो प्रतियोगिता है वह कैसे मिटेगी। यह भी पता नहीं चला कि इन सबके पीछे कौन-सा राजनीतिक दल और कौन नेता है और यह सहकारी समिति के गठन में बाधक होंगे या नहीं। अगर उन्होंने बाधा पहुंचाई तो लड़ाई कैसे चलेगी। इस राज्य में हस्तशिल्प के नाम पर जो मोटी धन राशि निर्धारित है वह कुछ लोगों और पार्टियों के जेब में चली जाती है। इससे जो नुकसान होता है उसे कौन मिटायेगा। अर्थनीति और राजनीति से सम्बन्धित ऐसे ही प्रश्न दिमाग में उठते रहे कि टी.वी. पर अंधेरा छा गया। कमरे की रोशनी जल उठी और कारलेकर मुझे अपने कमरे में लेकर चले गये।

कारलेकर का यह अपना कमरा है। दीवार पर दुनिया का नक्शा टंगा है। क्या ये लोग दुनिया को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं? सुना है ये सज्जन पहले संयुक्त राष्ट्र में थे। नामी कृषिविद। इन सब पदों को छोड़कर जनसेवा के क्षेत्र में उतर आये हैं। कारलेकर अपनी मेज के कागज-पत्र सजाते-सजाते मेरी ओर देख लेते थे। सुन्दर गोरा चेहरा है। ढला हुआ। बाल आगे से झड़ गये हैं जिससे ललाट प्रशस्त लगता है। स्टील फ्रेम का चश्मा। कुल मिलाकर विज्ञापनों के एक्जक्यूटिव लगते हैं। अब इन सज्जन पुरुष ने बातचीत शुरू की

आपने, आपने ही फोन किया था? आप ही दीपंकर के दोस्त हैं?

हां, इसके अलावा...

हम लोग बहुत दुखी हैं, सीड की

ओर से हमने उसके घर शोक संदेश भेजा है और ...

मैंने मूल प्रसंग उठाना चाहा।

कारलेकर बोले,

देखिए सच तो यह है कि इस दीपू की हत्या होने का मामला हम लोग एक तरह से पहले से जानते थे।

क्या मतलब?

नहीं, नहीं उस तरह नहींकारलेकर अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया को रोक लेते हैं

यह सब नहीं कि कब किसको कौन मारेगा, यह सब नहीं पर दीपू के सम्बन्ध में हमारे पास हफ्ता भर पहले तक जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जिस तरह की स्थिति वह क्रमशः निर्मित कर रहा था उससे लगता था कि ऐसा ही कुछ...

पर इसमें आप लोगों की, सीड की एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। क्योंकि...

कारलेकर हाथ उठाकर मुझे रोकते हैं। घंटी बजाकर एक चपरासी को बुलाते हैं और काफी का आर्डर देते हैं। फिर बुझे हुए पाइप के तम्बाकू को साफ करते हुए मेरी ओर भौंहें उठाकर देखते हैं। किंचित मुस्कुराकर फिर शुरू होते हैं

सुनिए, आपको पूरी बात थोड़ा समझाकर कहते हैं। सारी स्थिति मेरी जानकारी में तब आयी जब मि. हार्डवेकर ने मुझे सारी बातें बताईं। मेरी जिम्मेदारी पश्चिमी क्षेत्र की है, उधर का मामला मि. हार्डवेकर ही देखते हैं। मि. हार्डवेकर की रिपोर्ट से पता चला कि दीपू के साथ उनका मतभेद बढ़ रहा है। दीपू से पहले मैंने दो-एक बार ही मीट किया था। फाइन चैप, किन्तु प्रोफेसर खारेजा और मिसेज गुप्ता भी उसके साथ सम्पर्क नहीं रख सकीं। दीपू हटता जा रहा था और इस तरह की स्थिति में दीपू के लिए इस तरह अकेला पड़ना इतना भयानक होगा...

मतलब दीपू अकेला होता जा रहा था?

अकेला, मतलब हम लोगों से अलग होता जा रहा था। आपको अपनी परियोजना के बारे में बताते हैं। तब शायद आपको समझने में आसानी होगी। हम समझते हैं कि मनुष्य की उन्नति के लिए उसकी चेतना का विस्तार भी जरूरी है। उसे कुछ मूलभूत मामलों में सहायता करने से वह खुद ही आगे बढ़ सकता है। अर्थात वह समझ सकता है कि उसके चारों ओर की दुनिया में उसका भी अधिकार है। और इस समाज को वह और सुन्दर बना सकता है, सबके साथ मिलकर जैसा कि हम लोग लक्ष्मीगढ़ के कारीगरों के साथ कोशिश कर रहे हैं। कुछ आत्मनिर्भरता...

इस बीच मेज पर एक फोन बज उठाहैलो, हैलो...हैलो...हैलो जोर से बोलिए, कौन... फिलाडेल्फिया? मि. कुमार, गुड मार्निंग! क्या बजा है इस समय? आपके यहां अभी रात हैहां, हां बंगलादेश। खुलना का सेंटर

... मि. रहमान अब फिलाडेल्फिया के... सुनिए, इस मामले को जरा देखिए। अभी सैनिक शासन चल रहा है। आप अभी इसलामी नैतिक परियोजना में सहयोग करते रहिए। नहीं तो वहां की पोलिटिकल सिचुएशन बिगड़ सकती हैहैलो, हैलो...हां, उसी को फॉलो करिए। एम्सटर्डम को बता दीजिए। बंगलादेश को कुछ और महत्व दीजिए। ...बहुत वाइटल एरिया है। ...रहमान के हाथों भेज दीजिए... हां, हां अच्छा बाई।

फोन रखकर थोड़ा आराम करते हैं मि. कारलेकर। पाइप मुंह में लगाकर उसे जलाते रहते हैं। कमरे में एक सुदर्शन युवक प्रवेश करता है। चमकता हुआ चेहरा, जींस और सूती हाफ शर्ट। कारलेकर का चेहरा खुशियों से भर जाता हैअरे, आओ, आओ। कब आये? दोनों गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद मेरी ओर उन्मुख होते हैं। परिचय कराने के बाद कारलेकर कहते हैंये मेरे एक्टीविस्ट विनय देसाई हैं। कैलीफोर्निया से सोशियोलॉजी में एम.फिल करने के बाद बड़ौदा में पढ़ा रहे थे। वहां से छोड़कर अब सीड का काम कर रहे हैं। प्रशंसा सुनकर वह नौजवान शरमा जाता है। नपी-तुली मुस्कराहट के बाद ऊंचे खानदान के आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाता है। कारलेकर बात बढ़ाते हैं।

अरे हां, तुम तो दिल्ली के उस खदान वाले इलाके से आये हो। हमारा एक लड़का उधर काम करता था। कुछ दिन पहले उसकी हत्या हो गयी...

देसाई मुझे क्षण भर देखता है और फिर बोलता हैहां, पता है! इलाके में अभी तनाव है। मुझे मि. हार्डवेकर ने इस पूरे इलाके की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

ये मि. हार्डवेकर बस रिपोर्ट-रिपोर्ट करते रहते हैं। ब्रिटिश लोग बिलकुल किरानियों की तरह होते हैं। उनको कुछ अमेरिकन टच चाहिए। और दीपू तो खुद एक भयानक स्थिति निर्मित कर रहा था जिसका अंदाजा तो हम लोगों को था ही। अब रिपोर्ट तैयार करने से क्या फायदा?

नहीं, एक बात और है। दो-तीन दिन पहले और एक समाचार मिला है। दीपू के घनिष्ठ सहयोगी रामू की भी शायद हत्या हो गयी है। यह बात अभी बाहर बहुत नहीं फैली है।

रामू की भी हत्या हो गयी? मैं भी कुछ चौंक उठता हूं।

देसाई नजर बचाकर मुझे देख लेता है। कहता हैमि. कारलेकर, इस मामले में हमारा संगठन बदनाम हो गया है। किसी नागरिक अधिकार समिति का एक दल तथ्य जुटाने के लिए दो दिन पहले आया था। उससे भी तनाव बढ़ा। और अपनी रिपोर्ट में वे लोग क्या लिखेंगे, कौन जाने।

कारलेकर कुछ उत्तेजित से लगे। दो-एक बार घड़ी की ओर देखते हैं। अपनी ओर जोर से फाइल खींचते हैं। पाइप पीते हुए नीला धुआं और कीमती तम्बाकू की गंध कमरे में छोड़ते हैं। थोड़ी देर मौन छा जाता है। खाकी वर्दी वाला चपरासी तीन कप काफी लेकर

कमरे में प्रवेश करता है। देसाई एक विल्स सिगरेट जलाते हुए कुछ बोलने को उत्सुक होता है। कारलेकर उसको रोकते हैं।

ठहरो, मुझे शाम की फ्लाइट से रांची जाना होगा। वहां हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट स्टडी सेंटर का कल एक कार्यक्रम है। मिनिस्टर रहेंगे और जानते ही हो बिहार के मंत्री सब स्काउंड्रल हैं। राज कर रहे हो तो जरा ठीक से रहो। पर छोड़ो इसे। दीपू का मामला मुझे अच्छी तरह समझना होगा। पर पहले और सब बताओ। तुम कब तक हो?

मैं परसों सुबह की फ्लाइट से लौट जाऊंगा। उस दिन पूजा डोगरा का जन्मदिन है।

अच्छा, वाह! कारलेकर कुछ अस्वस्थ नजर आते हैं।

नहीं, एक दूसरी बात करते हैं। आप जब रांची जा ही रहे हैं तो के.के. राव से तो मुलाकात होगी ही। वे लोग कुछ ट्रबल में हैं। आंध्र की सीमा पर हमारा जो सेंटर है वहां कुछ पोलिटिकल ट्रबल पैदा हो गया है। ट्राइबल एरिया है। वहां एक्टिविस्ट हमारा विरोध कर रहे हैं।

लेकिन मि. सेन का ग्रुप तो हमारे साथ है। वे लोग कुछ...

नहीं, मि. कारलेकर। एक्टिविस्ट लोगों के तो कई ग्रुप हैं। मि. सेन के लोगों का वहां होल्ड नहीं है। इसके अलावा मि. सेन के ग्रुप की ताकत के बारे में मेरी धारणा अच्छी नहीं है। इसे छोड़िये, आप मि. राव के साथ बात कर लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर मि. सेन को ही...। पर बस्तर के इलाके में खूब अच्छा काम हो रहा है। शिवनाथन के साथ इस बीच भेंट हुई थी। पर वहां कुछ पोलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होने से खास झमेला नहीं है। और आम आदमी की भी पोलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। अभी जरूरत हमारी है। इन सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशनों को ही कामन आदमी के बीच काम करना होगा। तभी रियल सोशल डेवलपमेंट का काम बढ़ेगा।

मि. कारलेकर एक पैड पर कुछ-कुछ नोट करते जा रहे हैं। पाइप ढेर-ढेर सा धुआं उड़ाता जा रहा है। मुस्कुराते हुए फिर बोलना शुरू करते हैं।

यही तो यंगमैन जैसी बात है। आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे ही देखो। बेकार है सोचकर युनाइटेड नेशन से चला आया। यू.एन.ओ. आजकल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। नहीं तो उससे पैसा लेकर अपना आर्गनाइजेशन अच्छी तरह चलाया जा सकता है। हमने तो इस खदान मजदूरों की परियोजना के लिए आई.एल.ओ. से भी पैसे मांगे हैं। लगता है मिल जायेगा। पर यह नयी परेशानी पता नहीं कहां ले जाये। नागरिक कमेटी, उसके पहले रामू की घटना। दीपू के साथ घनिष्ठता को छोड़ दिया जाये तो भी रामू तो हमारी परियोजना में शामिल था। हमारा स्कूल, लड़कियों का शिक्षा केन्द्र इन सबमें उसका काफी सहयोग था। इसलिए हमारी परियोजना को लेकर ही बात उठ सकती है।

अब मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है। उठ ही सकती है। देखिए दीपू या रामू आपके काम से जुड़े हुए थे। दीपू तो आपके सीड का ही कर्मचारी था। इसलिए इनके मामले में आपकी जिम्मेदारी तो बनती ही है।

कारलेकर गम्भीर हो जाते हैंनहीं बनती है। क्योंकि दीपू अन्त तक हमारा कार्यकर्ता नहीं था।

क्या मतलब? क्या दीपू....

अपनी मृत्यु से लगभग एक महीना पहले उसने इस्तीफा भेज दिया था। पहले से ही कुछ समस्याएं थीं। मि. हार्डवेकर और दूसरे लोगों ने उससे बातचीत की थी। पर वे उसका दृष्टिकोण नहीं बदल पाये। इस्तीफा देने के बाद से वह हमारे स्कूल के मकान में भी नहीं रहता था। वह जाकर रामू की बस्ती में रहने लगा। इसलिए आफिशियली उसकी मृत्यु के मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।

देसाई फिर कंधे उचकाता हुआ बोला। मुझे मामले के बारे में अब तक जो भी रिपोर्ट मिली है उससे पता चलता है कि दीपू के साथ कुछ न कुछ होने वाला है, यह तो तय हो गया था। आप मि. सेन की बात कर रहे थे। उनके ग्रुप के तीन लड़के और लड़कियां हमारे प्रोजेक्ट में हैं। उन्होंने दीपू को पहले अपने साथ लिया पर अन्त में दीपू के विचारों से उनके विचार नहीं मिले। दीपू का काम हमारे प्रोजेक्ट के लक्ष्य के अनुरूप नहीं था। इसलिए प्रोफेसर खारेजा और मिसेज गुप्ता आदि भी उससे क्षुब्ध हो उठे। दीपू स्थानीय समस्याओं से, गूजरों के झमेले से, मजदूरी बढ़ाने के आंदोलन से, ट्रेड यूनियन से ...इन सबसे इस तरह जुड़ गया था...

कारलेकर मुझ पर नजर रख रहे थे आपसे कह रहा था न, क्रमशः वह अकेला पड़ता जा रहा था। असल में उसने राजनीति करनी शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि वह सेन के साथ था। सेन प्रोजेक्ट में राजनीति नहीं घुसाता था। दीपू ने ऐसा किया।

इसलिए सबको ऐसा लग रहा था कि उसे इस इलाके से हटा देने की जरूरत है।

देसाई ने सूत्र पकड़ा।

हम लोगों को तो उसने छोड़ ही दिया था। सेन ने भी उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। गूजर लोग तो इस काम से यूं ही नाराज थे। और ठेकेदार, दलाल तो दीपू के हर काम के खिलाफ थे। दीपू को उसके वे बिहारी भैया लोग बचा सकते थे पर वे लोग इमिग्रेंट कम्युनिटी हैं। अनआर्गनाइज्ड लेबर हैं। इस तरह जुलूस के दिन दीपू पर हमला होगा यह तो तय हो चुका था। हो सकता है दीपू को भी यह पता हो...और बस

पर रामू ...?

मि. कारलेकर की मेज पर एक चपरासी आकर प्लेन का टिकट रख जाता है।

उपन्यास

'एक तयशुदा मौत'

मोहित राय

परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ से शीघ्र प्रकाश्य

भिखमंगे !

मनबहकी लाल

●

भिखमंगे आये
नवयुग का मसीहा बनकर,
लोगों को अज्ञान, अशिक्षा और निर्धनता से मुक्ति दिलाने।
अद्‌भुत वक्तृता, लेखन-कौशल और
सांगठनिक क्षमता से लैस
स्वस्थ-सुदर्शन-सुसंस्कृत भिखमंगे आये
हमारी बस्ती में।
एशिया-अफ्रीका-लातिनी अमेरिका के
तमाम गरीबों के बीच
जिस तरह पहुंचे वे यानों और
वाहनों पर सवार,
उसी तरह आये वे हमारे बीच।
भीख, दया, समर्पण और भय की
संस्कृति के प्रचारक
पुराने मिशनरियों से वे अलग थे,
जैसे कि उनके दाता भी भिन्न थे
अपने पूर्वजों से।
अलग थे वे उन सर्वोदयी याचकों से भी
जिनके गांधीवादी जांघिये में
पड़ा रहता था
(और आज भी पड़ा रहता है)
विदेशी अनुदान का नाड़ा।

●

भिखमंगे आये
अलग-अलग टोलियों में।
कुछ ने अपने पश्चिमी वैभवशाली दाताओं की महिमा
बखानी,
तो कुछ का दावा था कि वे
लुटेरों को उल्लू बनाकर
रकम ऐंठ लाये हैं
जनहित के लिए और
जनक्रान्ति की तैयारी के लिए
कुछ का कहना था कि
क्रान्ति की तैयारियों का भारी बोझ
न पड़े इस देश की गरीब जनता पर
इसलिए उन्होंने भीख से
संसाधन जुटाने का नायाब तरीका अपनाया है।
कुछ का कहना था
कि क्रान्ति अभी बहुत दूर है
इसलिए वे तब तक कुछ सुधार ही
कर लेना चाहते हैं,
संवार देना चाहते हैं
दलितों-शोषितों-वंचितों का जीवन
एक हद तक
और फीस के तौर पर, बिना नेता-नौकरशाह
बनने का पाप किये,
खुद भी जुटा लेना चाहते हैं
घर, गाड़ी वगैरह कुछ अदना-सी चीजें
और अगर खुद वे आ गये हैं
जनता की खातिर इस नर्क जैसे देश में
तो क्या इतना भी चाहना अनुचित है
कि उनके बेटे-बेटी शिक्षा पायें
अमरीका में?
कुछ का कहना था कि
अशिक्षा ही हमारे दुर्भाग्य का मूल है
अतः वे हमें शिक्षित करने आये हैं,
स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन के बारे में
बताने आये हैं।
कुछ का कहना था कि
हम सहकारी संस्था बनाकर
उत्पादन करें
तो हल हो जायेंगी हमारी
सारी दिक्कतें।
कुछ ने कहा कि
जो ट्रेड-यूनियनें न कर सकीं,
वे वह कर दिखायेंगे,
राज्यसत्ता तो चांद मांगना है,
वे हमें चवन्नी-अठन्नी के लिए
नये सिरे से लड़ना सिखायेंगे।
कुछ ने कहा कि दोष
कोर्ट-कचहरी-कानून और
सरकार का नहीं
हमारे गंवारपन का है
अतः वे हमें हमारे अधिकारों,
संविधान और श्रम-कानूनों के बारे में
पढ़ायेंगे

और जब हम जान जायेंगे कि
हमें सरकार से क्या मांगना है
तो हम मांगेंगे एक स्वर से
और हमारी याचना के तुमुलनाद
से जागकर, डरकर,
सरकार हमें दे देगी वह सब कुछ
जो हम चाहेंगे।

●

भिखमंगों ने हमें लताड़ा
कि यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियां
पूरी नहीं करती
तो हम उसका मुंह क्यों जोहते हैं?
यदि वह नौकरियां नहीं देती
तो हम खुद क्यों नहीं कर लेते
कुछ काम-धाम?
यदि वह सभी कारखानों को
पूंजीपतियों को दे रही है
और पूंजीपति हमें रोजगार नहीं दे रहे
तो हम स्वयं मिलकर क्यों नहीं
शुरू कर लेते कोई उद्यम
और फिर भी नहीं चलता काम
तो कम क्यों नहीं कर लेते
अपनी जरूरतें?
बन्द क्यों नहीं कर देते
ऊपर की ओर देखना?
चरम पर्यावरणवादी बन
चले क्यों नहीं जाते
प्रकृति की गोद में निवास करने?

●

भिखमंगों ने बेरोजगार युवाओं से
कहा"तुम हमारे पास आओ,
हम तुम्हें जनता की सेवा करना सिखायेंगे,
वेतन कम देंगे
पर गुजारा-भत्ता से बेहतर होगा
और उसकी भरपाई के लिए
'जनता के आदमी' का
ओहदा दिलायेंगे,
स्थायी नौकरी न सही,
बिना किसी जोखिम के
क्रान्तिकारी बनायेंगे,
मजबूरी के त्याग का वाजिब
मोल दिलायेंगे।"
"रिटायर्ड, निराश, थके हुए क्रान्तिकारियो,
आओ, हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बतायेंगे।
वामपंथी विद्वानो, आओ
आओ सबआल्टर्न वालो,
आओ तमाम उत्तर मार्क्सवादियो,
उत्तर नारीवादियो वगैरह-वगैरह
आओ, अपने ज्ञान और अनुभव से
एन.जी.ओ. दर्शन के नये-नये शस्त्र और शास्त्र रचो,"
आह्वान किया भिखमंगों ने
और जुट गये दाता-एजेंसियों के लिए
नई रिपोर्ट तैयार करने में।

●

भिखमंगों ने भीख को नई गरिमा दी,
भूमण्डलीकरण के दौर में
उसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दी।
भिखमंगों ने क्रान्ति और बदलाव की
नई परिभाषाएं रचीं।
भिखमंगों ने कहा"भूल जाओ
'पैबन्द और कुर्ते का गीत' *
वह पुराना पड़ चुका है।
हम मांगकर लाते रहेंगे तुम्हारे लिए पैबन्द
तुम उन्हें सहेजना,
उन्हें जोड़कर एक दिन तैयार हो जायेगा
एक पूरा का पूरा कुर्ता।
भूख से तड़पते हुए मर जाओगे
यदि समूची रोटी चाहोगे।
हम तुम्हारे लिए मांगकर लाते रहेंगे
रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े,
तुम उन्हें खाते जाओ
एक दिन तुम्हारे पेट में होगी
एक साबुत रोटी।
मत करो बातें सारे कारखाने
और कोयला और खनिज और
मुल्क की हुकूमत पर कब्जे की,
ऐसी कोशिशें असफल हो चुकीं।"
हम पूछते हैं व्यग्र होकर,
"आखिर कब तक चलेगा
इस तरह"
वह तर्जनी उठाकर हमें रोकते हैं,
"हम एक अर्जी लिख रहे हैं।"
फिर वे एक रिपोर्ट लिखते हैं,
फिर चिन्तन करते हैं,
फिर दौरा करने किसी और दिशा में
चल देते हैं।
हम पाते हैं, भिखमंगे नहीं वे
अपहरणकर्ता हैं
बदलाव के विचारों के, स्वप्नों और आशाओं के।
आत्मा की ऊष्मा के खिलाफ
सतत सक्रिय
शीत की लहर हैं ये भिखमंगे।

---

* 'पैबन्द और कुर्ते का गीत'ब्रेष्ट की प्रसिद्ध कविता का सन्दर्भ

परिशिष्ट-1

साम्राज्यवाद का विनाश करो!
विश्व सामाजिक मंच (WSF) को बेनकाब करो!
समाजवादी विश्व ही विकल्प है!

साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता

मुम्बई में 19-20 जनवरी को आयोजित सम्मेलन के लिए जारी अपील का अंश

...साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण को लागू करने में जुटी साम्राज्यवादी देशों की विभिन्न संस्थाएं साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण तथा युद्ध के विरुद्ध विश्व जनता के विकसित हो रहे संघर्षों से घबराई हुई हैं और पुरजोर प्रयास कर रही हैं कि यह संघर्ष साम्राज्यवादी व्यवस्था को ही चुनौती देने की दिशा में विकसित न हो जाए। अपने प्रभाव के पारंपरिक वाहकों, यानि विभिन्न किस्म के प्रतिक्रियावादियों के चहरे से नकाब उठ जाने के कारण, प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए वाहक तैयार किये जा रहे हैं। पूंजीपतियों के परखे हुए प्रतिनिधि - यूरोप के सामाजिक जनवादी, साम्राज्यवादी देशों की वित्तीय संस्थाएं और उनके द्वारा बनाये गए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ, जिन्हें पहले स्वयंसेवी संस्थाएं कहा जाता था और अब नागरिक समाज - सिविल सोसायटी - संगठनों का नाम दिया जा रहा है) तथा ब्राजील की सामाजिक जनवादी वर्कर्स पार्टी ने इस "पवित्र" जिहाद में पहल की है। हर रंग के संशोधनवादी और किसिम-किसमि के प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवाद के सेवकों की अपनी चिथड़ी वर्दियां पहने हुए साम्राज्यवादियों और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कृपालु नजर के तहत इसमें शामिल होने के लिए उमड़े पड़ रहे हैं। इस संस्था का नाम है विश्व सामाजिक मंच (वर्ल्ड सोशल फोरम) और इसके खेल का नाम है "मानवीय चेहरे के साथ भूमण्डलीकरण"।

विश्व सामाजिक मंच सभी शक्तियों के मिलने का खुला स्थान होने का दावा करता है परन्तु इसमें भाग लेने से वे शक्तियां प्रतिबन्धित हैं जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन तरीकों से लड़ रही हैं, जिन्हें सरकारें पसन्द नहीं करतीं। इसका लक्ष्य है नागरिक समाज जहां न हल होने वाले अन्तर्विरोधों को, परस्पर विरोधी वर्गों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाकर, हल किया जायेगा, और उनका यह समाज, साम्राज्यवाद से मुक्त एक नए समाज, यानि समाजवादी दुनिया के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरे के हुए कल के इस जाली नोट को दुनिया के भविष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई का मंच नहीं है। बल्कि, कार्रवाई करने को तो यह मंच सख्ती से प्रतिबन्धित करता है। इसका प्रयास है कि प्रतिक्रियावादी शासकों को कुछ आश्वासनों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हीं शासकों को जो जनता के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यह ऊपर से किए जा रहे भूमण्डलीकरण का विरोधी है और जनता के माध्यम से भूमण्डलीकरण चाहता है, परन्तु इसका यह भूमण्डलीकरण भी साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण ही है। साम्राज्यवादियों के गन्दे काम की धुलाई-सफाई की व्यवस्था की जा रही है। इनका दावा है कि यह इस व्यवस्था को उन लोगों की भागीदारी के साथ बेहतर चला सकते हैं जो स्वयं इस व्यवस्था के सताए हुए हैं। सतही सुधारों के माध्यम से शोषित जनता की स्वीकृति निर्मित की जा रही है। वास्तविक उद्देश्य उन लोगों पर विजय पाने का है जो साम्राज्यवाद के वर्तमान हमले के विरुद्ध संघर्ष में कूद रहे हैं ताकि वे उन शक्तियों से न जुड़ जाएं जो साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया के विरुद्ध निरन्तर व सतत् संघर्ष कर रहे हैं। विकल्पों को सीमित किया जा रहा है ताकि समाजवाद को नकारा जा सके तथा प्राप्त किए जा सकने वाले उद्देश्यों के नाम पर पराजितों की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी अलग दुनिया अर्थहीन शब्दाडम्बर है और फंसाने के लिए एक खतरनाक फन्दा है। विश्व सामाजिक मंच पर साम्राज्यवाद की काली छाया मंडरा रही है और इसे क्रांतिकारी, प्रगतिशील, जनवादी तथा देशभक्त शक्तियां संघर्ष को बढ़ाने के लिए नए रूप में नहीं ढाल सकतीं। अतः हम साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया के विरुद्ध संघर्ष की पक्षधर सभी वास्तविक शक्तियों का आह्वान करते हैं कि वे विश्व सामाजिक मंच को छोड़ कर बाहर आएं और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करें।

विश्व सामाजिक मंच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गैर सरकारी संस्थाओं का इसकी प्रक्रिया पर पूरा प्रभुत्व है। इन संस्थाओं को साम्राज्यवाद की विभिन्न एजेंसियों द्वारा पैसा दिया जाता है। स्वयंसेविता, इसके इतिहास व भूगोल पर सैद्धान्तिक चर्चा का यहां कोई मतलब नहीं है। सीधी-सी बात यह है कि जिन गैर-सरकारी संस्थाओं का विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया में भूमिका है, उन सभी को विदेशों व सरकार से धन प्राप्त हो रहा है। जो शक्तियां जनता की गरीबी, दरिद्रता तथा उजड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्ही स्रोतों से, तीसरी दुनिया के देशों में गरीबों की सेवा करने के लिए, दसियों हजार करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है? ये उन साम्राज्यवादियों से पैसा लेकर पर्यावरण की रक्षा का झण्डा उठाती हैं जो पर्यावरण के विनाश के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ये राजसत्ता के व्यर्थ हो जाने का झण्डा बुलन्द करती हैं ताकि जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों से जनता का ध्यान हटाया जा सके जबकि ये खुद उसी सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न समितियों की सदस्य बनी रहती हैं। संघर्ष की भाषा का प्रयोग करते हुए यह संघर्ष कर रही शक्तियों पर ही हमला बोलती हैं और इस तरह संघर्ष की ज्वालाओं पर पानी के छींटे मारने का प्रयास करती हैं। जनता के संघर्षों को यह छोटे-छोटे तबकों के संघर्ष के रूप में बांट देती हैं और इन तबकों को एक दूसरे के विरुद्ध भिड़ा देती हैं ताकि वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध जनता की बढ़ती एकता को बाधित किया जा सके। मूलतः इनका

फौरी कार्य साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादियों को मिल रहे झटकों को रोकना है और इनका दीर्घकालीन उद्देश्य साम्राज्यवाद के आधार को मजबूत करना है। जहां साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित नीतियों के कारण जनता पर अभाव और दुख दर्द का प्रकोप बढ़ता है, वहां ये कुकुरमुत्ते की तरह उग आती हैं। क्रांतिकारी और जनवादी शक्तियों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे इन संगठनों के साम्राज्यवाद विरोधी दिखावों को बल मिले। हम सभी का आह्वान करते हैं कि विदेशों और सरकार से धन प्राप्त करके काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के षडयंत्र को समझें और इनके जाल में फंसने से बचें।

अन्य तीसरी दुनिया के देशों की तरह भारत के प्रतिक्रियावादी शासक भी साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित नीतियों को लागू कर रहे हैं जिससे मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्गों पर बोझ बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों, उत्पीड़ित जातियों, आदिवासियों और महिलाओं पर दमन बढ़ रहा है। मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकशों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात को छिपाने और साम्राज्यवाद की अपनी सेवा को और सुगम बनाने के लिए ये जनता को संकीर्ण आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं।

ऐसी परिस्थियों में निम्नलिखित जन संगठनों ने मुम्बई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि साम्राज्यवाद और प्रतिक्रिया के विरुद्ध संघर्ष की सही प्रक्रिया रेखांकित की जा सके, विश्व सामाजिक मंच तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रभुत्व के प्रति अपना रवैया स्पष्ट किया जा सके, तथा इस बात का स्पष्ट रूप से बयान किया जा सके कि साम्राज्यवादी दुनिया का विकल्प समाजवादी दुनिया ही है। किसी भी ऐसे प्रयास में जिसमें विश्व समाजिक मंच तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रति स्पष्ट रुख नहीं अपनाया जाए, जनता को असमंजस में डालने का खतरा बना रहेगा और इससे जनता में दुश्मनों के प्रति भ्रम पैदा होगा जिसका लाभ दुश्मनों को ही होगा। कोई भी समझौतापरस्त या अवसरवादी रुख समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के उद्देश्य को हानि पहुंचाएगा। *साम्राज्यवाद के विरुद्ध* जनता के रूप में हम लोग स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि हम विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया के विरुद्ध हम अपने विचारों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करते।

हम सभी देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हों और साम्राज्वाद के विरुद्ध हमारे संयुक्त संघर्ष को मजबूत करने के लिए इसमें अपने विचार व्यक्त करें। भविष्य जनता का है, साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादियों का नहीं। संघर्ष जनता की पहलकदमी से निर्धारित होगा, विदेशी पैसों से नहीं, यह वर्ग-संघर्ष से विकसत होगा, वर्ग-सहयोग से नहीं।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता

भागीदार : अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (ए.आई.के.एम.एस.), इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (इफ्टू), पीपुल्स आर्ट एण्ड लिटरेरी एसोसिएशन (पाला) तमिलनाडू, न्यू डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट (एन.डी.एल.एफ.) तमिलनाडु, बिगुल मजदूर दस्ता, दिशा छात्र संगठन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन (के.एल.ए.एस.), जन संघर्ष संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन, पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब, पी.डी.एस.यू., प्रोग्रेसिव यूथ लीग (पी.वाई.एल.), पी.ओ. डब्ल्यू., आन्ध्र प्रदेश, अरुणोदय, पी.एस.यू. पंजाब, नौजवान भारत सभा।

नोट :- सम्मेलन में उद्घाटन सत्र समेत चार सत्र होंगे। हर सत्र का अलग विषय होगा। भागीदार संगठनों के प्रतिनिधि तथा कई प्रगतिशील बुद्धिजीवी सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

1. साम्राज्यवादी हमला और जनता का प्रतिरोध, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित नीतियों तथा साम्राज्यवादी हमलों का असर।

2. साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष - दिशा तथा भटकाव।

3. एक अलग दुनिया साम्राज्यवादी विश्व ही हो सकता है।

परिकल्पना प्रकाशन की आगामी पुस्तकें (शीघ्र प्रकाश्य)

दुश्मन मक्सिम गोर्की का नाटक
चुनी हुई कहानियां गोर्की, तीसरा खंड
एक तयशुदा मौत उपन्यास- मोहित राय
न्गूगी वा थ्योंगो के लेख और साक्षात्कार
उपन्यास और जन समुदाय राल्फ फाक्स
आज की इराकी कविताएं
इंतिफादा : आज की फलस्तीनी कविताएं
तरुणाई का तराना उपन्यास याङ मो
मदन मोहन का कहानी संग्रह
भगतसिंह के लेखों, दस्तावेजों की पांच पुस्तिकाएं
नौजवानों से दो बातें पीटर क्रोपोटकिन

राहुल फाउण्डेशन के आगामी प्रकाशन (शीघ्र प्रकाश्य)

पार्टी जीवन और कार्यशैली के बारे में माओ त्से-तुङ
(एक बेहद जरूरी संकलन)
सेलेक्टेड रीडिंग्स (हिंदी में) माओ त्से-तुङ
सोवियत अर्थशास्त्र की आलोचना माओ त्से-तुङ
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का परिचय डी र्याजानोव
धर्म के बारे में मार्क्स-एंगेल्स
धर्म के बारे में लेनिन
पार्टी कार्यकर्ताओं की शिक्षा लेनिन
डब्ल्यूएसएफ : साम्राज्यवाद का नया ट्रोजन हॉर्स
(एक महत्वपूर्ण संकलन)

परिशिष्ट-2

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण एवं युद्ध के खिलाफ मुम्बई प्रतिरोध 2004 क्यों

(एक अंश)

जनता के संघर्ष ही कुंजी हैं

एम.आर. 2004 भूमण्डलीकरण के खिलाफ हर तरह के विरोध और प्रतिरोध को अपनाने के लिए खुले दिमाग से तैयार है पर इसकी समझ यह है कि लम्बे दौर में सुस्पष्ट आधारों पर और किसी भी लाग-लपेट के बिना जनता के संघर्ष ही एक नई विश्व व्यवस्था में न्याय, समानता और मुक्ति की कुंजी है। डब्ल्यूएसएफ जनता के संघर्षों, को कुछ मुद्दों पर सत्ता के केन्द्रों पर दबाव बनाने (लॉबी करने) का पर्यायवाची बना देता है, जिसमें किसी उसूल के सवाल से कोई लेना-देना नहीं होता और कुछ 'ईमानदार नौकरशाहों' के प्रयास भी परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। दूसरी ओर, एम.आर. 2004 एक सच्चे जनवाद के तहत जनता की सत्ता की अहमियत मानते और समझते हुए लोगों को सक्रिय रूप से गोलबन्द करना, कतारों को लामबंद करना, नेतृत्व जनसंगठनों के मातहत होना, खास कर के समाज के सबसे ज्यादा उत्पीड़ित व हाशिये पर फेंक दिये गये तबकों के हाथ में होनायह सब भूमण्डलीकरण के खिलाफ और बेहतर दुनिया के लिए जरूरी समझता है।

संघर्षों के रूप, जनता और परिस्थितियां तय करती हैं। जुझारूपन, आंदोलन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

एम.आर. 2004 का मानना है कि वैश्वीकरण के खिलाफ जंग लम्बी और दीर्घकालीन किस्म की होगी। यह अनेक मोर्चों और अनेक रूपों में लड़ी जायेगी। यह विभिन्न जुझारू लामबन्दियों का समर्थन करता है और उनका पक्ष लेता है। एम.आर. 2004 का मानना है कि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आज के विभिन्न जुझारू जन-आंदोलनों से ही मिल रही है। सिएटल, मेलबोर्न व जेनोआ की सड़कों पर हुई जंग, फलस्तीनी जनता का इंतिफादा, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया आदि के साम्राज्यवाद परस्त तानाशाही के सफल तख्तापलट, चियापास, नेपाल, कोलम्बिया, फिलीपीन्स, भारत, पेरू, तुर्की इत्यादि में वहां के मूल निवासियों एवं जनजातियों के लोगों के अपनी अस्मिता के लिए तथा अपने प्राकृतिक क्षेत्रों/इलाकों के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष, अमरीकी कब्जे का इराकी जनता द्वारा बढ़ता प्रतिरोधये सभी आज साम्राज्यवादी वैश्वीकरण का जन-आंदोलनों द्वारा प्रतिरोध की सबसे अहम मिसाल है। इसी के साथ, एम.आर. 2004 का यह भी मानना है कि प्रतिरोध का प्रत्येक रूप, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न मालूम होता हो, अगर विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का कमजोर करता हो, तो उसे अपनाया जाना चाहिए। समानता, न्याय और मुक्ति को हासिल करने के लिए हम संघर्ष के ऐसे किसी भी रूप को खारिज नहीं करते जो स्थितियों की मांग के अनुरूप हों। इस मायने में हम डब्ल्यूएसएफ से अलग हैं क्योंकि वह सैनिक संगठनों और ''राजनीतिक कार्रवाइयों के माध्यम के रूप में किसी की जान लेने वालों'' को बाहर रखते हुए दक्षिण अमेरिका के जुझारू आंदोलनों के बहुत बड़े हिस्सों को अपने खेमे से अलग कर रहा है। एम.आर. 2004 का मानना है कि न्याय, समानता और मुक्ति को हासिल करना प्रमुख उद्देश्य है। अपनी इस वैकल्पिक अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए जनता विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार संघर्ष का तरीका चुनती है। संघर्ष के रूपों के आधार पर किसी भी तरह का प्रतिबंध साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ उठ खड़ी होने वाली शक्तियों को विभाजित ही करेगा।

दूसरी दुनिया इस पूंजीवादी व्यवस्था के बाहर ही बनानी है, यह जनता की दुनिया होगीजो समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होगी!

''एक और दुनिया संभव है'' के रूप में डब्ल्यूएसएफ अमूर्त और अस्पष्ट धारणा उछालता है। एम.आर. 2004 इसे निरर्थक समझता है। यह अपनी वैकल्पिक सामाजिक-आर्थिक अवधारणा को ठोस रूप से परिभाषित करने का प्रयास करता है जो ऐसी अवधारणा के रूप में खड़ी हो और जो विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय या पारराष्ट्रीय कम्पनियों जैसी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की संस्थाओं तथा साम्राज्यवाद के, किसी निरंकुश राज्य के नियंत्रण, प्रभुत्व व अधीनता से पूर्ण विच्छेद करे व मुक्त हो। एम.आर. 2004 का मानना है कि दूसरे अविकसित देशों की ही तरह भारत में भी आत्म निर्भर आर्थिक ढांचे को खड़ा करके एक सच्ची समाजवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हुए ही वृद्धि और समृद्धि के कीर्तिमान स्थापित किये जा सकेंगे। ऐसा ढांचा और ऐसी व्यवस्था साम्राज्यवाद को पूरी तरह अस्वीकार करके ही अस्तित्व में आ सकती है। एम.आर. 2004 की राय यह है कि बाजार की सत्ता तथा उसके पीछे खड़े निरंकुश राज्य के खिलाफ जनवादी संघर्ष तथा अनवरत संघर्ष के जरिए ही नया ढांचा या नयी व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। इसके लिए विषमता पर आधारित मौजूदा पूंजीवादी ढांचे पर सीधा-सीधा आक्रमण करना होगाइस निश्चय के साथ कि हमें जनता की सहभागिता वाले जनवाद की ओर आगे बढ़ना है। अवश्य ही यह अंतहीन बहसों से संभव नहीं है, जो अक्सर अर्थहीन भी होती हैं।

ऊपर वर्णित सोच से आप समझ सकते हैं कि एम.आर. 2004 एक साथ आये इतने सारे संगठन मुंबई में आयोजित होने वाले डब्ल्यूएसएफ के कार्यक्रम के समानान्तर अपना आयोजन क्यों करने जा रहे हैं। यह कोई डब्ल्यूएसएफ के विरोध में आयोजन नहीं है। बल्कि एम.आर. 2004 एक सुस्पष्ट और ठोस व्याख्या रखकर आयोजित किया जा रहा है, जो कि डब्ल्यूएसएफ उपर्युक्त किसी भी पहलू पर नहीं रखता। एम. आर. 2004 एक मजबूत और सच्चा साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन खड़ा करने को प्रतिबद्ध है।

परिशिष्ट-3

वर्ल्ड सोशल फोरम का चार्टर

1. डब्ल्यूएसएफ विचारशील चिंतन, विभिन्न विचारों के बीच जनतांत्रिक वाद-विवाद, प्रस्तावों के सूत्रीकरण, अनुभवों के बेरोकटोक आदान-प्रदान और कारगर कार्रवाई के लिए नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) के उन समूहों और आंदोलनों को आपस में जोड़ने वाला एक खुला मंच है, जो नव-उदारवाद और पूंजी तथा साम्राज्यवाद के किसी भी रूप के वर्चस्व के विरोधी हैं, और मानवजाति के बीच तथा मानवजाति एवं पृथ्वी के बीच फलप्रद रिश्ते कायम करने की दिशा में निर्दिष्ट एक ग्रहीय समाज का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. पोर्तो एलेग्रे का वर्ल्ड सोशल फोरम दिक् और काल में सीमाबद्ध एक आयोजन था। अब इसके आगे, पोर्तो अलेग्रे में उद्घोषित इस अवश्यंभाविता कि "एक दूसरी दुनिया संभव है" के मद्देनजर यह विकल्पों की तलाश एवं उनका सृजन करने वाली एक प्रक्रिया बन गया है, जिसे महज उन आयोजनों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो इस प्रक्रियाको मजबूती प्रदान करते हैं।

3. वर्ल्ड सोशल फोरम एक वैश्विक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत होने वाली सभी मीटिंगों का एक अंतरराष्ट्रीय आयाम होता है।

4. वर्ल्ड सोशल फोरम में प्रस्तावित विकल्प भीमकाय बहुराष्ट्रीय निगमों और सरकारों, तथा राष्ट्रीय सरकारों की मिलीभगत से इन निगमों की सेवा में जुटी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के विरोध में खड़े होते हैं। इन विकल्पों का खाका इस तरह तैयार होता है कि एकजुटता का भूमण्डलीकरण विश्व इतिहास में एक नयी मंजिल के आगमन को सुनिश्चित करे। यह (भूमंडलव्यापी एकजुटता) सार्वभौमिक मानवाधिकारों का, और सभी राष्ट्रों एवं परिवेशों रहने वाले नागरिकों कासभी स्त्रियों एवं पुरुषों कासम्मान करेगी तथा यह सामाजिक न्याय, समानता और जनगण की संप्रभुता की सेवा करने वाली अंतरराष्ट्रीय जनतांत्रिक व्यवस्था एवं संस्थाओं पर आधारित होगी।

5. वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया के सभी देशों के केवल नागरिक समाज के संगठनों एवं आंदोलनों को एक साथ लाता है एवं उन्हें आपस में जोड़ता है, लेकिन यह विश्व नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय बनने की मंशा नहीं रखता।

6. वर्ल्ड सोशल फोरम की सभाएं वर्ल्ड सोशल फोरम को एक निकाय मानकर उसके एवज में विचार-विमर्श नहीं करतीं। इसलिए, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह फोरम के किसी संस्करण की ओर से इस रूप में विचार व्यक्त करने का दावा करे जैसे कि वे सभी भागीदार संगठनों के विचार हैं। फोरम के किसी भागीदार को, चाहे मतदान के जरिए या हाथ उठा कर अनुमोदन करके, सभी को, या बहुमत वचनबद्ध बनाने वाली घोषणाओं या प्रस्तावों पर एक निकाय के रूप में निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। और जिसे एक निकाय के रूप में फोरम की अवस्थिति के रूप में स्थापित किया जाए। इस प्रकार यह (फोरम) सत्ता का कोई केंद्र नहीं है जहां मीटिंगों के दौरान भागीदार विवाद करें, न ही यह (फोरम) इसमें भागीदारी करने वाले संगठनों तथा आंदोलनों द्वारा कोई कार्रवाई करने या आपस में संबंध कायम करने वाला एकमात्र विकल्प है।

7. इतना ही नहीं, फोरम की मीटिंगों में भाग लेने वाले संगठनों या संगठनों के समूहों को इन सभाओं के दौरान, चाहे अकेले या अन्य भागीदारों के साथ समन्वय स्थापित कर, घोषणाओं या कार्रवाईयों के बारे में निर्णय तक पहुंचने के लिए विचार-विमर्श का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए।

8. वर्ल्ड सोशल फोरम एक बहुलवादी, वैविध्यपूर्ण, गैर-संगठनात्मक (non-confessional), गैर सरकारी एवं गैर पार्टी संदर्भ/मंच है जो एक विकेंद्रिकृत तरीके से एक दूसरी दुनिया बनाने के लिए स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाइयों में जुटे संगठनों और आंदोलनों को आपस में जोड़ता है।

9. वर्ल्ड सोशल फोरम हमेशा बहुलवाद और क्रियाकलापों की विविधता तथा इसमें शामिल होने वाले संगठनों एवं आंदोलनों के काम करने के तरीकों की विविधिता के प्रति खुला रहेगा, साथ ही यह लिंगों, जातियों, संस्कृतियों, पीढ़ियों और शारीरिक क्षमताओं की विविधता के प्रति भी खुला रहेगा, यदि वे सिद्धांतों के इस चार्टर का पालन करते हैं। पार्टी प्रतिनिधि और सैन्य संगठन फोरम में शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार के प्रतिनिधियों या विधायिकाओं के उन सदस्यों का जो इस चार्टर की वचनबद्धताओं को स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत हैसियत से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

10. वर्ल्ड सोशल फोरम अर्थव्यवस्था, इतिहास और विकास के सभी सर्वसत्तावादी और अपचयनवादी (reductionist) विचारों का तथा राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण के लिए हिंसा का सहारा लेने का विरोधी है। यह मानवाधिकारों, वास्तविक जनवाद के अमल, भागीदारी जनवाद, शांतिपूर्ण रिश्ते, जनगणों, जातियों, लिंगों और लोगों के बीच समानता एवं एकजुटता का सम्मान करता है तथा वर्चस्व के सभी रूपों एवं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की अधीनता की भर्त्सना करता है।

11. वाद-विवाद के एक फोरम की तरह, वर्ल्ड सोशल फोरम, विचारों का एक आंदोलन है जो विचारशीलता को बढ़ावा देता है, और पूंजी के वर्चस्व की कार्यप्रणाली एवं उसके औजारों और उस वर्चस्व का प्रतिरोध करने एवं उस पर काबू पाने के तरीकों और कार्रवाइयों के बारे में, और पूंजीवादी भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया अपने नस्लवादी, लिंगभेदवादी और पर्यावरणीय विनाशकारी आयामों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देशों के भीतर जो बेदखली और असमानताओं की समस्याओं को जन्म दे रही है, उसके समाधान के लिए प्रस्तावित विकल्पों के बारे में उभर कर आए चिंतनों के निष्कर्षों के पारदर्शी ढंग से प्रचार-प्रसार का फोरम है।

12. अनुभवों के आदान-प्रदान के एक फ्रेमवर्क की तरह, वर्ल्ड सोशल फोरम अपने भागीदार संगठनों और आंदोलनों के बीच समझदारी और एक-दूसरे को मान्यता देने को प्रोत्साहित करता है, खासकर लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए एवं प्रकृति का सम्मान करने

के लिए, वर्तमान में एक भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आर्थिक गतिविधि एवं कार्रवाई का जो केंद्र समाज निर्मित कर रहा है, इन सब मसलों पर भागीदार संगठनों एवं आंदोलनों के बीच आपसी आदान-प्रदान को विशेष महत्व देता है।

13. अंतरसम्बंधों के एक संदर्भ की तरह, वर्ल्ड सोशल फोरम समाज के संगठनों एवं आंदोलनों के बीच नये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जन्म देने एवं उसे मजबूत बनाने की कोशिश करता है। यह निजी एवं सार्वजनिक जीवन के दोनों क्षेत्रों में जिस अमानवीकरण की प्रक्रिया से दुनिया गुजर रही है और राज्य जिस तरह हिंसा का सहारा ले रहे हैं उसके अहिंसक सामाजिक प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाएगा, और इन आंदोलनों एवं संगठनों की कार्रवाई द्वारा अपनाए जा रहे मानवीय साधनों को मजबूती प्रदान करेगा।

14. वर्ल्ड सोशल फोरम एक प्रक्रिया है जो इसमें भागीदार संगठनों एवं आंदोलनों को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी कार्रवाईयों को अवस्थित करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि विश्व नागरिकता के मुद्दे, और वैश्विक एजेंडे पर परिवर्तन हेतु प्रेरक क्रियाकलापों का प्रवर्तन करता है, जो एकजुटता के क्षेत्र में एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रयोगरत है।

(वर्ल्ड सोशल फोरम की सांगठनिक समिति में शामिल संगठनों द्वारा 9 अप्रैल, 2001 को साओ पाउलो में पारित एवं स्वीकृत तथा 10 जून, 2001 वर्ल्ड सोशल फोरम की अंतरराष्ट्रीय परिषद द्वारा संशोधनों के साथ पारित।)

परिशिष्ट-4

वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए धन कहाँ से आया

डब्ल्यूएसएफ अपनी फंडिंग के स्रोतों की बाबत पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा, डब्ल्यूएसएफ के ढांचे, जहां पर बहुत से संगठन अर्द्ध स्वायत्त तरीके से गतिविधियों को संचालित करते हैं,को देखते हुए समस्त गतिविधियों के लिए सभी दाता एजेंसियों द्वारा मुहैया कराये जाने वाले धन की शिनाख्त करना लगभग असंभव है।

अ. डब्ल्यूएसएफ सचिवालय के लिए निधियां

निकाय के तौर पर डब्ल्यूएसएफ को कुछ धन सीधे तौर पर मुहैया कराया जाता है। डब्ल्यूएसएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची धनराशि का ब्यौरा नहीं बताती।

डब्ल्यूएसएफ पार्टनर्स, डब्ल्यूएसएफ 2001:

ड्रोइट्स एट डेमोक्रेती : यह कनाडा के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाने वाला फाउंडेशन है।

फोर्ड फाउंडेशन

हाइनरिख बोल फाउंडेशन : यह जर्मनी में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जर्मन ग्रींस पार्टी का है, जिसके नेता जर्मनी के विदेश मंत्री युगोस्लाविया और अफगानिस्तान पर थोपे गये युद्धों के सक्रिय समर्थक थे।

आईसीसीओ : यह नीदरलैंड की सरकार और यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त एक अंतर चर्च संगठन है।

ल मोंद डिप्लोमतीक

आक्सफैम

आरआईटीएम-रेडे डि इनफार्मेकोस पारा ओ टेरेसेरो सेटा

रियो ग्रांडे डो सुल की राज्य सरकार

पोर्तो अलेग्रे का नगर प्रशासन

डब्ल्यूएसएफ पार्टनर्स 2002 :

आरआईटीएस, ईईडी, सीसीएफडी, एनओवाईबी, आक्सफैम जीबी, सेंट्रो नोर्टे सुल, एक्शन एड, आईसीसीओ, फंडाकाओ फोर्ड, गवर्नो दो एस्तादो डि रियो ग्रांडे दो सुल, प्रिफेटुरा डि पोर्टो अलेग्रे, प्रोसर्ग्स, वर्ल्ड फोरम फार अल्टरनेटिव्स।

डब्ल्यूएसएफ प्रतिभागियों के लिए फंडिंग

वस्तुतः दाता एजेंसियों की वित्तीय भूमिका डब्ल्यूएसएफ की तरह के उनके चंदों में प्रतिबिंबित हो सकने वाली भूमिका के मुकाबले काफी बड़ी है। क्योंकि इन्हीं एजेंसियों ने उन विभिन्न संगठनों को भी धन मुहैया कराया जिन्होंने डब्ल्यूएसएफ में हिस्सा लिया और वहां पर अपनी गतिविधियां आयोजित कीं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित सूची फोर्ड फाउंडेशन वेबसाइट डाटाबेस से ली गई है:

1. फोर्ड फाउंडेशन डब्ल्यूएसएफ और संबंधित अभियानों को अनुदान देता है (फोर्ड फाउंडेशन वेबसाइट डाटाबेस से; जाहिरा तौर पर ताजा फंडिंग शामिल नहीं है)।

फोर्ड के "निर्माण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम" के तहत निम्नलिखित अनुदान दिये गये जो "निम्न आय के व्यक्तियों और समुदायों की वित्तीय, प्राकृतिक, सामाजिक और मानवीय परिसम्पत्तियों के निर्माण में मदद के जरिये गरीबी और अन्याय को कम करने के प्रयत्नों को समर्थन देता है।"

संगठनः **ब्राजीलियाई एनजीओ का एसोसिएशन**
उद्देश्यः 2003 वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए; जहां पर सिविल सोसायटी के संगठन भूमण्डलीकरण के मौजूदा पैटर्नों के लिए मानवाधिकारों और टिकाऊ विकास पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकल्पों को विकसित करते हैं।
स्थानः ब्राजील
कार्यक्रमः शांति एवं सामाजिक न्याय
यूनिटः शासन और सिविल सोसायटी
विषयः सिविल सोसायटी
धनराशिः पांच लााख डालर

संगठनः **एनजीओ का ब्राजीलियाई एसोसिएशन**
उद्देश्यः जनवरी 2001 में ब्राजील के पोर्तो अलेग्रे में डब्ल्यूएसएफ की पहली बैठक के संगठन के लिए सहयोग
स्थानः ब्राजील
कार्यक्रमः शांति और सामाजिक न्याय
विषयः सिविल सोसायटी
धनराशिः एक लाख डालर

संगठनः **ब्राजीलियन कंज्यूमर डिफेंस इंस्टीट्यूट**
उद्देश्यः डब्ल्यूएसएफ और पैन-अमेजोनियन सोशल फोरम में मल्टीमीडिया सार्वजनिक सूचना अभियान के लिये।
स्थानः ब्राजील
कार्यक्रमः परिसम्पत्ति निर्माण और सामुदायिक विकास
यूनिटः सामुदायिक और संसाधन विकास
विषयः पर्यावरण और विकास
धनराशिः 30 हजार डालर

संगठनः **फेमिनिस्ट स्टडीज एंड असिस्टेंस सेंटर**
उद्देश्यः द्वितीय वर्ल्ड सोशल फोरम के दौरान मूलतत्ववादी कठमुल्लासूत्रों के खिलाफ अभियान को समन्वित करने के लिए
स्थानः ब्राजील
कार्यक्रमः शांति और सामाजिक न्याय
यूनिटः मानावाधिकार
विषयः मानवाधिकार
धनराशिः 65,600 डालर
संगठनः **इंटरन्यूज इंटरएक्टिव, आईएनसी**
उद्देश्यः भूमण्डलीकरण पर ब्रिज इनिशिएटिव के लिए, यह वर्ल्ड सोशल फोरम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिभागियों के लिये संचार के साधन मुहैया कराने वाली टेलीविजन एजेंसी आर्टिकल जेड के साथ सहयोग-सहकार है।
स्थानः सैन राफैल, कैलिफोर्निया
कार्यद्दमः शांति और सिविल सोसायटी
विषयः सिविल सोसायटी
धनराशिः 153,000 डालर

वर्ल्ड सोशल फोरम मीडिया सेंटर के प्रायोजक

परोक्ष फंडिंग का एक और उदाहरण है डब्ल्यूएसएफ मीडिया सेंटर।

तथाकथित स्वतंत्र मीडिया केंद्र (सिरांडा) के प्रायोजक थे ले मोंदे डिप्लोमेटिक और इंटर प्रेस सर्विसेज। गौरतलब है कि इंटर प्रेस सर्विसेज खुद निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित है।
स कनाडा की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा (सीआईडीए) ● सीडीजी (Carl Buisberg Gesellschaft)जर्म्मनी ● चार्ल्स स्टीवर्ट मॉट फाउंडेशन (अमरीका) ● डेनमार्क का विदेश मंत्रालय ● यूरोपीय संघ ● फिनलैंड का विदेश मंत्रालय ● संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्यसंगठन (एफएओ) ● फोर्ड फाउंडेशन (अमरीका) ● एफईएस (Freidrich Dbert Stiftung)जर्म्मनी ● जर्मनी का आर्थिक विकास और सहयोग मंत्रालय (बीएमजेड) ● जी 77 (77 का समूह) ● अंतरराष्ट्रीयश्रम संगठन (आईएलओ) ● इटली का विदेश मंत्रालय ● मैकार्थर फाउंडेशनअमरीका ● नीदरलैंड का विदेश मंत्रालय ● नीदरलैंड का अंतरराष्ट्रीय विकास एवं सहयोग संगठन (नोविब) ● यूरोपीय परिषद (नॉर्थ साउथ सेंटर) ● नार्वे की विकास एजेंसी (नोराद) ● नार्वे का विदेश मंत्रालय ● हेलसिंकी विश्वविद्यालय का छात्र संघ ● स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (सीडा) ● यूनीसेफ ● यूनीफेम ● यूएनडीपी ● यूनेस्को ● यूनेप ● यूएनएफपीए ● डब्ल्यू आल्टन जोंस फाउंडेशन (अमरीका)

3.चंदों के दूसरे स्रोत

पोर्तो अलेग्रे में पहले वर्ल्ड सोशल फोरम में मौजूद निर्वाचित अधिकारियों ने डब्ल्यूएसएफ के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संसद सदस्यों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क गठित करने पर सहमति जाहिर की। यूरोपीय संसद में संयुक्त वाम के अध्यक्ष फ्रांसिस वुट्र्ज ने बताया, यह सिद्धांत अंगीकार किया गया कि यूरोपीय संसद, संसदीय नेटवर्क के वित्तपोषण समेत उसके सभी तकनीकी पहलुओं के समन्वय की जिम्मेदारी उठायेगी।

बेहतर ज़िन्दगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है

घटिया साहित्य के घटाटोप और अपसंस्कृति के अंधेरे में उत्कृष्ट, स्तरीय, जनपक्षधर, क्रान्तिकारी, क्लासिकी साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने का एक अभियान

आम लोगों के लिए
जरूरी हैं वे किताबें
जो उनकी ज़िन्दगी की घुटन
और मुक्ति के स्वप्नों तक
पहुंचाती हैं विचार
जैसे कि बारूद की ढेरी तक
आग की चिनगारी।
घर-घर तक चिनगारी छिटकाने वाला
तेज हवा का झोंका बन जाना होगा
जिन्दगी और आने वाले दिनों का सच
बतलाने वाली किताबों को
जन-जन तक पहुंचाना होगा।

ऐसी किताबों को जन-जन तक पहुंचाना नये सर्वहारा नवजागरण-प्रबोधन का एक जरूरी कार्यभार है। वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने की मुहिम का एक अहम कदम है। बड़बोली विज्ञापनबाजी से दूर, 'जनचेतना' पिछले पन्द्रह वर्ष से चुपचाप इस अभियान में जुटी है।

'परिकल्पना प्रकाशन' **और** 'राहुल फाउण्डेशन' **के प्रकाशन प्रभाग की पुस्तकों का 'जनचेतना' मुख्य वितरक है।**

परिकल्पना प्रकाशन की प्रस्तुतियां

शहीदेआजम की जेल नोटबुक भगतसिंह
पृष्ठ : 204, मूल्य : रु. 60.00
विचारों की सान पर भगतसिंह के चुने हुए लेख और दस्तावेज
पृष्ठ : 104, मूल्य : रु. 25.00

मक्सिम गोर्की की आठ पुस्तकों की मंजूषा

मां (उपन्यास) पृष्ठ : , मूल्य : रु. 70.00
फोमा गोर्देयेव (उपन्यास) पृष्ठ : 256, मूल्य : रु. 55.00
अभागा (उपन्यास) पृष्ठ : 128, मूल्य : रु. 25.00
बेकरी का मालिक (उपन्यास) पृष्ठ : 110, मूल्य : रु. 25.00
तलछट (नाटक) पृष्ठ : 128, मूल्य : रु. 30.00

चुनी हुई कहानियां
खण्ड एक पृष्ठ : 168, मूल्यः रु. 35.00
खण्ड दो पृष्ठ : 264, मूल्य : रु. 55.00
खण्ड तीन शीघ्र प्रकाश्य

सृजन की प्रक्रिया और शिल्प के बारे में
पृष्ठ : 160, मूल्य : रु. 30.00
तोल्स्तोय : एक शब्दचित्र पृष्ठ : 80, मूल्य : रु. 20.00

अंतोन चेखव : चुनी हुई कहानियां
खण्ड एक : 40 रुपये, खण्ड दो : 40 रुपये
मार्क्सवाद और भाषाविज्ञान की समस्याएं
जे.वी. स्तालिन पृष्ठ : 48, मूल्य : रु. 15.00
निकोलाई आस्त्रोवस्की : जय जीवन!
पृष्ठ : 220, मूल्य : रु. 50.00
बेलिंस्की, हर्ज़न, चेर्नीशेव्स्की, दोब्रोल्युबोव
दर्शन, साहित्य और आलोचना पृष्ठ : 256, मूल्य : रु. 60.00
चिरस्मरणीय (उपन्यास) **निरंजन** पृष्ठ : 168, मूल्य : रु. 35
पांच कहानियां : पुश्किन मूल्य : रु. 20.00
दो अमर कहानियां : लू शुन मूल्य : रु. 20.00
श्रेष्ठ कहानियां : प्रेमचंद मूल्य : रु. 25.00
तीन कहानियां : गोगोल मूल्य : रु. 30.00
अब इंसाफ होने वाला है : शकील सिद्दीकी (सं.)
भारत और पाकिस्तान की प्रगतिशील उर्दू कहानियों का प्रतिनिधि संकलन। मूल्य : रु. 75.00
माओ त्से-तुङ की कविताएं राजनीतिक पृष्ठभूमि सहित विस्तृत टिप्पणियां एवं अनुवाद : **सत्यव्रत** मूल्य : रु. 20.00
इकहत्तर कविताएं और तीस छोटी कहानियां : बेर्टोल्ट ब्रेष्ट
मूल जर्मन से अनुवाद : **मोहन थपलियाल,** मूल्य : रु. 60.00
समर तो शेष है... इप्टा के दौर से आज तक के प्रतिनिधि क्रान्तिकारी समूहगीतों का अनन्य संकलन। मूल्य : रु. 35.00
मध्यवर्ग का शोकगीत : हान्स माग्नुस एंत्सेंसबर्गर
सम्पादन एवं अनुवाद : **सुरेश सलिल,** मूल्य : रु. 25.00
लहू है कि तब भी गाता है : पाश मूल्य : रु. 75.0
यह मुखौटा किसका है : विमल कुमार मूल्य : रु. 35.00
दुर्ग द्वार पर दस्तक : कात्यायनी मूल्य : रु. 50.00
माओवादी अर्थशास्त्र और समाजवाद का भविष्य
रेमण्ड लोट्टा, मूल्य : रु. 25.00
क्रान्ति का विज्ञान : लेनी वुल्फ मूल्य : रु. 10.00

राहुल फाउण्डेशन के प्रकाशन

उम्मीद एक ज़िन्दा शब्द है ('दायित्वबोध' के महत्वपूर्ण सम्पादकीय लेखों का संकलन) पृष्ठ : 224, मूल्य : रु. 60.00
एनजीओ : एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र
पृष्ठ : 104, मूल्य : रु. 25.00
कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र मूल्य : रु. 10.00
माओ त्से-तुङ : दर्शन विषयक पांच निबन्ध
पृष्ठ : 128, मूल्य : रु. 25.00
माओ त्से-तुङ : कला-साहित्य विषयक एक भाषण और पांच दस्तावेज पृष्ठ : 48 मूल्य : रु. 12.00
लेनिन : तोल्स्तोय के बारे में मूल्य : रु. 8.00
बोल्शेविक पार्टी का इतिहास पृष्ठः 352 मूल्य : 80/-
Mao Tse-tung : Selected Readings
A selection of Mao's most important articles.
Pages : 508 Price : Rs. 65.00
माओ त्से-तुङ की रचनाओं के उद्धरण मूल्य : रु. 35.00
Quotations from Mao Tse-Tung 40/-

लेनिन की नौ पुस्तकें

समाजवाद और युद्ध मूल्य : रु. 10.00
साम्राज्यवादः पूंजीवाद की चरम अवस्था मूल्य : रु. 25.00
राज्य और क्रान्ति मूल्य : रु. 25.00
सर्वहारा क्रान्ति और गद्दार काउत्स्की (शीघ्र प्रकाश्य)
दूसरे इण्टरनेशनल का पतन मूल्य : रु. 10.00
गांव के गरीबों से मूल्य : रु. 10.00
मार्क्सवाद का विकृत रूप तथा साम्राज्यवादी अर्थवाद 10/-
कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा मूल्य : रु. 10.00
पार्टी साहित्य और पार्टी संगठन लेनिन मूल्य : रु. 15.00

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद वी. अदोरात्सकी मूल्य : रु. 15.00
राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त (दो खण्ड)
(दि शंघाई टेक्स्टबुक आफ पोलिटिकल इकॉनमी) हर खण्ड : रु. 60.00
बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने के बारे में
चाङ चुन-चियाओ मूल्य : रु. 3.00
अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन अल्बर्ट रीस विलियम्स रु. 75.00
दायित्वबोध पुस्तिका श्रृंखला
अनश्वर हैं सर्वहारा संघर्षों की अग्निशिखाएं मूल्य : रु. 10/-
समाजवाद की समस्याएं, पूंजीवादी पुनर्स्थापना और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति मूल्य : रु. 12.00
क्यों माओवाद मूल्य : रु. 10.00
बिगुल पुस्तिकाएं
अक्टूबर क्रान्ति की मशाल 12/-
पेरिस कम्यून की अमर कहानी : 12/-
कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढांचा लेनिन 5/-
मकड़ा और मक्खी विल्हेल्म लीब्कनेख्त 3/-
ट्रेडयूनियन काम के जनवादी तरीके सेर्गेई रोस्तोवस्की 3/-
मई दिवस का इतिहास 5/-

पूरी पुस्तकसूची व पुस्तकें मंगाने के लिए सम्पर्क करें :

जनचेतना

● डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020 ● काफी हाउस के पास, हजरतगंज, लखनऊ (शाम 5 से 8.30) ● जाफरा बाजार, गोरखपुर-273001 ● 989, पुराना कटरा, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद ● 29, यूएनआई अपार्टमेंट, सेक्टर-11, वसुंधरा, गाजियाबाद ● जनचेतना ठेला, चौड़ा मोड़, नोएडा (शाम 5 से 8.30)
ग्राम भदईपुरा, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर
email : janchetna@rediffmail.com

ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन ही नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी है

इतिहास और राजनीतिशास्त्र की पुस्तकें

रोमिला थापर

सोमनाथ : इतिहास एक, स्वर अनेक 165.00/75.00

प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास 485.00 /175.00

द्विजेंद्र नारायण झा

भारतीय सामंतवाद 750.00

प्राचीन भारत 265.00/60.00

अयोध्या सिंह

हिंदुस्तान का स्वाधीनता आंदोलन और कम्युनिस्ट 225.00

फासीवाद 575.00

भारत का मुक्ति संग्राम 850.00/250.00

रॉल्फ मिलीबैंड

पूंजीवादी समाज में राजसत्ता 450.00

इरफ़ान हबीब

भारतीय इतिहास की व्याख्याएं और उसकी प्रमुख दृष्टियां (प्रकाश्य)

भारतीय इतिहास में मध्यकाल (संशोधित) 350.00

रोडनी हिल्टन (सं.)

सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण 250.00/125.00

हेरॉल्ड जे. लास्की

कम्युनिस्ट घोषणापत्र 200.00

राजनीति का व्याकरण 850.00/250.00

अमर्त्य सेन

अतीत का वर्तमान : भारतीय इतिहास के अध्ययन का संदर्भ 150.00

मुरली मनोहर प्रसाद सिंह

समाजवाद का सपना 650.00

स्वामी सहजानंद सरस्वती

खेत मजदूर और झारखंड के किसान 225.00

मेरा जीवन संघर्ष 550.00/200.00

क्रांति और संयुक्त मोर्चा 350.00/125.00

किसान कैसे लड़ते हैं? 50.00

वी.आई. लेनिन

साम्राज्यपाद : पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था 225.00/60.00

मार्क्स और एंगेल्स

कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 20.00

कार्ल मार्क्स

गोथा कार्यक्रम की आलोचना 50.00

टी. बी. बॉटमोर

समाजशास्त्र : समस्याओं और साहित्य का अध्ययन 475.00/175.00

जे.डी. बरनाल

विज्ञान की सामाजिक भूमिका 985.00

लिओ ह्यूबर्मन

मनुष्य की लौकिक संपदा 350.00/125.00

दामोदर धर्मानंद कोसंबी

मिथक और यथार्थ 450.00

जी.वी. प्लेखानोव

मार्क्सवाद की मूल समस्याएं 125.00

माइकेल विज़ेल

आर्यों के भारतीय मूल की कल्पना: इतिहास में मिथक का सृजन 225.00

कृष्णकान्त मिश्र

समाजवादी चिंतन का इतिहास (तीन भागों का सेट) 1650.00

देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय

प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज 750.00

समीर अमीन

विश्वीकरण के युग में पूंजीवाद 225.00

आर्थर मारविक.

इतिहास का स्वरूप 350.00

रजनी पाम दत्त

आज का भारत (अनु. रामविलास शर्मा) 850.00/250.00

फासीवाद और सामाजिक क्रांति 450.00

विश्व का राजनीतिक परिदृश्य 375.00

अलेक्जेंडर आई. चिचेरोव

मुगलकालीन भारत की आर्थिक संरचना 450.00

हरबंस मुखिया

फ्युडलिज्म और गैरयूरोपीय समाज 350.00

सुमित सरकार

बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 650.00/200.00

सामाजिक इतिहास लेखन की चुनौती 625.00

ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद

भारत का स्वाधीनता संग्राम 850.00/250.00

दीपक कुमार

प्रौद्योगिकी और भारत में अंग्रेजी राज 525.00

के.एन. पणिक्कर

औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक और विचारधारात्मक संघर्ष 325.00

आर्नल्ड हाउजर

कला का इतिहास दर्शन 500.00

अंतोनियो ग्राम्शी

सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन के बुनियादी सरोकार 985.00/250.00

विस्तृत जानकारी के लिए लिखें

ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बी-7, सरस्वती कामप्लेक्स, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092

दायित्वबोध

हिन्दी में अपने ढंग की अकेली पत्रिका

हर अंक में संग्रहणीय सामग्री

पिछले अंकों में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण सामग्री

नवम्बर'95–फरवरी'96

• साम्राज्यवाद आज भी कागजी बाघ है (भूमंडलीकृत पूंजीवाद के चरित्र और उसके अन्तर्निहित संकट का विस्तृत विश्लेषण) • सर्वहारा अधिनायकत्व के युग में अर्थनीति और राजनीति : *लेनिन* • जनवादी केन्द्रीयता का सवाल : *माओ त्से-तुङ* • शिखर पर रुदन : आत्मविश्लेषण और आत्म आलोचना से आत्म-भर्त्सना तक पश्चिम की विचारयात्रा • माओ और सुरजीत पातर की कविताएं • आइजेंस्टाइन और *'पूंजी'* पर फिल्म बनाने की योजना

मार्च–अगस्त 1996

• माओवादी नियोजन का सिद्धान्त और व्यवहार : एक स्वप्नदर्शी और व्यावहारिक समाजवाद के पक्ष में • भाषा, इतिहास और वर्ग संघर्ष • आज के दौर में नारीवादी लेखन : कुछ अहम सवाल, कुछ बुनियादी समस्याएं • *हावर्ड फास्ट के विश्वविख्यात उपन्यास* 'दि अमेरिकन' के अंश

सितम्बर–अक्टूबर 1996

• मार्क्स और पर्यावरण • क्रान्ति का विज्ञान • विज्ञान, कला और अधिरचना—*एमिल बर्न्स* • ताचाई की कहानी • 'जनवाद' का विभ्रम और सर्वहारा अधिनायकत्व

नवम्बर'96–फरवरी'97

समाजवाद के सिद्धान्त और प्रयोग, समस्याओं और चुनौतियों पर *विशेष सामग्री*

• माओ के अमर अवदान और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की युगान्तरकारी शिक्षाएं • स्तालिन : एक मूल्यांकन • स्तालिन के समय में सोवियत समाजवाद • रूसी क्रान्ति का मूलभूत अभिप्राय—*रोजा लक्ज़ेमबर्ग* • सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति क्या, क्यों और किस प्रकार • सोलहसूत्रीय सर्कुलर • सांस्कृतिक क्रान्ति के सैद्धान्तिक आधार के बारे में—*जार्ज थामसन* • कला में विचारधारात्मक अन्तर्वस्तु और यथार्थवाद पर मार्क्स-एंगेल्स • पाब्लो नेरूदा और माओ त्से-तुङ की कविताएं

मार्च–जून 1997

• मजदूर आन्दोलन पर कुछ सवाल • पेरिस कम्यून की महान शिक्षाएं • सर्वहारा अधिनायकत्व की विजय अमर रहे • सूचना क्रान्ति का सच

जुलाई–अक्टूबर 1997

• एक ऐतिहासिक विश्वासघात और उसके बाद की अंधकारमय अर्द्धशताब्दी • माओवादी अर्थशास्त्र और समाजवाद का भविष्य • चाङ चुन-चियाओ का लेख: बुर्जुआ वर्ग पर सर्वतोमुखी अधिनायकत्व लागू करने के बारे में • सेर्गेई आइजेंस्ताइन कला का मनोविज्ञान • मार्क्सवाद के विरोध में ''नव'' दक्षिणपंथी लोकरंजकतावाद के नये-नये मिथक

नवम्बर '97–फरवरी '98

बेर्टोल्ट ब्रेष्ट की अट्ठाइस कविताएं व ब्रेष्ट पर मोहन थपलियाल का लेख • गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों और दाता एजेंसियों का असली चरित्र • मदर टेरेसा और उनके उत्तराधिकारियों का ''मिशन'' : सेवा का सच • महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दस्तावेज • माओ त्से-तुङ की कविताएं

मार्च–जून 1998

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांगेस में प्रस्तुत रिपोर्ट • 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष लेख • ग्राम्शी का लेख 'बुद्धिजीवी' • पूंजीवाद की पूंजीवादी समालोचना के निहितार्थ • मदर टेरेसा : मिथक और यथार्थ • शशि प्रकाश की पच्चीस कविताएं

जुलाई–दिसम्बर 1998

ब्रेष्ट, लोर्का और रॉबसन की जन्मशती के अवसर पर विशेष सामग्री :

• बेर्टोल्ट ब्रेष्ट और उनका थियेटर • लोर्का की कविताएं • लोर्का पर नेरूदा की कविता • रॉबसन पर नाजिम हिकमत की कविता • उत्तर- औपनिवेशिक सिद्धान्त और 'उत्तर' -अवस्था : *एजाज अहमद* • गैर सरकारी संगठनों का असली मिशन • भूण्डलीकरण और सामाजिक विज्ञान • माओकालीन चीन में मार्क्सवाद : *जार्ज थामसन* • हेनरिख हाइने, फर्डिनांड फ्रेलिग्राथ, जार्ज वेयेर्थ और पाब्लो नेरूदा की कविताएं

जुलाई–सितम्बर 1999

• स्वयंसेवी संगठनों और दाता-एजेंसियों का नेटवर्क : एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र • तीसरी दुनिया में कृषि-अनुसंधान का ढांचा • भारतीय क्रान्ति व कृषि प्रश्न • बेर्टोल्ट ब्रेष्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक कृति 'थियेटर का एक संक्षिप्त तर्कशास्त्र'

अक्टूबर–दिसम्बर 1999

• जनता के सांस्कृतिक आन्दोलन की चुनौतियां • 'बीसवीं सदी की दूसरी महानतम क्रान्ति और उसकी प्रासंगिकता' • बुर्जुआ से सर्वहारा क्रान्ति की ओर : *जार्ज थामसन* • मूलाधार और अधिरचनाओं के सम्बन्ध के बारे में : *वोलोशिनोव* • विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम • *इस्तवान मेस्जारोस* की चर्चित कृति 'बियॉण्ड कैपिटल' की समीक्षा

जनवरी–मार्च 2000

• कम्युनिस्ट घोषणापत्र की स्मृति में : *अंतोनियो लाब्रियोला* और *रेमंड लोट्टा* के महत्वपूर्ण लेख • जार्ज लुकाच के विरोध में : *ब्रेष्ट* • कहां हैं हमारी भाषा के वे कारीगर हाथ : *आलोक श्रीवास्तव* • माओवादी चीन में स्त्रियां • महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दस्तावेज और लेख • नजरुल की कविता 'विद्रोही'

जुलाई–सितम्बर 2000

आपातकाल के कुछ अनुत्तरित यक्ष-प्रश्न और हमारा समय • *हांस आइसलर* का लेख एक नई संगीत संस्कृति के निर्माता • समाजवादी काल में वर्ग संघर्ष के नियम • स्त्री मुक्ति का राजनीतिक अर्थशास्त्र

जनवरी–मार्च 2001

इतिहास के लिए कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव •औपनिवेशिक भारत में लोकभाषाओं एवं लिपियों का शिक्षा व्यवस्था से निष्कासन • सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्याओं पर माओ का लेख • राष्ट्रीय प्रश्न पर जार्ज थामसन का लेख • 'मजदूर वर्गीय संगीत की समस्याएं'—हांस आइसलर • महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दस्तावेज

जुलाई–सितम्बर 2001

भारतीय कृषि का संकट और नरोदवादी-राष्ट्रवादी ''मार्क्सवाद'' • शेयर बाजार—एक मार्क्सवादी विश्लेषण : फ्रेडरिक एंगेल्स, हरपाड़ बराड़, तापस चक्रवर्ती, सत्यम वर्मा और प्रो. अरुण कुमार के लेख • निरंकुश दमनकारी राज्यतंत्र की ओर धकेलती आर्थिक नीतियां • 'सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्याएं ' की आलोचना—माओ त्से-तुङ • खाद्यान्न की वैश्विक राजनीति

अक्टूबर 2001–मार्च 2002

• दक्षिण एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद की चुनौती • अफगानिस्तान और उसके बाद • एन.जी.ओ. : साम्राज्यवाद के चाकर • एन.जी.ओ. की सैद्धान्तिकी और व्यवहारशास्त्र के बारे में हमारी समझ कैसे बनी?

जुलाई–सितम्बर 2003

• मार्क्सवाद पर अंबेडकर के विचार • इराक : मदमत्त हाथी फिर दलदल में • साम्राज्यवाद के बारे में • पश्चिम एशिया : शान्ति की शर्त फलस्तीन की आजादी • पूंजीवादी निवेश के कारण तबाह हो रहे हैं गरीब किसान • स्तालिन के निधन के पचास वर्ष बाद • दूरसंचार का निजीकरण

पत्रिका के पुराने अंकों के लिए लिखें :
प्रत्येक अंक का मूल्य : पन्द्रह रुपए

खत्म करो पूंजी का राज!
लड़ो, बनाओ लोक स्वराज!

गांव–गांव में अलख जगाकर
विदेशी लूट मिटाएंगे
देशी कफनखसोटों को भी
लड़कर मार भगाएंगे
कसम शहीदों की भारत में
लोक स्वराज बनाएंगे

...''देश के इतिहास के ऐसे मोड़ पर, जब समय के गर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव के बीज पल रहे हैं, हम पूंजीवादी जनतंत्र की खर्चीली धोखाधड़ी और तथाकथित पंचायती राज के कपटपूर्ण शगूफे को सिरे से खारिज करने के लिए उन सबका आह्वान करते हैं जो इस व्यवस्था में छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और आवाज उठाने पर कुचले जा रहे हैं। इस व्यवस्था में जिनका कोई भविष्य नहीं है, वे ही नई व्यवस्था बनाने के लिए आगे आएंगे। उन्हें आगे आना ही होगा!

...सवाल आज विदेशी गुलामी बनाम स्वदेशी का नहीं है। बल्कि सवाल सम्पूर्ण पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और पूंजीवादी सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रणाली को ही नष्ट करने का है, जो अनैतिहासिक और मानवद्रोही हो चुकी है।

21वीं सदी में इतिहास के एजेंडे पर यही केन्द्रीय मुद्दा है। क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य का नारा उस पूंजीवादी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष का नारा है, जिसने देशी पूंजीपतियों की लूट के साथ ही साम्राज्यवादी देशों और उनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट के लिए देश के दरवाजे खोल दिये हैं।

क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान पूंजीवादी जनतंत्र के सभी स्वांगों और छल-छद्मों का भण्डाफोड़ करते हुए वर्तमान संसदीय प्रणाली को सिरे से खारिज करने का और सरकारी पंचायती राज के असलियत को समझने का आह्वान करता है।

क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान व्यापक परिवर्तन के हर मोर्चे पर सन्नद्ध होने के साथ-साथ गांव-गांव में, शहर के मुहल्लों और मजदूर बस्तियों में जनता की वैकल्पिक सत्ता के क्रान्तिकारी केन्द्रों के रूप में लोक स्वराज्य पंचायतों के गठन का आह्वान करता है।

हम जानते हैं कि, यह रास्ता लम्बा है। पर यही एकमात्र विकल्प है। यही इतिहास का रास्ता है। इसलिए हमारा यह संग्रामी संकल्प है कि ''लोक स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम हर कीमत पर उसे लेकर रहेंगे।''

दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, बिगुल मज़दूर दस्ता, देहाती मज़दूर यूनियन, नारी सभा और दायित्वबोध मंच की ओर से पिछले नौ वर्षों से चलाये जा रहे

क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान के पर्चा संख्या-4 के अंश

प्रमुख सम्पर्क : ● अभिनव सिन्हा, 33, रामजस कॉलेज हास्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ● जनचेतना ठेला, चौड़ा मोड़, नोएडा (शाम 5 से 8) ● सत्यम, 29, यू.एन.आई. अपार्टमेंट, सेक्टर11, वसुंधरा, गाजियाबाद ● पंकज, 33, सेक्टर 15, सोनीपत ● 256 एल, माडल टाउन, हरियाणा स्कूल के पास, सोनीपत ● जनचेतना डी-68, निरालानगर, लखनऊ ● 'आह्वान' कार्यालय, कल्याणपुर, गोरखपुर ● जनचेतना, जाफरा बाजार, गोरखपुर ● जनचेतना, 989, पुराना कटरा, युनिवर्सिटी रोड, मनमोहन पार्क, इलाहाबाद ● डा. दूधनाथ, शहीद पुस्तकालय, मर्यादपुर, मऊ ● प्रो. प्यारेलाल, 139, फुलबाग कालोनी, पंतनगर● जनचेतना, ग्राम भदईपुरा, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ईमेल : dayitvabodh@rediffmail.com